GEO IAS
It's about quality

Jan. 2024

जियो दैनिक

डेली करंट अफेयर्स

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET Economic Times.com

Contents

सामान्य अध्ययन I 14

1. गोवा के काकोडा में 10वीं सदी का एक कदंब शिलालेख मिला - द हिंदू 14
2. अदालतों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच में गंभीर अंतर: सुप्रीम कोर्ट - द हिंद 14
3. झेलम बेसिन में पर्माफ्रॉस्ट संरचनाओं का मानचित्रण किया गया - डाउन टू अर्थ 15
4. भारत का सबसे पुराना जीवित शहर गुजरात के वडनगर में मिलाद हिंदू - 16
5. ONGC ने महानदी बेसिन ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज कीं द इकोनॉमिक टाइम्स - 17
6. भारत के आधे से अधिक उपजिलों में वर्षा का स्तर बढ़ रहा है- - द हिंदू 17
7. भारतीय विवर्तनिक प्लेट दो भागों में विभाजित हो रही है इंडिया टुडे - 18
8. अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया - द हिंदू 19
9. ASI ज्ञानवापी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेवाराणसी जिला अदालत : - द हिंदू 21
10. गणतंत्र दिवस पर झारखंड की झांकी ने आदिवासी महिलाओं के कौशल का प्रदर्शन किया द प्रिंट - 21
11. भारत ने मराठाओं के 12 किलों को यूनेस्को धरोहर के लिए नामांकित किया - द हिंदू 22

सामान्य अध्ययन II 23

12. सरकार नई मनरेगा भुगतान प्रणाली से छूट दे सकती है - द हिंदू/केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी के भुगतान हेतु ABPS अनिवार्य की - इंडियन एक्सप्रेस 23
13. भारत और पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की- द हिंदू/भारत,पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया - इंडियन एक्सप्रेस 23
14. अधिक चीनी, नमक, वसा वाले भोजन पर 20-30% स्वास्थ्य टैक्स लगाया जा सकता है - द हिंदू.. 24
15. सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों का विरोध समाप्त हुआ - द हिंदू/ गृह सचिव से बातचीत के बाद ट्रक ड्राइवरों ने विरोध को समाप्त किया - इंडियन एक्सप्रेस 25
16. 'लोकसभा चुनाव से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है' - द हिंदू/ CAA नियम, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जा सकते है - इंडियन एक्सप्रेस 26
17. CEC, EC की नियुक्ति के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - द हिंदू/ CEC, EC की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती - इंडियन एक्सप्रेस 27
18. भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अनुवाद परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की - द हिंदू 27
19. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच को जारी रखा, हिंडनबर्ग के 'आचरण' पर प्रकाश डाला - द हिंदू/ सुप्रीम कोर्ट ने जांच को CBI को सौंपने वाली याचिका को खारिज किया - इंडियन एक्सप्रेस 28

20. प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया - इंडियन एक्सप्रेस 29

21. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने के संबन्ध में अदालतों को दिशानिर्देश दिए - इंडियन एक्सप्रेस 30

22. जेलों में जातिगत भेदभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू 31

23. स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की - द हिंदू 31

24. हिमाचल प्रदेश HC ने हाटी समुदाय को ST में शामिल करने पर रोक लगा दी - द हिंदू 33

25. सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी पन्नून की हत्या के साजिशकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की - द हिंदू 33

26. चुनाव आयोग ने नई पार्टियों को चुनाव चिह्न आवंटन के नियमों में बदलाव किया - द हिंदू 34

27. भारत, नेपाल ने दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए - इंडियन एक्सप्रेस 35

28. भारत पड़ोसी साझेदारों के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध: विदेश मंत्री - इंडियन एक्सप्रेस 35

29. लाल सागर संकट के कारण शिपिंग और बीमा लागत में वृद्धि - इंडियन एक्सप्रेस 36

30. शिक्षा मंत्रालय ने PRERANA कार्यक्रम लॉन्च किया - पीआईबी 37

31. केंद्र सरकार ने 'पृथ्वी(PRITHVI)' पहल को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस 37

32. जम्मू-कश्मीर में कोई स्थानीय निकाय सदस्य नहीं होगा - द हिंदू 38

33. भारत और सऊदी अरब ने हज समझौते पर हस्ताक्षर किए - इंडियन एक्सप्रेस 39

34. गृह मंत्री 'नेशनल पैक्स (PACS) मेगा कॉन्क्लेव' की अध्यक्षता करेंगे - द हिंदू 39

35. सरकार जल्द ही वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानदंडों की घोषणा करेगी - – द हिंदू/ सरकार वस्तुओं को गुणवत्ता मानक के तहत लाएगी: पीयूष गोयल - इंडियन एक्सप्रेस 40

36. केंद्र ने फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया - द हिंदू/ सरकार ने दवा निर्माण के नए मानकों को अधिसूचित किया - इंडियन एक्सप्रेस 40

37. 'कुकिस, ज़ोमिस को ST सूची से हटाने के लिए याचिका - द हिंदू 41

38. व्यक्ति केवल कानून के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार: सर्वोच्च न्यायालय - इंडियन एक्सप्रेस 42

39. विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना - द हिंदू 43

40. विनियमन से किसी विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति ख़त्म नहीं होती: CJI - द हिंदू/विनियमन किसी विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा ख़त्म नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस 43

41. मद्रास HC ने सांसदों और विधायकों के चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज की - द हिंदू 44

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

42. भारत, ब्रिटेन ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए - द हिंदू 44

43. गैर सरकारी संगठनों और संघों को FCRA पंजीकरण प्राप्त हुआ - द हिंदू 45

44. ब्रिटेन भारतीय सेनाओं के साथ प्रशिक्षण के लिए उन्नत नौसैनिक समूह भेजेगा - द हिंदू/ ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए हिंद महासागर में नौसेना जहाज भेजेगा: रक्षा सचिव - इंडियन एक्सप्रेस..... 46

45. WHO ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड का शुभारंभ किया - पीआईबी 46

46. मालदीव, चीन रणनीतिक सहयोग को 'बढ़ाने' पर सहमत - द हिंदू..... 47

47. दक्षिण अफ़्रीका ने इज़राइल के ख़िलाफ़ हेग न्यायालय में मामला दायर किया - द हिंदू/ दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के खिलाफ ICJ में मामला दायर किया - इंडियन एक्सप्रेस 48

48. विश्व पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट- 2024 जारी - हिंदुस्तान टाइम्स..... 48

49. इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर - द हिंदू/स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023: राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर - इंडियन एक्सप्रेस..... 49

50. मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया - द हिंदू 50

51. भारत में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीन अभियान की तैयारी - इंडियन एक्सप्रेस..... 51

52. SC ने CEC, EC की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार किया - द हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने/ CEC, EC की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया इंडियन एक्सप्रेस - 52

53. 2. SC ने केरल सरकार द्वारा दायर मुकदमे की जांच करने हेतु सहमति दी- द हिंदू..... 53

54. भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा: इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वार्ता - इंडियन एक्सप्रेस..... 54

55. रेल मंत्रालय ने उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया - द हिंदू..... 54

56. महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष का दलबदल पर फैसला - द हिंदू-..... 55

57. अयोध्या की मस्जिद 'ताजमहल से भी खुबसूरत और भव्य होगी :IICF - द हिंदू..... 56

58. त्रिपुरा सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु भूमि का आवंटन किया द हिंदू - 56

59. भारतरूस रणनीतिक साझेदारी को विकसित करने पर सहमत- - इंडियन एक्सप्रेस 57

60. सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भारत से जानकारी प्राप्त हुई अधिक कार्य की आवश्यकता:USTR- द हिंदू 57

61. लाल सागर शिपिंग संकट यूरोप में भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकता है इंडियन एक्सप्रेस - 58

62. गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA पंजीकरण रद्द किया द हिंदू -..... 58

63. ICMR ने NEDL को संशोधित करना शुरू किया द हिंदू - 59

64. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर फैसला सुनाया - इंडियन एक्सप्रेस..... 60

65. भारत के KABIL ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया द हिंदू - 61

66. पीएम-जनमन पैकेज का उद्देश्य PVTG का विकास करना - द हिंदू..... 61

67. आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिएभारत- द हिंदू : 62

68. आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिएभारत- द हिंदू : 63

69. सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा इंडियन एक्सप्रेस -..... 64

70. केंद्रीय मंत्री ने MPLADS ईसाक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया - पीआईबी-..... 64

71. मालदीव ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की द हिंदू/भारतीय विदेश - मंत्री ने मालदीव के विदेश से मुलाकात की - इंडियन एक्सप्रेस..... 65

72. अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण: पैनल लाभ के समान वितरण पर गौर करेगा - द हिंदू-..... 65

73. चीन ने नई मेगा पोर्ट परियोजना के साथ दक्षिण अमेरिका में व्यापार राजमार्ग का विस्तार किया द हिंदू - 66

74. चीनकिर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे- (CKU-R) परियोजना - इंडियन एक्सप्रेस..... 67

75. चीन, फिलीपींस तनाव कम करने पर सहमत द हिंदू/ चीन -, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर पर तनाव कम करने पर सहमत इंडियन एक्सप्रेस -..... 68

76. कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते - केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय: द हिंदू 68

77. आंध्र प्रदेश 'जाति जनगणना' करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना द हिंदू - 69

78. केंद्र ने अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा हेतु जाँच समिति बनाई इंडियन एक्सप्रेस - 70

79. भारत म्यांमार सीमा पर जल्द ही बाड़बंदी की जाएगी: गृह मंत्री - द हिंदू /अनधिकृत प्रवेश रोकने- हेतु भारत-म्यांमारसीमा पर बाड़बंदी की जाएगीगृह मंत्री - इंडियन एक्सप्रेस :..... 70

80. भारत जाम्बिया में तांबा खनन परियोजनाओं हेतु उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा इंडियन एक्सप्रेस - 71

81. ईदी अमीन द्वारा युगांडा से भारतीयों का निष्कासन एक गलती थीमुसेवेनी - द हिंदू : 72

82. WHO के विवाद निपटान निकाय के पुनरुद्धार में देरी हो रही है: GTRI - इंडियन एक्सप्रेस..... 72

83. प्रधानमंत्री ने सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की- द हिंदू/ पीएम ने 1 करोड़ परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की - इंडियन एक्सप्रेस..... 73

84. केंद्र की RoDTEP योजना पर दोबारा काम करने की कोई योजना नहीं - द हिंदू/ RoDTEP योजना पूरी तरह से WTO के अनुरूप: अधिकारी - इंडियन एक्सप्रेस 74

85. उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश घोषित किया - द हिंदू 75

86. मालदीव ने अपने जल क्षेत्र में चीनी जहाज के अनुसंधान से इनकार किया - द हिंदू/ मालदीव के जलक्षेत्र में जहाज कोई शोध नहीं करेगा: मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस 75

87. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगेद हिंदू - 76

88. तमिलनाडु कैबिनेट ने महिलाओं के लिए नई नीति को मंजूरी दी द हिंदू - 77

89. केंद्र का महत्वाकांक्षी AI मिशन जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी हेतु जा सकता है इंडियन एक्सप्रेस - 77

90. द्विपक्षीय संबंधों व क्वाड की तारीखों पर चर्चा हेतु शीर्ष अमेरिकी अधिकारी भारत आएंगे द हिंदू - 78

91. तुर्की ने स्वीडन की NATO सदस्यता के लिए समर्थन किया इंडियन एक्सप्रेस - 78

92. केंद्र ने कुष्ठ रोग के इलाज हेतु तीनदवा प्रणाली शुरू की- - द हिंदू 79

93. केंद्र का लक्ष्य 2024 तक सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना द हिंदू - 80

94. प्रस्तावित प्रसारण विधेयक से अति-नियंत्रण की चिंताएं बढ़ सकती है - द हिंदू 81

95. गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं का नेतृत्व -द हिंदू 82

96. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता HC को नोटिस जारी किया- इंडियन एक्सप्रेसइंडियन एक्सप्रेस 82

97. इजराइल अपनी रक्षा करना जारी रखेगा: इज़रायली प्रधानमंत्री- द इंडियन एक्सप्रेस 82

98. भारत, फ्रांस निगरानी संबंधों पर सहमत हुए - द हिंदू 83

99. अमेरिका ने विवाद निपटान को फिर से शुरू करने के नए प्रस्ताव को रोका - इंडियन एक्सप्रेस... 84

100. सरकार उच्च शिक्षा हेतु मान्यता प्रणाली में बदलाव की योजना बना रही है - इंडियन एक्सप्रेस 85

101. स्कूलों द्वारा EWS की रिक्त सीटों को आगे बढ़ाने से RTI उल्लंघन नहीं दिल्ली :HC- इंडियन एक्सप्रेस 85

102. केरल ने ओबीसी सूची को संशोधित करने हेतु केंद्र से SECC डेटा का अनुरोध किया - द हिंदू 86

103. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई सौर नीति का अनावरण किया द हिंदू/ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई - सौर नीति की घोषणा की - इंडियन एक्सप्रेस 87

104. तालिबान के विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ क्षेत्रीय संबंधों पर चर्चा की - इंडियन एक्सप्रेस 87

105. केंद्र सरकार ने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने हेतु NCRF नीति तैयार की - इंडियन एक्सप्रेस... 88

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

106. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं है: SC - द हिंदू 89

107. फिलीपींस, वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए - द हिंदू . 89

108. भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर - इंडियन एक्सप्रेस 90

सामान्य अध्ययन III 91

109. केंद्र सरकार ने ने MSP संबंधी चिंताओं को चिह्नित किया: तेल आयात बढ़ने से कम रिटर्न - इंडियन एक्सप्रेस 91

110. छह साल में 1,117 सीमा चौकियों पर 4G सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी: केंद्र - द हिंदू 91

111. NARCL के स्ट्रेस्ड खातों के अधिग्रहण में तेजी लाएं, धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित करें: वित्त मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस 92

112. भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाने हेतु सार्थक कार्रवाई को बढ़ावा दिया - द हिंदू 92

113. म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जल्द ही समाप्त होगी, भारत में प्रवेश हेतु वीजा की जरूरत होगी - द हिंदू/ भारत सरकार, म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की योजना बना रही है - इंडियन एक्सप्रेस 93

114. आरबीआई ने निष्क्रिय खातों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए - इंडियन एक्सप्रेस 94

115. स्पेसएक्स के रॉकेट से भारत का GSAT-20 लॉन्च होगा- द हिंदू/संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत स्पेसएक्स रॉकेट का उपयोग करेगा - इंडियन एक्सप्रेस 95

116. PMI सर्वेक्षण के मुताबिक दिसंबर में विनिर्माण घटकर 18 माह के निचले स्तर पर- द हिंदू/ विनिर्माण PMI दिसंबर में 18 महीने के निचले स्तर पर - इंडियन एक्सप्रेस 96

117. 'साइबर क्राइम के अधिकांश मामले चीन, कंबोडिया और म्यांमार से - द हिंदू 97

118. भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना SKA में शामिल होगा - पीआईबी 98

119. नया एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है - द हिंदू 98

120. शोधकर्ताओं ने मेटाबोलिक इंजीनियरिंग में प्रगति हासिल की - द हिंदू 99

121. भारतीय नौसेना ने मालवाहक जहाज को अपहरण होने से बचाया - द हिंदू 100

122. 'डीप टेक' नीति को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजी जायेगी - द हिंदू 101

123. इसरो ने अंतरिक्ष में ईंधन सेल-आधारित बिजली प्रणाली का परीक्षण किया - द हिंदू/इसरो ने ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया - इंडियन एक्सप्रेस 101

124. जीएसटी राजस्व राज्यों में उपभोग वृद्धि में असंगति को दर्शाता है - द हिंदू 103

125. आदित्य-L1 सफलतापूर्वक L1 कक्षा में स्थापित हो गया -द हिंदू/आदित्य-L1, अपनी अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया - इंडियन एक्सप्रेस 103

126. भारत में वेक्टर-जनित रोगों के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी करना जरुरी - हिन्दू................ 104
127. ज़ांज़ीबार में समुद्री शैवाल की खेती - डाउन टू अर्थ.. 105
128. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KRS जलाशय के पास खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया - द हिंदू 106
129. आय असमानता में गिरावट: भारतीय स्टेट बैंक - इंडियन एक्सप्रेस 106
130. वेब ब्लॉकिंग आदेशों में उल्लेखनीय वृद्धि - द हिंदू.. 107
131. सरकार ने व्यापारिक रूकावटें के समाधान हेतु टास्क फोर्स का गठन किया - इंडियन एक्सप्रेस / वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया - द इकोनॉमिक टाइम्स................ 108
132. चंद्रमा की 'स्टिकीनेस की खाड़ी' का पता लगाने हेतु नासा ने पेरेग्रीन लैंडर लॉन्च किया - इंडिया टुडे 109
133. अधिकांश भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार की जरूरत -द हिंदू...................................... 110
134. 'Ai संचालित गलत सूचना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा' - द हिंदू.. 111
135. ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट & सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी - द हिंदू.................................... 112
136. प्रत्यक्ष कर संग्रह 2023-24 के आंकड़े जारी - द हिंदू... 113
137. ग्रुप इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के लिए विधायी परिवर्तन की आवश्यकता : आरबीआई गवर्नर - इंडियन एक्सप्रेस.. 113
138. ग्लोबल पल्स कन्वेंशन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा -द हिंदू... 114
139. विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का टेलीस्कोप परियोजना हेतु हवाई का दौरा- इंडियन एक्सप्रेस 115
140. खुदरा मुद्रास्फीति दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर - द हिंदू... 116
141. भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर 8 महीने के निचले स्तर पर - द हिंदू....................... 117
142. पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की द हिंदू -................. 118
143. केंद्र सरकार किशोरियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगी द हिंदू -.......................... 118
144. भारतीय खाद्य निगम पारदर्शिता और सक्रिय दृष्टिकोण से काम करेगाखाद्य मंत्री - द हिंदू :....... 119
145. दिल्ली का AQI गंभीर, वाहनों और निर्माण कार्यों पर रोकइंडियन एक्सप्रेस -.............................. 120
146. भारतीय सेना दिवस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीं :शुभकामनाएं हिंदुस्तान टाइम्स -................ 121
147. डिजी यात्रा ऐप में सुरक्षा को लेकर शिकायतें द हिंदू -.. 121
148. फिनटेक SRO को विकासोन्मुख, स्वतंत्र होना चाहिए :RBI- इंडियन एक्सप्रेस 122
149. भारत की बहुआयामी गरीबी दर घटकर 11.28% हो गई इंडियन एक्सप्रेस -................................ 123

150. रक्षा मंत्रालय, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकाई के नेतृत्व में सर्वोच्च निकाय इंडियन एक्सप्रेस - 123

151. आरबीआई पैनल ने राज्य गारंटी के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव रखा इंडियन एक्सप्रेस - 124

152. ग्रीनलैंड में पहले की अपेक्षा अधिक बर्फ गिरी द हिंदू -.. 125

153. सरकार ने PLI योजना के तहत 4415 करोड़ रुपये वितरित किये इंडियन एक्सप्रेस - 126

154. GM सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगीसरकार - द हिंदू : 126

155. एयरबस और CSIR-IIP सतत विमानन ईंधन पर सहयोग करेंगे द हिंदू - 127

156. जापान चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पांचवां देश बना इंडियन एक्सप्रेस -.............................. 128

157. वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया इंडियन एक्सप्रेस -........................... 128

158. नासा के अंतरिक्ष यान ने चंद्रयान-3 लैंडर को पिंग किया द हिंदू - 129

159. अमृत धरोहर पहल से प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा द हिंदू -.. 130

160. NISAR मिशन जल्द ही लॉन्च होने की राह परनासा - द हिंदू : 131

161. सरकार ने IFSC में वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाया - द हिंदू.. 131

162. MNRE ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की - डाउन टू अर्थ 132

163. भारतीय शेयर बाजार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना - इंडियन एक्सप्रेस 133

164. सीमा सुरक्षा बल का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार द हिंदू - 133

165. बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी घाटा उच्च स्तर पर इंडियन एक्सप्रेस -... 134

166. फ्लैश इंडिया PMI के अनुसार जनवरी में निजी क्षेत्र कीऔद्योगिक और सेवा गतिविधियों में तेजी - द हिंदू 135

167. सफ्रान भारत में लड़ाकू विमान तकनीक हस्तांतरित करने को तैयार - द हिंदू............................ 136

168. अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दी - द हिंदू.. 137

169. लाल सागर संकट: भारतीय निर्यातकों ने केंद्र से अधिक ऋण का अनुरोध किया - द इंडियन एक्सप्रेस.. 138

170. केंद्र ने OMCs में FY24 पूंजी निवेश आधा कर दिया -द हिंदू बिजनेसलाइन 138

171. भारतीय परमाणु संयंत्रों से न्यूनतम रेडियोधर्मी निर्वहन: अध्ययन - द हिंदू................................ 139

172. सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण के-दायरे में लाया इंडियन एक्सप्रेस - 140

173. NIA ने नेशनल टेरर डेटाबेस फ़्यूज़न एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की - इंडियन एक्सप्रेस..... 141

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

174. EPFO ने "कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने" हेतु नया सर्वेक्षण शुरू किया - इंडियन एक्सप्रेस 141
175. दिल्ली HC ने GST के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों को बरकरार रखा - इकोनॉमिक टाइम्स142
176. IVF तकनीक से सफेद गैंडों को विलुप्त होने से बचाया जायेगा - इंडियन एक्सप्रेस 143
फैक्ट फटाफट 144
1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 144
2. 16वाँ वित्त आयोग 144
3. राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली 144
4. भारत का पहला पूर्णतः कन्या सैनिक स्कूल 145
5. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) 145
6. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) 145
7. चुनावी बॉण्ड 146
8. साल्टन सागर 146
9. **"न्यायपालिका की स्थिति" रिपोर्ट** 146
10. **एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन** 147
11. **सरना धर्म** 147
12. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** 147
13. **मनरेगा योजना** 147
14. **साइबर किडनैपिंग** 148
15. **भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC)** 148
16. **हट्टी समुदाय** 148
17. **नरसंहार कन्वेंशन 1948** 148
18. **कर्मन रेखा** 149
19. **वीवीपैट (VVPAT) मशीनें** 149
20. **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** 149
21. **शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्यधारा में लाने का दायरा (स्मार्ट) 2.0 कार्यक्रम** 150
22. **स्वदेश दर्शन 2.0 योजना** 150
23. **प्रोजेक्ट चीता** 150
24. **असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART)** 150
25. **वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली** 151

26. पॉलीगोनम चतुर्भुजनम 151
27. सिमिलिपाल काई चटनी 151
28. पूर्वोत्तर अफ़्रीकी चीता 151
29. आईएनएस चेन्नई 152
30. पृथ्वी पहल 152
31. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 152
32. कारगिल एएलजी पर नाईट लैंडिंग 153
33. प्रोजेक्ट वीर गाथा 153
34. सोहराई पेंटिंग 153
35. चंद्रा एक्स-रे वेधशाला 154
36. इंद्रायणी नदी 154
37. पलास फिश ईगल 154
38. तंजावुर डॉल 154
39. प्रथम अग्रिम अनुमान 155
40. ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य 155
41. बोब्बिली वीणा 155
42. आईडेक्स (iDEX) योजना 156
43. ट्राइकोडर्मा 156
44. भौगोलिक संकेत (GI) टैग 156
45. कारावास सजा में क्षमादान 156
46. चंद्रबी महोत्सव 157
47. सिसल पौधा 157
48. अग्निपथ योजना 157
49. अलीगढ आंदोलन 158
50. कॉकस सिस्टम 158
51. कोहरा 158
52. प्रसादम् 158
53. स्काई ड्यू 159
54. उग्रम 159
55. दृष्टि 10 'स्टारलाइनर' 159
56. गणतंत्र दिवस की झाँकियाँ 159
57. शास्त्रीय भाषा 160
58. स्पाइरल गैलेक्सी 160

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

59. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) 161
60. मछली रोग ऐप की रिपोर्ट 161
61. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) 161
62. कतील यक्षगान मेला 162
63. व्यायाम सी ड्रैगन-24 162
64. आइंस्टीन जांच (EP) 162
65. कालाराम मंदिर 163
66. युवा निधि योजना 163
67. वाइपर (VIPER) रोवर 163
68. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) योजना 164
69. HD 63433d 164
70. AN-32 विमान 164
71. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' 165
72. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 165
73. थर्टी मीटर टेलीस्कोप)TMT) 165
74. काबो वर्डे 165
75. हिमालयी वुल्फ (भेड़िया) 166
76. PM-eBus सेवा योजना 166
77. भारत का प्रथम डार्क स्काई पार्क 166
78. आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति)GEAC) 166
79. ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट (SGRTD) योजना 167
80. पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क)PNHZP) 167
81. कच्छी खरेक 168
82. बहुआयामी गरीबी 168
83. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि)PM-KISAN) 168
84. फ़ारसी भाषा 168
85. अप्रत्याशित टैक्स 169
86. 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल 169
87. एल नीनो और ला नीना 169
88. पैरामाइरोथेसियम इंडिकम 170
89. पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 170
90. पनामा नहर 170
91. नीली अर्थव्यवस्था 170

92. ग्रीनलैंड 171
93. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग)CCI) 171
94. स्टीडफ़ास्ट डिफेंडर 2024 171
95. डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर)DAT-SG) 171
96. तिरुवल्लुवर दिवस 172
97. क़नात प्रणाली 172
98. रोगाणुरोधक प्रतिरोध)AMR) 172
99. GM फसल 173
100. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 173
101. जगन्नाथ मंदिर 173
102. रोगाणुरोधक प्रतिरोध)AMR) 174
103. खेलो इंडिया योजना 174
104. गुरुवयूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर 174
105. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 175
106. कैडिसफ्लाइज़ 175
107. भारतीय गिद्ध 175
108. ग्लोबल एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्लिटी- 176
109. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 176
110. मधिका 176
111. मॉस्किटोफिश 177
112. कुमकी 177
113. टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल (THCBD) 177
114. वैक्सीन 'हेविश्योर 177
115. परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 178
116. अनुच्छेद 341 178
117. नवाचार के लिए महामारी की तैयारी का गठबंधन)CEPI) 178
118. एक्सरसाइज साइक्लोन 179
119. मत्स्य पालन पर FAO की समिति 179
120. फ़िलोबॉट 179
121. स्क्रब सन्निपात 180
122. कर्पूरी ठाकुर 180
123. मेलानिस्टिक टाइगर सफारी 180
124. अरामबाई तेंगगोल 180

125. भारत रत्न 181
126. बताद्रवा थान 181
127. रेटबा झील 181
128. भारतीय दंड संहिता)IPC) की धारा 420 182
129. यूरोपीय बंदरगाह एलायंस 182
130. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 182
131. पद्म पुरस्कार-2024 183
132. ब्लैक टाइगर सफारी (ओडिशा) 183
133. भूटान चुनाव 183
134. इकोवास (ECOWAS) 184
135. वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV) 184
136. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) 184
137. सपिंडा विवाह 184
138. पूजा स्थल अधिनियम, 1991 185
139. ग्रांथम शिलालेख 185
140. हम्बोल्ट एनिग्मा 185
141. नाइट्रोजन हाइपोक्सिया 185
142. अल्पेंग्लो 186
143. सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व 186
144. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) 186
145. शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद 187
146. नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) 187
147. स्नो लेपर्ड 187
148. अगस्त्यगमा किनारा 188
149. माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफ़ेक्टर F (MceF) 188
150. एक्सरसाइज -सदा तनसीक 188

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन I

1. गोवा के काकोडा में 10वीं सदी का एक कदंब शिलालेख मिला - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- चालुक्यों
- कदंब काल

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

समाचार:

- एक शिलालेख जो **कन्नड़** और **संस्कृत** में लिखा गया है और **10वीं शताब्दी ईस्वी** का बताया जाता है
- **दक्षिणी गोवा** के **काकोडा** में **महादेव मंदिर** में **कदंब काल** की खोज की गई है।

पृष्ठभूमि

- गोवा के **कदम्ब कल्याण** के **चालुक्यों** के अधीनस्थ थे ।
- **चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय** ने **राष्ट्रकूटों** को उखाड़ फेंकने में मदद के लिए **कदम्ब शास्तादेव** को गोवा का **महामंडलेश्वर** नियुक्त किया।
- **कदम्ब शास्त्रदेव** ने **960 ई.** में **शिलाहारों** से **चंदवारा शहर** पर विजय प्राप्त की।
- बाद में, उसने **गोपकपट्टन (वर्तमान गोवा)** के **बंदरगाह** पर विजय प्राप्त की।
- तलारा नेवय्या के **पुत्र गुंडैया** ने शायद इस लड़ाई में भाग लिया था, और अपने जीवन की कीमत पर बंदरगाह जीता था।
- उनके पिता ने संभवतः अपने बेटे की वीरतापूर्ण लड़ाई की स्मृति में **कैकोडा** के **महादेव** के **मंदिर** में **शिलालेख** के साथ एक **स्मारक पत्थर** बनवाया होगा।

चालुक्य

- इसने **6वीं शताब्दी** से **12वीं शताब्दी** के बीच **दक्षिणी** और **मध्य भारत** के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
- चालुक्य वंश तीन अलग-अलग लेकिन संबंधित थे।

बादामी चालुक्य

- सबसे पुराने **चालुक्यों** की राजधानी **कर्नाटक के बादामी (वातापी)** में थी ।
- उन्होंने **6ठी शताब्दी** के मध्य से शासन किया और **642 ई.** में अपने सबसे महान **राजा पुलकेशिन द्वितीय** की मृत्यु के बाद उनका पतन हो गया।

पूर्वी चालुक्य

- **पुलकेशिन द्वितीय** की मृत्यु के बाद **पूर्वी दक्कन** में **वेंगी** में **राजधानी** के साथ उभरा।
- उन्होंने 11वीं शताब्दी तक शासन किया।

पश्चिमी चालुक्य

- **बादामी चालुक्यों** के वंशज, वे **10वीं शताब्दी** के अंत में उभरे और **कल्याणी** से शासन किया।

2. अदालतों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच में गंभीर अंतर: सुप्रीम कोर्ट - द हिंद

प्रीलिम्स टेकअवे
- सुप्रीम कोर्ट
- जिला अदालत

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** के **सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग** की एक हालिया रिपोर्ट पूरे **भारत** में **जिला न्यायालयों** के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है।
- विकलांग लोगों को न्याय तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों पर ज़ोर देना।

मुख्य बिंदु

विकलांगता की चिंता

- आधे से अधिक **जिला न्यायालय परिसरों** में **रैम्प** का अभाव है।
- केवल **25.2%** ही पहुंच के लिए **व्हीलचेयर** प्रदान करते हैं।

दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्शनीय पेविंग

- केवल 5.1% **जिला न्यायालयों** में **दृष्टिबाधित लोगों** की सहायता के लिए **स्पर्शनीय पेविंग** है।
- समावेशिता के लिए **स्पर्शनीय** या **श्रवण निर्देशों** के महत्व पर जोर देता है।

सुलभ शौचालय

- केवल **30.4% जिला न्यायालय परिसरों** में अलग से **विकलांग-अनुकूल शौचालय हैं ।**
- सुलभ सुविधाओं के **मूलभूत महत्व** को **रेखांकित** करता है।

श्रवण बाधित

- उच्च न्यायालयों में सांकेतिक भाषा दुभाषियों के साथ आभासी बहस के सकारात्मक उदाहरण है। हालाँकि, भारत में **केवल 2.8% जिलों** में **अदालती कार्यवाही** के लिए **सांकेतिक भाषा दुभाषियों** की पहुंच है।

इंफ्रास्ट्रक्चर गैप

- **25,081 स्वीकृत न्यायाधीशों** में से, **4,250 न्यायालय कक्षों** का बुनियादी ढांचा अंतर है।
- **73.5% अदालत परिसर न्यायपालिका** के स्वामित्व में हैं, **2.6% किराए** पर हैं।
- पुरानी इमारतों में बदलाव या अस्थायी आवासों में **संरचनात्मक सीमाओं** और जगह की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- कुछ **उच्च न्यायालय** मौजूदा **संरचनाओं को संशोधित** करने में कठिनाइयों का हवाला देते हैं।

सिफारिश

- रिपोर्ट में **जिला न्यायाधीशों** के समन्वय से **लोक निर्माण विभाग** जैसी एजेंसियों द्वारा **नियमित निरीक्षण** का आह्वान किया गया है, ताकि पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा **अदालत भवनों** में संशोधन का पता लगाया जा सके।
- यह **न्यायिक बुनियादी ढांचे** में इस गंभीर कमी को दूर करने के लिए ध्यान देने और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

3. झेलम बेसिन में पर्माफ्रॉस्ट संरचनाओं का मानचित्रण किया गया - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। वगैरह।

प्रीलिम्स टेकअवे

- रॉक ग्लेशियर
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ़्लड (GLOFs)
- कश्मीर हिमालय

समाचार:

- एक नए अध्ययन में **कश्मीर हिमालय** में **'रॉक ग्लेशियर'** के नाम से जानी जाने वाली **100 से अधिक पर्माफ्रॉस्ट संरचनाओं** का मानचित्रण किया गया है।
- अध्ययन **क्षेत्र** पर **पर्माफ्रॉस्ट** के पिघलने के **प्रभाव** और **प्राकृतिक आपदाओं** में इसके संभावित योगदान के बारे में चिंता जताता है।

रॉक ग्लेशियर

- ये **चट्टान, बर्फ, बर्फ, मिट्टी** और **पानी का एक समूह** है जो **गुरुत्वाकर्षण** के प्रभाव में एक पहाड़ से धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ता है।
- बर्फ के **ग्लेशियर** के विपरीत, **चट्टानी ग्लेशियरों** की सतह पर **आमतौर** पर बहुत कम बर्फ दिखाई देती है।
- ये चट्टानी ग्लेशियर, जिनके **भीतर बर्फ की मात्रा है, पर्माफ्रॉस्ट की गति या पिघलने के** महत्वपूर्ण संकेतक हैं ।
- वे आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में **पर्माफ्रॉस्ट, चट्टानी मलबे** और **बर्फ** के साथ बनते हैं। अध्ययन **कश्मीर हिमालय** में **झेलम बेसिन** पर केंद्रित था।
- जबकि **ग्रीनलैंड**, **अलास्का** और **साइबेरिया** जैसे क्षेत्रों में **पर्माफ्रॉस्ट** पर शोध **उन्नत** है, **हिमालय** में **रॉक ग्लेशियरों** के बारे में बहुत कम जानकारी है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **उपग्रह चित्रों** और **क्षेत्र भ्रमण** के माध्यम से **कश्मीर हिमालय** में **100** से अधिक **रॉक ग्लेशियरों** की पहचान की गई।
- शोधकर्ताओं ने उन्हें **पर्माफ्रॉस्ट** स्थिति के आधार पर **'सक्रिय'** या **'अवशेष'** के रूप में वर्गीकृत किया है।
- सक्रिय **रॉक ग्लेशियर, पर्माफ्रॉस्ट** गतिविधि का संकेत देते हुए, **क्षेत्र के गर्म होने** पर अस्थिरता और **संभावित प्राकृतिक आपदाओं** के बारे में चिंताएँ बढ़ाते हैं।

पर्माफ्रॉस्ट पिघलने के निहितार्थ

- पिघलती प**र्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों** को अस्थिर बनाती है, जिससे आस-पास की **बस्तियों** और **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे** के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
- अध्ययन में **रॉक ग्लेशियरों** से उत्पन्न खतरों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs)** का खतरा भी शामिल है।
- **चिरसर झील** जैसी **हिमनदी झीलों** के पास रॉक ग्लेशियर, **GLOFs** के खतरे को बढ़ाते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।
- इससे **पिघलती बर्फ** पर **ज़मीन कमजोर** होने के साथ-साथ **भूस्खलन** भी अधिक हो सकता है।

4. भारत का सबसे पुराना जीवित शहर गुजरात के वडनगर में मिलाद हिंदू -

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मेसोपोटामिया
- डार्क ऐज

समाचार:

- पांच प्रमुख संस्थानों के एक संयुक्त अध्ययन में **हड़प्पा सभ्यता** के पतन के बाद भी **वर्तमान गुजरात** के **वडनगर** में **सांस्कृतिक** निरंतरता के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि **"डार्क ऐज "** एक मिथक था।

मुख्य बिंदु

- अध्ययन से यह भी पता चलता है कि **3,000 साल** की अवधि के दौरान विभिन्न **राज्यों का उत्थान** और **पतन** और **मध्य एशियाई योद्धाओं** द्वारा भारत पर **बार-बार आक्रमण, वर्षा या सूखे** जैसे **जलवायु** में **गंभीर परिवर्तनों** से प्रेरित थे।
- वडनगर एक **बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक** (बौद्ध, हिंदू, जैन और इस्लामी) **बस्ती** थी।
- **सिंधु घाटी सभ्यता** के **पतन** और **लौह युग** और **गांधार, कोशल** और **अवंती** जैसे **शहरों के उद्भव** के बीच की **अवधि को पुरातत्वविदों** द्वारा अक्सर **डार्क ऐज** के रूप में चित्रित किया गया है।
- साक्ष्य **वडनगर** को **भारत** में अब तक खोदे गए **एक ही किले** के भीतर **सबसे पुराना जीवित शहर** बनाते हैं।
- हमारी हाल की कुछ अप्रकाशित **रेडियोकार्बन तिथियों** से पता चलता है कि यह बस्ती **1400 ईसा पूर्व** जितनी पुरानी हो सकती है, जो **उत्तर-शहरी हड़प्पा काल** के **अंतिम चरण** के **समकालीन** है।

हड़प्पा की सभ्यता

- इतिहास **सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)** के जन्म से शुरू होता है , जिसे **हड़प्पा सभ्यता** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह लगभग **2,500 ईसा पूर्व,** दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, समकालीन **पाकिस्तान औ**र **पश्चिमी भारत** में फला-फूला है।
- सिंधु घाटी **मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत** और **चीन की चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं** में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी।
- **वर्ष 1920** के दशक में, **भारतीय पुरातत्व विभाग** ने **सिंधु घाटी** में खुदाई की, जिसमें **दो पुराने शहरों, मोहनजोदड़ो** और **हड़प्पा के खंडहरों** का पता चला।
- **वर्ष 1924** में ASI के **महानिदेशक जॉन मार्शल** ने **सिंधु घाटी** में एक **नई सभ्यता** की खोज की घोषणा दुनिया के सामने की।

5. ONGC ने महानदी बेसिन ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज कीं द इकोनॉमिक - टाइम्स

प्रासंगिकता: दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित); विश्व के विभिन्न हिस्सों (भारत सहित) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्राकृतिक गैस
- कोयला

समाचार:
- राज्य के स्वामित्व वाली **ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)** ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन गहरे पानी ब्लॉक में बैक-टू-बैक **प्राकृतिक गैस** खोज हासिल की है।
- ये खोजें उच्च जोखिम वाले गहरे पानी की खोज में **ONGC** के **रणनीतिक** कदम का हिस्सा हैं।

खोज विवरण
- यह खोज **MN-DWHP-2018/1 ब्लॉक** में हुई, जिसे **वर्ष 2019** में **ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी** के तहत नीलामी के तीसरे दौर में **ONGC** द्वारा सुरक्षित किया गया था।
- विशेष रूप से, ये खोजें उस क्षेत्र में हैं जिसे पहले **राष्ट्रीय सुरक्षा हितों** के कारण **'नो-गो' ज़ोन** के रूप में नामित किया गया था।
- पहली खोज, जिसका नाम **उक्तल** है**, 714 मीटर** की पानी की गहराई पर है और **प्रारंभिक परीक्षण** के दौरान गैस का एक महत्वपूर्ण प्रवाह प्रदर्शित हुआ।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए निहितार्थ
- ये खोजें **भारत की ऊर्जा सुरक्षा** में **सकारात्मक योगदान** देती हैं , जिसका लक्ष्य **गैस आयात** पर निर्भरता को कम करना है।
- भारत का लक्ष्य **वर्ष 2030** तक अपने **ऊर्जा मिश्रण** में **प्राकृतिक गैस** की हिस्सेदारी को **15%** तक बढ़ाना है, जिसमें प्राकृतिक गैस **वर्ष 2070** तक **शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन** की ओर बढ़ने में भूमिका निभाएगी।

सरकारी पहल और अन्वेषण त्वरण
- वर्ष 2022 में लगभग **एक लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र** को प्रतिबंधों से मुक्त करने के **सरकार** के फैसले के बाद **ONGC** की खोज में तेजी आई।
- पहले **मिसाइल परीक्षण** या **उपग्रह प्रक्षेपण मार्गों** के कारण **'नो-गो' क्षेत्रों** के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जिससे **ऊर्जा कंपनियों** को **तेल** और **गैस** की खोज करने की अनुमति मिल गई।

सहयोग और तकनीकी विशेषज्ञता
- ONGC ने **महानदी** और **अंडमान बेसिन** में गहरे पानी के **अपतटीय क्षेत्र** पर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए **फ्रांसीसी ऊर्जा दिग्गज टोटलएनर्जीज** के साथ सहयोग किया।
- इस सहयोग का उद्देश्य गहरे पानी की खोज और उत्पादन में **टोटलएनर्जीज़** की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

भविष्य का दृष्टिकोण
- ONGC की खोजें घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयातित गैस पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों के अनुरूप हैं।
- प्राकृतिक गैस, अपने कम कार्बन **पदचिह्न** के साथ, भारत में **जीवाश्म ईंधन** से हटकर एक संक्रमणकालीन ईंधन माना जाता है।
- **प्राकृतिक गैस** के बढ़ते उपयोग से **बिजली उत्पादन** में **कोयले** और **उद्योगों** में **तरल ईंधन** की जगह लेने की उम्मीद है।

6. भारत के आधे से अधिक उपजिलों में वर्षा का स्तर बढ़ रहा है- - द हिंदू

प्रासंगिकता: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। आदि, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-निकायों और बर्फ-टोपियों सहित) और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दक्षिण पश्चिम मानसून
- उत्तर पूर्वी मानसून

समाचार:

- पहली बार **तहसील स्तर** पर किए गए **भारतीय मानसून** में बदलाव के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, **भारत** की **4,400** से अधिक **तहसीलों** या **उप-जिलों** में से **आधे से अधिक में वर्षा** बढ़ रही है।
- **55% तहसीलों** में वर्षा में वृद्धि देखी गई है, उनमें से लगभग **11%** में वर्षा में कमी देखी गई है।

मुख्य बिंदु

- अधिक चिंता की बात यह है कि यह कमी बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण **दक्षिण पश्चिम मानसून** के दौरान हुई।
- इनमें से अधिकांश तहसीलें **सिंधु-गंगा** के **मैदानी इलाकों** में हैं - जो **भारत** के आधे से अधिक कृषि उत्पादन में योगदान करती हैं
  - साथ ही पूर्वोत्तर भारत और भारतीय हिमालयी क्षेत्र में भी।

1. **जिला स्तर पर अति**

- **जिला स्तर** पर एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के **30% जिलों** में कई वर्षों तक कम वर्षा देखी गई और **38% जिलों** में कई वर्षों तक **अत्यधिक वर्षा** देखी गई।

2. **वर्षा के पैटर्न में लगातार वृद्धि हो रही है**

- **पूर्वोत्तर मानसून** से वर्षा - जो **अक्टूबर, नवंबर** और **दिसंबर** के दौरान मुख्य रूप से **प्रायद्वीपीय** भारत में होती है
  - **पिछले दशक (वर्ष 2012-2022)** में क्रमशः **तमिलनाडु** की लगभग **80% तहसीलों, तेलंगाना** में **44%** और **आंध्र प्रदेश** में **39%** से अधिक की वृद्धि हुई है।
- **भारत की वार्षिक** वर्षा का लगभग **76% दक्षिण-पश्चिम मानसून** के कारण होता है, जिसमें लगभग **11% उत्तर-पूर्व मानसून** से आता है।
- पूर्वी तट पर **महाराष्ट्र** और **गोवा, ओडिशा** और **पश्चिम बंगाल** की कई **तहसीलों** में भी इन **सर्दियों** के **महीनों** के दौरान **वर्षा में वृद्धि** की सूचना मिल रही है।
  - इस वृद्धि को **आंशिक रूप** से **अरब सागर** और **बंगाल की खाड़ी** में **चक्रवाती गतिविधि** के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **मौसम** की बढ़ती **चरम घटनाओं** के साथ, **जलवायु कार्रवाई** और **आपदा जोखिम** में कमी लाने में **भारत** को अग्रणी बनाए रखने के लिए **अति-स्थानीय जलवायु जोखिम आकलन** और **कार्य योजनाएं** ही रास्ता हैं।

7. भारतीय विवर्तनिक प्लेट दो भागों में विभाजित हो रही है इंडिया टुडे -

प्रासंगिकता: विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- हीलियम -3
- विवर्तनिक प्लेटें

समाचार:

- एक नई खोज में जो **पृथ्वी** के सबसे **ऊंचे पहाड़ों** को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकती है
- शोधकर्ताओं ने नए **भूकंपीय डेटा** का अनावरण किया है जो दर्शाता है कि **तिब्बती पठार** के नीचे भारतीय विवर्तनिक प्लेट **दो भागों** में विभाजित हो रही है।

मुख्य बिंदु

- यह रहस्योद्घाटन **सैन फ्रांसिस्को** में **अमेरिकी भूभौतिकीय संघ सम्मेलन** में प्रस्तुत किया गया था और यह **विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला** के निर्माण पर एक **नया दृष्टिकोण** प्रस्तुत करता है।
- दशकों से, भूविज्ञानी जानते हैं कि **हिमालय** की विशाल उपस्थिति **भारतीय** और **यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेटों** के टकराव के कारण है।
- यह प्रक्रिया, जो लगभग **60 मिलियन वर्ष** पहले शुरू हुई थी
- भारतीय प्लेट पृथ्वी के आवरण के भीतर पिघली हुई चट्टान की धाराओं द्वारा अपने उत्तरी पड़ोसी के नीचे संचालित हो रही है।
- समय के साथ, इस **टेक्टोनिक इंटरैक्शन** ने **यूरेशियाई भूभाग** को आकाश की ओर धकेल दिया है, जिससे ग्रह की **उच्चतम ऊंचाई** बन गई है।
- हालाँकि, नवीनतम विश्लेषण **भारतीय प्लेट** के उत्प्लावन के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देता है।

- मेंटल की गहराई में आसानी से डूबने के बजाय, **भूकंपीय डेटा** एक अधिक जटिल परिदृश्य का सुझाव देता है जहां प्लेट नष्ट हो रही है।
- भारतीय प्लेट का **सघन आधार** छिल रहा है और **मेंटल** में उतर रहा है, जबकि इसका **हल्का शीर्ष** भाग **यूरेशियन प्लेट** के ठीक नीचे खिसक रहा है।
- निष्कर्षों से पता चलता है कि **भारतीय स्लैब** न तो समान रूप से फिसल रहा है और न ही सिकुड़ रहा है, बल्कि एक **रहस्यपूर्ण संरचनात्मक** पृथक्करण से गुजर रहा है।
- प्लेट के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत अक्षुण्ण दिखाई देते हैं, जबकि अन्य सतह से लगभग **100 किलोमीटर** नीचे खंडित हो रहे हैं, जिससे **आधार पृथ्वी** के **उग्र कोर** में विकृत हो रहा है।
- यह भूकंपीय जांच **हीलियम-3** समृद्ध झरने के पानी और सतह के पास **फ्रैक्चर** और **भूकंप** के पैटर्न पर आधारित **भूवैज्ञानिक मॉडल** के साथ संरेखित होती है।
- साथ में, साक्ष्य के ये टुकड़े हिमालय के नीचे गहराई में **विवर्तनिक उथल-पुथल** की तस्वीर चित्रित करते हैं।
- इस अध्ययन के निहितार्थ न केवल पर्वत निर्माण की हमारी समझ के लिए बल्कि **भूकंप की भविष्यवाणी** के तरीकों के लिए भी गहरे हैं।

8. अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- परकोटा
- बंसी पहाड़पुर क्षेत्र

समाचार:
- **22 जनवरी को अयोध्या** के क्षितिज पर **सुंदर बलुआ पत्थरों** के नए युग के **वास्तुशिल्प चमत्कार** के रूप में भारत का संरचनात्मक और आध्यात्मिक दोनों तरह का एक **नया मील का पत्थर उभर** आया है।
  - भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति के साथ शिल्पकारों द्वारा परिश्रमपूर्वक नक्काशी की गई।

मुख्य बिंदु
- अयोध्या में भव्य **राम मंदिर** एक विशाल संरचना है, जिसे **इंजीनियरिंग चुनौतियों** पर काबू पाने और प्रकृति के प्रति उचित संवेदनशीलता के साथ बनाया गया है।
- मंदिर में **राम लला की नई मूर्ति** की **प्राण-प्रतिष्ठा** की गई, इस कार्यक्रम का नेतृत्व **प्रधानमंत्री** ने किया और कहा कि यह एक नए युग के आगमन का प्रतीक है।
- भव्य संरचना के निर्माण में **किसी भी लोहे या स्टील** का उपयोग नहीं किया गया है ।
- पत्थर **राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र** से मंगाए गए हैं ।

नागर शैली
- पारंपरिक **नागर शैली में निर्मित** मंदिर परिसर **पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा** और **161 फीट** ऊंचा होगा।
- खुदाई कार्य के दौरान यह पाया गया कि जमीन **शिलान्यास** के लिए अनुपयुक्त है
  - एक चुनौती जिसे इंजीनियरों ने एक **"कृत्रिम नींव"** बनाकर पार कर लिया जिस पर अधिरचना बैठती है।
- भगवान हनुमान, अन्य देवताओं, मोरों और फूलों के पैटर्न की छवियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं, जो संरचना को एक दिव्य रूप प्रदान करती हैं।

अनूठी खासियत
- भव्य मंदिर के चारों ओर एक **आयताकार परिधि** है जिसे **परकोटा** कहा जाता है, यह विशेषता **दक्षिण भारत** के **मंदिरों** में पाई जाती है, लेकिन आम तौर पर उत्तर भारत में नहीं।
  - परकोटा 14 फीट चौड़ा और परिधि 732 मीटर होगी।
- मंदिर को **पेरकोटा परिधि के भीतर बसाया जाएगा।**

- इस महीने की शुरुआत में मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथियों, शेरों, भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियाँ स्थापित की गईं।
- शीर्ष अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया।
- इसने फैसला सुनाया कि मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड खोजा जाना चाहिए।
- बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई है।

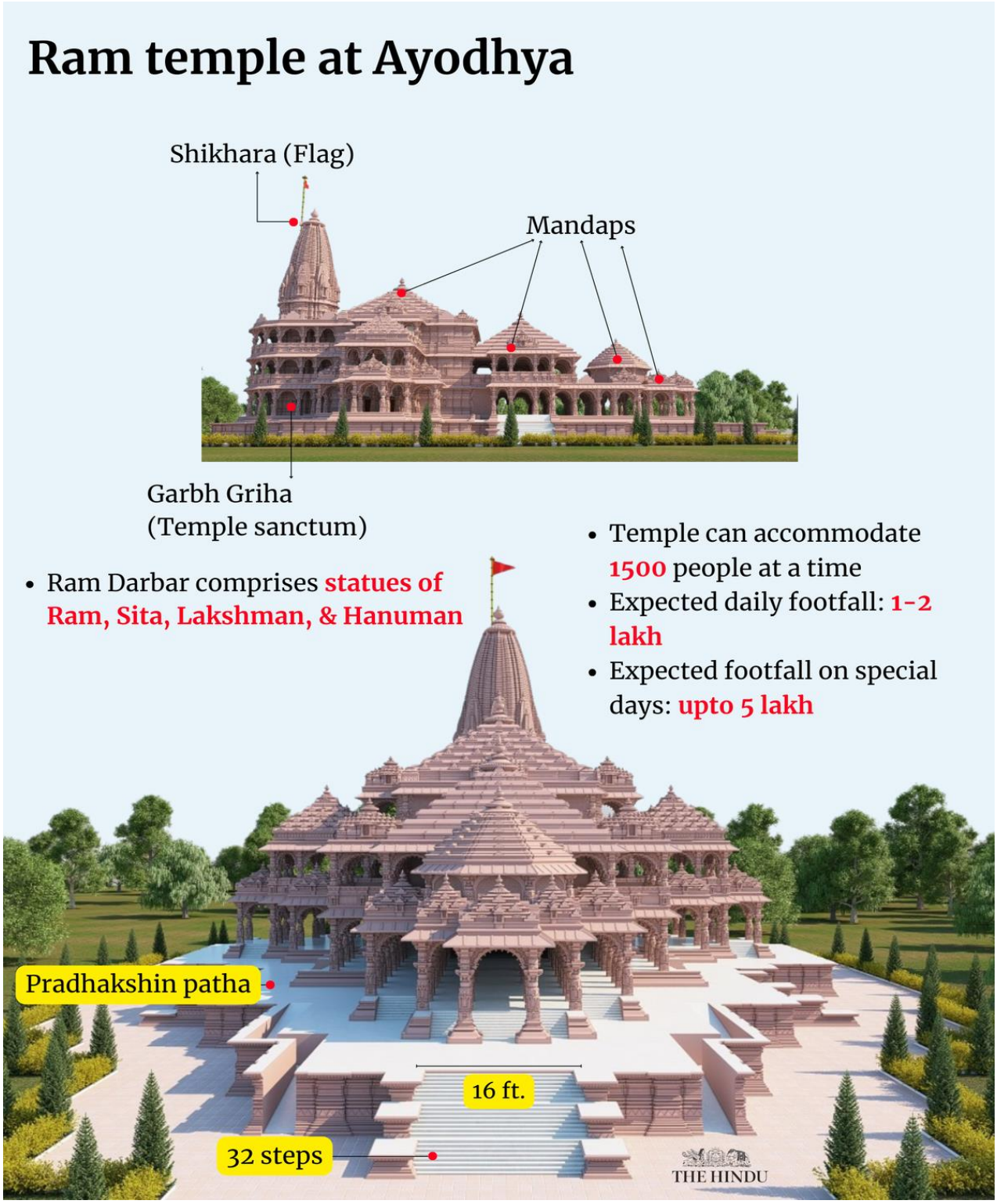

9. ASI ज्ञानवापी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेवाराणसी जिला अदालत : - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- ज्ञानवापी
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

समाचार:
- **वाराणसी जिला** अदालत **ज्ञानवापी मस्जिद** परिसर पर **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** की वैज्ञानिक **सर्वेक्षण रिपोर्ट हिंदू** और **मुस्लिम दोनों पक्षों** को उपलब्ध कराने पर सहमत हुई।
- संबंधित पक्षों को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करना होगा.

मुख्य बिंदु
- यह घटनाक्रम **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** द्वारा **वाराणसी जिला न्यायालय** के समक्ष **सीलबंद लिफाफे** में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक महीने से अधिक समय बाद सामने आया है
- हालाँकि, **ASI** ने अपनी **ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट** को **सार्वजनिक डोमेन** में जारी करने को स्थगित करने की मांग की थी।
- पैनल ने **वाराणसी** के **जिला न्यायाधीश** से खुलासे में देरी करने का आग्रह किया था
  - इस डर से कि जनता के लिए **रिपोर्ट की सामग्री अनुचित** होगी और **अफवाहों** और **गलत सूचनाओं** को बढ़ावा देगी।
- **ASI** ने **काशी विश्वनाथ मंदिर** के बगल में स्थित **ज्ञानवापी परिसर** का **वैज्ञानिक सर्वेक्षण** किया
  - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या **17वीं सदी** की **मस्जिद** का **निर्माण किसी हिंदू मंदिर** की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था।
- **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** द्वारा **वाराणसी जिला अदालत** के आदेश को बरकरार रखने के बाद सर्वेक्षण शुरू हुआ था
- इसने फैसला सुनाया कि यह कदम "**न्याय के हित** में आवश्यक" था और इससे विवाद में **हिंदू और मुस्लिम** दोनों पक्षों को फायदा होगा।
- इलाहाबाद **हाई कोर्ट** के आदेश के बाद **ज्ञानवापी समिति आदेश** के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** चली गई

10. गणतंत्र दिवस पर झारखंड की झांकी ने आदिवासी महिलाओं के कौशल का प्रदर्शन किया द प्रिंट -

प्रीलिम्स टेकअवे
- उष्णकटिबंधीय तसर
- भौगोलिक संकेत टैग

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

समाचार:
- शुक्रवार को **गणतंत्र दिवस परेड** में **झारखंड की झांकी** में **तसर रेशम** के **उत्पादन** में **आदिवासी महिलाओं** के **कौशल** का प्रदर्शन किया गया।

तसर रेशम
- यह एक प्रकार का जंगली रेशम है, जो **आसन और अर्जुन** जैसे पौधों को खाने वाले रेशम के कीड़ों से बनाया जाता है।
- भारत के विभिन्न भागों के लोग इसे **तुसार, तुसर, तुषार, तुसा, तस्सोर और तसर** आदि कहते हैं।
- वैश्विक स्तर पर इसका उत्पादन **चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश** में होता है।
- भारत **टसर रेशम** का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** और **भारतीय टसर** (उष्णकटिबंधीय टसर के रूप में भी जाना जाता है) का विशेष उत्पादक है।
  - जिसकी देखभाल बड़े पैमाने पर **आदिवासियों** द्वारा की जाती है।
- भारत में इसका उत्पादन मुख्य रूप से **मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़** में होता है ।

- वर्तमान में, **झारखंड सबसे बड़े उत्पादकों** में से एक है ।
- **झारखंड** ने अपने **तसर रेशम** के लिए प्रतिष्ठित **जीआई टैग** के लिए भी आवेदन किया है

झांकी की चयन प्रक्रिया

- **रक्षा मंत्रालय (MoD) परेड** के **संचालन** और **राज्यों** और **अन्य एजेंसियों** के साथ समन्वय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है।
- राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्याय बन चुके इस समारोह की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं।
- इस प्रक्रिया में **झांकियों** का **चयन और शॉर्टलिस्टिंग** शामिल है।
- संस्कृति मंत्रालय, **झांकी की सांस्कृतिक** और **कलात्मक प्रकृति को** देखते हुए, **सांस्कृतिक प्रदर्शनों** के **मूल्यांकन** और **प्रचार में सहायता** करते हुए, चयन प्रक्रिया में **रक्षा मंत्रालय** के साथ सहयोग करता है।

11. भारत ने मराठाओं के 12 किलों को यूनेस्को धरोहर के लिए नामांकित किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मराठा
- विश्व धरोहर स्थल

समाचार:

- भारत ने **वर्ष 2024-25** के लिए **यूनेस्को की विश्व विरासत सूची** में शामिल करने के लिए "**मराठा सैन्य परिदृश्य**" को नामांकित किया है।
- यह किलों का एक **नेटवर्क** है जो **मराठा शासन** की **रणनीतिक सैन्य शक्तियों** को प्रदर्शित करता है,

मुख्य बिंदु

- इस नामांकन के 12 किले निम्नलिखित हैं:
  - सलहेर के किले
  - शिवनेरी, लोहागढ़
  - खंडेरी, रायगढ़
  - महाराष्ट्र में राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला।

असाधारण दुर्ग

- **"मराठा सैन्य परिदृश्य**", जिसका विकास **17वीं और 19वीं शताब्दी** के बीच हुआ।
  - **मराठा शासकों** द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण **किलेबंदी और सैन्य प्रणाली** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इनमें से आठ **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI**) द्वारा संरक्षित हैं
  - जबकि **चार महाराष्ट्र सरकार** के **पुरातत्व** और **संग्रहालय निदेशालय** द्वारा संरक्षित हैं।

शिवाजी के काल से

- **मराठा सैन्य विचारधारा** की शुरुआत **17वीं शताब्दी** में **मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज** के शासनकाल के दौरान **1670 ईस्वी** में हुई थी।
  - और 1818 ई. तक **पेशवा शासन** तक बाद के नियमों के माध्यम से जारी रहा।
- नामांकन सांस्कृतिक **संपत्ति की श्रेणी** में है
- वर्तमान में भारत में **42 विश्व धरोहर स्थल** हैं जिनमें से **34 सांस्कृतिक स्थल, सात प्राकृतिक स्थल** और **एक मिश्रित स्थल** है।
- **"मराठा सैन्य परिदृश्य"** महाराष्ट्र से **विश्व विरासत सूची** में शामिल करने के लिए नामांकित **छठी सांस्कृतिक** संपत्ति है
  - इसे पहले 2021 में **विश्व धरोहर स्थलों** की **अस्थायी सूची** में शामिल किया गया था।

सामान्य अध्ययन II

12. सरकार नई मनरेगा भुगतान प्रणाली से छूट दे सकती है - द हिंदू/केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी के भुगतान हेतु ABPS अनिवार्य की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आधार-आधारित भुगतान प्रणाली
- आधार

समाचार:
- नरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए अब **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)** अनिवार्य हो गई है
- सरकार ने कहा कि यदि किसी ग्राम पंचायत को **"तकनीकी समस्याओं"** का सामना करना पड़ता है तो वह **"मामला-दर-मामला आधार"** पर छूट पर विचार कर सकती है।

पृष्ठभूमि
- ABPS के तहत, श्रमिकों के **12 अंकों** के **आधार नंबर** उनके **जॉब कार्ड** के साथ-साथ उनके बैंक खातों से जुड़े हुए हैं।
- इस प्रणाली को पहली बार **1 फरवरी, 2023** से अनिवार्य बनाया गया था
  - लेकिन, कई विस्तारों के माध्यम से, केंद्र ने **31 दिसंबर, 2023** तक **ABPS** और **NACH** के **मिश्रित** मार्ग की अनुमति दी, जो एक **इंटरबैंक प्रणाली** है जिसका उपयोग **सब्सिडी** और **वेतन** जैसे **थोक भुगतान** के लिए किया जाता है।
- राज्यों को **31 दिसंबर** से आगे कोई विस्तार नहीं दिए जाने के कारण, **1 जनवरी, 2024** से **ABPS** अनिवार्य हो गया।
- "भारत सरकार ने अकुशल श्रमिकों का वेतन भुगतान **APBS** के माध्यम से करने का निर्णय लिया है
  - लाभार्थी द्वारा बार-बार **बैंक खाता** बदलने की स्थिति में भी लाभार्थियों का भुगतान उनके बैंक खाते में सुनिश्चित करना

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)
- यह प्रणाली पहली बार **वर्ष 2017** में शुरू की गई थी।
- यह प्रणाली **धन हस्तांतरित** करने के उद्देश्य से प्राप्तकर्ता की पहचान करने के लिए उसके **आधार नंबर** का उपयोग करती है।
- यह प्रणाली **वेतन भुगतान** में **पारदर्शिता** को बढ़ावा देती है और किसी भी **अनधिकृत पहुंच** को रोकने में मदद करती है।
- यह **श्रमिकों के वेतन भुगतान में** उनके **बैंक खातों** से **संबंधित समस्याओं** के कारण होने वाले किसी भी व्यवधान को रोकता है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, **मार्च 23 में 84%** स्थानांतरण **ABPS** पर आधारित थे।

13. भारत और पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की- द हिंदू/भारत,पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- परमाणु बिजली संयंत्र
- परमाणु ऊर्जा

समाचार:
- **तीन दशक** से अधिक समय से जारी **अभ्यास** को जारी रखते हुए, **भारत** और **पाकिस्तान** ने हाल ही में एक **द्विपक्षीय समझौते** के तहत अपने **परमाणु प्रतिष्ठानों(संपति)** की सूची का **आदान-प्रदान** किया।
- यह दोनों पक्षों को एक-दूसरे की **परमाणु सुविधाओं** पर हमला करने से रोकता है।

पृष्ठभूमि

- सूची का आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ।
- यह नई **दिल्ली** और **इस्लामाबाद** में **राजनयिक चैनलों** के माध्यम से एक साथ किया गया था।
- इस समझौते पर **31 दिसंबर, 1988** को **हस्ताक्षर** किए गए और **27 जनवरी, 1991** को यह लागू हुआ।
- यह दोनों देशों को हर **कैलेंडर वर्ष** की **पहली जनवरी** को समझौते के तहत शामिल होने वाले **परमाणु प्रतिष्ठानों** और **सुविधाओं** के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने का आदेश देता है।
- यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार **33वां** आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान **1 जनवरी 1992** को हुआ था।

14. अधिक चीनी, नमक, वसा वाले भोजन पर 20-30% स्वास्थ्य टैक्स लगाया जा सकता है - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वस्तु एवं सेवा टैक्स (जीएसटी)
- स्वास्थ्य टैक्स

समाचार:

- चीनी, **शुगर स्वीटेंड बेवरेज(SSB)** पर **जीएसटी** के अलावा **20% से 30%** के बीच **स्वास्थ्य टैक्स** लगाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह सिफारिश नीति आयोग द्वारा कराए गए एक अध्ययन का नतीजा है, जो **खाद्य उत्पादों** पर **स्वास्थ्य कर** और **चेतावनी लेवल** लगाने के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।

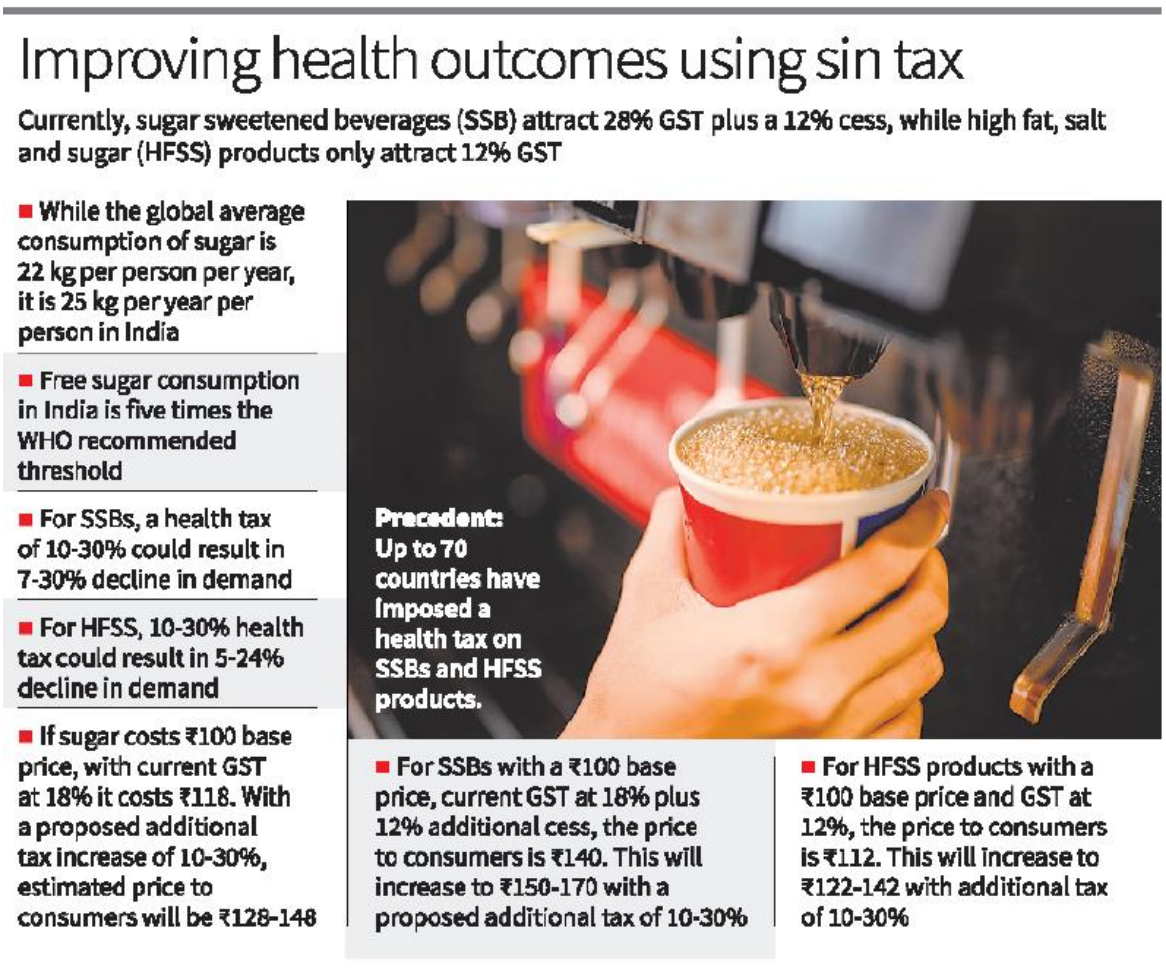

15. सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों का विरोध समाप्त हुआ - द हिंदू/ गृह सचिव से बातचीत के बाद ट्रक ड्राइवरों ने विरोध को समाप्त किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आईपीसी की धारा 304-A
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 106

समाचार :
- भारतीय न्याय संहिता ने **हिट-एंड-रन** मामलों के लिए सज़ा बढ़ा दी है।
- इसके चलते देशभर में **ट्रांसपोर्टरों** ने हड़ताल कर दी है।
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय** की ओर से **ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस** की बैठक बुलाई गई है

मामला क्या है ?
- **बस** और **टैक्सी यूनियनों** सहित **ट्रांसपोर्टरों** ने **1 जनवरी से 30 जनवरी** तक **देशव्यापी हड़ताल** का आह्वान किया है।
- यह हड़ताल BNS की **धारा 106** का विरोध करने के लिए है
- यह **धारा तेज गति** और **लापरवाही** से गाड़ी चलाने के मामलों में **अधिकतम 10 साल** की **सजा का प्रावधान** करती है।
- सरकार ने अनुभाग के कार्यान्वयन को **अधिसूचित** नहीं किया है।

हड़ताल का प्रभाव
- **ट्रक ड्राइवरों** की हड़ताल के कारण कई राज्यों में **ईंधन** की घबराहट भरी खरीदारी शुरू हो गई।
- ड्राइवरों ने अपने **वाहन सड़कों** पर चलाने से इनकार कर दिया है
- हड़ताल का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है
  - विशेष रूप से उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और मध्य प्रदेश में।

सरकार का रुख
- अगर **किसी ड्राइवर** ने गलती से किसी को टक्कर मार दी और समय पर **पुलिस को सूचित** कर दिया, तो उसे **पांच साल** की **कम सजा का सामना** करना पड़ेगा।
- **सुप्रीम कोर्ट** की टिप्पणियों के बाद ऐसे मामलों में सजा की **अवधि 10 साल** तक बढ़ा दी गई थी

ड्राइवरों का दावा
- जब भी कोई दुर्घटना होती है तो **भारी वाहन चालक** के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जाता है।
  - भले ही छोटी गाड़ी के ड्राइवर की गलती है
- मार-पिटाई होने की संभावना है
- कुछ मामलों में, ड्राइवरों को पीट-पीटकर मार डाला गया है ।
- ड्राइवर एक असंगठित वर्ग हैं।
- कभी-कभी ड्राइवर खुद को भीड़ से बचाने के लिए भागते हैं।

नये कानून के तहत अलग-अलग सजा
- नए कानून के तहत लापरवाही से मौत पर **डॉक्टरों** को **दो साल** की सजा का प्रावधान है
- **BNS** की **धारा 106(1)** में **"0-5 साल"** की सज़ा का प्रावधान है, जबकि धारा 106(2) में **"हिट एंड रन"** मामलों में **"0-10 साल"** की सज़ा का प्रावधान है ।
- **धारा 106(1),** जहां सजा कम है, यानी **पांच साल तक है** , और एक जमानती अपराध है। **धारा 106(2)** एक गैर जमानती अपराध है।

सज़ा पर वर्तमान स्थिति
- वर्तमान में, **भारतीय दंड संहिता (IPC)** की **धारा 304A** के तहत, जिसे संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, लापरवाही से मौत की **सजा दो साल** की **कैद** और **जुर्माना**, या **दोनों** है।

16. 'लोकसभा चुनाव से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है' - द हिंदू/ CAA नियम, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जा सकते है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- असम समझौता
- CAA, 2019

समाचार :
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम **दिसंबर 2019** में **भारत** की **संसद** द्वारा पारित किया गया था।
- इसके कार्यान्वयन के नियमों को **वर्ष 2024** के **लोकसभा चुनाव** से पहले **अधिसूचित** किया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की स्थिति
- विधेयक में **हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों** और **ईसाइयों** को तेजी से **भारतीय नागरिकता** देने की मांग की गई है, लेकिन **मुसलमानों** को नहीं।
  - **पाकिस्तान, अफगानिस्तान** और **बांग्लादेश** में **धार्मिक उत्पीड़न** के कारण **भारत** आ गए ।
- इस विधेयक को **वर्ष 2019** में **भारत** के **राष्ट्रपति** की **सहमति** मिल गई।
- नियम लागू होने के बाद नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने **यात्रा दस्तावेजों** के बिना **भारत** में **प्रवेश** किया था।
- आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
- जिन आवेदकों ने **वर्ष 2014** के बाद आवेदन किया था, उनके अनुरोधों को नए नियमों के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।
- केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक **आठ बार** तारीख बढ़ाई है।
- पिछले दो वर्षों में, नौ राज्यों के 30 से अधिक **जिला मजिस्ट्रेटों** और **गृह सचिवों** को अधिनियम के तहत **भारतीय नागरिकता प्रदान** करने की **शक्तियां** दी गई हैं।

असम समझौते पर CAA का प्रभाव
- **असम** में **विरोध प्रदर्शन** इस आशंका से भड़के थे कि यह **कानून राज्य** की **जनसांख्यिकी** को स्थायी रूप से बदल देगा।
- CAA को असम में **वर्ष 1985** के **असम समझौते** के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो **1 जनवरी, 1966** के बाद लेकिन **25 मार्च, 1971** से पहले **असम आए विदेशी प्रवासियों** को **नागरिकता** लेने की अनुमति देता है।
- CAA के तहत नागरिकता बढ़ाने की अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2014** है।

कानून के विरुद्ध याचिकाएँ
- CAA की **संवैधानिक वैधता** को चुनौती देते हुए **इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग** सहित कई याचिकाएं **सुप्रीम कोर्ट** के समक्ष हैं।
- याचिका में आरोप लगाया गया है कि **CAA म्यांमार** के प्रताड़ित **रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध** और **श्रीलंका** के **तमिलों** को बाहर कर देता है।

सरकार का रुख
- केंद्र ने कहा कि **वर्ष 2019 अ**धिनियम द्वारा किए गए "**उचित वर्गीकरण**" का आधार धर्म नहीं था
  - लेकिन पड़ोसी देशों में " **धार्मिक भेदभाव** " जो "एक राज्य धर्म के साथ काम कर रहे हैं"।
- यह कानून दुनिया भर के मुद्दों का सर्वव्यापी समाधान नहीं था।
- **भारतीय संसद** से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह **दुनिया** के **विभिन्न देशों** में होने वाले संभावित **उत्पीड़न** पर ध्यान देगी।
- वर्तमान अधिनियम **धार्मिक देशों** में **धर्म के आधार** पर **उत्पीड़न** के **विरुद्ध** एक प्रकार की माफी है।
- **CAA** की **संवैधानिकता** का परीक्षण उस **विधायी क्षेत्र** के भीतर किया जाना चाहिए।
- संवैधानिकता को उस उद्देश्य और मुद्दे के **संसदीय संज्ञान** के पीछे के कारणों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

17. CEC, EC की नियुक्ति के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - द हिंदू/ CEC, EC की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत का संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जनहित याचिका (PIL)
- भारत चुनाव आयोग

समाचार:
- **CEC और EC की नियुक्ति प्रक्रिया** में हालिया संशोधनों को लेकर **सुप्रीम कोर्ट** में एक **जनहित** याचिका दायर की गई थी।
- जनहित याचिका में उस नए कानून को **रद्द करने की मांग** की गई है जो **केंद्र सरकार** को **चुनाव आयोग** में **नियुक्तियां** करने में **व्यापक शक्तियां प्रदान** करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023
- **CJI** को **चयन समिति** से हटाने को लेकर **नए कानून** की आलोचना की गई।
- यह अब **राष्ट्रपति** को **चयन समिति** की सिफारिश के आधार पर **CEC और EC** की नियुक्ति करने का अधिकार देता है
  - प्रधानमंत्री
  - लोक सभा में विपक्ष के नेता
  - प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- इसमें चयन समिति के विचार के लिए **उम्मीदवारों** का एक **पैनल** तैयार करने के लिए **केंद्रीय कानून मंत्री** की **अध्यक्षता** में एक **सर्च समिति** के प्रावधान शामिल हैं।

विपक्ष का आरोप
- विपक्ष ने सरकार पर **मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट** के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया।
- मार्च 2023 के **सुप्रीम कोर्ट** के आदेश में **CEC और EC** के चयन में **प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता** और **CJI** की भागीदारी निर्दिष्ट की गई थी।

स्वतंत्र व्यवस्था की जरूरत
- जनहित याचिका में **"चयन की स्वतंत्र** और **पारदर्शी प्रणाली"** लागू करने का आह्वान किया गया है।
- इसमें **CEC और EC** की नियुक्ति के लिए एक **तटस्थ** और **स्वतंत्र चयन समिति** गठित करने का सुझाव दिया गया है।
- यह प्रमुख चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति में **निष्पक्ष** और **निष्पक्ष प्रक्रिया** के महत्व पर जोर देते हुए चयन समिति में **CJI** को शामिल करने की मांग करता है।

18. भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अनुवाद परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

प्रीलिम्स टेकअवे
- e-SCR पोर्टल
- कॉमन कोर वोकैबुलरी पहल
- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG)

समाचार:
- भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने **वर्ष 2023** में अपनी **अनुवाद पहल** को सफलतापूर्वक तेज कर दिया।
- **e-SCR पोर्टल** के माध्यम से **31,000** से अधिक निर्णयों का विभिन्न अ**नुसूचित भाषाओं** में अनुवाद पूरा किया।

अनुवाद प्रक्रिया
- वर्तमान **CJI** के तहत **अनुवाद प्रक्रिया** में तेजी आई, **एआई-आधारित सॉफ्टवेयर अनुवादों** को सही करने के लिए **सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय** के **न्यायाधीशों** और **कानून क्लर्कों** को नियुक्त किया गया।

- इस पहल को कानूनी शब्दावली का अनुवाद करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर **तमिल** जैसी भाषाओं में, जहां **मानकीकृत शब्दावली** का अभाव है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- कानूनी विशेषज्ञ अनुवादित निर्णयों की व्यावहारिक उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं जब **उच्च न्यायालय हिंदी भाषी राज्यों** को छोड़कर **क्षेत्रीय भाषाओं** में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।
- क्षेत्रीय भाषाओं में **मानकीकृत कानूनी शब्दावलियों** की अनुपस्थिति **सटीकता** और **सुसंगतता** को लेकर चिंता पैदा करती है।

कॉमन कोर वोकैबुलरी पहल

- **बार काउंसिल ऑफ इंडिया** सभी **भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं** में कानूनी शब्दावली को मानकीकृत करने के लिए एक **"कॉमन कोर वोकैबुलरी"** बनाने पर काम कर रही है।
- आलोचकों का तर्क है कि अ**दालती कार्यवाही** में **क्षेत्रीय भाषाओं** को अनुमति देना एक **व्यापक शब्दावली** विकसित करने के लिए आवश्यक है जो **आम आदमी** की समझ के अनुरूप हो।

e-SCR पोर्टल

- शीर्ष अदालत के निर्णयों का **डिजिटल संस्करण** उसी प्रकार उपलब्ध कराने की पहल जिस प्रकार उन्हें **आधिकारिक कानून रिपोर्ट** में बताया गया है।
- यह वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को **SC** के **लगभग 34,000 निर्णयों** तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है।
- ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके **मोबाइल ऐप** और **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** (NJDG) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** की मदद से **e-SCR** के **डेटाबेस** में **इलास्टिक खोज** तकनीकों को शामिल करते हुए एक **सर्च इंजन** विकसित किया है।
- **e-SCR** में खोज सुविधा मुफ्त पाठ खोज, खोज के भीतर खोज, केस प्रकार और केस वर्ष खोज, न्यायाधीश खोज, वर्ष और वॉल्यूम खोज और बेंच स्ट्रेंथ खोज विकल्प प्रदान करती है।

19. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच को जारी रखा, हिंडनबर्ग के 'आचरण' पर प्रकाश डाला - द हिंदू/ सुप्रीम कोर्ट ने जांच को CBI को सौंपने वाली याचिका को खारिज किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सेबी
- सुप्रीम कोर्ट

समाचार:

- हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **हिंडनबर्ग रिसर्च** के कार्यों पर चिंताओं को उजागर करते हुए एक निर्णय जारी किया
- इसने **भारतीय प्रतिभूति** और **विनिमय बोर्ड (सेबी)** और **जांच एजेंसियों** को **अदानी समूह** की छोटी स्थिति से संबंधित संभावित कानूनी उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया ।

पृष्ठभूमि

- अदालत का फैसला **हिंडनबर्ग रिसर्च** की रिपोर्ट के बाद निवेशकों की संपत्ति में **गिरावट** और **बाजार** में अस्थिरता का हवाला देने वाली याचिकाओं पर आधारित था।
    - अडानी समूह पर शेयर की कीमतों में हेरफेर करने और सेबी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

प्रभाव आकलन

- फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि **अडानी समूह** में **सेबी की जांच** ने **आत्मविश्वास** जगाया और मामले को अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित करने के विचार को खारिज कर दिया।

सेबी जांच और संशोधन

- अदालत ने सेबी को तीन महीने के भीतर लंबित जांच पूरी करने का आदेश दिया

- इसने उन दावों को खारिज कर दिया कि सेबी के नियामक संशोधनों ने जांच में बाधा उत्पन्न की।
- कथित तौर पर संशोधन **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) विनियम** और **ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR)** विनियम से संबंधित थे।

विनियामक संशोधन

- अदालत ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संशोधनों ने नियामक ढांचे को सख्त कर दिया है।

हितों के टकराव के आरोप:

- अदालत ने **जस्टिस सप्रे समिति** के सदस्यों के खिलाफ **हितों के टकराव के आरोपों** को खारिज कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि वे गंभीरता से विचार करने लायक नहीं थे।

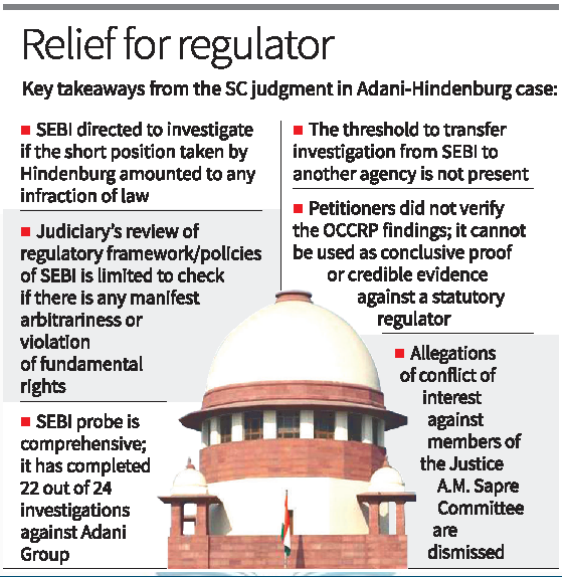

20. प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- कावारत्ती

समाचार:

- हाल ही में **प्रधानमंत्री** ने **केंद्र शासित प्रदेश** में **1,150 करोड़ रुपये** की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्य परियोजनाएँ

- लक्षद्वीप अब **पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर** केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो **संचार बुनियादी** ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
- इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी।
- प्रधान मंत्री ने कदमत में निम्न तापमान **थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD) संयंत्र** का भी उद्घाटन किया, जो हर दिन **1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल** का उत्पादन करेगा।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने **अगत्ती** और **मिनिकॉय द्वीपों** के सभी घरों में कार्यात्मक **घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** राष्ट्र को समर्पित किया।
- प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में **कावारत्ती** में **सौर ऊर्जा संयंत्र** शामिल है, जो लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है।
- उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के नवीनीकरण और **एंड्रोथ, चेटलाट, कदमत, अगत्ती** और **मिनिकॉय** के **पांच द्वीपों** में **पांच मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों** (नंद घर) के निर्माण की आधारशिला भी रखी।

लक्षद्वीप

- भारत का **सबसे छोटा केंद्र** शासित प्रदेश **लक्षद्वीप** एक **द्वीपसमूह** है जिसमें **36 द्वीप** हैं और **क्षेत्रफल 32 वर्ग** किमी है।
- यह एक **जिला-केंद्र शासित प्रदेश** है और **द्वीपों** को **वर्ष 1956** में एक **केंद्र शासित प्रदेश** का गठन किया गया था।
- इसमें **12 एटोल, 3 चट्टानें, 5 जलमग्न तट** और **10 द्वीप आबादी** वाले आदि द्वीप शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में प्रमुख द्वीप **मिनिकॉय** और **अमिनदीवी** समूह के द्वीप हैं।
- सबसे पूर्वी द्वीप **केरल राज्य** के तट से लगभग **185 मील (300 किमी)** दूर स्थित है।
- 10 द्वीपों में आबादी है।
- इसकी राजधानी कवरत्ती है

21. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने के संबन्ध में अदालतों को दिशानिर्देश दिए - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- उच्च न्यायालय
- सुप्रीम कोर्ट

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने **अदालतों** द्वारा **सरकारी अधिकारियों** को नियमित रूप से बुलाने और अपमानित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- यह कदम अप्रैल 2023 के **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के आदेश का पालन करता है, जिसके कारण पूर्व **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** के लिए घरेलू मदद के नियमों से संबंधित मुद्दों पर **उत्तर प्रदेश सरकार** के **वरिष्ठ अधिकारियों** की गिरफ्तारी हुई थी।

मुख्य बिंदु

सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश
- भारत के **मुख्य न्यायाधीश** ने **न्यायिक कार्यवाही** में सम्मान का माहौल बनाने के महत्व पर जोर देते हुए **मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)** की स्थापना की ।

भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता
- SOP में कहा गया है कि **अधिकारियों** की **भौतिक उपस्थिति** की आवश्यकता केवल दस्तावेजों या **मौखिक बयानों** जैसे सबूतों से निपटने के दौरान ही हो सकती है।
- अन्यथा, अदालतों को सलाह दी जाती है कि वे **भौतिक उपस्थिति** के लिए **नियमित निर्देशों** से बचते हुए हलफनामे और अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करें।

असाधारण मामले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- **व्यक्तिगत उपस्थिति** की आवश्यकता वाले असाधारण मामलों में, अदालत को **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** को पहले विकल्प के रूप में मानने की सलाह दी जाती है।
- **व्यक्तिगत उपस्थिति** के निर्देश देने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए, और **अधिकारियों** को तैयारी के लिए **पर्याप्त नोटिस** और **एक निर्दिष्ट समय स्लॉट** दिया जाना चाहिए।

व्यावसायिकता और ड्रेस कोड
- अदालतों से आग्रह किया जाता है कि वे व्यावसायिकता बनाए रखें और अधिकारियों की उपस्थिति, कपड़े, शिक्षा या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचें।
- SOP पोशाक पर टिप्पणियों से बचने पर जोर देती है जब तक कि **निर्दिष्ट ड्रेस कोड** का उल्लंघन न हो।

उत्तर प्रदेश मामले की पृष्ठभूमि
- ये दिशा-निर्देश **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा **उत्तर प्रदेश सरकार** के **अधिकारियों** को बार-बार तलब किए जाने को लेकर **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** की अस्वीकृति से प्रेरित थे।
- उच्च न्यायालय के **पूर्व न्यायाधीशों** को **घरेलू मदद** के नियमों पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर **उच्च न्यायालय** ने **अधिकारियों** के खिलाफ **जमानती वारंट** जारी करने सहित कार्रवाई की थी।

न्यायालय की अस्वीकृति और चेतावनी

- सुप्रीम कोर्ट ने **हाई कोर्ट** के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि **अधिकारियों** को बुलाना एक नियमित उपाय नहीं होना चाहिए और इसे केवल **सीमित परिस्थितियों** में ही नियोजित किया जाना चाहिए।

22. जेलों में जातिगत भेदभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मॉडल कारागार अधिनियम 2023
- मौलिक अधिकार

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में कहा कि **भारत भर** की **जेलों की चारदीवारी** के भीतर **कैदियों** के साथ **जाति-आधारित भेदभाव** एक **"बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा"** है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्य बिंदु

- भारत के **मुख्य न्यायाधीश** की अध्यक्षता वाली **तीन-न्यायाधीशों** की पीठ ने पाया कि **10** से **अधिक राज्यों** में **जेल मैनुअल** में ऐसे प्रावधान हैं जो जेलों में जाति के **आधार पर भेदभाव** और **जबरन श्रम** को मंजूरी देते हैं।
  - राज्य में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं।

सुनील बत्रा मामला

- एक कैदी को सभी **संवैधानिक अधिकार** और **सुरक्षा** प्राप्त हैं, सिवाय उन अधिकारों के जो कारावास के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से और सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं

मॉडल कारागार अधिनियम 2023

- जेलों में मोबाइल फोन जैसी **प्रतिबंधित वस्तुओं** के **इस्तेमाल** पर **कैदियों** और **जेल कर्मचारियों** के लिए सजा का प्रावधान।
- उच्च सुरक्षा जेलों, खुली जेल (खुली एवं अर्ध-खुली) की स्थापना एवं प्रबंधन।
- दुर्दांत अपराधियों और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए प्रावधान।
- अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, छुट्टी और समय से पहले रिहाई प्रदान करना।
- जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से **जेल प्रशासन** में **प्रौद्योगिकी** के उपयोग के प्रावधान हैं।
- अदालतों के साथ **वीडियोकांफ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक** और **तकनीकी हस्तक्षेप** आदि का प्रावधान।

23. स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध
- पहुंच, निगरानी और रिजर्व (AWaRe)
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC)

समाचार:

- हाल ही में **स्वास्थ्य मंत्रालय** ने **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** द्वारा किए गए एक **सर्वेक्षण** के **नतीजे जारी** किए ।
- सर्वेक्षण में **नवंबर 2021** और **अप्रैल 2022** के बीच **15 राज्यों** और **दो केंद्र शासित प्रदेशों** के **20 तृतीयक** देखभाल संस्थानों में **मरीजों का सर्वेक्षण** मैप किया गया

एंटीबायोटिक प्रतिरोध संबंधी चिंताएँ

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी भी **सूक्ष्मजीव** द्वारा **संक्रमण** के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली **रोगाणुरोधी** दवाओं के खिलाफ अर्जित प्रतिरोध है।
- यह तब होता है जब एक **सूक्ष्मजीव** समय के साथ बदलता है और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता है जिससे **संक्रमण** का इलाज करना कठिन हो जाता है।

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने **सार्वजनिक स्वास्थ्य** के लिए शीर्ष खतरों में से एक के रूप में **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)** की पहचान की है।
- **अत्यधिक** और **अनुचित एंटीबायोटिक** का उपयोग **एंटीबायोटिक प्रतिरोध** का एक प्रमुख चालक है।

मुख्य निष्कर्ष

- भारत में लगभग **10,000 सर्वेक्षण** किए गए अस्पताल के मरीजों में से **50%** से अधिक को उपचार के बजाय **रोकथाम** के लिए **एंटीबायोटिक्स** निर्धारित किए गए थे।
- **94%** ने पुष्टिकृत निदान से पहले **एंटीबायोटिक्स** प्राप्त कीं, जिससे बढ़ती **एंटीबायोटिक प्रतिरोध** के बारे में चिंता बढ़ गई।
- लगभग 3% नुस्खे "अनुशंसित नहीं" समूह के थे।

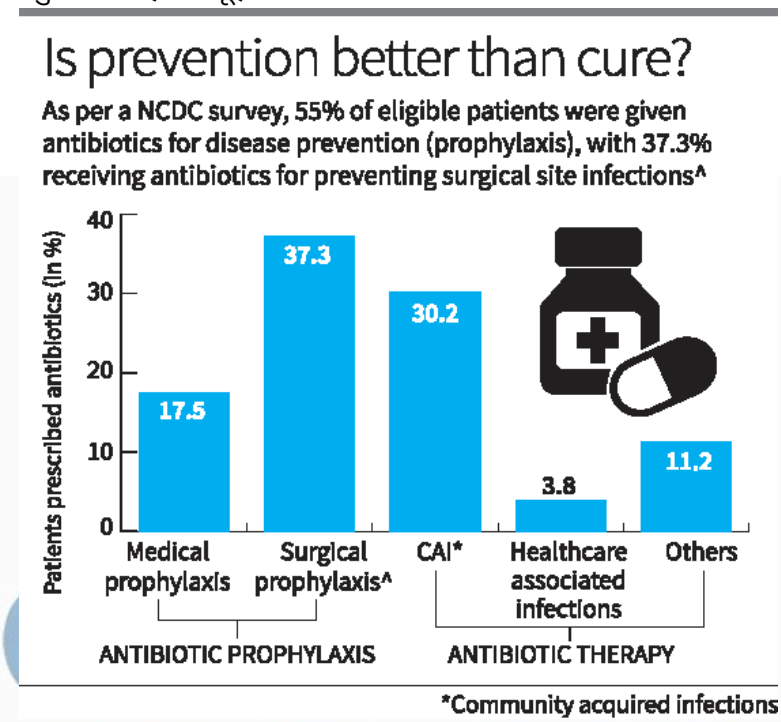

वैश्विक परिदृश्य

- WHO की **वैश्विक बिंदु प्रसार सर्वेक्षण पद्धति** का उद्देश्य अस्पतालों में निर्धारित पैटर्न को समझना है।
- यह रोगी स्तर पर **एंटीबायोटिक्स** कैसे निर्धारित और उपयोग किए जाते हैं, इस बारे में **सीमित** जानकारी को संबोधित करने का प्रयास करता है।
- इस पद्धति का उपयोग करके भारत में कुछ अध्ययन आयोजित किए गए हैं।

अस्पताल की असमानताएँ

- अस्पतालों में व्यापक भिन्नताएँ हैं, जिनमें **37% रोगियों** को **एंटीबायोटिक्स** लिखने से लेकर अन्य में **100%** तक शामिल हैं।
- कुल मिलाकर, **12,342 एंटीबायोटिक** नुस्खे थे, जिनमें से **86.5% पैरेंट्रल मार्ग** के माध्यम से निर्धारित थे यानी मौखिक रूप से नहीं लिए गए थे।

WHO की पहुंच, निगरानी और रिजर्व के अनुसार एंटीबायोटिक वर्गीकरण (AWaRe)

- **अभिगमन**
  - सबसे आम और गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है।
  - केवल 38% नुस्खे एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक्स के लिए थे, जो सर्वोत्तम चिकित्सीय मूल्य प्रदान करते थे।
- **निगरानी**
  - स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में हर समय एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं।
  - 57% वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स के लिए थे, जिनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध की अधिक संभावना थी।

- **संरक्षित**
  - एंटीबायोटिक्स का उपयोग कम मात्रा में किया जाना चाहिए या संरक्षित किया जाना चाहिए और केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
  - केवल 2% "अंतिम उपाय" रिज़र्व समूह से थे।

भारत में AMR पर नज़र रखना

- NCDC AMR **रोकथाम** पर भारत के **राष्ट्रीय कार्यक्रम** के लिए **नोडल एजेंसी** है।
- यह अपने द्वारा स्थापित **राष्ट्रीय एंटीबायोटिक उपभोग नेटवर्क (NAC-NET)** के माध्यम से **एंटीबायोटिक** के उपयोग की निगरानी करता है।
- NAC-NET के माध्यम से, नेटवर्क साइटें अपने संबंधित **स्वास्थ्य सुविधाओं** में **एंटीबायोटिक खपत** पर डेटा संकलित करती हैं और इसे **NCDC** को भेजती हैं।

24. हिमाचल प्रदेश HC ने हाटी समुदाय को ST में शामिल करने पर रोक लगा दी - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लोकुर समिति
- अनुसूचित जनजाति

समाचार:

- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा **हाटी समुदाय** को **अनुसूचित जनजाति (ST)** सूची में शामिल करने के निर्देश जारी करने के कुछ दिनों बाद , **हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय** ने **4 जनवरी, 2024** को अंतरिम रोक जारी की ।
- अदालत ने संसद के फैसले की **तर्कसंगतता पर सवाल** उठाया और **राज्य** और **केंद्र सरकारों** से जवाब मांगा।

समावेशन मानदंड पर न्यायालय की आलोचना:

- अदालत ने **ब्राह्मण** और **राजपूत** जैसे **प्रमुख जाति समुदायों** को **हाटी** के रूप में शामिल करने पर चिंताओं को उजागर किया, जिसमें कहा गया कि यह असमानों को समान मानता है।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी कठिन **भौगोलिक क्षेत्र** में निवास मात्र से **अगड़ी जातियों** को **अनुसूचित जनजातियों** को होने वाले नुकसान का दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए।

समावेशन के लिए विशेषताओं का अभाव:

- अदालत ने बताया कि **डिप्टी सॉलिसिटर जनरल** और **अटॉर्नी जनरल** यह बताने में असमर्थ थे कि प्रमुख **जाति समुदाय लोकुर समिति** द्वारा उल्लिखित चार विशेषताओं को कैसे पूरा करते हैं।
- **ST समावेशन** के लिए **पैरामीटर** निर्धारित करने के लिए **वर्ष 1965** में **लोकुर समिति** का गठन किया **गया था:**
  - आदिम लक्षण
  - विशिष्ट संस्कृति
  - संपर्क में शर्म
  - पिछड़ापन

25. सुप्रीम कोर्ट ने अलगाववादी पन्नून की हत्या के साजिशकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वियना कन्वेंशन
- संयुक्त राष्ट्र

समाचार:

- **सुप्रीम कोर्ट** ने खालिस्तानी कार्यकर्ता **गुरपतवंत सिंह पन्नून** की हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्राग में हिरासत में लिए गए एक **भारतीय नागरिक** की याचिका खारिज कर दी।
- **न्यायमूर्ति संजीव खन्ना** ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला **सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय** कानून से जुड़ा है और इसे संबोधित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए न्यायिक सम्मान

- न्यायमूर्ति खन्ना ने **अंतरराष्ट्रीय कानून** और **अदालतों की संप्रभुता** का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।
- **वियना कन्वेंशन** के तहत **कांसुलर** पहुंच को स्वीकार किया गया, **न्यायाधीश** ने **याचिकाकर्ता** को सलाह दी कि यदि इनकार किया जाता है तो अधिकारियों से संपर्क करें।

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन

- इस कन्वेंशन को **14 अप्रैल 1961 को वियना, ऑस्ट्रिया** में आयोजित **राजनयिक संपर्क** और **प्रतिरक्षा** पर **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** द्वारा अपनाया गया था, **भारत** ने इस **कन्वेंशन** की पुष्टि की है।।
- यह **24 अप्रैल, 1964** को लागू हुआ और लगभग **सार्वभौमिक** रूप से अनुमोदित है, **पलाऊ** और **दक्षिण सूडान** अपवाद हैं।
- यह विशेष नियम, **विशेषाधिकार** और **उन्मुक्तियाँ** निर्धारित करता है जो **राजनयिक मिशनों** को स्थानीय कानूनों को लागू करने के माध्यम से बिना किसी दबाव या उत्पीड़न के डर के कार्य करने और अपनी भेजने वाली सरकारों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है।
- **यह निम्न के लिए प्रावधान करता है: -**
  - किसी मिशन को वापस लेना - जो आर्थिक या भौतिक सुरक्षा के आधार पर हो सकता है
  - राजनयिक संबंधों के उल्लंघन के लिए जो प्रतिरक्षा के दुरुपयोग या भेजने वाले और प्राप्त करने वाले राज्यों के बीच संबंधों में गंभीर गिरावट के जवाब में हो सकता है।
- "प्राप्तकर्ता राज्य" का तात्पर्य मेजबान राष्ट्र से है जहां एक राजनयिक मिशन स्थित है।

26. चुनाव आयोग ने नई पार्टियों को चुनाव चिह्न आवंटन के नियमों में बदलाव किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां

प्रीलिम्स टेकअवे

- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- निर्वाचन आयोग

समाचार:

- भारत के चुनाव आयोग ने **पंजीकृत गैर-मान्यता** प्राप्त **राजनीतिक दलों (RUPPs)** को प्रतीकों के आवंटन के लिए नए नियम लाए।

मुख्य बिंदु

- चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है:
  - पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित खाते
  - पिछले दो चुनावों के व्यय विवरण
  - चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन पत्र के साथ पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर।

पृष्ठभूमि

- **RUPP** या तो **नव-पंजीकृत पार्टियां** हैं या जिन्होंने **राज्य पार्टी** बनने के लिए **विधानसभा** या **आम चुनाव** में **पर्याप्त प्रतिशत वोट** हासिल नहीं किए हैं।
  - या जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा।
- **RUPP** को इस वचनपत्र के आधार पर सामान्य प्रतीक प्रदान किए जाते हैं कि वे "**किसी राज्य के विधान सभा चुनाव** के संबंध में कुल उम्मीदवारों में से **कम से कम 5%**" को खड़ा करेंगे।
- पहले **RUPP** ये ब्योरा अलग से दे रहे थे।
- अब इन ब्यौरों को सामान्य प्रतीकों के लिए **आवेदन के प्रारूप** का हिस्सा बनाया जा रहा है.
- **चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न (**आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के **पैरा 10 B** के प्रावधानों के तहत प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्धारित **प्रोफार्मा** में **RUPP** से आवेदन प्राप्त होते हैं।
- **सितंबर 2022** में, **EC** ने **86** गैर-मौजूद **RUPPs** को सूची से हटा दिया था और अन्य 253 को **'निष्क्रिय RUPPs'** घोषित कर दिया था।

27. भारत, नेपाल ने दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेपाल-भारत संयुक्त आयोग
- नवीकरणीय ऊर्जा
- स्थान आधारित प्रश्न

समाचार:
- भारत के **विदेश मंत्री** अपने **नेपाली समकक्ष** के साथ **सातवें नेपाल-भारत संयुक्त आयोग** की **सह-अध्यक्षता** के लिए **दो दिवसीय यात्रा** पर हैं।

बिजली निर्यात समझौता
- **नेपाल** और **भारत** ने अगले **10 वर्षों** में **भारत** को **10,000 मेगावाट बिजली** के **निर्यात** के लिए एक **दीर्घकालिक समझौते** पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते को **नेपाल** के **बिजली क्षेत्र** में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग
- **नेपाल विद्युत प्राधिकरण** और **नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,** भारत के बीच **नवीकरणीय ऊर्जा** में **सहयो**ग के लिए एक **समझौता ज्ञापन** पर **हस्ताक्षर** किए गए।
- यह समझौता दोनों देशों के बीच **नवीकरणीय ऊर्जा** के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के आपसी प्रयासों को दर्शाता है।

क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें
- भारत के **विदेश मंत्री** और उनके **नेपाली समकक्ष** द्वारा **तीन सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों** का वस्तुतः उद्घाटन किया गया।
- **ट्रांसमिशन लाइनों** में भारत की सहायता से पूरी की गई **132 केवी रक्सौल-परवानीपुर, 132 केवी कुशहा-कटैया** और **न्यू नौतनवा-मैनहिया** लाइनें शामिल हैं।

चर्चाओं का दायरा
- चर्चाएं **द्विपक्षीय संबंधों** के **विभिन्न पहलुओं** पर केंद्रित रहीं
  - व्यापार और आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, कृषि, ऊर्जा, बिजली, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, लोगों से लोगों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और विकास साझेदारी।
- विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि चर्चा में **नेपाल-भारत संबंधों** के व्यापक **स्पेक्ट्रम** को शामिल किया गया, जिसमें कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया।

28. भारत पड़ोसी साझेदारों के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध: विदेश मंत्री - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत-नेपाल संयुक्त आयोग
- नेपाल

समाचार:
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसियों, विशेषकर **नेपाल** के साथ अपने **संबंधों** को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्य बिंदु
- उनकी टिप्पणी **7वें भारत-नेपाल संयुक्त आयोग** की बैठक के दौरान दोनों देशों द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद आई है।
  - जिसमें भारत द्वारा अगले **10 वर्षों** में **10,000 मेगावाट जलविद्युत** आयात करने का समझौता भी शामिल है।
- भारत ने **वर्ष 2015** के भूकंप से प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए **1,000 करोड़** रुपये (या 75 मिलियन अमरीकी डालर) का **नेपाली वित्तीय पैकेज** बढ़ाने का भी फैसला किया है।
- दोनों पक्षों ने **द्विपक्षीय संबंधों** के सभी पहलुओं के साथ-साथ सहयोग के क्षेत्रों की भी समीक्षा की।
- वर्ष 1950 की **शांति** और **मित्रता संधि, सुरक्षा** और **सीमा संबंधी मामलों** पर भी चर्चा की गई
- प्रधानमंत्री ने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान **भारत-नेपाल संबंधों** के लिए **'HIT' फॉर्मूला** दिया था, "राजमार्गों के लिए H, I के लिए। और ट्रांसवेज़ के लिए T, HIT" का फॉर्मूला दिया था।

29. लाल सागर संकट के कारण शिपिंग और बीमा लागत में वृद्धि - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लाल सागर
- केप ऑफ़ गुड होप

समाचार:
- **लाल सागर व्यापार मार्ग** पर व्यवधान के कारण **शिपिंग** और **बीमा लागत** बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि जहाजों ने आगे के हमलों के डर से लंबे मार्ग अपनाना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु
- व्यापारी निकट भविष्य के लिए **अफ्रीका** के **केप ऑफ गुड होप** के आसपास **लाल सागर मार्गों** से सभी जहाजों को मोड़ रहे हैं, और ग्राहकों को महत्वपूर्ण व्यवधान के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहे हैं।
- दुनिया भर के **जहाज़ लाल सागर** (स्वेज़ नहर के माध्यम से एशिया से यूरोप तक का सबसे छोटा मार्ग) से दूर जा रहे हैं
  - यमन में **ईरान समर्थित हौथी उग्रवादियों** ने गाजा में **इजराइल** से लड़ रहे **फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास** के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं।
- अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा के समय में लगभग 10 दिन बढ़ सकते हैं और अधिक ईंधन और चालक दल-समय की आवश्यकता होती है, जिससे **शिपिंग लागत** बढ़ जाती है।
- **हौथी उग्रवादियों** द्वारा अपने एक जहाज पर हमले के बाद **डेनमार्क** ने **लाल सागर** की ओर जाने वाले सभी जहाजों को रोक दिया है, और तब से **अफ्रीका** के **चारों** ओर **जहाजों** को पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया है।
- इस सप्ताह की शुरुआत में, **अमेरिका** और **ग्यारह** अन्य देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर **लाल सागर** में **हौथी हमलों** को समाप्त करने का आह्वान दोहराया है।

लाल सागर
- **अफ्रीका और एशिया** के बीच **हिंद महासागर का प्रवेश द्वार** ।
- दुनिया में सबसे अधिक खारे पानी वाले निकायों में से एक।
- **सीमावर्ती देश:** मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती ।
- **बाब अल मांडेब जलडमरूमध्य** और **अदन की खाड़ी** के **माध्यम** से **दक्षिण** में **हिंद महासागर** से जुड़ा हुआ है।
- उत्तर में **सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी** और **स्वेज़ की खाड़ी** (स्वेज़ नहर की ओर जाने वाली) हैं।
- यह **ग्रेट रिफ्ट वैली** (एफ्रो-अरेबियन रिफ्ट वैली) के एक हिस्से पर स्थित है।

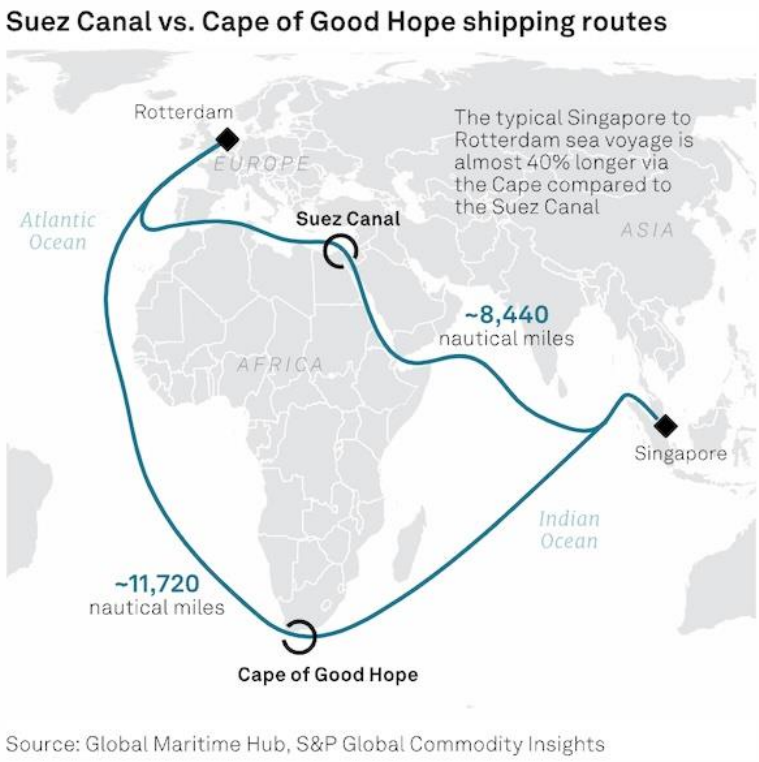

30. शिक्षा मंत्रालय ने PRERANA कार्यक्रम लॉन्च किया - पीआईबी

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वर्नाक्युलर स्कूल
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

समाचार:
- भारत सरकार के **शिक्षा मंत्रालय** के **स्कूली शिक्षा** एवं **साक्षरता विभाग** ने ' **प्रेरणा(PRERANA)**: एक **अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम**' लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु
- **उद्देश्य**
  - सभी प्रतिभागियों को **एक सार्थक, अद्वितीय** और **प्रेरक अनुभव प्रदान** करना, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके।
  - भारतीय शिक्षा प्रणाली के **सिद्धांतों** और **मूल्य-आधारित शिक्षा** के दर्शन को एकीकृत करना जो **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** की आधारशिला है।
- प्रेरणा(PRERANA) **नौवीं** से **बारहवीं कक्षा** के **चयनित छात्रों** के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है।
- यह सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक वाले छात्रों के लिए एक **अनुभवात्मक** और **प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम** है जहां विरासत नवाचार से मिलती है।
- देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह **20 चयनित छात्रों (10 लड़के** और **10 लड़कियां)** का एक **बैच कार्यक्रम** में भाग लेगा।
- प्रेरणा (PRERANA) कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक, **वडनगर, जिला मेहसाणा, गुजरात** में **वर्ष 1888** में स्थापित **वर्नाक्युलर स्कूल** से चलेगा।
- दिन-वार कार्यक्रम अनुसूची में **योग, माइंडफुलनेस** और **ध्यान सत्र** शामिल होंगे, इसके बाद अनुभवात्मक शिक्षा, विषयगत सत्र और व्यावहारिक दिलचस्प शिक्षण गतिविधियाँ होंगी।
- शाम की गतिविधियों में **प्राचीन** और **विरासत स्थलों** का दौरा, **प्रेरणादायक फिल्म स्क्रीनिंग, मिशन जीवन रचनात्मक गतिविधियां, प्रतिभा शो** आदि शामिल होंगे जो **समग्र शिक्षण दृष्टिकोण सुनिश्चित** करेंगे।
- इसके अलावा, छात्र विविध गतिविधियों में संलग्न होंगे, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाएंगे और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से सीखेंगे।

31. केंद्र सरकार ने 'पृथ्वी(PRITHVI)' पहल को मंजूरी दी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पृथ्वी पहल
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

समाचार:
- सरकार ने हाल ही में **'पृथ्वी(PRITHVI)'** नामक एक नई पहल को मंजूरी दी है।

'पृथ्वी' पहल
- यह पांच साल की अवधि में अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के लिए आवंटित **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के भीतर **अंतर-विषयक परियोजनाओं** और **धन के संयुक्त उपयोग** की अनुमति देता है।
  - वायुमंडल, क्रायोस्फीयर, जियोस्फीयर और महासागर विज्ञान जैसे पारंपरिक कार्यक्षेत्रों के विपरीत।
- **उद्देश्य:** पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान को सुव्यवस्थित करना, अंतर-विषयक परियोजनाओं को बढ़ावा देना और अनुसंधान करने में आसानी बढ़ाना।
- यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को एक **एकीकृत इकाई** के रूप में मानता है।
- मंत्रालय के पास **4,797 करोड़ रुपये का बजट** है, जिसमें **पृथ्वी विज्ञान** से संबंधित **पांच अलग-अलग उप-योजनाओं** के लिए आवंटन शामिल है।

- **उप-योजनाओं**
  - वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ
  - महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी
  - ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान
  - भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान
  - अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को **विदेशी संस्थानों को** अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान करके उनके साथ सहयोग करने में भी सक्षम बनाता है।

32. जम्मू-कश्मीर में कोई स्थानीय निकाय सदस्य नहीं होगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जिला विकास परिषद
- 73वां संशोधन

समाचार:
- **जम्मू** और **कश्मीर** के लोगों को, जिनका वर्ष **2018** के बाद से कोई **विधानसभा प्रतिनिधित्व** नहीं मिला है, जमीनी स्तर पर भी कोई **चुनावी प्रतिनिधित्व** नहीं मिलेगा।

मुख्य बिंदु
- लगभग **30,000 स्थानीय प्रतिनिधियों** का **पांच साल** का **कार्यकाल** समाप्त होने वाला है
- **नगर निकायों** और **पंचायतों** का अगला चुनाव कब होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है
  - क्योंकि **केंद्र सरकार** ने पहले **परिसीमन अभ्यास** करने का निर्णय लिया है।
- पिछली बार **वर्ष 2018** के अंत में **पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर** में पंचायत चुनाव हुए थे।
- कुल **27,281 पंच (पंचायत सदस्य)** और **सरपंच (ग्राम प्रधान)** चुने गए, और **10 जनवरी, 2019** को पद की शपथ ली।
- जम्मू-कश्मीर में **12,776 सरपंच** और **पंच** की **सीटें** खाली हैं।

परिसीमन प्रस्ताव
- **पंचायती राज विभाग** ने **जम्मू-कश्मीर** के सभी **खंड विकास अधिकारियों** को पत्र भेजकर **नगरपालिका वार्डों** और **पंच निर्वाचन क्षेत्रों** की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
  - इस प्रकार कि जहां तक संभव हो, प्रत्येक के पास समान संख्या में मतदाता होंगे।
- 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को **30 सितंबर, 2024** तक **जम्मू-कश्मीर** में **विधानसभा चुनाव** कराने का निर्देश दिया।
- सितंबर 2018 में, **केंद्र सरकार** ने संविधान के **73वें संशोधन** के तहत **29 विषयों** के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया।
- संवैधानिक संशोधन अधिनियम **के बाद सिफारिशों को आंशिक रूप से अपनाया था**
  - **पंचायती राज संस्थाओं** को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान करने का प्रस्ताव **वर्ष 1993** में **संसद** द्वारा पारित किया गया था।
- वर्ष 2020 में, **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **जम्मू और कश्मीर** पंचायती राज अधिनियम, 1989 के अनुकूलन को मंजूरी दी, जिसे उसी वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया था।
- इससे **केंद्र शासित प्रदेश** में **जिला विकास परिषदों** के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं
  - विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का इस प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है।
- इस कदम से देश के अन्य हिस्सों की तरह जमीनी स्तर के **लोकतंत्र** के **सभी तीन स्तरों** को स्थापित करने में मदद मिलेगी

33. भारत और सऊदी अरब ने हज समझौते पर हस्ताक्षर किए - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन

प्रीलिम्स टेकअवे
- मक्का
- हज यात्रा

समाचार:
- **भारत** और **सऊदी अरब** ने रविवार को एक **द्विपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत **नई दिल्ली** को इस साल की **वार्षिक हज यात्रा** के लिए **1,75,025 तीर्थयात्रियों** का कोटा आवंटित किया गया है।
- इसमें कहा गया है कि बिना **मेहरम वाली महिलाओं (LWM)** श्रेणी के तहत भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सरकार की पहल पर भी चर्चा की गई और इसकी सराहना की गई।

हज सब्सिडी
- यह **सरकारी स्वामित्व** वाली **एयरलाइनों** द्वारा दिए गए **रियायती हवाई किराए** को संदर्भित करता है।
- इसमें घरेलू यात्रा के लिए **मुस्लिम तीर्थयात्रियों** को विशेष रूप से डिजाइन किए गए **हज प्रस्थान हवाई अड्डे** के **टर्मिनलों** तक पहुंचने, **आवास, चिकित्सा देखभाल और भोजन** की सहायता भी शामिल है।
- **हज सब्सिडी** पहली बार **वर्ष 1932** में शुरू की गई थी जब **ब्रिटिश सरकार** ने एक **सरकारी वित्त पोषित हज समिति** की **व्यवस्था** की थी और **बॉम्बे** और **कलकत्ता** को **दो बंदरगाहों** के रूप में नामित किया था जहां से **मुसलमान** अपनी **तीर्थयात्रा** पर जा सकते थे।

हज यात्रा
- **हज** मुसलमानों के लिए सबसे **पवित्र शहर मक्का, सऊदी अरब** की एक **वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा** है।
- ऐसा करना **शारीरिक** और **आर्थिक** रूप से सक्षम सभी **वयस्क मुसलमानों** के लिए एक अनिवार्य **धार्मिक** कर्तव्य माना जाता है।

34. गृह मंत्री 'नेशनल पैक्स (PACS) मेगा कॉन्क्लेव' की अध्यक्षता करेंगे - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जन औषधि केंद्र
- PACS

समाचार:
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) जन औषधि केंद्रों** के रूप में संचालित करने के लिए तैयार हैं
- गृह एवं सहकारिता मंत्री **अमित शाह** यहां **राष्ट्रीय राजधानी** में आयोजित होने वाले **"नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव"** में नई पहल का जायजा लेंगे।

मुख्य बिंदु
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र** (PMBJK) **आम जनता** को गुणवत्तापूर्ण **जेनेरिक दवाएं** प्रदान करते हैं
  - जिसकी कीमत खुले बाजार में उपलब्ध **ब्रांडेड** दवाओं से **50-90%** कम है।
- केंद्रों के माध्यम से **आम नागरिकों** को 2,000 से अधिक प्रकार की **जेनेरिक दवाएं** और लगभग 300 **सर्जिकल आइटम** सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- PACS को हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
- इस पहल के लिए **34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** की 4,400 से अधिक **PACS/सहकारी समितियों** ने **भारत सरकार** के **फार्मास्यूटिकल्स विभाग** के पोर्टल पर अपने **ऑनलाइन** आवेदन जमा किए हैं।
- जिनमें से 2,300 से अधिक **सहकारी समितियों** को पहले ही प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है और उनमें से **149 जन औषधि केंद्र** के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

अधिक ग्रामीण नौकरियाँ
- इसमें कहा गया है कि इससे ग्रा**मीण क्षेत्रों** में **रोजगार** के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी ।
- सरकार ने **PACS** को मजबूत करने के लिए उनके **कम्प्यूटरीकरण,** उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने और **मॉडल उपनियम** लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं।

35. सरकार जल्द ही वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानदंडों की घोषणा करेगी - – द हिंदू/ सरकार वस्तुओं को गुणवत्ता मानक के तहत लाएगी: पीयूष गोयल - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020
- परख(PARAKH)

समाचार:
- **केंद्रीय वाणिज्य, खाद्य** और **उपभोक्ता मामलों** के **मंत्री पीयूष गोयल** ने कहा कि **केंद्र** जल्द ही लगभग **2,500 वस्तुओं** के लिए **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)** लाएगा।

मुख्य बिंदु
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** के **77वें स्थापना दिवस** पर एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि **वर्ष 2014** तक **106 उत्पादों** के लिए केवल **14 QCO** थे।
  - लेकिन यह **वर्ष 2024** तक **672 उत्पादों** के लिए **156 QCO** तक बढ़ गया।

प्रधान मंत्री जी का दृष्टिकोण
- प्रधानमंत्री ने **उच्च गुणवत्ता** वाले उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए **'शून्य दोष, शून्य प्रभाव'** का दृष्टिकोण सामने रखा था जो टिकाऊ, पर्यावरण के **अनुकूल** और **शून्य जलवायु प्रभाव** वाले हों।
- **केंद्रीय मंत्री** ने कहा कि युवा **ई-लर्निंग** को बढ़ावा दे सकते हैं
  - वे **कॉलेजों** और **विश्वविद्यालयों** में **समग्र विकास (PARAKH)** पहल के लिए **प्रदर्शन मूल्यांकन**, **समीक्षा** और **ज्ञान** के विश्लेषण को उन्नत कर सकते हैं।

परख(PARAKH)
- इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020** के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है
  - इसने नए **मूल्यांकन पैटर्न** और **नवीनतम शोध** के संबंध में **स्कूल बोर्डों** को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक-निर्धारण निकाय की परिकल्पना की।
- NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगी ।
- इसे **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)** और **राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण** जैसे समय-समय पर सीखने के **परिणाम परीक्षण** आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
- यह **तीन प्रमुख मूल्यांकन** क्षेत्रों **बड़े पैमाने पर मूल्यांकन**, **स्कूल-आधारित मूल्यांकन** और **परीक्षा सुधार** पर काम करेगा।

36. केंद्र ने फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया - द हिंदू/ सरकार ने दवा निर्माण के नए मानकों को अधिसूचित किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुसूची M
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945

समाचार:
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने **औषधि** एवं **प्रसाधन सामग्री नियम, 1945** की **अनुसूची M** के तहत अद्यतन नियमों की घोषणा की है
- इसका उद्देश्य **फार्मास्युटिकल** और **बायोफार्मास्युटिकल उत्पादों** के लि**ए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण** सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि
- अनुसूची M **फार्मास्युटिकल उत्पादों** के लिए अच्छी **विनिर्माण पद्धतियां (GMP)** की रूपरेखा तैयार करती है।

- GMP पहली बार **वर्ष 1988** में पेश किया गया था, अंतिम **संशोधन जून 2005** में किया गया था।
- **संशोधित अनुसूची M** 'अच्छी विनिर्माण पद्धतियां' को '**फार्मास्युटिकल उत्पादों** के लिए परिसर, **संयंत्र** और **उपकरण** की अच्छी **विनिर्माण पद्धतियां** और **आवश्यकताओं**' से प्रतिस्थापित करती है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों, विशेषकर **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के मानकों के अनुरूप होना है।
- अधिसूचित परिवर्तनों में शामिल हैं:
  - फार्मास्युटिकल गुणवत्ता प्रणाली (PQS) की शुरूआत
  - गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (QRM)
  - उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा (PQR)
  - उपकरण की योग्यता और सत्यापन
  - दवा उत्पादों के लिए कम्प्यूटरीकृत भंडारण प्रणाली।

निर्माता जिम्मेदारियाँ

- निर्माताओं को **फार्मास्युटिकल उत्पादों** की **गुणवत्ता, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं** का **अनुपालन** और रोगियों को होने वाले **जोखिमों से बचाव सुनिश्चित** करना अनिवार्य है।
- सत्यापन के लिए पर्याप्त उत्पाद नमूने को अपने पास रखते हुए, **सामग्री** के **संतोषजनक परीक्षण परिणामों** के बाद ही बाजार में **रिलीज** की अनुमति दी जाती है।

श्रेणियाँ और नए दिशानिर्देश

- संशोधित अनुसूची M में **फार्मास्युटिकल दवाओं** के निर्माण के लिए दिशानिर्देशों के साथ **13 भाग** शामिल हैं।
- दवाओं की **पांच नई श्रेणियां** पेश की गईं, जिनमें **खतरनाक पदार्थ** (लैंगिक हार्मोन, स्टेरॉयड, साइटोटॉक्सिक पदार्थ, जैविक उत्पाद और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स) शामिल हैं।

37. 'कुकिस, ज़ोमिस को ST सूची से हटाने के लिए याचिका - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मैतेई
- लोकुर समिति

समाचार:

- **केंद्र** ने **मणिपुर सरकार** से **मणिपुर** में **अनुसूचित जनजाति (ST)** सूची से **"घुमंतू चिन-कुकी"** को हटाने के अनुरोध की जांच करने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2023 में, विभिन्न मैतेई समूहों ने **मैतेई पंगल्स** की अपील के साथ, ST सूची में शामिल होने की मांग की ।
- मई 2023 में घाटी स्थित **मैतेई लोगों** और **पहाड़ी आधारित कुकी**-ज़ो लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए और विस्थापन हुआ।
- 19 मार्च, 2023 को **मणिपुर उच्च न्यायालय** के एक आदेश ने विवाद को जन्म दिया, जिसमें **राज्य सरकार** को **मैतेई** के लिए **ST दर्जे** की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया।

अनुसूचित जनजाति और आपत्तियों के लिए मानदंड

- समुदायों को **ST** घोषित करने के लिए **लोकुर समिति** के **वर्ष 1965** के मानदंडों में **आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, शर्मीलापन** और **पिछड़ापन** शामिल हैं।
- विशिष्ट चिंताओं में ST सूची में **जनजाति** के नामों की अनुपस्थिति, **गैर-स्वदेशी व्यक्तियों** के नामांकन के लिए जगह की अनुमति शामिल है।

मैतेई के समावेशन की ऐतिहासिक अस्वीकृति

- रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि **ST सूची** में शामिल करने के लिए **मैतेई समुदाय** के प्रस्ताव को **वर्ष 1982** और **वर्ष 2001** में खारिज कर दिया गया था।
- अधिकारियों ने उनमें **जनजातीय विशेषताओं** की कमी का हवाला दिया और उन्हें **मणिपुर** में **"प्रमुख समूह"** के रूप में सूचीबद्ध किया।

38. व्यक्ति केवल कानून के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार: सर्वोच्च न्यायालय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 142
- अनुच्छेद 14

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने **बिलकिस बानो** मामले के दोषियों को सजा में छूट देने के **गुजरात सरकार** के फैसले को पलटते हुए, **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** और **कानून के शासन** के बीच संबंध पर गौर किया।

कानून के शासन का महत्व
- अदालत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को **अनुच्छेद 21** के तहत एक **मौलिक अधिकार** के रूप में स्वीकार करती है लेकिन यह सवाल उठाती है कि क्या कानून का शासन इसे खत्म कर सकता है।
- **जॉन एडम्स** द्वारा परिभाषित कानून के नियम को कार्यकारी अराजकता के खिलाफ जांच के रूप में जाना जाता है, जो विधायी मंजूरी के बिना कोई **मनमानी गिरफ्तारी** या **हिरासत सुनिश्चित** नहीं करता है।

कानून के शासन की न्यायालय की व्याख्या
- अदालत **कानून के शासन** की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में करती है कि राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, निष्क्रियता, मनमाने कार्यों या कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफलताओं के कारण कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकता है।
- कानून के शासन का उल्लंघन **अनुच्छेद 14** के तहत समानता को नकारने के रूप में देखा जाता है, जिससे इसके प्रवर्तन के लिए न्यायिक जांच आवश्यक हो जाती है।

न्यायपालिका कानून के शासन के संरक्षक के रूप में
- अदालत इस बात पर जोर देती है कि लोकतंत्र में चुनिंदा अनुप्रयोग और खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए न्यायपालिका को कानून के शासन को कायम रखने में एक मार्गदर्शक होना चाहिए।

कानून का शासन बनाम मनमानी
- अदालत ने न्यायमूर्ति **एच आर खन्ना** के असहमतिपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून का शासन मनमानी के विपरीत है।
- यह वर्ष 2014 के फैसले का संदर्भ देता है, जिसमें कहा गया है कि **न्याय में न केवल दोषियों के अधिकार** शामिल हैं, बल्कि **पीड़ितों** और **समाज के कानून** का पालन करने वाले वर्गों के अधिकार भी शामिल हैं।

स्वतंत्रता की याचिका को अस्वीकार करना
- अदालत ने **स्वतंत्रता** की सुरक्षा के लिए **दोषियों** की याचिका को खारिज कर दिया, और कहा कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए, और माफी के आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- यह संविधान के **अनुच्छेद 142** का आह्वान करता है, जिसमें कहा गया है कि इसका उपयोग व्यक्तियों को जेल से बाहर रहने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है जब आदेशों को अमान्य माना जाता है।

यथास्थिति की बहाली
- **अनुच्छेद 14** के तहत **कानून** के **समान संरक्षण** के सिद्धांत का पालन करते हुए, **अदालत दोषियों** को **स्वतंत्रता** से वंचित करने को उचित ठहराती है क्योंकि उन्हें गलती से कानून के खिलाफ रिहा कर दिया गया था।
- अदालत यथास्थिति बहाल करने पर जोर देती है, क्योंकि **दोषियों की स्वतंत्रता** की रक्षा करने की याचिका को खारिज करते हुए सजा माफी के आदेशों को रद्द कर दिया गया है।

39. विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विकासशील भारत संकल्प यात्रा
- नमो ड्रोन दीदी योजना

समाचार:
- प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित **भारत संकल्प यात्रा (VBSY)** का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाएं सभी योग्य लोगों तक पहुंचे।

मुख्य बिंदु
- सरकार ने '**नमो ड्रोन दीदी योजना**' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों की संख्या को **दो करोड़** तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके तहत **VBSY** के दौरान लगभग **एक लाख ड्रोन** का प्रदर्शन किया गया था।
- फिलहाल ड्रोन के इस्तेमाल का **प्रशिक्षण केवल कृषि क्षेत्र** में ही दिया जा रहा है

विकसित भारत संकल्प यात्रा
- यह सभी **ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों** और **शहरी स्थानीय निकायों** को कवर करते हुए देश भर में **भारत सरकार** की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए **आउटरीच गतिविधियों** के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक **राष्ट्रव्यापी अभियान** है।
- यह अभियान **भारत सरकार** के विभिन्न **मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार** के **संगठनों** और **संस्थानों** की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य उन कमजोर लोगों तक पहुंचना है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अब तक लाभ नहीं उठा पाए हैं।

40. विनियमन से किसी विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति ख़त्म नहीं होती: CJI - द हिंदू/विनियमन किसी विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा ख़त्म नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ
- अनुच्छेद 30

समाचार:
- भारत के **मुख्य न्यायाधीश** की **अध्यक्षता** वाली **सात-न्यायाधीशों** की **पीठ** ने कहा कि कोई **शैक्षणिक संस्थान** केवल इस आधार पर अपनी **अल्पसंख्यक स्थिति** नहीं खो देता है कि उसका **प्रशासन** एक **क़ानून द्वारा विनियमित** होता है।

मुख्य बिंदु
- अदालत ने कहा कि एक **शैक्षणिक संस्थान** को केवल धार्मिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- संविधान के **अनुच्छेद 30** में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि **शैक्षणिक संस्थान** का प्रशासन पूरी तरह से **अल्पसंख्यक समुदाय** के **सदस्यों** द्वारा किया जाना चाहिए।
- **प्रशासन धर्मनिरपेक्ष** हो सकता **था और किसी भी समुदाय के छात्रों को प्रवेश मिल सकता था**
- **अदालत किसी** शैक्षणिक संस्थान को **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान** मानने के **सूचकांकों** के बारे में सवालों पर एक संदर्भ पर विचार कर रही है।
- मामले में संदर्भ के बिंदु **एस अज़ीज़ बाशा** बनाम **भारत संघ** मामले में अदालत की **पांच-न्यायाधीशों** की पीठ द्वारा **वर्ष 1967** के फैसले से उपजे हैं।
  - जिसने **वर्ष 1920** के **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय** अधिनियम में किए गए संशोधनों को मान्य किया।
- **एस अज़ीज़ बाशा फैसले** ने निष्कर्ष निकाला था कि **विश्वविद्यालय** एक **केंद्रीय विश्वविद्यालय** था और इसे **अल्पसंख्यक दर्जा** नहीं दिया जा सकता।

41. मद्रास HC ने सांसदों और विधायकों के चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज की - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त पार्टियाँ
- निर्वाचन आयोग

समाचार:
- मद्रास हाई कोर्ट ने **चार सांसदों** और **आठ विधायकों** के **चुनाव** को **रद्द घोषित** करने से **इनकार** कर दिया
- उन्होंने क्रमशः **वर्ष 2019** के आम चुनाव और **वर्ष 2021** के **विधानसभा चुनाव** में अन्य **राजनीतिक दलों** के **आरक्षित प्रतीकों** पर चुनाव लड़ा था।

संविधान का अनुच्छेद 329(B)
- उन्होंने कहा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी चुनाव पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका और किसी भी कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- इनका उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार के दौरान किया जाता है और **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs)** पर दिखाया जाता है, जहां मतदाता प्रतीक चुनता है और संबंधित पार्टी को वोट देता है।
- **वर्ष 1960** के दशक में, यह प्रस्तावित किया गया था कि **चुनावी प्रतीकों** का **विनियमन, आरक्षण** और **आवंटन संसद** के एक कानून, यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- इस प्रस्ताव के जवाब में, ECI ने कहा कि **राजनीतिक दलों** की मान्यता की निगरानी **चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी तरह प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा।
- **चुनाव आयोग चुनाव** के उद्देश्य से **राजनीतिक दलों** को **पंजीकृत** करता है और उनके **चुनाव प्रदर्शन** के आधार पर उन्हें **राष्ट्रीय** या **राज्य दलों** के रूप में मान्यता देता है।
- अन्य दलों को तो बस पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल घोषित कर दिया जाता है।

42. भारत, ब्रिटेन ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत और ब्रिटेन
- स्थान आधारित प्रश्न

समाचार:
- **भारत** और **ब्रिटेन** ने हाल ही में **भारत के रक्षा मंत्री** की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

समझौते
- द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन।
- अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग पर व्यवस्था पत्र (LoA) ।
  - **अनुसंधान एवं विकास** पर **LoA** पर **भारत** के **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन** (**DRDO**) और **ब्रिटेन** की **रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (DSTL)** के बीच हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिंदु
- **दो दशकों** से **अधिक समय** के बाद किसी **भारतीय रक्षा मंत्री** की यह पहली **ब्रिटेन** यात्रा है।
- रक्षा मंत्री ने कई **मुद्दों पर सार्थक चर्चा** पर प्रकाश डाला।
  - इनमें **रक्षा सहयोग, सुरक्षा** और **रक्षा औद्योगिक सहयोग** बढ़ाने पर भी चर्चा शामिल है।
- **हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्रोत्साहन देगा**
  - लोगों के बीच आदान-प्रदान को , विशेष रूप से युवाओं के बीच
  - दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान सहयोग के व्यापक क्षेत्र को

43. गैर सरकारी संगठनों और संघों को FCRA पंजीकरण प्राप्त हुआ - द हिंदू

प्रासंगिकता: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग - गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गैर सरकारी संगठनों
- FCRA

समाचार:
- दिल्ली में **ताइवान मुख्यालय** वाले एक **बौद्ध मठ** को **विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010** के तहत मंजूरी दे दी गई है, जिससे **संगठन विदेशी धन प्राप्त** करने में सक्षम हो गया है।

पृष्ठभूमि
- **फ़ो गुआंग शान सांस्कृतिक** और **शैक्षिक केंद्र** को अपने **"धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक** और **सामाजिक**" कार्यक्रम के लिए **FCRA पंजीकरण** प्राप्त हुआ है।
- **फ़ो गुआंग शान मठ व्यवस्था** की **शुरुआत 1960** के **दशक** में **ताइवान** में हुई थी और **दिल्ली केंद्र** की स्थापना **वर्ष 2008** में हुई थी।
- "यह एक **बौद्ध धार्मिक ट्रस्ट** है।
- कुल मिलाकर, 30 **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** और **संघों** को वर्ष के पहले महीने में **FCRA पंजीकरण** प्रदान किया गया है।

FCRA पंजीकरण वाला NGO
- पिछले साल **रिकॉर्ड संख्या में 1,111 गैर सरकारी संगठनों** को **विदेशी दान प्राप्त** करने की अनुमति दी गई थी, जो **वर्ष 2014** के बाद से सबसे अधिक है।
- **गृह मंत्रालय** के आंकड़ों से पता चलता है कि **धार्मिक श्रेणी** के तहत ताजा **FCRA पंजीकरणों** में से लगभग आधे **ईसाई गैर सरकारी संगठनों** के लिए हैं
- **विदेशी चंदा प्राप्त** करने के लिए **FCRA** के तहत **पंजीकरण अनिवार्य** है।
- पंजीकृत होने के लिए **NGO** के पास एक **निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक** या **सामाजिक** कार्यक्रम होना चाहिए।
- मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, **वर्ष 2014** से **वर्ष 2023** तक **3,294 संघों** को नया पंजीकरण दिया गया।
- मंत्रालय ने **19 दिसंबर, 2023** को **लोकसभा** को यह भी बताया कि **वर्ष 2021** और **वर्ष 2022** में **FCRA** के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त **कुल 1,615 आवेदनों** में से
- **कम से कम 722** को मंजूरी दे दी गई जबकि **225 आवेदन खारिज** कर दिए गए।
- मंत्रालय ने कहा कि इन आवेदनों को **FCRA 2010** के **प्रावधानों** और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
- इसमें कहा गया है कि **वित्तीय वर्ष 2019-2020**, **वित्तीय वर्ष 2020-21** और **वित्तीय वर्ष 2021-22** में **कुल 13,520 संघों** को **₹55,741.51 करोड़** का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ।
- 10 जनवरी तक, **देश में 16,987 FCRA-पंजीकृत NGO सक्रिय थे।**
- लगभग **6,000 NGO** के **FCRA पंजीकरण 1 जनवरी, 2022** से निष्क्रिय हो गए थे क्योंकि मंत्रालय ने उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था या **NGO** ने एक के लिए आवेदन नहीं किया था ।
- पंजीकरण **पांच साल** के लिए वैध है।

44. ब्रिटेन भारतीय सेनाओं के साथ प्रशिक्षण के लिए उन्नत नौसैनिक समूह भेजेगा - द हिंदू/ ब्रिटेन प्रशिक्षण के लिए हिंद महासागर में नौसेना जहाज भेजेगा: रक्षा सचिव - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- हिंद महासागर क्षेत्र
- अटलांटिक महासागर

समाचार:
- **ब्रिटेन नौसेना** इस साल के अंत में अपने **लिटोरल रिस्पांस ग्रुप** को **हिंद महासागर क्षेत्र** में भेजेगी, जिसके **कैरियर स्ट्राइक ग्रुप** की **वर्ष 2025** में भारत यात्रा की योजना है।
- भारतीय सेनाओं के साथ **संचालन** और **प्रशिक्षण** करेंगे

मुख्य विचार
- दोनों देशों ने **संयुक्त अभ्यास** से लेकर ज्ञान साझा करने और **प्रशिक्षकों** के आदान-प्रदान तक रक्षा में भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा की।
- ये कदम 2021 में घोषित 2030 **भारत-ब्रिटेन रोडमैप** में परिकल्पित व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं।

सामान्य चुनौतियाँ
- आने वाले वर्षों में, **ब्रिटेन और भारत** भी अपनी-अपनी सेनाओं के बीच अधिक जटिल अभ्यास शुरू करेंगे
  - वर्ष 2030 के अंत से पहले आयोजित किए जाने वाले एक ऐतिहासिक **संयुक्त अभ्यास** का निर्माण
  - बयान में कहा गया, "**महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों** की सुरक्षा और **अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित प्रणाली** को कायम रखने" के साझा लक्ष्यों का समर्थन करना।
- ब्रिटेन और भारत के बीच **रणनीतिक रक्षा साझेदारी में** उद्योग के साथ सहयोग भी महत्वपूर्ण है
- दोनों देश **विद्युत प्रणोदन** प्रणालियों पर एक साथ काम कर रहे हैं जो हमारे भविष्य के बेड़े को शक्ति प्रदान करेंगे, और जटिल हथियारों के विकास पर सहयोग कर रहे हैं
- दोनों पक्षों ने **द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम** के लिए एक **समझौता ज्ञापन (MoU)** और अनुसंधान और **विकास** में **रक्षा सहयोग** पर एक **व्यवस्था पत्र (LoA)** पर भी हस्ताक्षर किए।

45. WHO ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड का शुभारंभ किया - पीआईबी

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पारंपरिक बीमारियाँ
- WHO

समाचार:
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **आयुष मंत्रालय नई दिल्ली** में **ICD 11 TM मॉड्यूल 2, मॉर्बिडिटी कोड कार्यक्रम** लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।
- इस पहल का उद्देश्य **आयुर्वेद, सिद्ध** और **यूनानी प्रणालियों** पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को **WHO** की **अंतर्राष्ट्रीय रोगों के वर्गीकरण (ICD) श्रृंखला** में एकीकृत करना है।

मुख्य विकास

ASU चिकित्सा में वैश्विक एकरूपता
- **वैश्विक एकरूपता** के लिए **ICD-11** में **आयुर्वेद, सिद्ध** और **यूनानी आंकड़ों** को शामिल करना।
- **ASU चिकित्सा** में रोगों को परिभाषित करने के लिए शब्दावली की एक सार्वभौमिक संहिता की स्थापना करना।

CBHI की भूमिका और आयुष संहिता विकास
- स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत **केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI)**, **ICD** गतिविधियों के लिए **WHO** सहयोग केंद्र है।
- आयुष मंत्रालय ने **NAMSTE पोर्टल** के माध्यम से **आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कोड** विकसित किए।

दाता समझौता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना:

- आयुष मंत्रालय ने **WHO** के साथ एक **डोनर समझौते** पर हस्ताक्षर किए।
- इस सहयोग का उद्देश्य भारत की **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण, अनुसंधान, आयुष बीमा कवरेज** और **नीति-निर्माण प्रणालियों** को बढ़ाना है।

पारंपरिक चिकित्सा रोगों का समावेश

- बीमारियों को नियंत्रित करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले कोड।
- अन्य WHO सदस्य देश भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

रोग वर्गीकरण के उदाहरण

- **पारंपरिक बीमारियाँ** जैसे **संक्रामक रोग** (जैसे, मलेरिया) और **जीवनशैली** से जुड़ी **बीमारियाँ** (जैसे, पुरानी अनिद्रा) शामिल हैं।
- **वर्टिगो गाइडेंस डिसऑर्डर** जैसे विकारों के लिए **आयुर्वेद, सिद्ध** और **यूनानी** से विशिष्ट उदाहरण।

46. मालदीव, चीन रणनीतिक सहयोग को 'बढ़ाने' पर सहमत - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत और मालदीव
- बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)
- कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव

समाचार:

- हाल ही में, **चीन** और **मालदीव** ने अपने संबंधों को व्यापक **रणनीतिक सहकारी साझेदारी** तक बढ़ाने की घोषणा की।
- एक **संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति** में बढ़े हुए रणनीतिक सहयोग, विस्तारित **व्यावहारिक सहयोग** और **साझा भविष्य** की दिशा में संयुक्त प्रयासों का उल्लेख किया गया।

राजनयिक विकास

- दोनों देश **अंतरराष्ट्रीय** और **बहुपक्षीय मामलों** पर सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - यह कदम **वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI)** में **मालदीव** की भागीदारी के बाद उठाया गया है।
- वे **वर्ष 2024** से **वर्ष 2028** तक **चीन-मालदीव व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी** के निर्माण के लिए एक **"कार्य योजना"** तैयार करने पर सहमत हुए।
- **दोनों सरकारें कई क्षेत्रों** को कवर करते हुए **20 समझौता ज्ञापनों (MoUs)** पर हस्ताक्षर करती हैं।
  - इनमें **नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था**, **BRI** से जुड़ा **बुनियादी ढांचा विकास**, **आपदा** और **जोखिम शमन** और **समाचार सहयोग** शामिल हैं।

विदेश नीति में बदलाव

- दिसंबर में भारत के नेतृत्व वाले **कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव** की **NSA-स्तरीय** बैठक में **मालदीव** के शामिल न होने के बाद उल्लेखनीय निर्णय आए।
- यह **सोलिह सरकार** की पिछली नीति से विचलन का सुझाव देता है, जिसमें **भारत** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ **घनिष्ठ रक्षा** और **सुरक्षा सहयोग** पर जोर दिया गया था।

भारत के साथ राजनयिक तनाव

- **मालदीव** के **राष्ट्रपति** की यात्रा **मालदीव** और **भारत** के बीच एक **राजनयिक विवाद** के साथ मेल खाती है, जो **भारतीय प्रधानमंत्री** के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ है।
- तनाव के कारण **मालदीव के बहिष्कार** का आह्वान करने वाले **ऑनलाइन अभियान** शुरू हो गए, जिससे देश के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ा।

पर्यटन पर केन्द्रित

- मालदीव के राष्ट्रपति ने चीनी पर्यटकों को आगमन के मामले में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो पहले पिछले दो वर्षों से भारतीय पर्यटकों के पास था।
- बैठकों में, **मालदीव** के **राष्ट्रपति** ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के लिए समर्थन पर प्रकाश डाला और सहयोग बढ़ाने के लिए उत्साह व्यक्त किया।
- चीन ने **मालदीव के विकास पथ** के प्रति सम्मान और समर्थन का वादा किया और उसके आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध किया।

47. दक्षिण अफ़्रीका ने इज़राइल के ख़िलाफ़ हेग न्यायालय में मामला दायर किया - द हिंदू/ दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के खिलाफ ICJ में मामला दायर किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विश्व मामले

प्रीलिम्स टेकअवे
- नरसंहार सम्मलेन
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

समाचार:
- **दक्षिण अफ्रीका** ने **7 अक्टूबर** के **हमास हमले** की **सैन्य प्रतिक्रिया** में **इज़राइल** पर **नरसंहार** करने का आरोप लगाते हुए **ICJ** में एक मामला लाया है।
- **दक्षिण अफ़्रीकी** मामले में **इज़रायली** द्वारा **व्यापक बमबारी** के **उपयोग** और **गाजा** को भोजन, पानी और दवा की आपूर्ति में कटौती का संदर्भ शामिल है।

वर्तमान मामले में ICJ का क्षेत्राधिकार
- ICJ **अंतरराष्ट्रीय कानून** के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों पर **स्वतः निर्णय** नहीं ले सकता है ।
- यह केवल उन मामलों पर निर्णय ले सकता है जो इसके **अधिकार क्षेत्र** पर सहमति देने वाले **राज्यों** द्वारा इसके समक्ष लाए गए हैं।
  - कन्वेंशन के अनुसार, नरसंहार के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी सहित **कन्वेंशन** की व्याख्या करने, लागू करने या पूरा करने से संबंधित विवादों को ICJ में जाना चाहिए, यदि इसमें शामिल कोई भी पक्ष इसके लिए कहता है।
  - **दक्षिण अफ़्रीका** और **इज़राइल** दोनों ही कन्वेंशन के पक्षकार हैं।
- यदि ICJ कोई आदेश पारित करता है, तो **नरसंहार कन्वेंशन** के **पक्षकार सभी राज्यों** के लिए इसका **कानूनी महत्व** होगा।

संयुक्त राष्ट्र का 1948 नरसंहार सम्मेलन
- **नरसंहार** के **अपराध की रोकथाम** और **सजा पर कन्वेंशन** एक **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि** है जिसने पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया।
- यह 9 दिसंबर, 1948 को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाई गई पहली **मानवाधिकार संधि** थी और **12 जनवरी, 1951** से प्रभावी है।
- कन्वेंशन नरसंहार को **पांच शारीरिक कृत्यों** के रूप में परिभाषित करता है ।
  - एक समूह के सदस्यों को मारना
  - गंभीर शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाना
  - समूह पर जीवन की स्थितियाँ थोपकर उनका शारीरिक विनाश करने की योजना बनाई गई
  - एक समूह के भीतर जन्मों को रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना
  - समूह के बच्चों को किसी अन्य समूह में जबरन स्थानांतरित करना, किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से प्रतिबद्ध है।

48. विश्व पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट- 2024 जारी - हिंदुस्तान टाइम्स

प्रासंगिकता: रिपोर्ट और सूचकांक

प्रीलिम्स टेकअवे
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
- वीज़ा

समाचार:
- हाल ही में जारी वर्ष 2024 **हेनले पासपोर्ट इंडेक्स** से पता चलता है कि **वर्ष 2006** के बाद से **वीज़ा-मुक्त** गंतव्यों की औसत संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- यात्रियों के लिए **वीज़ा-मुक्त गंतव्यों** की औसत संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, **वर्ष 2006** में **58** से बढ़कर **वर्ष 2024** में **111** हो गई है।

शीर्ष रैंक वाले पासपोर्ट
- छह देशों ने **शीर्ष स्थान** हासिल किया है, जो नागरिकों को **227 वैश्विक गंतव्यों** में से **194 तक वीज़ा-मुक्त** पहुंच प्रदान करते हैं।।

- इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं।
- **जापान** और **सिंगापुर** ने लगातार **पांचवें साल** अपना **नेतृत्व बरकरार** रखा है।
- **शीर्ष 10** में बड़े पैमाने पर **यूरोपीय देशों** का दबदबा है।
- केवल **28 देशों** में बिना **वीजा** के प्रवेश के मामले में **अफगानिस्तान** सबसे **निचले स्थान** पर है।

भारत की पासपोर्ट रैंकिंग

- **भारत** वर्ष2024 **हेनले पासपोर्ट इंडेक्स** में **80वें** स्थान पर है।
- भारतीय पासपोर्ट **62 गंतव्यों** तक वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति देता है, जिसमें **थाईलैंड, इंडोनेशिया**, **मॉरीशस, श्रीलंका** और **मालदीव** जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

- यह दुनिया के **सभी पासपोर्टों की मूल, आधिकारिक रैंकिंग** है, जो उन गंतव्यों की संख्या पर आधारित है, जहां उनके धारक पहले से **वीजा प्राप्त** किए बिना यात्रा कर सकते हैं।
- एक **विशिष्ट पासपोर्ट** जितने देशों तक पहुंच सकता है, वह उसका **वीज़ा-मुक्त 'स्कोर'** बन जाता है।
- इसे **वैश्विक नागरिकता** और **निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स** द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है।
  - **इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA**) के विशेष डेटा पर आधारित।
- इसमें 1**99 अलग-अलग पासपोर्ट** और **227** अलग-अलग यात्रा गंतव्य शामिल हैं।

49. इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर - द हिंदू/स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023: राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्वच्छ सर्वेक्षण
- स्वच्छ भारत मिशन

समाचार:

- हाल ही में, **केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय** के वार्षिक **स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023** में **सूरत** और **इंदौर** को **संयुक्त रूप** से **भारत** के **सबसे स्वच्छ शहर** घोषित किया गया।
- दोनों शहरों में **100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण**, **98% स्रोत पृथक्करण** और **100% कचरा निपटान** का प्रदर्शन किया गया है।
- यह लगातार **सातवां वर्ष** है जब **इंदौर** को **भारत** के **सबसे स्वच्छ शहर** का **दर्जा** दिया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की मुख्य विशेषताएं

- महाराष्ट्र को **89.24% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण** और **67.76% स्रोत पृथक्करण** के साथ **सबसे स्वच्छ राज्य** के रूप में **मान्यता** दी गई थी।
- **कम रैंक वाले पांच राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा
- स्वच्छता कर्मियों के लिए **सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों** के लिए **चंडीगढ़** को **सम्मानित** किया गया।
- उत्तर प्रदेश में **वाराणसी** और **प्रयागराज** दोनों ने **सबसे स्वच्छ गंगा शहरों** में **शीर्ष दो पुरस्कार** जीते।
- मध्य प्रदेश में **महू छावनी बोर्ड** को **सबसे स्वच्छ छावनी** घोषित किया गया।

Ranking cleanliness

The tables list the cleanest cities with more than 1 lakh population and the best-performing States, according to the Swachch Survekshan Awards. Indore bagged the tag of India's cleanest city for the seventh consecutive time

Cleanest cities with >1 lakh population		States ranking	
Rank	City	Rank	State
1	Indore	1	Maharashtra
1	Surat	2	M.P.
3	Navi Mumbai	3	Chhattisgarh
4	Greater Visakhapatnam	4	Odisha
5	Bhopal	5	Telangana

स्वच्छता सर्वेक्षण

- **स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया** का सबसे बड़ा **शहरी स्वच्छता** और **स्वच्छता सर्वेक्षण** है।
- **वर्ष 2016** में **73 शहरों** के साथ शुरू हुई, **वार्षिक रैंकिंग** में **वर्ष 2023** में **4,416 शहरी स्थानीय निकायों, 61 छावनियों** और **88 गंगा कस्बों** को शामिल किया गया है।
- यह **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** के दायरे में संचालित किया जाता है।
- इसे **आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा **क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI)** के साथ इसके **कार्यान्वयन भागीदार** के रूप में **लॉन्च** किया गया था।
- **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर **नागरिक भागीदारी** को **प्रोत्साहित करना** और **कस्बों** और **शहरों** को रहने के लिए **बेहतर स्थान** बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में समाज के **सभी वर्गों के बीच जागरूकता** पैदा करना।
- स्वच्छता मापने की पद्धति **दो मुख्य मानदंडों** अर्थात **नागरिक प्रतिक्रिया** और **क्षेत्र मूल्यांकन** पर आधारित है।

50. मंत्रालय ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945
- अच्छी विनिर्माण प्रथाएँ (GMP)

समाचार:

- **स्वास्थ्य** और **परिवार कल्याण मंत्रालय** ने हाल ही में **औषधि** और **प्रसाधन सामग्री नियम, 1945** की **अनुसूची M** के तहत संशोधित नियम पेश किए हैं ।

संशोधन का उद्देश्य

- **अनुसूची M** के संशोधन का उद्देश्य **भारत** में **फार्मास्युटिकल विनिर्माण मानकों** को मजबूत करना है।
- यह **वैश्विक जांच** और **भारत से निर्यात** की जाने वाली **घटिया दवाओं** के बारे में चिंताओं के जवाब में है।
- **अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों** के **अनुरूप सुरक्षित, प्रभावी** और **उच्च गुणवत्ता** वाली दवाओं का निर्माण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (GMP) की** सिफारिशों को **वैश्विक मानकों,** विशेषकर **WHO** के मानकों के साथ संरेखित करना है।

वैश्विक संवीक्षा

- WHO द्वारा डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कफ सिरप के दूषित होने के संबंध में चेतावनी जारी करने के बाद भारत को वैश्विक जांच का सामना करना पड़ा, जिसे विषाक्त और संभावित रूप से घातक माना जाता है।
- पंजाब स्थित कंपनी QP फार्मकिम लिमिटेड का कफ सिरप गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से जुड़ा होने के बाद उसका विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

संशोधित श्रेणियाँ और अनुभाग

- दवाओं की **पांच नई श्रेणियां** पेश की गई हैं, जिनमें **खतरनाक पदार्थों** वाले **फार्मास्युटिकल उत्पाद** भी शामिल हैं।
  - इनमें यौन हार्मोन, स्टेरॉयड, साइटोटॉक्सिक पदार्थ, जैविक उत्पाद और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
- **अतिरिक्त अनुभाग**
  - फार्मास्युटिकल गुणवत्ता प्रणाली (PQS), गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (QRM), उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा (PQR) का परिचय
  - उपकरण की योग्यता और सत्यापन
  - औषधि उत्पादों के लिए कम्प्यूटरीकृत भंडारण प्रणाली
- निर्माता को **फार्मास्युटिकल उत्पादों** की **गुणवत्ता** की **जिम्मेदारी** लेनी होगी।
  - उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, **लाइसेंस आवश्यकताओं** का अनुपालन करते हैं, और **रोगियों** के लिए जोखिम पैदा नहीं करते हैं।

गुणवत्ता आश्वासन उपाय

- कंपनियों को सामग्री के **परीक्षण** से **संतोषजनक परिणाम** प्राप्त करने के बाद ही तैयार उत्पाद का विपणन करना चाहिए।
- किसी बैच के **बार-बार परीक्षण** या **सत्यापन** के लिए **मध्यवर्ती** और **अंतिम उत्पादों** के पर्याप्त नमूने रखे जाने चाहिए।

कार्यान्वयन समयसीमा

- **250 करोड़ रुपये** से कम **सालाना कारोबार** वाले **छोटे निर्माताओं** के पास **संशोधित नियमों** को लागू करने के लिए **12 महीने** का समय होगा।
- **250 करोड़ रुपये** से अधिक **वार्षिक कारोबार** वाले **बड़े निर्माताओं** को कार्यान्वयन के लिए **छह महीने** का समय दिया जाएगा।

51. भारत में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु वैक्सीन अभियान की तैयारी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- HPV वैक्सीन
- सर्वाइकल कैंसर
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

समाचार:

- भारत सरकार **सर्वाइकल कैंसर** की घटनाओं को कम करने के लिए **ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान** शुरू करने के लिए तैयार है।

HPV टीकाकरण अभियान

- इसे तीन वर्षों में **तीन चरणों** में योजनाबद्ध किया गया है और इसका लक्ष्य लगभग **8 करोड़ बच्चों** का **टीकाकरण** करना है।
- यह **भारतीय महिलाओं** में दूसरा सबसे आम **कैंसर सर्वाइकल कैंसर** से निपटने के लिए **9-14 वर्ष** की लड़कियों को लक्षित करेगा।
- यह टीका **अनूस, वेजाइना , ऑरोफरीनक्स** और **जननांग वर्ट्स** के कैंसर का कारण बनने वाले **HPV** उपभेदों से भी बचाता है।
- वर्तमान में व्यावसायिक रूप से इसकी कीमत **2,000 रुपये प्रति खुराक** है, सरकार के **टीकाकरण** कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यह मुफ्त में उपलब्ध होगी।

भारत में सर्वाइकल कैंसर का खतरा

- **वैश्विक सर्वाइकल कैंसर** के मामलों का लगभग **पांचवां हिस्सा** भारत में है, यहां सालाना **1.25 लाख** नए मामले और **75,000 मौतें** होती हैं।
- भारत में लगभग **83 प्रतिशत** आक्रामक स**र्वाइकल कैंसर** के मामलों का कारण **HPV 16** या **18** है।

टीकाकरण लॉजिस्टिक्स

- टीकाकरण अभियान **स्कूलों** और मौजूदा **टीकाकरण केंद्रों** के माध्यम से चलाया जाएगा।
- **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया** की **स्वदेशी रूप** से विकसित **क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन सेरवावैक** का उपयोग किया जाएगा।

एकल खुराक

- टीकाकरण पर **राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI)** ने **ICMR** को **9-15 आयु वर्ग** में **एकल खुराक** की प्रभावकारिता पर **परीक्षण** करने की सिफारिश की है।
- जबकि विश्व स्तर पर उपलब्ध **HPV** टीके **दो-खुराक** कार्यक्रम की सिफारिश करते हैं, **WHO** सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए **एकल खुराक** की अनुमति देता है।

52. SC ने CEC, EC की नियुक्ति के नए कानून पर रोक लगाने से इनकार किया - द हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने/CEC, EC की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां

प्रीलिम्स टेकअवे

- सर्च कमेटी
- **मुख्य चुनाव आयुक्त** और **अन्य चुनाव आयुक्त** (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि (अधिनियम, 2023

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और **चुनाव आयुक्तों (ECs)** का चयन करने वाले पैनल से **भारत के मुख्य न्यायाधीश** को बाहर करने वाले **नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने** के अनुरोध को **अस्वीकार** कर दिया।

मुख्य बिंदु

- संविधान के **अनुच्छेद 324(2)** में कहा गया है कि **CEC** और **ECs** की नियुक्ति **मंत्रिपरिषद** की **सहायता** और **सलाह** से **राष्ट्रपति** द्वारा की जाएगी।
  - जब तक **संसद चयन** के **मानदंड, सेवा की शर्तें** और **कार्यकाल** तय करने वाला कानून नहीं बना लेती।
- इसके बाद, सरकार ने एक नया कानून **मुख्य चुनाव आयुक्त** और अन्य **चुनाव आयुक्त** (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) **अधिनियम, 2023** बनाया।
  - **CJI** को **चयन पैनल** से बाहर करना।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

- यह **चुनाव आयोग** (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) **अधिनियम, 1991** का स्थान लेता है।

- यह **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और **चुनाव आयुक्तों (EC)** की **नियुक्ति, वेतन** और **निष्कासन** का प्रावधान करता है।
- चयन समिति की सिफारिश पर **CEC** और **EC** की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

चयन समिति

- चयन समिति में **प्रधान मंत्री,** एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** और **लोकसभा** में **विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल** के नेता शामिल होंगे।
- इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी **चयन समिति** की सिफारिशें मान्य होंगी।
- **कैबिनेट सचिव** की **अध्यक्षता** वाली एक **सर्च कमेटी** चयन समिति को नामों का एक **पैनल** प्रस्तावित करेगी।
- पदों के लिए **पात्रता** में **केंद्र सरकार** के **सचिव** के समकक्ष पद धारण करना (या धारण करना) शामिल है।
- CEC और EC का **वेतन** और **सेवा** शर्तें **कैबिनेट सचिव** के बराबर होंगी।
- वर्ष 1991 के अधिनियम के तहत, यह **सुप्रीम कोर्ट** के **न्यायाधीश** के वेतन के बराबर था।

53. 2. SC ने केरल सरकार द्वारा दायर मुकदमे की जांच करने हेतु सहमति दी- द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे

- राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट **केरल** द्वारा **दायर एक मूल मुकदमे की जांच** करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के **वित्त में केंद्र** का **हस्तक्षेप शासन** के **संघीय ढांचे** का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदु

कानूनी सम्मन और अंतरिम राहतें:

- **केरल** अंतरिम राहत चाहता है, जिसमें राज्य की **₹26,226 करोड़** की **उधारी को प्रतिबंधित** करने से **केंद्र के खिलाफ निषेधाज्ञा** भी शामिल है।
- केरल का तर्क है कि, **संघीय प्रणाली** में, एक **राज्य के पास बजट** तैयारी और **प्रबंधन** के माध्यम से अपने **वित्त को विनियमित** करने की **विशेष शक्ति** होती है।

- **केंद्र** की हालिया **कार्रवाइयों, संशोधनों** और **कार्यकारी आदेशों** को **केरल** को **वित्तीय संकट** में डालने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

मनमाने ढंग से उधार लेने पर प्रतिबंध के आरोप:

- **राज्य का तर्क** है कि **केंद्र** ने मनमाने ढंग से **शुद्ध उधार सीमा** लागू कर दी, जिससे **खुले बाजार** सहित **सभी स्रोतों** से **उधार लेना सीमित** हो गया।
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के उधारों से **कटौती** और **विदेशी ऋणों** पर लगाई गई शर्तों को **वित्तीय तनाव** पैदा करने वाले उपायों के रूप में उद्धृत किया गया है।
- केरल का दावा है कि **राजकोषीय उत्तरदायित्व** और **बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003** में संशोधन राज्य **के विधायी डोमेन** का उल्लंघन है।
- ये परिवर्तन कथित तौर पर राज्य की उधार लेने और उसके **वित्त को विनियमित** करने की क्षमता पर **असंवैधानिक सीमाएँ** लगाकर **राजकोषीय संघवाद** का उल्लंघन करते हैं।

54. भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा: इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वार्ता - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी

समाचार:

- **भारतीय रक्षा मंत्री** की हाल की **दो दिवसीय यात्रा** के दौरान **यूनाइटेड किंगडम** से **भारतीय युद्धपोतों** के लिए **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक** प्राप्त करने पर चर्चा आगे बढ़ी।

मुख्य बिंदु

गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट:

- विशेष रूप से **बड़े भारतीय नौसेना** के **युद्धपोतों** को शक्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटेन से **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन** प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए संभावित **गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट** की खोज एक केंद्र बिंदु थी।

वर्तमान प्रोपल्शन प्रणाली:

- भारतीय युद्धपोत वर्तमान में **डीजल इंजन, गैस** या **भाप टर्बाइन** का उपयोग करते हैं, जिनमें **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली** का अभाव है।
- इसके विपरीत, **ब्रिटेन** की **रॉयल नेवी** अपने **क्वीन एलिजाबेथ क्लास विमान वाहक** में एकीकृत **पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन** जहाजों का उपयोग करती है।

संयुक्त कार्यदल:

- **भारत** और **ब्रिटेन** के बीच एक **संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन** कार्य समूह की स्थापना की गई, जिसकी बैठक फरवरी में **ब्रिटेन** में और पिछले वर्ष मार्च में **कोच्चि** में **रॉयल नेवी फ्रिगेट HMS लैंकेस्टर** पर हुई।

परीक्षण और कार्यान्वयन:

- प्रस्तावित **इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी 6,000 टन** से अधिक के **विस्थापन** के साथ **बड़े भारतीय युद्धपोतों** पर लागू होने का अनुमान है।
- **लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक्स** और **अगली पीढ़ी** के **विध्वंसक विमानों** पर **प्रारंभिक परीक्षण** अपेक्षित है।

55. रेल मंत्रालय ने उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अमृत भारत स्टेशन योजना
- कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड

समाचार:

- **कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL)** नेटवर्क के तहत **उडुपी स्टेशन** पर ध्यान देने की सख्त जरूरत थी
- इसे पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय की **अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS)** में शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु

- मंत्रालय ने **उडुपी** को शामिल किए जाने की जानकारी **KRCL** को दी।
- जब **फरवरी 2023** में **केंद्रीय बजट** में **भारतीय रेलवे नेटवर्क** के **1,275 स्टेशनों** को कवर करने की घोषणा की गई थी, तब **KRCL** के किसी भी स्टेशन को **ABSS** के तहत शामिल नहीं किया गया था ।
- ऐसा इसलिए था क्योंकि **KRCL रेल मंत्रालय** के अधीन एक **सार्वजनिक क्षेत्र** का उपक्रम बना रहा और **भारतीय रेलवे** का अभिन्न अंग नहीं था।
- गैर-समावेशन ने **पश्चिमी तट** - **महाराष्ट्र, गोवा** और **कर्नाटक** में **रेलवे संरक्षकों** के बीच बहुत नाराजगी पैदा की
  - जिन्होंने भारत की आजादी के **75 साल** पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई **योजना** से **नेटवर्क** को बाहर रखने के लिए मंत्रालय को फटकार लगाई।
- इस **योजना** में **पुनर्विकास** के लिए **मास्टर प्लान** बनाना और उन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना शामिल था।
- पुनर्विकास में मोटे तौर पर **कवर्ड शेल्टर, कवर्ड फुट ओवरब्रिज, बेहतर सर्कुलेटिंग** और **वाहन पार्किंग क्षेत्रों** के साथ प्लेटफार्म सुधार शामिल है

56. महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष का दलबदल पर फैसला - द हिंदू-

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दल बदल विरोधी-कानून
- संविधान 91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

समाचार:
- महाराष्ट्र अध्यक्ष ने **महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री** के नेतृत्व वाले गुट के पास मौजूद **"विधायी बहुमत"** से यह समझ लिया कि वे **"वास्तविक"** शिवसेना हैं।

मुख्य बिंदु
- हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की एक **संविधान पीठ** ने **शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे** विवाद का फैसला करते हुए **मई 2023** के फैसले में निर्देश दिया था
  - अध्यक्ष को इस बात पर अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए कि कौन सा समूह **राजनीतिक दल** का गठन करता है, इस आधार पर कि किस समूह के पास विधान सभा में बहुमत है"।
- संविधान **(91वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003** ने **दसवीं अनुसूची** के **पैराग्राफ 3** में **'विभाजन'** के प्रावधान को हटा दिया।
- **दसवीं अनुसूची** से **पैराग्राफ 3** को हटाने का अपरिहार्य परिणाम यह है कि **अयोग्यता** की कार्यवाही का सामना करने वाले **सदस्यों के लिए विभाजन** की रक्षा अब उपलब्ध नहीं है।
- अन्यथा धारण करने का अर्थ होगा **दसवीं अनुसूची** में **'विभाजन'** की रक्षा को पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना।
- यह अनुमति योग्य नहीं है और **पैराग्राफ 3** को हटाना निरर्थक हो जाएगा।

दल-बदल विरोधी कानून
- दल-बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर **संसद सदस्यों (MP)/विधान सभा सदस्यों (MLA)** को दंडित करता है।
- विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके **सरकारों** में स्थिरता लाने के लिए संसद ने **वर्ष 1985** में इसे **संविधान** की **दसवीं अनुसूची** के रूप में जोड़ा।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम के नाम से **दसवीं अनुसूची** को **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
- यह किसी अन्य **राजनीतिक दल** में **दलबदल के आधार** पर **निर्वाचित सदस्यों** की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है।
- यह **वर्ष 1967** के **आम चुनावों** के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।

57. अयोध्या की मस्जिद 'ताजमहल से भी खुबसूरत और भव्य होगी :IICF - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे
- बाबरी मस्जिद
- ताज महल

समाचार:
- **अयोध्या मस्जिद** निर्माण की देखरेख करने वाला **इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF)** राम **मंदिर परियोजना** की सफलता से प्रेरित होकर एक **नई फंडिंग रणनीति** की योजना बना रहा है।

मुख्य बिंदु

प्रारंभिक योजना और चुनौतियाँ
- इसका लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी **कुरान के साथ**, **ताज महल** को पीछे छोड़ते हुए **भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों** में से एक का निर्माण करना है।
- मस्जिद में **पाँच मीनारें**, एक **शून्य-कार्बन-फ़ुटप्रिंट डिज़ाइन** और **प्रार्थना** के साथ एक **जल**-और-**लाइट शो** होगा।
- योजनाओं में एक **विशाल मछली मछलीघर** और **अस्पताल** और **सामुदायिक रसोई** का रखरखाव शामिल है।
- निर्माण **रमज़ान** के बाद **वर्ष 2024** की **दूसरी छमाही** में शुरू होने वाला है।
- **कुरान** की **आयतों** वाली एक **प्रतीकात्मक ईंट स्थल** पर रखे जाने से पहले सऊदी अरब और **प्रमुख दरगाहों** तक जाएगी।

ऐतिहासिक संदर्भ:
- मस्जिद, जिसे **वर्ष 2020** में **अयोध्या** के **धन्नीपुर** में **पांच एकड़** का **भूखंड आवंटित** किया गया था, ध्वस्त **बाबरी मस्जिद** के स्थान पर **राम मंदिर** के निर्माण के लिए **सुप्रीम कोर्ट** की मंजूरी के बाद सामने आई।

राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद विवाद
- यह अयोध्या में **2.77 एकड़** के **एक भूखंड** के बारे में है जिसमें **बाबरी मस्जिद** और **राम जन्मभूमि** है।
- यह विशेष **टुकड़ा हिंदुओं के बीच पवित्र माना जाता है** क्योंकि यह भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है।
- मुसलमानों का तर्क है कि **उस भूमि** पर **बाबरी मस्जि**द है, जहां उन्होंने विवाद शुरू होने से पहले वर्षों तक प्रार्थना की थी।
- विवाद इस बात पर है कि क्या बाबरी मस्जिद **16वीं सदी** में **राम मंदिर** को **तोड़कर** या **संशोधित** करके उसके ऊपर बनाई गई थी।
- दूसरी ओर, मुसलमानों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण **वर्ष 1528 ई**. में **मीर बाकी** ने किया था और **वर्ष 1949 ई.** में हिंदुओं ने इस पर नियंत्रण कर लिया, जब कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर **भगवान राम** की मूर्तियाँ रख दीं।

58. त्रिपुरा सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु भूमि का आवंटन किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ब्रू शरणार्थी
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:
- **त्रिपुरा सरकार** ने **मिजोरम ब्रू शरणार्थियों** के अंतिम बैच के **पुनर्वास** के लिए **भूमि आवंटित** की है
  - जिन्हें **16 जनवरी, 2020** को हस्ताक्षरित **गृह मंत्रालय** द्वारा शुरू किए गए **चतुर्पक्षीय समझौते** के माध्यम से **त्रिपुरा में स्थायी** निपटान की अनुमति दी गई थी।

मुख्य बिंदु
- समझौते के अनुसार, कुल **6,959** ब्रू (जिसे **रियांग** भी कहा जाता है) **जनजाति परिवारों** में **37,136 व्यक्ति** शामिल थे, जिन्हें राज्य के **चार जिलों** में **12 अलग-अलग स्थानों** पर **स्थायी** रूप से बसाया जाना था।
- **राज्य सरकार** द्वारा **शरणार्थियों** के अंतिम समूह के लिए भूमि की **पहचान** और **आवंटन** के साथ निपटान प्रक्रिया अब पूरी हो गई है।

- **12वीं बस्ती** कॉलोनी दक्षिण **त्रिपुरा जिले** के **शांतिरबाजार उपखंड** में स्थित **लौगांगसोम** में स्थापित की गई है
- अंतिम बस्ती कॉलोनी में **633 ब्रू परिवार** रहेंगे।
- यह **30 हेक्टेयर** के उस क्षेत्र में फैला होगा जो पहले अप्रयुक्त था।

मासिक राशन

- भूमि आवंटन के अलावा, शरणार्थियों को **गृह मंत्रालय (MHA)** और **त्रिपुरा** और **मिजोरम** की सरकारों द्वारा **ब्रू शरणार्थियों** के प्रतिनिधियों के साथ **हस्ताक्षरित चतुर्पक्षीय समझौते** के अनुसार **मासिक राशन** मिल रहा है।
  - जो **अक्टूबर 1997** में **मिजोरम** में **जातीय भेदभाव** की वजह से चले गए थे।

59. भारतरूस रणनीतिक साझेदारी को विकसित करने पर सहमत- - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- ब्रिक्स

समाचार:

- **भारतीय प्रधान मंत्री** और **रूसी राष्ट्रपति** ने **भारत** और **रूस** के बीच "विशेष और **विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी"** के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए एक **"गुड कन्वर्सेशन "** की।
- दोनों नेता चर्चा के दौरान भविष्य की पहल के लिए एक **रोडमैप** तैयार करने पर सहमत हुए।

मुख्य बिंदु

ब्रिक्स एजेंडा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय

- दोनों देशों ने **ब्रिक्स एजेंडे** के दृष्टिकोण में **निकट समन्वय** के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि की, साथ ही **भारत** ने **रूस की अध्यक्षता** के लक्ष्यों का **समर्थन करने** का इरादा व्यक्त किया।
- **यूक्रेन** के आसपास की स्थिति सहित **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों** पर चर्चा की गई, जिसमें चल रहे **रूस-यूक्रेन संघर्ष** पर प्रकाश डाला गया।

यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की भूमिका

- यह बातचीत **दावोस** में **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों** की एक बैठक के बाद हुई, जहां **स्विट्जरलैंड** ने **रूस** के साथ अपने प्रभाव के कारण **यूक्रेन शांति वार्ता** में भारत की संभावित भूमिका पर जोर दिया।

वार्षिक शिखर सम्मेलन की चुनौतियाँ

- पिछले साल यह दौरा नहीं हुआ था.
- शेड्यूलिंग चुनौतियों का हवाला दिया गया है, अंतिम शिखर सम्मेलन **6 दिसंबर, 2021** को होगा

60. सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भारत से जानकारी प्राप्त हुई अधिक कार्य की: आवश्यकताUSTR- द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत अमेरिका व्यापार नीति-) फोरमTPF)
- सामाजिक सुरक्षा समझौता

समाचार:

- **अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि** (USTR) ने कहा कि अमेरिका को हाल ही में प्रस्तावित **सामाजिक सुरक्षा समझौते** पर भारत से जानकारी मिली है और इस विषय पर बहुत काम किया जाना बाकी है।

मुख्य बिंदु

- **ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF**) की बैठक में **सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौता** भारतीय पक्ष की प्रमुख मांगों में से एक है।
  - क्योंकि यह देशों के बीच **सेवा व्यापार** को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और उन **भारतीय आईटी पेशेवरों** को मदद करेगा जो **अस्थायी रूप से अमेरिका** में काम करते हैं

- भारत ने अपनी **सामाजिक सुरक्षा** योजनाओं पर सभी **प्रासंगिक डेटा** जमा कर दिया है जो समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका द्वारा मांगा गया था।
- समझौते के तहत, किसी भी देश में रहने वाले **प्रवासी** को **मेजबान देश** की **सामाजिक सुरक्षा योजना** में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- इससे कई भारतीयों को लाभ होगा, खासकर आईटी क्षेत्र से, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और **सामाजिक सुरक्षा** का भुगतान कर रहे हैं लेकिन इसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

भारत-अमेरिका TPF

- भारत-अमेरिका TPF का लक्ष्य **कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा** के क्षेत्र में अपने कार्य समूहों को सक्रिय करना है।
  - बार-बार मिलना और आपसी हित के मुद्दों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद तरीके से संबोधित करना।
- इसका उद्देश्य बकाया **बाजार पहुंच मुद्दों** को हल करके **दोनों देशों** को ठोस लाभ पहुंचाना है।

61. लाल सागर शिपिंग संकट यूरोप में भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकता है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- निर्यात ऋण गारंटी निगम
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **लाल सागर शिपिंग संकट** यूरोप में **भारत के निर्यात** को प्रभावित कर सकता है
  - यूरोप के लिए लगभग **80 प्रतिशत निर्यात लाल सागर क्षेत्र** के माध्यम से होता है

मुख्य बिंदु

- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि **रूस-यूक्रेन युद्ध** की पृष्ठभूमि में कमजोर मांग के कारण **यूरोपीय संघ (EU)** को भारत का **माल निर्यात** पहले ही धीमा हो गया है।
- कुल माल निर्यात में यूरोपीय **संघ का योगदान 15 प्रतिशत** से अधिक है ।
- कार्बन सीमा **समायोजन तंत्र** और **यूरोपीय संघ** के **वनों की कटाई कानून** जैसे कई **पर्यावरण संबंधी** व्यापार उपायों से भविष्य में **भारत के निर्यात** पर असर पड़ने की आशंका है।
- मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर हमलों में वृद्धि हुई है
  - नवंबर के मध्य से **निचले लाल सागर** से यात्रा हो रही है और **यूरोप** के साथ **भारत** का **80 प्रतिशत** व्यापारिक **व्यापार लाल सागर** से होकर गुजरता है।

वैश्विक मुद्दा

- विश्व भर में समस्त वस्तुएँ **लाल सागर** मार्ग से **पूर्वी से पश्चिमी भाग** की ओर आती हैं
- लाल सागर क्षेत्र **वैश्विक कंटेनर यातायात** के **30 प्रतिशत** और **वैश्विक व्यापार** के **12 प्रतिशत** के लिए महत्वपूर्ण है
- लगभग **95 प्रतिशत जहाजों** ने **केप ऑफ गुड होप** के आसपास अपना मार्ग बदल लिया है, जिससे यात्रा में **4000 से 6000 समुद्री मील** और **14 से 20 दिन** लग गए हैं।
- यूरोप में **कृषि** और **कपड़ा** जैसे कम मूल्य वाले उत्पादों के **भारतीय शिपमेंट** को मुख्य रूप से **लाल सागर** क्षेत्र में व्यवधान के प्रभाव का सामना करने की उम्मीद है।
- **यूरोप** में **शिपिंग** की बढ़ती लागत के बीच **केंद्र सरकार** ने **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC)** से **बीमा प्रीमियम** नहीं बढ़ाने को कहा है।

62. गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA पंजीकरण रद्द किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- FCRA
- नीति अनुसंधान केंद्र

समाचार:

- **केंद्रीय गृह मंत्रालय** ने नई दिल्ली में एक प्रमुख सार्वजनिक **नीति अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR)** का विदेशी योगदान **विनियमन अधिनियम (FCRA)** पंजीकरण रद्द कर दिया है।

निलंबन का कालक्रम

- उल्लंघन के आधार पर **CPR** के लिए **FCRA** पंजीकरण निलंबित कर दिया गया।

रद्द करने का कारण

- गृह मंत्रालय रद्दीकरण के आधार के रूप में "**उल्लंघन**" का हवाला देता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि **CPR** ने "**वर्तमान मामलों के कार्यक्रमों**" पर रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे **FCRA** का उल्लंघन माना जाता है।

CPR का अनुपालन और परिप्रेक्ष्य

- **भारतीय सार्वजनिक जीवन** और **नीति-निर्माण** के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले शोध का संचालन करते हुए **कानूनी ढांचे के भीतर काम किया है ।**
- CPR अपने **मूल लक्ष्यों** के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका मानना है कि मामले को **संवैधानिक मूल्यों** के अनुसार हल किया जाएगा।

आयकर विभाग की कार्यवाही (2023)

- **टैक्स छूट निरस्तीकरण**: **वर्ष 2023** में, आयकर विभाग **CPR** की **टैक्स** छूट स्थिति रद्द कर देता है।
- **आरोप** : CPR पर उन व्यक्तियों को भुगतान करने का आरोप है जिन्होंने व्यक्तिगत **आयकर रिटर्न** दाखिल नहीं किया है, और **CPR** द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रकृति पर सवाल उठाया गया है।

आईटी विभाग को CPR का जवाब

- **CPR** ने **आईटी विभाग** द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।
- FCRA पंजीकरण रद्द होने से CPR के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं, जो गृह मंत्रालय और आयकर विभाग दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है।

63. ICMR ने NEDL को संशोधित करना शुरू किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
- NEDL

समाचार:

- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** ने **राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची (NEDL)** के लिए संशोधन प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
  - वर्ष 2019 में इसकी **प्रारंभिक रिलीज़** के बाद से अपडेट की आवश्यकता का हवाला देते हुए।

NEDL का उद्देश्य

- **NEDL** विभिन्न **स्वास्थ्य देखभाल** स्तरों पर आवश्यक समझे जाने वाले **मौलिक नैदानिक परीक्षणों** को सूचीबद्ध करने का कार्य करता है
  - जिसमें गाँव, **उप-स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य** और **कल्याण केंद्र** और **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य **वर्ष 2018** से **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की सिफारिशों के अनुरूप **स्वास्थ्य सेवा पिरामिड** में **महत्वपूर्ण परीक्षणों** की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

समावेशन के लिए मानदंड

- **ICMR** इस बात पर जोर देता है कि **NEDL** में **नैदानिक परीक्षणों** को शामिल करना बीमारी के बोझ के आंकड़ों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर आधारित है
  - राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संरेखण, और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन।
- परिषद रोग की व्यापकता, सार्वजनिक **स्वास्थ्य प्रासंगिकता** को ध्यान में रखते हुए **स्वास्थ्य देखभाल** आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाले आवश्यक **नैदानिक परीक्षणों** की रूपरेखा तैयार करती है।

हितधारक की भागीदारी

- हितधारकों से बीमारी के बोझ, **सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों** के साथ **तालमेल** और **उपकरण, बुनियादी** ढांचे और जनशक्ति की उपलब्धता पर विचार करते हुए प्रस्तावित परीक्षणों की अनिवार्यता का आकलन करने का आग्रह किया जाता है।
- सुझाए गए नैदानिक परीक्षणों को **रोग निदान** और **प्रबंधन** पर स्पष्ट प्रभाव के साथ **उच्च रोग बोझ** स्थितियों पर **ध्यान केंद्रित** करना चाहिए।
- प्रस्ताव में 2022 के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के साथ तालमेल पर जोर दिया गया है।

64. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर फैसला सुनाया इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका

प्रीलिम्स टेकअवे
- जनहित याचिका केंद्र
- CBI बनाम RR किशोर

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने कथित **कौशल विकास घोटाले** से संबंधित **FIR** को रद्द करने की **आंध्र प्रदेश** के **पूर्व मुख्यमंत्री** की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।

मुख्य बिंदु

'पिछली मंजूरी' की आवश्यकता पर असहमतिपूर्ण राय
- **2 न्यायाधीशों** की इस बात पर अलग-अलग राय है कि क्या **आंध्र प्रदेश CID** को **नायडू** के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से **'पूर्वानुमति'** की आवश्यकता थी।

जस्टिस बोस का परिप्रेक्ष्य
- दावा किया कि सीआईडी की जांच के लिए **पूर्वानुमति** आवश्यक थी ।
- जांच आरंभ के दौरान अनुमोदन की अनुपस्थिति को इंगित करता है ।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी का परिप्रेक्ष्य
- तर्क है कि अनुमोदन की आवश्यकता केवल **वर्ष 2018** के बाद किए गए अपराधों के लिए है, जब आवश्यकता पेश की गई थी।

'पिछली स्वीकृति' आवश्यकता का विकास

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम संशोधन (2003)
- यदि अधिकारी **संयुक्त सचिव** से उच्च पद पर हो तो **भ्रष्टाचार के अपराधों** की जांच के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 2014 में **सुप्रीम कोर्ट** ने खारिज कर दिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन (2018)
- धारा 17A के समान 'पिछला अनुमोदन' प्रावधान पेश किया गया।
- **आधिकारिक कर्तव्यों** के दौरान अपराध करने वाले **लोक सेवकों** से जुड़ी जांच के लिए अनुमोदन आवश्यक है।

CPIL द्वारा प्रावधान को चुनौती (2018)
- जनहित याचिका केंद्र (CPIL)
- संवैधानिकता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह जांच में बाधा डालता है और **भ्रष्ट अधिकारियों** को बचाता है।
- वर्ष 2014 के एक मामले का संदर्भ देता है जहां इसी तरह की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था।

पूर्वव्यापी आवेदन पर SC का पिछला रुख

संविधान पीठ का फैसला (2023)
- अधिकारी **धारा 6A** के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से छूट का दावा नहीं कर सकते, यहां तक कि इसे हटाने से पहले के अपराधों के लिए भी **अधिकारी छूट** का दावा नहीं कर सकते **(CBI बनाम RR किशोर)।**
- **राकेश अस्थाना केस** (2018-2022)
- दिल्ली के पूर्व **पुलिस कमिश्नर** पर रिश्वतखोरी की जांच।

- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल **पी एस नरसिम्हा** द्वारा पूर्व अनुमोदन के विरुद्ध राय।
- वर्ष 2022 में **अस्थाना की सेवानिवृत्ति** के बाद मामले को स्थगित कर दिया गया और निष्फल घोषित कर दिया गया।

65. भारत के KABIL ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है औरया भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।/

प्रीलिम्स टेकअवे
- अर्जेंटीना
- वाइट गोल्ड

समाचार:
- हाल ही में**, भारत** ने **अर्जेंटीना** में **पांच लिथियम ब्लॉक** के **अधिग्रहण की घोषणा** की ।
- खनन मंत्रालय ने **खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड)KABIL)** के माध्यम से **अर्जेंटीना** की **सरकारी स्वामित्व वाली CAMYEN** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु
- इस समझौते के साथ, **KABIL** ने **पांच ब्लॉकों** के लिए **अन्वेषण** और **विशिष्टता** अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।
- यह समझौता राज्य के स्वामित्व वाली इकाई को **मूल्यांकन, संभावना और अन्वेषण** करने की अनुमति देगा।
- **लिथियम खनिजों** की बाद की खोज पर, **वाणिज्यिक उत्पादन** के लिए **शोषण के अधिकार** भी प्रदान किए गए हैं।
- यह **भारत** में किसी **सरकारी कंपनी** द्वारा शुरू की गई **पहली लिथियम अन्वेषण** और खनन परियोजना है।
- इससे न केवल **लिथियम की सोर्सिंग** के लिए देश की खोज को बढ़ावा मिलेगा बल्कि **ब्राइन प्रकार लिथियम-अन्वेषण, शोषण** और **निष्कर्षण** के लिए **तकनीकी** और **परिचालन अनुभव** भी मिलेगा।
- **भारत** की लगभग **₹24,000 करोड़** की **लिथियम** आवश्यकताएँ **आयात के माध्यम** से पूरी की जाती हैं, जिनमें से अधिकांश आपूर्ति **चीन** से होती है।
- लिथियम, जिसे अक्सर '**सफेद सोना**' कहा जाता है, देश के **हरित ऊर्जा** विकल्पों में परिवर्तन की आधारशिला बनाता है।
- इसका उपयोग विभिन्न **श्रेणियों** में किया जाता है, जिसमें **ऊर्जा भंडारण समाधान, मोबाइल फोन** के लिए **बैटरी और EV** शामिल हैं ।
- चिली और बोलीविया के साथ **अर्जेंटीना** दुनिया के **"लिथियम त्रिकोण"** का हिस्सा है, और **तीनों** के पास दुनिया के कुल **लिथियम संसाधनों** का आधे से अधिक हिस्सा है।
- **अर्जेंटीना** को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े **लिथियम संसाधन**, **तीसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार** और **चौथे सबसे बड़े उत्पादन** का गौरव भी प्राप्त है।

66. पीएम-जनमन पैकेज का उद्देश्य PVTG का विकास करना - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- PVTG
- पीएमजनमन-

समाचार:
- सरकार के **पीएम-जनमन पैकेज** का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर **जनजातीय समूहों (PVTG)** का विकास करना है ।
  - इसमें महिला लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है जो दूर-दराज के समुदाय के सदस्यों तक लाभ पहुंचाने के लिए संदेशवाहक के रूप में काम करती हैं।

मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री ने पक्के मकानों के लिए धनराशि जारी
- प्रधानमंत्री ने **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)** के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की।
  - PVTG के लिए आवश्यक सुविधाओं, जैसे पक्के घर, बिजली और पानी के कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करना।

जनमन संगी (स्वयंसेवक) के रूप में महिलाएं

- प्रमुख लाभार्थियों में पहाड़ी कोरबा जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं।
  - जनमन संगी बन रहे हैं और स्वेच्छा से अपने समुदायों को पैकेज के तहत योजनाओं के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।

पीएम-जनमन अभियान के उद्देश्य

- पीएम-जनमन अभियान, 15 नवंबर को शुरू किया गया

उद्देश्य:

- इसका लक्ष्य **नौ मंत्रालयों** के **11 हस्तक्षेपों** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **PVTG समुदायों** के अनुमानित **36 लाख** लोगों के साथ **22,000 बस्तियों** को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
- PVTG को **अनुसूचित जनजातियों** में सबसे पिछड़ा माना जाता है।

सूचना एवं शिक्षा अभियान

- पैकेज में **सूचना और शिक्षा अभियान, PVTG बस्तियों** में शिविर आयोजित करना शामिल है
  - आधार, पीएम जन धन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि कार्ड आदि जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए निवासियों को पंजीकृत करना।

वित्तीय आवंटन

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने अगले **तीन वर्षों** में **पैकेज** पर **₹24,000 करोड़** से अधिक खर्च करने की योजना को मंजूरी दी।
- एक **लाख लाभार्थी परिवारों** के लिए **पक्के घरों** के निर्माण सहित **₹4,700 करोड़** की परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

67. आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिएभारत- द हिंदू :

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- रुपयारियाल व्यापार-
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **भारत** ने **पाकिस्तान** के **बलूचिस्तान प्रांत** में कथित **आतंकी शिविरों** पर **ईरान के मिसाइल हमलों** के प्रति समर्थन व्यक्त किया और इसे **आत्मरक्षा** की कार्रवाई बताया।

मुख्य बिंदु

- **विदेश मंत्रालय (MEA)** ने उसी दिन **इराक** और **सीरिया** के कुर्द इलाकों में **ईरान** के हमलों पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए **आतंकवाद** पर अपने **अडिग रुख** पर प्रकाश डाला।

1. **मुद्दे का द्विपक्षीय स्वरूप**

- **विदेश मंत्रालय** ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला **ईरान** और **पाकिस्तान** के बीच **द्विपक्षीय** है और **भारत आतंकवाद** पर **शून्य-सहिष्णुता** की स्थिति रखता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और पश्चिम एशिया में तनाव**

- ईरान की कार्रवाइयों के लिए **भारत** का समर्थन **व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद** की निंदा के विपरीत है, जो **इराक** के खिलाफ **हमलों को लापरवाह** और **अचूक** बताते हुए आलोचना करता है।
- **पश्चिम एशिया** में तनाव, विशेष रूप से **अमेरिका** से जुड़े, **गाजा** में **इज़राइल** की कार्रवाई, **यमन** में **अमेरिकी हमले** और **हौथी विद्रोही हमले**, स्थिति में **जटिलता** जोड़ते हैं।

3. **ईरान का नजरिया**

- **ईरान** के **विदेश मंत्री** ने दोहराया कि हमलों का उद्देश्य **ईरान, पाकिस्तान**, **इराक** और **क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाना** था।
- उन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर **आतंकवादी खतरों** से निपटने के लिए **ईरान** की **प्रतिबद्धता** पर जोर देते हुए **पाकिस्तान** और **इराक** की संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर दिया।

भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंध

- पिछले कुछ वर्षों में, **ईरान** के साथ **भारत** के **व्यापार** में महत्वपूर्ण **उतार-चढ़ाव** देखा गया है।
- **वर्ष 2019-20** में, **ईरान** से **भारत का आयात**, मुख्य रूप से **कच्चा तेल, वर्ष 2018-19** में **13.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की तुलना में लगभग **90% गिरकर 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया।
- इसके अलावा **ईरान** ने **वोस्ट्रो खाते** में अपने रुपये के भंडार में कमी देखी है, जिससे **बासमती चावल** और **चाय** जैसी **प्रमुख भारतीय वस्तुओं** को **आयात** करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **भारत** और **ईरान** के बीच **व्यापार** को **पुनर्जीवित** करने के लिए, जो **अमेरिकी** और **पश्चिमी प्रतिबंधों** से प्रभावित हुआ है, दोनों **देश रुपया-रियाल व्यापार** के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

रुपया-रियाल व्यापार

- यह **भारत** और **ईरान** के बीच उनकी संबंधित मुद्राओं, **भारतीय रुपया (INR)** और **ईरानी रियाल (IRR)** का उपयोग करके **व्यापार को संदर्भित** करता है।
    - **अमेरिकी डॉलर (USD**) जैसी व्यापक रूप से स्वीकृत **अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं** का उपयोग करने के बजाय।

68. आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिएभारत- द हिंदू :

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मानचित्र आधारित प्रश्न
- ताइवान

समाचार:

- **13 जनवरी** को, **ताइवान** ने अपने **लोकतांत्रिक चुनाव** संपन्न किए, जिसके परिणामस्वरूप **डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP)** से **लाई चिंग-ते** को **नए राष्ट्रपति** के रूप में चुना गया।

मुख्य बिंदु

1. **कूटनीतिक बदलाव**

- चुनाव के तुरंत बाद, एक छोटे से द्वीप **राष्ट्र नाउरू** ने **ताइपे** से **बीजिंग** में **राजनयिक** बदलाव की घोषणा की।

2. **बीजिंग की रणनीति**

- चीन ने **ताइवान** के **राजनयिक स्थान** को कम करने के लिए **वित्तीय निवेश** और **बुनियादी ढांचे** के विकास के वादे के साथ **छोटे देशों** को लुभाने की रणनीति अपनाई है।
- DPP's के कथित **स्वतंत्रता-समर्थक** रुख के कारण **बीजिंग** पर दबाव बढ़ गया है, जिससे **ताइवान** को मान्यता देने वाले देशों की संख्या में गिरावट आई है।

3. **चीन-ताइवान संबंध और 1992 की आम सहमति**

- विवाद का मुख्य मुद्दा **राष्ट्रपति त्साई** का '**वर्ष 1992** की **आम सहमति**' को स्वीकार करने से इनकार करना है, जो 'एक चीन' को स्वीकार करता है।

4. **चीनी राष्ट्रपति के लक्ष्य**

- **चीनी राष्ट्रपति** ने **ताइवान** को **'पवित्र क्षेत्र'** मानते हुए **चीनी राष्ट्र** का **कायाकल्प** करने और **ताइवान** को **फिर से एकीकृत** करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।
- चीन की नाराजगी के बावजूद, **DPP** की चुनावी जीत से संकेत मिलता है कि **ताइवान** के लोग पुनर्मिलन की जल्दी में नहीं हैं।

5. **ताइवान में लोकतंत्र**

- वर्ष 1996 में स्थापित **ताइवान** का **लोकतंत्र, चीनी असंतोष** के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है।
- **ताइवान** का **कामकाजी लोकतंत्र** इस धारणा को चुनौती देता है कि **चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC)** चीनी लोगों के लिए **एकमात्र राजनीतिक** विकल्प है।

69. सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा इंडियन - एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सातवीं अनुसूची
- 'इंडियन स्टाम्प बिल, 2023

समाचार:
- सरकार ने **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899** को निरस्त करने और देश में **स्टाम्प शुल्क व्यवस्था** के लिए एक **नया कानून** लाने का प्रस्ताव दिया है।
- वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने **'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023'** के मसौदे पर जनता से **30 दिनों की अवधि** के भीतर **सुझाव आमंत्रित** किए हैं।

मुख्य बिंदु
- "राजस्व विभाग, **वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** ने इसे **आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था** के साथ संरेखित करने के लिए एक मसौदा **'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023'** तैयार किया है।
- एक बार अधिनियमित होने के बाद, **विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899** का स्थान ले लेगा
- **भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899** लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों पर **स्टाम्प** के रूप में लगाए गए कर के लिए **कानूनी प्रावधान** बताता है।
- **स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार** द्वारा लगाया जाता है, लेकिन **राज्यों** के भीतर संविधान के **अनुच्छेद 268** के प्रावधानों के अनुसार संबंधित **राज्यों द्वारा एकत्र** और **विनियोजित** किया जाता है।
- **सातवीं अनुसूची** की **संघ सूची** की **प्रविष्टि 91** में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क शामिल है
  - विनिमय के बिल, चेक, वचन पत्र, लदान के बिल, ऋण पत्र, बीमा की पॉलिसियां, शेयरों का हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदें) संघ द्वारा लगाए जाते हैं।
- दस्तावेज़ों पर अन्य स्टांप शुल्क राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
- मंत्रालय ने कहा कि **भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899,** एक **संविधान-पूर्व अधिनियम** है, जिसे अधिक **आधुनिक स्टांप शुल्क व्यवस्था** को सक्षम करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया गया है।

70. केंद्रीय मंत्री ने MPLADS ईसाक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया - पीआईबी-

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ईसाक्षी-
- MPLADS

समाचार:
- **सांख्यिकी** और **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के **राज्य मंत्री** (स्वतंत्र प्रभार) ने **MPLADS ई-साक्षी मोबाइल** एप्लिकेशन लॉन्च किया
- इसका उद्देश्य **नई दिल्ली** में **MPLAD** योजना के तहत **संशोधित निधि प्रवाह** प्रक्रिया है।

MPLAD योजना का उद्देश्य
- MPLAD योजना का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के आधार पर टिकाऊ **सामुदायिक संपत्ति** बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली **विकासात्मक परियोजनाओं** की सिफारिश करने के लिए **संसद सदस्यों** (सांसदों) को सशक्त बनाना है।
- संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य बेहतर कार्यक्षमता, **कार्यान्वयन** और **निगरानी** पर जोर देते हुए योजना के दायरे का विस्तार करना है।

ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन के लाभ
- यह क्रांतिकारी बदलाव लाएगा कि कैसे **सांसद** अपने **निर्वाचन क्षेत्रों** में **विकास परियोजनाओं** के साथ जुड़ते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं, जिससे उन्हें सुविधा और पहुंच मिलती है।
- यह सांसदों को वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और निगरानी करने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और उभरती जरूरतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

- **ई-साक्षी मोबाइल ऐप** सांसदों को उनकी **प्रस्तावित परियोजनाओं** की **स्थिति** और **प्रगति** पर त्वरित **अपडेट प्रदान** करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- यह **पारदर्शिता जवाबदेही** बढ़ाती है और **MPLADS निधियों** के **आवंटन** और **उपयोग** में जनता का विश्वास पैदा करती है।

बजट प्रबंधन सुविधाएँ

- **मोबाइल एप्लिकेशन** में **बजट प्रबंधन** की विशेषताएं शामिल हैं, जिससे **सांसद** अपनी अनुशंसित परियोजनाओं से संबंधित व्यय की निगरानी कर सकते हैं।
- यह MPLADS निधियों की **वित्तीय निगरानी** और **जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग** सुनिश्चित करता है।

71. मालदीव ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की द - हिंदू/भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के विदेश से मुलाकात की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अदन की खाड़ी
- मलक्का जलडमरूमध्य

समाचार:

- हाल ही में, **भारत** ने कहा कि **मालदीव द्वीपों** में **भारतीय सैनिकों** की तैनाती को लेकर **मालदीव** के साथ विवाद के समाधान की उम्मीद है
- मालदीव सरकार ने इन्हें हटाने के लिए **15 मार्च** की समय सीमा तय की है।

मुख्य बिंदु

- सैनिकों को हटाने की तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला **मालदीव मजलिस** या संसदीय चुनाव **17 मार्च** को होने वाला है
  - **श्री मुइज्जू** के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका **सत्तारूढ़ गठबंधन** इस सप्ताह माले मेयर का चुनाव हार गया है।
- **श्री मुइज्जू मालदीव** के पहले **राष्ट्रपति** हैं जो अपनी **पहली विदेश यात्रा** पर भारत नहीं आये।

मालदीव का महत्व

- **मालदीव क्षेत्र** की **राजनीतिक स्थिरता** और **सुरक्षा बनाए** रखने के साथ-साथ **भारतीय वाणिज्य** और **निवेश** की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **हिंद महासागर** में **स्थिरता** और **सुरक्षा सुनिश्चित** करना स्पष्ट रूप से **भारत** और **मालदीव** की जिम्मेदारी है।
- महत्वपूर्ण **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन (ISLs)** के संबंध में **मालदीव की भौगोलिक स्थिति** के रणनीतिक महत्व के कारण है।
- **हिंद महासागर दुनिया** भर में **ऊर्जा** के **हस्तांतरण और व्यापार** का एक प्रमुख मार्ग है ।
- **मलक्का जलडमरूमध्य** और **अदन की खाड़ी**, **पश्चिमी हिंद महासागर** में **दो चोकपॉइंट,** मालदीव के दोनों ओर स्थित हैं, जो **भौतिक रूप** से उनके बीच एक **"टोल गेट"** की तरह स्थित है।
- **मालदीव भारत** की **स्थायी सदस्यता** और **वर्ष 2020-21** के लिए **गैर-स्थायी सीट** के लिए **भारत** की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

72. अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण: पैनल लाभ के समान वितरण पर गौर करेगा- - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मैडिगा समुदाय
- अनुसूचित जाति के बीच उप-वर्गीकरण

समाचार:

- **केंद्र सरकार** ने **भारत में 1,200** से अधिक **अनुसूचित जातियों (SC)** के बीच **लाभों, योजनाओं** और **पहलों** के वितरण के लिए एक **निष्पक्ष पद्धति** का आकलन करने और तैयार करने के लिए **पांच सदस्यीय समिति** की स्थापना की है।

- प्राथमिक ध्यान **सर्वाधिक पिछड़े समुदायों की शिकायतों** को दूर करने पर है जिन पर **अपेक्षाकृत अगड़े** और **प्रभावशाली समुदायों** का प्रभाव पड़ा है।

पृष्ठभूमि

- इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** के बीच **उप-वर्गीकरण** की **अनुमति पर विचार-विमर्श** करने के लिए तैयार है।
- **कैबिनेट सचिव** की **अध्यक्षता** वाली **समिति** को वर्तमान में विचाराधीन **आरक्षण संबंधी प्रश्नों** पर चर्चा करने से बचने का आदेश दिया गया है।

मडिगा समुदाय का संघर्ष:

- **तेलंगाना** की **अनुसूचित जाति** आबादी का **50% हिस्सा मडिगा** समुदाय 1994 से **उप-वर्गीकरण** की वकालत कर रहा है।
- पिछले आयोगों ने लक्षित लाभों की आवश्यकता पर बल देते हुए **उप-वर्गीकरण** की व्यवहार्यता को स्वीकार किया है।

राज्य-स्तरीय प्रयास और कानूनी विचार:

- **पंजाब, बिहार** और **तमिलनाडु** जैसे राज्यों ने **सुप्रीम कोर्ट** का फैसला आने तक **उप-वर्गीकरण** के लिए **राज्य-स्तरीय आरक्षण कानून** बनाने का प्रयास किया है।
- **वर्ष 2005** में, **केंद्र सरकार** ने कानूनी विकल्पों पर विचार किया, **संवैधानिक संशोधन** की आवश्यकता पर राय विभाजित थी।
- कानूनी विशेषज्ञ **उप-वर्गीकरण** को उचित ठहराने के लिए एक व्यापक **जाति जनगणना** और **सामाजिक-आर्थिक डेटा** की वकालत करते हैं।

73. चीन ने नई मेगा पोर्ट परियोजना के साथ दक्षिण अमेरिका में व्यापार राजमार्ग का विस्तार किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे

- मानचित्र आधारित प्रश्न
- एशियाप्रशांत आर्थिक सहयोग-

समाचार:

- सितंबर में, **ब्राजील** के **किसानों** और **अधिकारियों** के एक **प्रतिनिधिमंडल** ने **पेरू** के **चांके शहर** का दौरा किया, जहां **3.5 बिलियन डॉलर** का एक **नया चीनी मेगा बंदरगाह** निर्माणाधीन है।

मुख्य बिंदु

- **चीन** की **कॉस्को शिपिंग** के बहुमत स्वामित्व वाला यह बंदरगाह , **दक्षिण अमेरिका** के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए **बीजिंग** के महत्वाकांक्षी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **पिछले एक दशक** में **क्षेत्र** के **सबसे बड़े व्यापार भागीदार** के रूप में **अमेरिका** को पीछे छोड़ दिया है।

चान्के मेगा पोर्ट अवलोकन

- चीन द्वारा नियंत्रित **3.5 बिलियन डॉलर** का गहरे पानी का बंदरगाह, इस साल के अंत में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है।
- यह **लीमा** से **80 किलोमीटर** उत्तर में स्थित है और **दक्षिण अमेरिका** में **पहला चीनी-नियंत्रित बंदरगाह** है।

सामरिक महत्व

- **चीन** की **'बेल्ट एंड रोड'** पहल का हिस्सा, **चांके बंदरगाह** का उद्देश्य **चीन** को **दक्षिण अमेरिका** के **संसाधन-समृद्ध क्षेत्र** के लिए सीधा प्रवेश द्वार प्रदान करना है।
- दक्षिण अमेरिका में चीन के व्यापार प्रभुत्व ने उसे क्षेत्र में राजनीतिक, वित्तीय और तकनीकी लाभ हासिल करने में मदद की है।
- चीनी राष्ट्रपति **पेरू** में **एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)** शिखर सम्मेलन के दौरान **बंदरगाह** का उद्घाटन कर सकते हैं।
- **ब्राजील** के **ट्रकों** की **बंदरगाह** तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पर रसद, **स्वच्छता** और **नौकरशाही बाधाओं** को हल करने की योजना।

लैटिन अमेरिका में अमेरिका और चीन का प्रभाव

- पिछले दशक में **चीन दक्षिण अमेरिका** में **प्रमुख व्यापार भागीदार** के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है।

74. चीनकिर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे- (CKU-R) परियोजना - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे

- मध्य एशियाई देश
- चीन उज्बेकिस्तान-किर्गिस्तान-) रेलवेCKU-R)

समाचार:

- **चीन** अपने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के हिस्से के रूप में **चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे (CKU-R)** का निर्माण कर रहा है।
- इसका उद्देश्य **मध्य एशिया** में **कनेक्टिविटी** को बढ़ाना है।

मुख्य विचार

- परियोजना, जिसकी शुरुआत **वर्ष 1990** के दशक में की गई थी, **भू-राजनीतिक बदलावों** और वैकल्पिक **व्यापार मार्गों** की आवश्यकता के कारण गति पकड़ रही है।
- हालाँकि, इसे वित्तीय बाधाओं, सुरक्षा चिंताओं और भू-राजनीतिक जटिलताओं सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान कनेक्टिविटी और चीन का अवसर

- वर्तमान में, केवल **दो आउटलेट** चीन के **झिंजियांग** को **दक्षिण और मध्य एशिया** से जोड़ते हैं।
- चीन **CKU-R** के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर देखता है, जो काशगर को **ओश** और **एंडीजान** से जोड़ता है, अंततः **यूरोपीय रेलवे नेटवर्क** से जुड़ता है।

सामरिक महत्व

- **CKU-R चीन** के लिए एक **रणनीतिक** और **आर्थिक** वरदान है, जो **शिनजियांग** और **यूरेशिया** के दिल फ़रगना घाटी के बीच सीधा लिंक प्रदान करता है।
- रेलवे का लक्ष्य **रूस** के माध्यम से लंबे मार्गों को दरकिनार करते हुए **मध्य एशिया, दक्षिण काकेशस** और **यूरोप** जाने वाले माल ढुलाई में चीन की उपस्थिति को बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- किर्गिस्तान की **राजनीतिक** और **वित्तीय** चुनौतियाँ, जिसमें मार्ग के अपने हिस्से के लिए धन की कमी **($4.7 बिलियन)** भी शामिल है, जो की प्रगति में बाधक है।
- **कर्ज** के **जाल** में **फंसने का डर** और **चीनी विस्तारवाद** की चिंताएं इस परियोजना में बाधाएं खड़ी कर रही हैं।

भूराजनीतिक विचार

- मध्य एशियाई भू-राजनीति, जिसमें रूस से संबंध और पश्चिम के प्रति **उज़्बेकिस्तान** का खुलापन शामिल है, इस परियोजना में जटिलता जोड़ते हैं।
- चीन की सहभागिता की बदलती शर्तें **द्विपक्षीय दृष्टिकोण** को बढ़ावा देती हैं, जिससे **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** जैसे सर्वसम्मति-आधारित समूहों पर निर्भरता कम हो जाती है।

रूस की भूमिका से तुलना

- **मध्य एशियाई** देशों के साथ **चीन का व्यापार,** कुछ मामलों में **रूस** से आगे निकल जाना, **आर्थिक प्रभाव** में बदलाव को दर्शाता है।
- रूस के मुखर रुख के विपरीत, **चीनी राजनयिक आर्थिक जुड़ाव** पर **ध्यान केंद्रित** करते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाते हैं।
- यह परियोजना संभावित रूप से **दक्षिण-उत्तर निर्देशित कनेक्टिविटी** में **रूस** के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी** और **प्रभाव** को नया आकार दे सकती है।

75. चीन, फिलीपींस तनाव कम करने पर सहमत द हिंदू/ चीन -, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर पर तनाव कम करने पर सहमत इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दक्षिण चीन सागर
- रेन'आई चट्टान

समाचार:
- चीन और फिलीपींस ने कहा कि वे **दक्षिण चीन सागर** में अपने जहाजों के बीच एक साल तक **सार्वजनिक** और **तनावपूर्ण** टकराव के बाद तनाव कम करने पर काम करने पर सहमत हुए हैं, जिससे क्षेत्र में **सशस्त्र भागीदारी** की चिंता बढ़ गई है।

मुख्य विचार
- **रेन'आई रीफ** उस चीनी नाम का नाम है जिसे **फिलीपींस अयुंगिन शोल** कहता है और **अमेरिका** दूसरा **थॉमस शोल** कहता है।
  - हाल के महीनों में दोनों देशों के जहाजों के बीच कई टकरावों का स्थल।
- नवंबर में, **मनीला** ने कहा कि एक चीनी तट **रक्षक जहाज** और उसके साथ आए जहाजों ने खतरनाक युद्धाभ्यास किया
  - विवादित जल क्षेत्र में **फिलीपीन** के एक आपूर्ति **जहाज** को **वाटर कैनन** से उड़ा दिया। चीन ने इस खाते पर विवाद करते हुए कहा कि उसने उचित कार्रवाई की।
- **चीन** और **फिलीपींस** ने कहा कि वे **शंघाई** में **दक्षिण चीन सागर** पर एक बैठक में तनाव को सीमित करने पर सहमत हुए, जो **वर्ष 2017** में शुरू हुई श्रृंखला में आठवीं बैठक थी।
- **दक्षिण चीन सागर** में **क्षेत्रीय विवादों** को **व्यापक रूप** से **सशस्त्र संघर्ष** के संभावित **फ्लैशप्वाइंट** के रूप में देखा जाता है।
- **ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, मलेशिया** और **चीन** सहित कई देशों ने **दक्षिण चीन सागर** के पानी पर अपना दावा किया है।
- **ताइवान,** एक **स्वशासित द्वीप** है जिस पर चीन दावा करता है, उसने उस पार्टी के उम्मीदवार को चुना जो ताइवान को स्वतंत्र मानती है।

76. कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते केंद्रीय: शिक्षा मंत्रालय - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश
- मानसिक स्वास्थ्य

समाचार:
- **शिक्षा मंत्रालय** ने हाल ही में **कोचिंग सेंटरों को विनियमित** करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश पेश किए हैं।
- **उद्देश्य:** एक **कानूनी ढांचा** स्थापित करना और **निजी कोचिंग केंद्रों** की **अनियंत्रित वृद्धि** का प्रबंधन करना।
- ये दिशानिर्देश छात्र आत्महत्याओं, आग की घटनाओं और कोचिंग सुविधाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के जवाब में पेश किए गए हैं।

मुख्य दिशानिर्देश
- **आयु प्रतिबंध और शैक्षणिक योग्यताएँ**
  - कोचिंग सेंटर **16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों** का नामांकन नहीं कर सकते।
  - **विद्यार्थियों** का नामांकन **माध्यमिक विद्यालय परीक्षा** के बाद ही होना चाहिए
  - **ट्यूटर्स** के पास कम से कम **स्नातक की योग्यता** होनी चाहिए।
  - **कोचिंग सेंटर** किसी भी **ट्यूटर** या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो **नैतिक अधमता** से जुड़े किसी भी **अपराध के लिए दोषी** ठहराया गया हो।

- **भ्रामक वादे**
  - **कोचिंग संस्थानों** को **भ्रामक वादे** करने, **रैंक की गारंटी** देने या माता-पिता को अच्छे अंक सुनिश्चित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  - कोचिंग की **गुणवत्ता या परिणामों** के बारे में **भ्रामक विज्ञापनों** का प्रकाशन सख्त वर्जित है।
- **मानसिक स्वास्थ्य**
  - कोचिंग सेंटरों को छात्रों के **मानसिक स्वास्थ्य** के लिए कदम उठाने चाहिए।
  - संकट में फंसे छात्रों के लिए **तत्काल हस्तक्षेप तंत्र स्थापित** किया जाना चाहिए।
  - **छात्रों** को **सुधार क्षेत्रों** के बारे में प्रभावी ढंग से बताने के लिए **शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य** के मुद्दों पर **प्रशिक्षण** ले सकते हैं।
- **परामर्श प्रणाली**
  - **कोचिंग सेंटरों** में एक **परामर्श प्रणाली** होनी चाहिए और इसके बिना **संस्थान का पंजीकरण** नहीं किया जाएगा।
  - **प्रशिक्षित परामर्शदाताओं** की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनकी उपलब्धता की जानकारी **छात्रों** और **अभिभावकों** को प्रदान की जानी चाहिए।
- **उचित एवं उचित शुल्क**
  - **ट्यूशन फीस निष्पक्ष** और **तर्कसंगत** होनी चाहिए और ली गई **फीस की रसीदें उपलब्ध** कराई जानी चाहिए।
  - **रिफंड नीतियां** निर्दिष्ट की गई हैं, जो बीच में **पाठ्यक्रम छोड़ने** वाले **छात्रों** के लिए **आनुपातिक रिफंड सुनिश्चित** करती हैं।
  - **अत्यधिक फीस** वसूलने पर, जिससे तनाव के कारण छात्र आत्महत्या कर सकते हैं या कदाचार में शामिल होने पर, जुर्माना, जिसमें **₹1 लाख तक का जुर्माना** या **पंजीकरण रद्द** करना शामिल है।
- **निगरानी और पंजीकरण**
  - दिशानिर्देश लागू होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण।
  - **राज्य सरकारें कोचिंग सेंटर** की गतिविधियों पर नजर रखेंगी और **पात्रता मानदंडों** का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
- कोचिंग सेंटरों के पास एक वेबसाइट होगी जिसमें **ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या**, पूरा होने की अवधि, **छात्रावास सुविधाएं** और **ली जाने वाली फीस** का अद्यतन विवरण होगा।

77. आंध्र प्रदेश 'जाति जनगणना' करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना द हिंदू -

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- SECC
- जनगणना

समाचार:
- **आंध्र प्रदेश सरकार** ने राज्य में सभी **समुदायों** की गणना के लिए अपनी व्यापक **जाति जनगणना** शुरू कर दी है।।

मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश **बिहार** के बाद **जाति जनगणना** करने वाला **दूसरा राज्य** बन गया है।
- **YSRCP सरकार** ने **जाति जनगणना** को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है और उसे लगता है कि गणना लोगों के जीवन स्तर को बदल सकती है।
- इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, **आंध्र प्रदेश सरकार** ने **राज्य भर** के **जाति प्रतिनिधियों** से राय मांगी।
- जाति जनगणना को **निष्पक्ष** और **व्यापक** तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से, **दक्षिणी राज्य** अपनी **गणना प्रक्रिया** को पूरे देश में एक **रोल मॉडल** के रूप में पेश करना चाहता है।
- हालाँकि जाति **जनगणना** की शुरुआत में केवल **139 पिछड़ा वर्ग (BC) समुदायों** को शामिल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसके दायरे में **आंध्र प्रदेश** की सभी जातियाँ शामिल हैं।

भारत में जनगणना:
- भारत में जनगणना की शुरुआत **वर्ष 1881** की **औपनिवेशिक** प्रक्रिया से हुई।

- जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी को पकड़ने, संसाधनों तक पहुंचने, सामाजिक परिवर्तन का नक्शा बनाने और परिसीमन अभ्यास करने के लिए किया जाता है।
- हालाँकि, विशेष जांच के लिए अनुपयुक्त एक कुंद उपकरण के रूप में इसकी आलोचना की गई है।

SECC (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना):

- **SECC** पहली बार **वर्ष 1931** में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए **ग्रामीण** और **शहरी दोनों क्षेत्रों** में **भारतीय परिवारों** की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना था।
- यह विभिन्न **जाति समूहों** की **आर्थिक स्थितियों** का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट **जाति नामों** पर डेटा भी एकत्र करता है।

78. केंद्र ने अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा हेतु जाँच समिति बनाई इंडियन - एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मडिगा समुदाय
- अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण

समाचार:

- **मडिगा** जैसे अ**नुसूचित जाति समुदायों** के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच के लिए एक **उच्च स्तरीय पैनल** का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु

- पैनल **अनुसूचित जाति** के सबसे वंचित **समुदायों** को लाभ का **उचित आवंटन सुनिश्चित** करने का प्रयास करेगा
  - जिन पर तुलनात्मक रूप से समृद्ध और प्रभावशाली समूहों का प्रभाव पड़ा है।
- यह उन **प्रशासनिक** कदमों की जांच करेगा जो मडिगा और ऐसे अन्य समूहों जैसे **अनुसूचित जाति समुदायों** के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकते हैं।
  - जिन्होंने दर्शाया है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल रहा है।
- **समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे**
  - गृह मंत्रालय के सचिव
  - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय
  - कानूनी मामलों का विभाग
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग।
- **सरकार** को **अनुसूचित जाति** के **उप-वर्गीकरण** के लिए **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना** और **कर्नाटक** सहित राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।
  - जिसमें **मडिगा समुदाय** भी शामिल है, इस आधार पर कि **आरक्षण** और **कल्याण/विकासात्मक योजनाओं** का लाभ उनके बीच समान रूप से नहीं पहुंच रहा है।
- मामला विभिन्न अदालतों के समक्ष रखा गया है और **वर्तमान** में **सात न्यायाधीशों** वाली **सुप्रीम कोर्ट पीठ** के समक्ष विचाराधीन है।

79. भारत म्यांमार सीमा पर जल्द ही बाड़बंदी की जाएगी: गृह मंत्री - द हिंदू-/अनधिकृत प्रवेश रोकने हेतु भारत-म्यांमारसीमा पर बाड़बंदी की जाएगी गृह : मंत्री - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत और उसके पड़ोसी-संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- म्यांमार
- मुक्त आवागमन व्यवस्था

समाचार:

- **केंद्र सरकार** जल्द ही **भारत और म्यांमार** के बीच **1,643 किलोमीटर लंबी सीमा** पर बाड़ लगाएगी और पड़ोसी देश के साथ अपने **मुक्त आंदोलन शासन (FMR)** समझौते को समाप्त करने पर विचार करेगी।

मुख्य बिंदु

- **FMR**, भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के हिस्से के रूप में **वर्ष 2018** में लागू किया गया
  - सीमा पर रहने वाले **दोनों देशों** के **निवासियों** को **बिना वीज़ा के एक-दूसरे के क्षेत्र** में **16 किमी** तक **यात्रा करने की अनुमति** दी गई।
- भारत में लोगों के **अनधिकृत प्रवेश** को रोकने के लिए **बांग्लादेश** के साथ **भारत** की **4,096 किलोमीटर लंबी** सीमा के अधिकांश हिस्से को **दोहरी बाड़** लगा दी गई है, जो **पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप** से **असम** के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

अब कोई स्वतंत्र आवाजाही नहीं

- सरकार **म्यांमार के साथ भारत के FMR समझौते** पर भी पुनर्विचार कर रही है और जल्द ही **भारत में मुक्त आवाजाही** को समाप्त कर देगी
- मणिपुर चाहता है कि **म्यांमार सीमा** पर बाड़ लगा दी जाए और **म्यांमार के नागरिकों** का निर्बाध प्रवेश बंद हो जाए, जिन पर मौजूदा **जातीय संघर्ष** को भड़काने का आरोप है।
- **दूसरी** ओर, **मिजोरम** और **नागालैंड, म्यांमार** के **मोर्चे पर दोहरे कदम** के खिलाफ हैं क्योंकि उन राज्यों में **अंतरराष्ट्रीय सीमा** के दोनों ओर के लोग एक ही **जातीय समुदाय** से हैं।
- फरवरी 2021 से गृह युद्धग्रस्त म्यांमार के लगभग 30,000 चिन लोगों ने भी मिजोरम में शरण ली है।

80. भारत जाम्बिया में तांबा खनन परियोजनाओं हेतु उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ताँबा
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- भारत के खान मंत्रालय ने **संभावित तांबे की खोज** और **खनन परियोजनाओं** पर चर्चा के लिए **जाम्बिया में एक संयुक्त उद्योग प्रतिनिधिमंडल** भेजने का सुझाव दिया है।
- रुचि व्यक्त करने वाली उल्लेखनीय कंपनियों में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ओला इलेक्ट्रिक और लिथियम-आयन बैटरी रिसाइक्लर लोहुम शामिल हैं।

जाम्बिया के तांबे के भंडार और महत्व

- **जाम्बिया** के पास दुनिया का लगभग **6% तांबा भंडार** है और **वर्ष 2022** में यह **आठवां** सबसे **बड़ा तांबा उत्पादक** था।
- **निर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, परिवहन** और **सौर पैनल** और **इलेक्ट्रिक वाहन** जैसी **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** सहित विभिन्न उद्योगों में तांबा महत्वपूर्ण है।

संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठकें

- **भारत** और **जाम्बिया** के **खान मंत्रालयों** के बीच एक **समझौता ज्ञापन (MoU)** के तहत स्थापित **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** की **दूसरी बैठक जाम्बिया** में होने वाली है।
- इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच **खनिज संसाधनों** में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

हाल के घटनाक्रम

- दिसंबर 2023 में **खनन क्षेत्र** में **द्विपक्षीय सहयोग** बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए **जाम्बिया** में **भारत** के **उच्चायुक्त** से मुलाकात की।
- **KABIL** ने **लिथियम अन्वेषण** के लिए **अर्जेंटीना** की एक **सरकारी स्वामित्व** वाली **कंपनी** के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

जाम्बिया के तांबे के खनन में भारतीय उपस्थिति

- **जाम्बिया** के **तांबा खनन क्षेत्र** में **भारत की सीमित** उपस्थिति है ।
- **कोंकोला कॉपर माइंस (KCM)** के नियंत्रण में **वेदांता** ने तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए जाम्बिया में **1.2 बिलियन डॉलर** से अधिक का **निवेश** करने की योजना बनाई है।

- **जाम्बिया** के तांबे में अन्य निवेशकों में **कनाडा** स्थित **फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स** और **चीन** की **CNMC** शामिल हैं।

तांबे की बढ़ती भारतीय मांग

- भारत में घरेलू तांबे की मांग **वित्त वर्ष 2022-2023** में **16%** बढ़ी, **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** में **तांबे** की मांग में **32%** की वृद्धि हुई।
- **सीमित घरेलू आपूर्ति** ने **भारतीय खनन कंपनियों** को **तांबा खनन ब्लॉकों** के **विदेशी अधिग्रहण** पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

81. ईदी अमीन द्वारा युगांडा से भारतीयों का निष्कासन एक गलती थी मुसेवेनी - द : हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतयुगांडा संबंध-
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- युगांडा के तानाशाह द्वारा अपने देश के **भारतीय समुदाय** को **निष्कासित** करने के लगभग **52 साल** बाद, **युगांडा के राष्ट्रपति** ने उस कदम को एक **"गलती"** कहा।

मुख्य बिंदु

- **राजधानी कंपाला** में आयोजित **19वें NAM शिखर सम्मेलन** में **राष्ट्रपति** की टिप्पणी एक घटना के बारे में खेद की एक **दुर्लभ अभिव्यक्ति** थी
  - इसे लंबे समय से 20वीं सदी में प्रवासी भारतीयों के लिए आघातकारी घटनाओं में से एक माना जाता है।
- NAM देश भी कभी-कभी युगांडा जैसी गलतियाँ करते हैं।
- **अगस्त 1972** में, **ईदी अमीन ने भारतीयों** और अन्य **दक्षिण एशियाई लोगों** को निष्कासित करने का आदेश दिया जो उस समय तक **युगांडा** के जीवन का अभिन्न अंग थे।
- अंत में, लगभग **80,000 भारतीयों** और **हजारों पाकिस्तानियों** और **बांग्लादेशी नागरिकों** को **युगांडा** से **निष्कासित** कर दिया गया, जिससे उन्हें अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी।
  - जिसमें यूके, कनाडा, केन्या और भारत शामिल हैं।
  - उन निष्कासित भारतीयों में से कई नए स्थानों पर अपना भविष्य बनाने के लिए चले गए।

भारत-युगांडा संबंध

- भारत ने **वर्ष 1965** में अपनी **राजनयिक उपस्थिति** स्थापित की, भले ही देशों के संबंध उसी युग से चले आ रहे हैं
- **व्यापारी ढोओं** में सामान भरकर **हिंद महासागर** के पार ले जाते थे, जिसके कारण अंततः कई **भारतीय पूर्वी अफ्रीका** में बस गए और कई लोगों ने **युगांडा** को अपना घर बना लिया।
- **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** ने **युगांडा** के शुरुआती कार्यकर्ताओं को **उपनिवेशवाद** से लड़ने के लिए प्रेरित किया और देश को **वर्ष 1962** में आजादी मिली।
- **वर्ष 1970** के दशक में **ईदी अमीन** की तानाशाही के तहत, लगभग **60000 भारतीयों और PIO** को **युगांडा** से निष्कासित कर दिया गया था।
- हालाँकि, इस नीति को **80 के दशक** में उलट दिया गया था और वर्तमान में, देश में **30000** से **अधिक भारतीय/PIO** हैं

82. WHO के विवाद निपटान निकाय के पुनरुद्धार में देरी हो रही है: GTRI - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व व्यापार संगठन
- विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान

समाचार:

- **ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)** की रिपोर्ट के अनुसार , पूरी तरह कार्यात्मक **WTO** विवाद निपटान निकाय की बहाली में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

- यह **विकसित और विकासशील देशों** के बीच महत्वपूर्ण अंतर के कारण है।

संरक्षणवाद और अमेरिकी भागीदारी

- एक कार्यात्मक **विवाद निपटान निकाय** की **अनुपस्थिति** के कारण **संरक्षणवाद** में वृद्धि हुई है।
- **वर्ष 2017** से, अमेरिका यह दावा करते हुए **WTO's** की अपीलीय अदालत में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधा डाल रहा है कि यह उसके हितों के लिए हानिकारक है।
  - सभी विवादों में से एक चौथाई से अधिक में अमेरिकी कानूनों या उपायों को चुनौती दी जाती है

MC13 पर भारत की प्राथमिकता

- **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13**) में **GTRI** इस बात पर जोर देता है कि विवाद निपटान प्रणाली में सुधार **भारत** के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
- संघर्षों को सुलझाने के लिए एक विश्वसनीय तरीके के बिना, **WTO नियम** अप्रभावी बने रहते हैं।

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान

- विवाद तब उत्पन्न होता है जब एक सदस्य सरकार को लगता है कि कोई अन्य सदस्य सरकार उस समझौते का उल्लंघन कर रही है जो उसने WTO में किया है।
- **WTO** में **शिकायत दर्ज** होने के बाद विवाद को निपटाने के **दो मुख्य तरीके** हैं
  - पार्टियाँ पारस्परिक रूप से सहमत समाधान ढूंढती हैं, विशेषकर द्विपक्षीय परामर्श के चरण के दौरान।
  - न्यायनिर्णयन के माध्यम से जो विवाद निपटान निकाय द्वारा एक बार अपनाए जाने के बाद पार्टियों पर बाध्यकारी होते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण हैं**
  - पार्टियों के बीच विचार-विमर्श
  - पैनलों द्वारा और, यदि लागू हो, अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय।
  - फैसले का कार्यान्वयन
    - इसमें हारने वाली पार्टी द्वारा फैसले को लागू करने में विफलता की स्थिति में जवाबी उपायों की संभावना शामिल है।

WTO की अपीलीय संस्था

- **वर्ष 1995** में स्थापित **अपीलीय निकाय सात सदस्यों** की एक **स्थायी समिति** है।
- यह **विश्व व्यापार संगठन** के सदस्यों द्वारा लाए गए **व्यापार-संबंधी विवादों** में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील की अध्यक्षता करता है।
- यदि देशों को लगता है कि मुद्दे की जांच के लिए **गठित पैनल** की रिपोर्ट की कानून के बिंदुओं पर समीक्षा की जानी चाहिए तो वे **अपीलीय निकाय** से संपर्क कर सकते हैं।
- हालाँकि, मौजूदा सबूतों की **दोबारा जाँच** नहीं की जाती है बल्कि **कानूनी व्याख्याओं** की समीक्षा की जाती है।
- **अपीलीय निकाय विवाद** की सुनवाई करने वाले **पैनल के कानूनी निष्कर्षों** को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है।
- **WTO** में **अपीलीय निकाय** ने **दिसंबर 2019** से काम करना बंद कर दिया, लेकिन पैनल अभी भी काम कर रहे हैं।

83. प्रधानमंत्री ने सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की- द हिंदू/ पीएम ने 1 करोड़ परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप योजना की घोषणा की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सौर ऊर्जा
- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

समाचार:

- **प्रधान मंत्री** ने **सार्वजनिक रूप** से **एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा** से **विद्युतीकृत** करने की योजना की घोषणा की।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

- इस योजना में **एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर** लगाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान में, **भारत में छत** पर सौर स्थापना वाले घरों की संख्या का कोई **केंद्रीय रूप** से संकलित अनुमान नहीं है।
- **लोकसभा** में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, **31 जुलाई, 2023** तक, भारतीय घरों में केवल 2.2 **गीगावॉट (1 गीगावॉट 1,000 मेगावाट)** मूल्य की छत स्थापित की गई थी।
- सरकार, 2010 से, 2022 तक **100 गीगावॉट, उपयोगिता परियोजना (**मेगा केंद्रित सौर पार्क) से **60 गीगावॉट** और छत पर सौर ऊर्जा से **40 गीगावॉट** स्थापित करने का दावा कर रही है।
- अब तक, **उपयोगिताओं में लगभग 56 गीगावॉट** (जुलाई 2023) और **छतों** पर **12 गीगावॉट** स्थापित किया गया है।
- छत पर स्थापित **सौर ऊर्जा संयंत्रों** में कार्यालयों और **घरों में पैनल** शामिल हैं।
- **JMK रिसर्च** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **जुलाई 2023** तक लगभग **12 गीगावॉट छत सौर प्रतिष्ठानों** में से लगभग **87% "गैर-आवासीय"** हैं।
- भारत ने लगातार लगभग **2 गीगावॉट सालाना** (छत पर) जोड़ा है, लेकिन इनमें से अधिकांश कार्यालयों और **इमारतों** में हैं।
- वर्तमान में, प्रोत्साहन संरचनाएं ऐसी हैं कि इससे **व्यक्तिगत घरों** (सौर पैनल स्थापित करने के लिए) की तुलना में वाणिज्यिक संस्थाओं को अधिक लाभ होता है।

84. केंद्र की RoDTEP योजना पर दोबारा काम करने की कोई योजना नहीं - द हिंदू/ RoDTEP योजना पूरी तरह से WTO के अनुरूप: अधिकारी - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- RoDTEP
- विश्व व्यापार संगठन

समाचार:
- **केंद्र** की **निर्यातकों** के लिए लोकप्रिय **निर्यातित उत्पादों** पर **शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP)** योजना पर दोबारा काम करने की कोई योजना नहीं है।

मुख्य बिंदु
- **अमेरिकी सरकार** द्वारा इसके खिलाफ **सब्सिडी विरोधी शुल्क** लगाने के बावजूद सरकारी आदेश
- समस्या **योजना** की **WTO** अनुकूलता के साथ नहीं थी, बल्कि **अमेरिकी जांच टीमों** को पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्यातकों की असमर्थता के साथ थी।
- **विदेश व्यापार महानिदेशालय** (**DGFT**) और **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGFT)** अब निर्यातकों को परिचित कराने पर काम कर रहे हैं।

'छूट योजना'
- "RoDTEP एक छूट योजना है और **पूरी तरह से WTO के अनुरूप** है।
- **जनवरी 2021** में घोषित **RoDTEP योजना** ने WTO-असंगत **MEIS योजना** का स्थान ले लिया
  - जिसे **WTO** में साझेदार देशों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि यह पारदर्शी रूप से निर्धारित नहीं किया गया था।
- **RoDTEP** को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था कि यह **पूरी तरह से पारदर्शी** था और **रिफंड दरें अंतर्निहित कर्तव्यों** और **करों पर आधारित** थीं
  - जैसे परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर वैट, मंडी टैक्स और निर्यातित वस्तुओं के निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली पर शुल्क।
- हालाँकि, इस **वित्तीय वर्ष** की शुरुआत में, **अमेरिका** और **यूरोपीय संघ दोनों** ने **RoDTEP भुगतान** के बदले भा**रतीय उत्पादों पर काउंटरवेलिंग (**सब्सिडी-विरोधी) शुल्क लगाया था।

85. उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश घोषित किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सियोल
- फियोंगयांग

समाचार:
- हाल ही में **उत्तर कोरिया** ने **दक्षिण कोरिया** को **उत्तर कोरिया** का **दुश्मन देश** घोषित कर दिया।

मुख्य बिंदु
- **शांतिपूर्ण पुनर्मिलन** के विचार को त्याग दिया गया, यह संकेत है कि **प्योंगयांग** अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है।
- इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि किम शासन यथास्थिति को बदलना चाहता है।
- सरकार **दक्षिण कोरिया, जापान** और **अमेरिका** के बीच बढ़ते **सैन्य अभिसरण** को **सुरक्षा खतरे** के रूप में देखती है।
- **तीनों देशों** ने हाल ही में अपने **मिसाइल रडार डेटा** को एक दूसरे के साथ जोड़ा है।
- **अमेरिका** और **दक्षिण कोरिया** भी नियमित रूप से **संयुक्त सैन्य अभ्यास** करते हैं, जिस पर उत्तर **कोरिया** की ओर से तीखी प्रतिक्रिया होती है।
- अतीत में, अपनी बयानबाजी के बावजूद, **उत्तर कोरिया दक्षिण** और **अमेरिका** के साथ **राजनयिक जुड़ाव** के लिए खुला था।

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ समझौता
- **वर्ष 1994** में, यह **क्लिंटन प्रशासन** के साथ सहमत रूपरेखा पर पहुंच गया ।
- इसके हिस्से के रूप में, वह अपने **परमाणु रिएक्टरों** के **संचालन** और **निर्माण** को रोकने पर सहमत हुआ।
- **जॉर्ज बुश जूनियर प्रशासन** के दौरान सहमत ढांचे के पतन के बाद **प्योंगयांग परमाणु ऊर्जा संपन्न** हो गया।
- **अमेरिका** के साथ सुलह के रास्ते को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए, **प्योंगयांग ने कोरियाई प्रायद्वीप** के **परमाणु निरस्त्रीकरण** पर बातचीत से इनकार कर दिया है और **चीन** और **रूस** के साथ **संबंधों को मजबूत** करने के लिए कदम उठाए हैं।
- दो कोरिया, एक **परमाणु शक्ति संपन्न** और **दूसरा दुनिया** के सबसे **शक्तिशाली** देश द्वारा समर्थित, के बीच सीधा संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा।
- **तनाव कम करना** और **अंतर कोरियाई संबंधों** में **विश्वास बहाल** करना सभी हितधारकों **सियोल, प्योंगयांग और वाशिंगटन** के लिए तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

86. मालदीव ने अपने जल क्षेत्र में चीनी जहाज के अनुसंधान से इनकार किया - द हिंदू/ मालदीव के जलक्षेत्र में जहाज कोई शोध नहीं करेगा: मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- एशियाई विकास बैंक
- त्रिंकोमाली बंदरगाह

समाचार:
- **मालदीव सरकार** ने कहा है कि **चीनी अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग** 03 **मालदीव** के **जल क्षेत्र** में **अनुसंधान** नहीं करेगा, बल्कि **पोर्ट कॉल** के लिए आएगा।

मुख्य बिंदु
- **मालदीव** की ओर जा रहे **चीनी जहाज** की रिपोर्टों ने भारत में काफी ध्यान आकर्षित किया है
  - विशेष रूप से **श्रीलंका** द्वारा द्वीप के बंदरगाहों पर **विदेशी अनुसंधान जहाजों** को बुलाने पर एक साल की रोक की घोषणा के मद्देनजर, जब **भारत ने एक चीनी जहाज** की यात्राओं पर चिंता व्यक्त की थी।
- मंत्रालय ने कहा, "**मालदीव के जलक्षेत्र** में जहाज कोई शोध नहीं करेगा।"
- मंत्रालय ने कहा कि **मालदीव** हमेशा **मित्र देशों** के **जहाजों के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य** रहा है।

- और **शांतिपूर्ण उद्देश्यों** के लिए **बंदरगाह** पर जाने वाले **नागरिक** और **सैन्य जहाजों** दोनों की मेजबानी करना जारी रखता है।

- इस तरह की पोर्ट कॉल न केवल **मालदीव** और उसके साथी देशों के बीच **द्विपक्षीय संबंधों** को बढ़ाती हैं, बल्कि **मालदीव** के **लोगों की सदियों पुरानी परंपरा** को भी प्रदर्शित करती हैं।
- जहाज को पहले **श्रीलंकाई बंदरगाहों** पर बुलाया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मिली
- माले के साथ अपने संबंधों के चुनौतीपूर्ण चरण के दौरान, **मालदीव में चीनी जहाज** की यात्रा **नई दिल्ली** के लिए तनाव का नवीनतम स्रोत है।

त्रिंकोमाली बंदरगाह:

- त्रिंकोमाली बंदरगाह **श्रीलंका** के **उत्तरपूर्वी तट** पर है।
- यह **त्रिंकोमाली खाड़ी** में एक **प्रायद्वीप** पर स्थित है जिसे पहले **कोडियार खाड़ी** कहा जाता था।
- त्रिंकोमाली **भारत** के **चेन्नई** का निकटतम **बंदरगाह** है।
- **भू-राजनीतिक** और **सामरिक महत्व** हिंद महासागर में इस **बंदरगाह** का स्थान **रणनीतिक महत्व** रखता है, यह **भारत, जापान** और **अमेरिका** सहित कई देशों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है।
- जापान ने **त्रिंकोमाली बंदरगाह** के विकास पर **2020 ADB (एशियाई विकास बैंक)** अध्ययन शुरू किया।

87. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगेद हिंदू -

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस
- राफेल लड़ाकू

समाचार:

- **छह भारतीय** और **छह नेपाली 95 सदस्यीय फ्रांसीसी विदेशी सेना दल** का हिस्सा होंगे जो **गणतंत्र दिवस** पर **नई दिल्ली** में **कर्तव्य पथ** पर मार्च करेंगे।
- इस साल परेड में **मुख्य अतिथि फ्रांस** के **राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन** हैं।

मुख्य बिंदु

- **फ्रांसीसी मार्चिंग दल** के साथ **33 सदस्यीय फ्रांसीसी सैन्य बैंड** भी होगा।
- **फ्रांसीसी वायु** और **अंतरिक्ष बल** के **दो राफेल लड़ाकू विमान** और एक **Airbus-a330 मल्टी-रोल टैंकर** परिवहन **विमान फ्लाईपास्ट** का हिस्सा होंगे।

पहली बार के लिए

- परेड में पहली बार एक **उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर और मध्यम दूरी** की सतह से हवा में मार करने वाली **मिसाइल प्रदर्शित** की जाएगी।
- परेड में पहली बार सभी महिलाओं की त्रि-सेवा टुकड़ी भी हिस्सा लेगी।
- **14 जुलाई 2023** को, **भारतीय प्रधान मंत्री फ्रेंच बैस्टिल** डे परेड में **मुख्य अतिथि** थे
  - जिसमें **242 सदस्यीय भारतीय त्रि-सेवा दल** ने **चैंप्स-एलिसीस** पर मार्च करते हुए देखा, **भारतीय वायु सेना** के **राफेल जेट** ने भी **फ्लाईपास्ट** में भाग लिया।

फ्रेंच बैस्टिल दिवस

- **फ्रांस** का **राष्ट्रीय दिवस,** जिसे **बैस्टिल दिवस** भी कहा जाता है, हर साल **14 जुलाई** को मनाया जाता है।
- **फ्रेंच** में **ला फेटे नेशनले** या ले **14 जुइलेट** के नाम से जाना जाने वाला यह दिन **आतिशबाजी** और **परेड** के साथ मनाया जाता है।
- **फ्रांस के इतिहास** में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक, यह **बैस्टिल**, एक **सैन्य किले** और **राजनीतिक जेल** के पतन का प्रतीक है, जिसे उस समय **राजशाही और शस्त्रागार** का प्रतीक माना जाता था।

88. तमिलनाडु कैबिनेट ने महिलाओं के लिए नई नीति को मंजूरी दी द हिंदू -

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016
- महिलाओं के लिए राज्य की नई नीति

समाचार:
- **तमिलनाडु कैबिनेट** ने महिलाओं के लिए **राज्य की नई नीति को मंजूरी** दी, जिसका **मसौदा दिसंबर 2021** में जारी किया गया था।

मुख्य बिंदु
- **मुख्य सचिवों की अध्यक्षता** में एक **राज्य-स्तरीय समिति** और **कलेक्टरों की अध्यक्षता** में **जिला-स्तरीय** समितियाँ
  - **नीति** के **कार्यान्वयन की निगरानी** और **भेदभाव** के किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए गठित किया जाएगा।
- **समाज कल्याण** एवं **महिला** अ**धिकारिता विभाग** भी **क्रियान्वयन** की निगरानी करेगा।
- उन्होंने बताया कि **वर्ष 200**1 में **राष्ट्रीय स्तर** की **नीति** जारी होने के **23 साल बाद राज्य** ने एक **नई नीति** बनाई है।
- पिछले **साल सरका**र द्वारा घोषित सभी **विभागों** में **लैंगिक बजटिंग सेल** के गठन में देरी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया चल रही थी।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016
- वर्ष 2016 में, **भारत की केंद्र सरकार** ने महिलाओं के लिए **राष्ट्रीय नीति** के **मसौदे** का अनावरण किया
- इसका उद्देश्य **"सामाजिक रूप** से **समावेशी अधिकार-आधारित दृष्टिकोण"** का पालन करके महिला सशक्तिकरण को **"पुनर्लेखन"** करना है।
- इसे **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)** द्वारा जारी किया गया था।
- यह नीति मोटे तौर पर **वर्ष 2012** में **MWCD** द्वारा गठित **पाम राजपूत समिति** की रिपोर्ट पर आधारित है
  - जिसने **वर्ष 2016** में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसमें महिलाओं के लिए सुझाई गई **राष्ट्रीय नीति** और **महिलाओं** के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना शामिल थी।
- **मातृ एवं प्रसवपूर्व मृत्यु दर प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा**
  - सुरक्षित प्रसव के लिए **समन्वित रेफरल परिवहन प्रणाली** पर ध्यान केंद्रित करना
  - कठिन, दूरस्थ और पृथक क्षेत्रों में आपातकालीन प्रसूति देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह सभी उम्र की महिलाओं के **पोषण को प्राथमिकता** देने और **60 वर्ष** से अधिक **उम्र की महिलाओं,** जो **आबादी का 8.4%** हैं, को संबोधित करने के लिए **वृद्धावस्था सेवाओं** को मजबूत करने पर केंद्रित है।

89. केंद्र का महत्वाकांक्षी AI मिशन जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी हेतु जा सकता है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- C-DAC

समाचार:
- हाल ही में, **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री** ने खुलासा किया कि **भारत सरकार** का AI **मिशन 10,000 करोड़ रुपये** से अधिक के **प्रस्तावित बजट** के साथ **कैबिनेट की मंजूरी** लेने के लिए तैयार है।

AI मिशन के उद्देश्य
- **'सॉवरेन AI'** विकसित करना, घरेलू स्तर पर **कम्प्यूटेशनल क्षमता** बढ़ाना और **भारतीय स्टार्टअप्स** को **एक सेवा** के रूप में गणना प्रदान करना।
- **आर्थिक विकास** के लिए **AI** का उपयोग करना, **कृषि , स्वास्थ्य सेवा** और **शिक्षा** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

कंप्यूटिंग क्षमता और भागीदारी

- सरकार **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल के माध्यम से **10,000 से 30,000 GPU** का लक्ष्य रखते हुए **गणना क्षमता** बनाने की योजना बना रही है।
- PSU **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)** के माध्यम से अतिरिक्त **1,000-2,000 GPU** विकसित किए जाने हैं।

प्रोत्साहन संरचनाएँ

- भारत में **कंप्यूटिंग केंद्र** स्थापित करने के लिए **निजी कंपनियों** को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न **प्रोत्साहन संरचनाओं** की खोज की जा रही है।
- **प्रोत्साहन मॉडल में** पूंजीगत व्यय सब्सिडी, परिचालन **व्यय-आधारित प्रोत्साहन** और **"उपयोग" शुल्क** शामिल हैं।
- **सरकार स्टार्टअप्स** को **कम्प्यूटेशनल क्षमता** तक लागत प्रभावी पहुंच प्रदान करने के लिए **GPU असेंबली** से एक **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** बनाने की कल्पना करती है।

डेटा पहल

- **कंप्यूटिंग क्षमता** के साथ-साथ, **सरकार सक्रिय** रूप से **डेटासेट बनाने** और उन्हें **भारतीय स्टार्टअप** के लिए उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।
- एक **राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति** एक **भारतीय डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म** के निर्माण का प्रस्ताव करती है जिसमें **स्टार्टअप** और **शोधकर्ताओं** के लिए **गैर-व्यक्तिगत** और **अज्ञात डेटासेट** शामिल होंगे।
- **सरकार फेसबुक, गूगल और अमेज़ॅन** जैसी प्रमुख **तकनीकी कंपनियों** के लिए **अज्ञात व्यक्तिगत डेटा** को भारत **डेटासेट प्लेटफॉर्म** के साथ साझा करने के निर्देशों पर विचार कर रही है।

90. द्विपक्षीय संबंधों व क्वाड की तारीखों पर चर्चा हेतु शीर्ष अमेरिकी अधिकारी भारत आएंगे द हिंदू -

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- क्वाड
- रशियन ऑयल

समाचार:

- शीर्ष **अमेरिकी राजनयिक द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग** पर चर्चा के लिए इस सप्ताह **दिल्ली की यात्रा** करेंगे

मुख्य बिंदु

- उम्मीद है कि वे **अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया-जापान-भारत** के नेताओं के साथ **क्वाड शिखर सम्मेलन** की संभावित तारीखों पर चर्चा करेंगे और साथ ही पिछले कुछ महीनों में 'विराम' की अनुमानों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे।
- नई दिल्ली ने पहले इस सप्ताह के अंत में **27 जनवरी** को **शिखर सम्मेलन** आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था।
- **भारतीय प्रधानमंत्री** ने **26 तारीख** को **गणतंत्र दिवस** पर **अमेरिकी राष्ट्रपति** को **मुख्य अतिथि** के तौर पर आमंत्रित किया था
- हालाँकि, पिछले महीने **अमेरिका** द्वारा **निमंत्रण अस्वीकार** कर दिए जाने के बाद
- **फ्रांसीसी राष्ट्रपति** इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गए और **गुरुवार को भारत** आने वाले हैं।
- **गणतंत्र दिवस** के **निमंत्रण** को ठुकराने के **अमेरिका के फैसले** और **पन्नून मामले** में **अमेरिका** के **आरोपों** के कारण **भारत-अमेरिका संबंधों** में परेशानी की अटकलें लगने लगी थीं।
- हाल ही में, **अमेरिकी राजकोष** ने घोषणा की कि वह **रशियन ऑयल** को **"कीमत सीमा से ऊपर"** ले जाने के लिए **संयुक्त अरब अमीरात** की एक कंपनी पर वर्ष का पहला प्रतिबंध लगा रहा है।
  - जो ऐसे लेनदेन के लिए **बीमा, शिपिंग** और **माल ढुलाई** जैसी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है।
  - अधिकारियों ने कहा कि हालांकि **भारत गैर-संयुक्त राष्ट्र** के **एकतरफा प्रतिबंधों** को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसने अब तक अपनी खरीद को मूल्य सीमा से नीचे रखा है।

91. तुर्की ने स्वीडन की NATO सदस्यता के लिए समर्थन किया इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- NATO
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **तुर्की** की **संसद** द्वारा इसकी **सदस्यता का समर्थन** करने के बाद **NATO** में शामिल होने के **स्वीडन** के प्रयास में एक बड़ी बाधा दूर हो गई।

मुख्य बिंदु

- किसी **नए देश** को **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन** (**NATO)** में शामिल होने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों को इसका अनुमोदन करना होगा।
- **तुर्की** और **हंगरी** लगभग पिछले **दो वर्षों** से **स्वीडन** के **प्रवेश का विरोध** कर रहे थे।

स्वीडन की NATO में शामिल होने की प्रेरणा

- स्वीडन की ऐतिहासिक तटस्थता और दो शताब्दियों तक युद्ध से बचना
- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रुख में बदलाव
- जनता की राय NATO सदस्यता के पक्ष में है
- **वर्ष 2022** में **फ़िनलैंड** के साथ **संयुक्त आवेदन, फ़िनलैंड** की बोली पहले ही स्वीकृत हो चुकी है

स्वीडन की NATO बोली का तुर्की का विरोध

- स्वीडन पर PKK जैसे समूहों के प्रति उदारता बरतने का आरोप
- विवादास्पद कुरान जलाने का विरोध संबंधों को प्रभावित कर रहा है
- स्वीडन को तुर्की के समर्थन को अमेरिका द्वारा F-16 लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री के साथ जोड़ना

NATO में स्वीडन का योगदान

- **भू-राजनीतिक महत्व:** रूस-नियंत्रित क्षेत्रों को छोड़कर, NATO लगभग सभी बाल्टिक सागर तटरेखा पर कब्ज़ा कर रहा है
- **सामरिक लाभ** : रूस से निकटता, सुव्यवस्थित आपूर्ति लाइनें और बढ़ी हुई रक्षा क्षमताएं
- **उन्नत विमान** और **पनडुब्बी क्षमताओं** के साथ **स्वीडन** की **आधुनिक** और **अनुभवी सेना** का अवलोकन

92. केंद्र ने कुष्ठ रोग के इलाज हेतु तीनदवा प्रणाली शुरू की- - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- कुष्ठ रोग
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)NLEP)

समाचार:

- **भारत सरकार** ने हाल ही में **वर्ष 2027** तक **उप-राष्ट्रीय** स्तर पर संचरण को रोकने के लक्ष्य के साथ कुष्ठ रोग के लिए एक **नए उपचार** के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS)** को **पॉसी-बैसिलरी (PB)** मामलों के लिए **तीन-दवा व्यवस्था** लागू करने के लिए **सक्षम प्राधिकारी** से मंजूरी मिल गई है।
  - **PB** मामलों के लिए **तीन-दवा वाली व्यवस्था** छह महीने के लिए मौजूदा **दो-दवा वाली व्यवस्था** की जगह लेगी।
- यह बदलाव **नवीनतम विश्व स्तर** पर **स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों** और **साक्ष्य-आधारित प्रथाओं** पर आधारित है।
- **PB** और **मल्टी-बैसिलरी (MB**) मामलों के लिए संशोधित **वर्गीकरण और उपचार व्यवस्था** 1 अप्रैल, वर्ष 2025 से प्रभावी होगी।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 1 अप्रैल, 2025 से संशोधित दवा आहार की आपूर्ति करेगा।
- **सभी राज्यों** और **केंद्र शासित प्रदेशों** को **12 महीने पहले कुष्ठ रोग रोधी दवाओं** की मांग करने का निर्देश दिया गया है।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण

- संभावित **दुष्प्रभावों** के बारे में चिंताएं जताई गई हैं, **क्लोफ़ाज़िमाइन** के कारण **त्वचा का एक विशिष्ट लाल** रंग हो जाता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों** का तर्क है कि **दो-दवा** के **आहार** में पर्याप्त प्रभावकारिता है, और **तीसरी दवा** को शामिल करना सख्ती से आवश्यक नहीं हो सकता है।

कुष्ठ रोग

- **माइकोबैक्टीरियम लेप्री** के कारण होने वाला **कुष्ठ रोग** एक **दीर्घकालिक संक्रामक रोग** है।
- यह रोग मुख्य रूप से **त्वचा** और **परिधीय तंत्रिकाओं** को प्रभावित करता है। उपचार न किए जाने पर यह **रोग प्रगतिशील** और **स्थायी विकलांगता** का कारण बन सकता है।
- यह **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में अधिक आम है।
- यह एक **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD)** है जो अभी भी **120** से अधिक देशों में होता है, हर **साल 200,000** से अधिक नए मामले सामने आते हैं।
- यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है।
- **ट्रांसमिशन:** उपचार न किए गए मामलों के साथ निकट संपर्क के दौरान **नाक और मुंह** से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से।
- **लक्षण**
  - विकृत त्वचा के घाव, गांठ या उभार जो कई हफ्तों या महीनों के बाद भी दूर नहीं होते।
  - तंत्रिका क्षति से हाथ-पैरों में संवेदना की हानि और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है
- WHO-अनुशंसित उपचार आहार, जिसे **मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT)** के रूप में जाना जाता है, में **तीन दवाएं** शामिल हैं जैसे **डैपसोन, रिफैम्पिसिन** और **क्लोफ़ाज़िमिन**।

93. केंद्र का लक्ष्य 2024 तक सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना द हिंदू -

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- जल जीवन मिशन

समाचार:

- **जल जीवन मिशन** द्वारा लगभग **सभी क्षेत्रों** में **नल का पानी** उपलब्ध कराया जाता है।
- **वर्ष 2019** में **प्रधान मंत्री** द्वारा शुरू किया गया **जल जीवन मिशन** पहले ही **73% ग्रामीण घरों** में **नल का पानी उपलब्ध** करा चुका है।

जल जीवन मिशन

- **वर्ष 2019** में लॉन्च किया गया, इसमें **वर्ष 2024** तक कार्यात्मक **घरेलू नल कनेक्शन** (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक **ग्रामीण घर** में **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी** की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- **JJM पानी** के लिए **एक जन आंदोलन** बनाना चाहता है, जिससे यह हर किसी की **प्राथमिकता** बन सके।
- यह **जल शक्ति मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।

उद्देश्य:

- मिशन मौजूदा **जल आपूर्ति प्रणालियों** और **जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी** और **परीक्षण** के साथ-साथ **टिकाऊ कृषि** की **कार्यक्षमता सुनिश्चित** करता है।
- यह संरक्षित जल के **संयुक्त उपयोग**, **पेयजल स्रोत संवर्धन, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे वाटर उपचा**र और इसके **पुन: उपयोग** को भी **सुनिश्चित** करता है।
- **JJM स्थानीय स्तर** पर पानी की **एकीकृत मांग** और **आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे:
  - वर्षा जल संग्रहण
  - भूजल पुनर्भरण
  - पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ मिलकर किया जाता है।
- **यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें शामिल है**
  - विस्तृत जानकारी
  - मिशन के प्रमुख घटक के रूप में शिक्षा और संचार।

- **पानी समितियाँ** गाँव की **जल आपूर्ति प्रणालियों** की **योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन** और **रखरखाव** करती हैं।
- **समितियाँ गाँव** के सभी **उपलब्ध संसाधनों** को मिलाकर एक बार की **गाँव कार्य योजना** तैयार करती हैं। **कार्यान्वयन** से पहले योजना को **ग्राम सभा** में अनुमोदित किया जाता है।

94. प्रस्तावित प्रसारण विधेयक से अति-नियंत्रण की चिंताएं बढ़ सकती है - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995।
- प्रसारण सेवाएँ (विनियमन) विधेयक, 2023
- प्रसारण सलाहकार परिषद

समाचार:
- प्रस्तावित **प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023** ने **अति-नियंत्रण और अति-विनियमन** की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- **नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, इंडिया** (NWMI) ने इस संबंध में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** को एक आवेदन दिया है।
- वर्तमान में यह बिल **जनता** और **हितधारकों** से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए खुला है।.

मुख्य बिंदु
- प्र**सारण विधेयक 1995** के **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम** को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य **टेलीविजन** से लेकर **स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म** तक सभी प्रकार की **प्रसारण सामग्री** के लिए एक **व्यापक नियामक व्यवस्था** प्रदान करना है।
- सरकार इस विधेयक के माध्यम से खुद को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करती है।

NWMI द्वारा उठाई गई चिंताओं की सूची
- विधेयक को **व्यापक और विस्तृत परामर्श** की आवश्यकता है ।
- मीडिया परिदृश्य को अत्यधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है ।
- **नियंत्रण** और **अति-विनियमन** का यह इरादा **स्वस्थ, स्वतंत्र मीडिया** के हित में नहीं है।
- भारत में **स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र भाषण** और **रचनात्मक स्वतंत्रता** को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- विधेयक में अस्पष्ट शब्दों वाले प्रावधान हैं, जिनमें **'समाचार** और **समसामयिक मामलों** के कार्यक्रमों' की परिभाषा भी शामिल है।
- यह बिल व्यक्तिगत **YouTubers, पेशेवर पत्रकारों** और यहां तक कि **नागरिक पत्रकारों** के **सोशल मीडिया खातों** को अनावश्यक रूप से कवर करेगा।
- यह विधेयक **समाचार संगठनों** पर **अतिरिक्त आवश्यकताएँ** और भार डालता है।
- यह बिल छोटे समाचार संचालकों के लिए हानिकारक है।

मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार का दबदबा
- विधेयक के एक भाग के रूप में **कार्यक्रम संहिता** और **विज्ञापन संहिता** की रूपरेखा पर गहन विचार-विमर्श नहीं किया गया है।
- विधेयक समाचार पत्रों के काम को **सामग्री मूल्यांकन समितियों (CEC)** के अधीन करता है।
- विधेयक **केंद्र सरकार** को सामग्री **मूल्यांकन समितियों (CECs)** के गठन में एक प्रमुख भूमिका देता है।
- OTT प्लेटफार्मों के संदर्भ में, **CEC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)** की कार्यप्रणाली की नकल करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जो खुद आलोचना का विषय है।
- **श्याम बेनेगल** की अध्यक्षता में **OTT** पर विशेषज्ञों की समिति ने इन **प्लेटफार्मों पर उदार नियंत्रण** का सुझाव दिया।
- बिल के तहत **ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल** के गठन का काम **केंद्र सरकार** के हाथ में होगा.

95. गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं का नेतृत्व -द हिंदू

प्रासंगिकता: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास ।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम
- कर्तव्य पथ

समाचार:
- 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर **75वें गणतंत्र दिवस परेड** का नेतृत्व महिलाओं ने किया

मुख्य बिंदु
- सेना सेवा कोर की **मेजर सौम्या शुक्ला** ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
  - **262 फील्ड रेजिमेंट** की **लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा** ने **पिनाका रॉकेट सिस्टम** का नेतृत्व किया

नारी शक्ति के सूचक
- पहली बार सभी महिलाओं की **त्रि-सेवा** टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया।
- **CRPF, BSF और SSB** की महिला कर्मियों ने **मोटरसाइकिलों** पर साहसिक करतब दिखाए।
- **महिला आरक्षण विधेयक** संसद द्वारा पारित होने के कुछ ही महीने बाद **गणतंत्र दिवस परेड** होती है।
- यह कानून **लोकसभा** और **राज्य विधानसभाओं** में **महिलाओं** के लिए एक **तिहाई सीटें आरक्षित** करने का प्रावधान करता है।
- भारत में एक **महिला राष्ट्रपति** हैं, वह भी आदिवासी समुदाय से है

96. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता HC को नोटिस जारी किया- इंडियन एक्सप्रेसइंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

प्रीलिम्स टेकअवे
- डिवीजन बेंच (प्रभाग पीठ)
- अंतरिम प्रवास

समाचार:
- **कलकत्ता उच्च न्यायालय** में, **एक न्यायाधीश** ने अपने **साथी न्यायाधीश** पर इस राज्य में कुछ **राजनीतिक दल** के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने का आरोप लगाया।

मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता HC को नोटिस जारी किया.
- **माननीय न्यायालय** ने **राज्य** में **MBBS उम्मीदवारों** के प्रवेश में कथित अनियमितताओं की **CBI जांच** के निर्देशों पर भी रोक लगा दी।

न्यायिक मतभेद और परिणाम
- **कलकत्ता उच्च न्यायालय** की **एकल-न्यायाधीश पीठ** ने निर्देश दिया था कि राज्य में **MBBS प्रवेश में कथित** अनियमितताओं की **CBI जांच** का आदेश दिया जाए।
- **कलकत्ता** उच्च **न्यायालय की खंडपीठ** द्वारा **एकल पीठ** के आदेश पर अंतरिम रोक जारी की गई थी ।
- एक खंडपीठ के विपरीत आदेश के बावजूद, इस जांच को जारी रखने का आदेश दिया गया था ।
- **सुप्रीम कोर्ट** ने इस संबंध **में पांच जजों** की बेंच गठित की है
- इसमें **CJI डीवाई चंद्रचूड़** और **सुप्रीम कोर्ट** के **चार सबसे वरिष्ठ जज यानी जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस** शामिल होंगे।
- शीर्ष अदालत ने मामले में **कलकत्ता उच्च न्यायालय के** समक्ष सभी संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी

97. इजराइल अपनी रक्षा करना जारी रखेगा: इज़रायली प्रधानमंत्री- द इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, उनकी संरचना और अधिदेश

प्रीलिम्स टेकअवे
- नरसंहार
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

समाचार:
- **इज़रायली प्रधानमंत्री** ने दावा किया कि **इज़रायल अपनी रक्षा** के लिए "वह करना जारी रखेगा जो आवश्यक है"।

मुख्य बिंदु

- यह बयान **संयुक्त राष्ट्र** के शीर्ष यानी **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ**) के एक फैसले की **पृष्ठभूमि** में आया है।
- ICJ ने **गाजा पट्टी** में हमास के खिलाफ **इजरायल के युद्ध** की आलोचना की।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** ने **दक्षिण अफ्रीका** द्वारा दायर नरसंहार मामले में गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया।
- अदालत ने मांग की कि **इज़राइल छोटे तटीय क्षेत्र** में अपने **सैन्य हमले** में मौत और क्षति को रोकने की कोशिश करे।
- **इज़रायल प्रधान मंत्री** ने **नरसंहार** के दावों को "**अपमानजनक**" बताते हुए खारिज कर दिया

नरसंहार

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, **नरसंहार** का तात्पर्य किसी विशिष्ट **जातीय, नस्लीय, धार्मिक या राष्ट्रीय समूह** के जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश से है।
- यह विनाश **विभिन्न तरीकों** से प्रकट हो सकता है जैसे**:**
- बड़े पैमाने पर हत्याएँ
- बलपूर्वक स्थानांतरणकुष्ठ रोग
- कठोर जीवन स्थितियों को लागू करना
- बड़े पैमाने पर मौत
- **संयुक्त राष्ट्र नरसंहार** के अपराध को बनाने वाले **दो प्राथमिक घटकों** की रूपरेखा प्रस्तुत करता है**:**
  - **मानसिक तत्व:** इसमें किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने का इरादा शामिल है।
  - **भौतिक तत्व:** इसमें विशिष्ट कृत्यों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें शामिल हैं::
    - समूह के सदस्यों को मारना
    - समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
    - जानबूझकर जीवन की ऐसी स्थितियाँ थोपना जिससे समूह का पूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश हो सके।

98. भारत, फ्रांस निगरानी संबंधों पर सहमत हुए - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल
- संयुक्त निगरानी मिशन

समाचार:

- भारत और फ्रांस **वर्ष 2020** और **वर्ष 2022** में **फ्रेंच ला रीयूनियन** से किए जाने वाले **संयुक्त निगरानी** मिशनों के आधार पर **दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर** में अपने सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए हैं।

मुख्य बिंदु

- **फ्रांस** पहली प्रमुख **पश्चिमी सैन्य शक्ति** है जिसके साथ **भारत ने संयुक्त गश्त** की है
  - जिसके तहत **भारतीय नौसेना** के **P-8I समुद्री गश्ती विमान** को **फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रीयूनियन** में तैनात किया गया था।
- उन्होंने भारत के समुद्री पड़ोस में उन बातचीत के विस्तार का भी स्वागत किया।
- दोनों देशों ने **ऑस्ट्रेलिया** के साथ **त्रिपक्षीय सहयोग** को "**पुनर्जीवित**" करने, **संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** के साथ सहयोग को गहरा करने और क्षेत्र में **नए सहयोग** तलाशने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।
- इस संबंध में, **संयुक्त** बयान में **सफ्रान** द्वारा **भारत में लीप (LEAP) इंजनों** के लिए रखरखाव, मरम्मत और **ओवरहाल (MRO)** की स्थापना का उल्लेख किया गया।
- **राफेल इंजन** के लिए **MRO** जोड़ने की योजना, **HAL** और **सफरान** के बीच **भारतीय मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (IMRH)** इंजन के लिए एक **संयुक्त उद्यम** के साथ एक व्यापक **हेलीकॉप्टर** साझेदारी।
  - और **अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों** का निर्माण भारत में किया गया, जिसमें स्वदेशीकरण भी शामिल है।

- भारतीय दूत का कहना है कि **फ्रांस के साथ जेट इंजन सौदा प्रौद्योगिकी तक 100%** पहुंच प्रदान करेगा

अंतरिक्ष सहयोग

- **अंतरिक्ष सहयोग** के क्षेत्र में, दोनों देशों ने **अंतरिक्ष सहयोग** के सभी पहलुओं में "**रणनीतिक मार्गदर्शन** और **दिशा**" प्रदान करने के लिए **जून 2023** में रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद शुरू किया था।

99. अमेरिका ने विवाद निपटान को फिर से शुरू करने के नए प्रस्ताव को रोका - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।

प्रीलिम्स टेकअवे

- MPIA
- WTO

समाचार:

- **WTO** के **अपीलीय निकाय** में रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए **130 WTO** सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को **संयुक्त राज्य अमेरिका** से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है।

मुख्य बिंदु

- जारी गतिरोध ने अपीलीय निकाय की कार्यक्षमता के बारे में चिंता पैदा कर दी है, जिससे भू-राजनीतिक चुनौतियों और संरक्षणवादी रुझानों के बीच वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ गया है।

अमेरिकी द्वारा लगातार रूकावट:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने अपीलीय निकाय के सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए **ग्वाटेमाला** द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव को **73वीं** बार रोक दिया है ।
- वर्ष 2017 से, **अमेरिका** ने **WTO** में **न्यायिक सक्रियता** पर चिंताओं और **अमेरिकी संप्रभुता** से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए **नए न्यायाधीशों** की नियुक्ति का विरोध किया है।

वैश्विक व्यापार प्रभाव

- एक कार्यात्मक **अपीलीय निकाय** की अनुपस्थिति चिंताजनक है, खासकर जब बढ़ते **भू-राजनीतिक** तनाव के बीच **वैश्विक व्यापार** पहले से ही धीमा हो रहा है।
- विकसित देशों द्वारा **कार्बन टैक्स** जैसे **अंतर्मुखी व्यापार उपायों** को अपनाने से **व्यापार परिदृश्य** और **अधिक जटिल** हो गया है, जिसका **असर भारत** जैसे देशों पर पड़ रहा है।

विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और सुधार प्रयास

- अबू धाबी में 13वें **विश्व व्यापार संगठन** मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले, भारत का लक्ष्य इस प्रणाली के समाधान की वकालत करना है।

विवादास्पद अमेरिकी परिप्रेक्ष्य

- अमेरिका का दावा है कि पुरानी प्रणाली कई सदस्यों के लिए काम नहीं कर रही थी, इस बात पर जोर देते हुए कि अपीलीय निकाय चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से अंतर्निहित चिंताओं का समाधान नहीं होता है।
- 130 सह-प्रायोजक देशों के बीच प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण समर्थन को देखते हुए, इस बयान पर कुछ सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया।

वैकल्पिक उपाय और अमेरिकी प्रभाव

- कार्यशील अपीलीय निकाय की अनुपस्थिति में अपील अधिकारों को बनाए रखने के लिए **बहुदलीय अंतरिम अपील व्यवस्था (MPIA)** की खोज करने का सुझाव दिया ।
- अमेरिकी कानूनों को चुनौती देने वाले बड़ी संख्या में विवादों का हवाला देते हुए **अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि** का तर्क है कि **अपीलीय निकाय** की उचित **कार्यप्रणाली** अमेरिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

100. सरकार उच्च शिक्षा हेतु मान्यता प्रणाली में बदलाव की योजना बना रही है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)
- वन नेशन, वन डेटा प्लेटफॉर्म
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

समाचार:
- राष्ट्रीय **मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)** ने हाल ही में **उच्च शिक्षा संस्थानों** के लिए मान्यता प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की।

प्रमुख सुधार

बाइनरी प्रत्यायन प्रणाली
- **उच्च शिक्षा संस्थानों** को अब वर्तमान **ग्रेडिंग प्रणाली** को समाप्त करते हुए या तो **"मान्यता प्राप्त"** या "गैर मान्यता प्राप्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- "गैर मान्यता प्राप्त" में मानकों के अनुपालन के आधार पर **दो श्रेणियां** शामिल हैं, जैसे **"मान्यता की प्रतीक्षा"** और **"गैर मान्यता प्राप्त"**।
  - **मान्यता की प्रतीक्षा:** वे संस्थान जो आवश्यकताओं को लगभग पूरा करते हैं लेकिन सुधार की आवश्यकता है
  - **गैर मान्यता प्राप्त:** वे संस्थान जो मान्यता के मानकों से काफी नीचे हैं।
- मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए **"स्तर एक"** से "स्तर पांच" तक प्रगति के लिए परिपक्वता-आधारित श्रेणीबद्ध प्रणाली का परिचय देता है।
- **"बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान** और **शिक्षा** के लिए **वैश्विक उत्कृष्टता संस्थान"** का दर्जा प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ, सुधार को प्रोत्साहित करता है।

वन नेशन, वन डेटा प्लेटफॉर्म
- एक नया सार्वजनिक मंच, **"वन नेशन, वन डेटा", विश्वविद्यालयों** से **व्यापक डेटासेट** एकत्र और प्रदर्शित करेगा ।
- **उद्देश्य:** पारदर्शिता, विश्वसनीयता बढ़ाना और समय के साथ अनुमति, मान्यता और रेटिंग जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
  - मूल्यांकन और मान्यता के मौजूदा मैनुअल को प्रतिस्थापित करता है जहां विशेषज्ञ परिसर का दौरा करने और प्रस्तुत किए गए डेटा को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, **प्लेटफ़ॉर्म में डेटा** की सत्यता की जांच करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र भी होगा।

आईआईटी के लिए भविष्य के निहितार्थ
- इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या **आईआईटी** को नई मान्यता प्रणाली में भाग लेना अनिवार्य होगा।
  - **राधाकृष्णन समिति** ने सिफारिश की थी कि आईआईटी को एक एकीकृत मान्यता प्रक्रिया के तहत लाया जाए।
- वर्तमान में, **आईआईटी अपने कार्यक्रमों** के आ**वधिक मूल्यांकन और मूल्यांकन** के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों का पालन करते हैं।

101. स्कूलों द्वारा EWS की रिक्त सीटों को आगे बढ़ाने से RTI उल्लंघन नहीं दिल्ली :HC- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 21
- RTE अधिनियम

समाचार:
- **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि **आर्थिक रूप** से **कमजोर वर्ग/वंचित समूह (EWS/DG) श्रेणी** में **अधूरी रिक्तियों** को आगे बढ़ाना वैध है।

- फैसला वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ है।

मुख्य बिंदु

- एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि **EWS/DG** की **अधूरी रिक्तियों** को अगले वर्ष अगली कक्षा में **ले जाना** बच्चों के **मुफ्त** और **अनिवार्य शिक्षा** के अधिकार (**RTE**) अधिनियम या किसी अन्य कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है ।
- **EWS/DG** छात्रों को अपनी प्रवेश स्तर की **कक्षा की क्षमता** के कम से कम **25%** तक प्रवेश देना प्रत्येक स्कूल का **वैधानिक दायित्व** है, जो **RTE अधिनियम** की धारा **2(n)(iv)** के अंतर्गत आता है।
- HC ने रेखांकित किया है की यदि कोई स्कूल चूक करता है, तो उसे अगले **वर्ष अगली उच्च कक्षा** में घाटे को पूरा करने का निर्देश देने में कुछ भी अवैध नहीं है, "

RTE अधिनियम

- RTE अधिनियम का लक्ष्य **6 से 14 वर्ष** की **आयु के सभी बच्चों** को **प्राथमिक शिक्षा** प्रदान करना है।
- यह शिक्षा को **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21)** के रूप में लागू करता है।
- यह **अधिनियम समाज** के वंचित वर्गों के लिए **25% आरक्षण** का आदेश देता है जहां वंचित समूहों में शामिल हैं::
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
  - सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग
  - निःशक्तजन
- यह **गैर-प्रवेशित बच्चे** को **आयु के अनुरूप कक्षा** में **प्रवेश देने** का भी प्रावधान करता है।
- इसमें **"नो डिटेंशन पॉलिसी"** का एक खंड था जिसे बच्चों के **मुफ्त** और **अनिवार्य शिक्षा** का **अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** के तहत हटा दिया गया है।

102. केरल ने ओबीसी सूची को संशोधित करने हेतु केंद्र से SECC डेटा का अनुरोध किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे

- भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त
- जाति जनगणना

समाचार:

- **केरल सरकार** ने **सुप्रीम कोर्ट** को बताया कि उसे राज्य में **सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्गों** की पहचान के लिए **वर्ष 2011** में **केंद्र** द्वारा आयोजित **जाति जनगणना** पर उम्मीदें टिकी हैं।।

मुख्य बिंदु

- राज्य को अपनी **पिछड़ा वर्ग सूची** को समय-समय पर संशोधित करने के न्यायिक आदेशों की **"जानबूझकर अवज्ञा"** करने के लिए **सर्वोच्च न्यायालय** में **अवमानना कार्यवाही** का सामना करना पड़ रहा है।
  - सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।
- जबकि **बिहार** जैसे **राज्यों** ने **लोकसभा चुनाव** से पहले अपना **जाति सर्वेक्षण** कराया है
- **राज्य** ने **केरल में पिछड़े वर्गों** की पहचान के लिए **वर्ष 2011** के **जाति सर्वेक्षण डेटा रिपोर्ट** की एक प्रति के लिए **4 नवंबर, 2022** को **केंद्र** से अनुरोध किया था।
- रिपोर्ट **मई 2023** में ही **केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग** के अध्यक्ष को भेज दी गई थी।
- **राज्य सरकार** के अनुसार, रिपोर्ट **केरल राज्य** के भीतर **सामाजिक और शैक्षिक रूप** से **पिछड़े वर्गों** की पहचान के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी।

जाति जनगणना

- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) द्वारा संचालित - शहरी क्षेत्र।।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** - ग्रामीण क्षेत्र
- **गृह मंत्रालय:** भारत के **रजिस्ट्रार जनरल** और **जनगणना आयुक्त** जाति जनगणना के लिए जिम्मेदार हैं।

103. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई सौर नीति का अनावरण किया द हिंदू/ दिल्ली के - मुख्यमंत्री ने नई सौर नीति की घोषणा की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- पीएम) कुसुम-PM-KUSUM)
- सृष्टि योजना)SRISTI)

समाचार:
- **दिल्ली** के **मुख्यमंत्री** ने **दिल्ली सौर नीति-2024** का अनावरण किया
- नीति के तहत, अपनी **छतों पर सौर ऊर्जा पैनल** स्थापित करने वाले उ**पभोक्ताओं** को **पीढ़ी-आधारित प्रोत्साहन** दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु
- सरकार के अनुसार, **वर्ष 2027** तक दिल्ली की लगभग **20% बिजली** की खपत सौर ऊर्जा से होगी।
- नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार **₹570 करोड़ खर्च** करेगी।
- **मुख्यमंत्री** ने कहा कि यह योजना उन घरों के **बिजली बिलों को शून्य करने** में मदद करेगी यदि उनकी बिजली की खपत उनके द्वारा उत्पादित **बिजली के मुकाबले** समायोजित करने के बाद **प्रति माह 200 यूनिट** से कम है।

सौर ऊर्जा बनने की दिशा में भारत की पहल
- **सौर पार्क योजना:** सौर पार्क योजना कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना बना रही है।
- **रूफटॉप सोलर योजना** : रूफटॉप सोलर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा का उपयोग करना है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
- **सृष्टि योजना(SRISTI)** : भारत में छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के सौर परिवर्तन (SRISTI) योजना का सतत छत कार्यान्वयन।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है।
- **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM): ग्रामीण क्षेत्रों** में **ऑफ ग्रिड सौर पंपों** की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए नवीन और **नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा **पीएम-कुसुम (PM-KUSUM)** योजना शुरू की गई थी।

104. तालिबान के विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ क्षेत्रीय संबंधों पर चर्चा की इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- उत्तरपश्चिम सीमांत प्रांत-
- तालिबान

समाचार:
- तालिबान के विदेश मंत्री ने **भारत समेत 11 पड़ोसी** और **क्षेत्रीय देशों** के **राजनयिकों** की बैठक की।
- उन्होंने "**क्षेत्र-केंद्रित अभिलेख**" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा

बैठक का उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य **अफगानिस्तान** और **क्षेत्रीय देशों** के बीच **सकारात्मक** और **रचनात्मक** जुड़ाव के लिए **क्षेत्रीय सहयोग** विकसित करना है।
- **तालिबान** के **विदेश मंत्री** और **काबुल स्थित भारत** के **राजनयिकों** के बीच यह पहली प्रचारित बैठक है।
- **जून 2022** से, **भारत** ने **अफगानिस्तान** को **मानवीय सहायता** और **सहायता पहुंचाने** के घोषित उद्देश्य के साथ एक तकनीकी टीम तैनात की है।

- **क्षेत्रीय सहयोग सामान्य क्षेत्रीय लाभों** के आधार पर **क्षेत्र-केंद्रित** और **जुड़ाव** के **रास्ते तलाशने** पर **केंद्रित** हो सकता है-
  - क्षेत्र में मौजूदा और संभावित खतरों से निपटने के लिए अफगान सरकार के साथ सकारात्मक और रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक क्षेत्र-केंद्रित अभिलेख बनाना;

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का इतिहास

- **आधुनिक भारत और अफगानिस्तान** के लोगों के बीच संपर्क **सिंधु घाटी सभ्यता** के दिनों से ही मौजूद है।
- **10वीं शताब्दी** से **18वीं शताब्दी** के मध्य तक कई **आक्रमणकारियों** ने **भारत** के **उत्तरी क्षेत्रों** पर आक्रमण किया।
- खान अब्दुल गफ्फार खान **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन** के प्रमुख नेताओं और **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** के सक्रिय समर्थकों में से एक थे।
- भले ही **उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP)** पाकिस्तान का **खैबर पख्तूनख्वा** प्रांत बन गया
- **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम** के लिए सर्वसम्मत **पश्तून समर्थन** से **पश्तून स्वायत्तता** और **स्वतंत्रता** के लिए भारत में बड़ी सहानुभूति पैदा हुई।
- भारत सरकार ने **NWFP** में अधिक **पश्तून स्वतंत्रता** की **पैरवी में पश्तून नेता खान अब्दुल गफ्फार खान** का समर्थन करना जारी रखा।

105. केंद्र सरकार ने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने हेतु NCRF नीति तैयार की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफेरेंस फ्रेमवर्क (NCRF)
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम

समाचार:

- भारत विशेष रूप से **बैंकिंग**, **दूरसंचार** और **ऊर्जा** जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए **घरेलू स्तर** पर विकसित **साइबर सिक्योरिटी उत्पादों** और **सेवाओं** के उपयोग की सिफारिश करने के लिए तैयार है।
- यह पहल बढ़ते **साइबर सुरक्षा खतरों** के **मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा** को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित है।

नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफेरेंस फ्रेमवर्क (NCRF)

- सरकार ने **साइबर सिक्योरिटी** के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करने, **भूमिकाओं और जिम्मेदारियों** को रेखांकित करने के लिए एक **व्यापक नीति NCRF** तैयार की है।
- NCRF कार्यान्वयन योग्य उपाय प्रदान करने के लिए मौजूदा कानूनों, नीतियों और दिशानिर्देशों का सहारा लेता है ।
- इसे **नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)** द्वारा **नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (NCSC)** के समर्थन से विकसित किया गया है।
  - NCIIPC **प्रधान मंत्री कार्यालय** को रिपोर्ट करती है।
- हालाँकि, **NCRF** एक दिशानिर्देश है यानी इसकी **सिफारिशें बाध्यकारी** नहीं होंगी।

साइबर सिक्योरिटी बजट आवंटन

- NCRF यह सिफारिश कर सकता है कि उद्यम **अपने कुल आईटी बजट** का कम से कम 10% विशेष रूप से **साइबर सिक्योरिटी** के लिए आवंटित करें।
- यह आवंटन सामान्य **आईटी संसाधनों** से अलग होना चाहिए, **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं** के साथ संरेखित होना चाहिए और **संगठनात्मक साइबर सिक्योरिटी** स्थिति को बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए।

विनियामक निरीक्षण

- **NCRF** यह भी सुझाव दे सकता है कि **महत्वपूर्ण क्षेत्रों** की **निगरानी** करने वाले **नियामक सूचना सुरक्षा** आवश्यकताओं को परिभाषित करें।
- इसके अतिरिक्त, इन नियामकों को **महत्वपूर्ण क्षेत्र** के संचालन से संबंधित **सेंसिटिव डेटा** तक पहुंचने के लिए प्रभावी **सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS)** उदाहरणों की आवश्यकता हो सकती है।

- यह निर्धारित कर सकता है कि **राष्ट्रीय नोडल एजेंसियां** विभिन्न संस्थाओं से **डेटा की मशीन-प्रोसेसिंग** के लिए **प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाएं** विकसित करें।
    - इस दृष्टिकोण का उद्देश्य **ऑडिट अनुपालन, ऑडिट प्रभावशीलता** और **ऑडिटरों की ग्रेडिंग** के **क्षेत्रीय और क्रॉस-सेक्टोरल विश्लेषण** को सुविधाजनक बनाना है।

साइबर सिक्योरिटी घटनाएं

- हाल के **हाई-प्रोफाइल साइबर हमलों,** जिसमें **2022 में एम्स दिल्ली सिस्टम** का उल्लंघन भी शामिल **है,** ने एक मजबूत **साइबर सिक्योरिटी** ढांचे की तात्कालिकता को रेखांकित किया है।
- व्यापक ढांचे की कमी ने **केंद्रीय मंत्रियों** के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं और **क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों** की आवश्यकता पर जोर दिया है।

106. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं है: SC - द हिंदू

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ब्रासीलिया घोषणा
- अनुच्छेद 47

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि **राष्ट्रीय** और **राज्य राजमार्गों** के बाहरी किनारे के **500 मीटर** के भीतर **शराब की बिक्री** पर **दिसंबर 2016** में लगाया गया **प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों** तक लागू नहीं होगा।

मुख्य बिंदु

- मार्च 2023 के आदेश ने **पुडुचेरी उत्पाद शुल्क विभाग** द्वारा एक **शराब खुदरा विक्रेता** को दी गई अनुमति की पुष्टि करने वाले **मद्रास उच्च न्यायालय** के फैसले को रद्द कर दिया था।
- **500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक**
- अदालत ने **राजमार्गों** पर **शराब** की उपलब्धता के **संकेत** और **विज्ञापन** पर रोक लगा दी और मौजूदा संकेतों को **राष्ट्रीय और राज्य दोनों राजमार्गों** से तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि राजमार्ग किसी भी **विकर्षण या आकर्षण** से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए।
- न तो वे **राजमार्गों से सीधे** पहुंच योग्य होने चाहिए और न ही **वे राजमार्गों या सर्विस लेन** के बाहरी किनारे से **500 मीटर** की दूरी पर स्थित होने चाहिए।
- एक याचिका में कहा गया कि, **भारत सड़क सुरक्षा** पर **ब्रासीलिया घोषणा** का एक **हस्ताक्षरकर्ता** है
- यह जरूरी है कि **सड़क दुर्घटनाओं** पर **नियंत्रण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश** बनाये जाएं।
- **भारत के संविधान** के **अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21** की भावना के अनुरूप **भारतीय राज्यों** और **केंद्र शासित प्रदेशों** की **व्यायाम नीतियों** में संशोधन किया जाना चाहिए।

107. फिलीपींस, वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दक्षिण चीन सागर
- मानचित्र आधारित प्रश्न

समाचार:

- **फिलीपींस** और **वियतनाम** ने **दक्षिण चीन सागर** में घटनाओं को रोकने के लिए **समझौते पर हस्ताक्षर** किये
- बढ़ते गठबंधन को **चीन की ओर से अस्वीकृति** का सामना करना पड़ सकता है

प्रमुख समझौते और सहयोग

- सूचना-साझाकरण और प्रशिक्षण आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा
- व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना
- चावल पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर

दक्षिण चीन सागर में तनाव
- चीन के साथ तनावपूर्ण टकराव की पृष्ठभूमि
- क्षेत्रीय टकराव की तीव्रता

वियतनामी प्रतिक्रिया और समझौते का विवरण
- घटनाओं को रोकने और प्रबंधित करने पर समझौतों का विशिष्ट विवरण जारी नहीं किया गया
- समुद्री सहयोग पर समझौते को शीघ्र क्रियान्वित करने का महत्व

संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त प्रस्तुतिकरण
- महाद्वीपीय शेल्फ सीमा पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को वियतनाम के साथ संयुक्त प्रस्तुतिकरण में रुचि
- उचित समय पर सहयोग करने की इच्छा को सीमित करती है

राइस डील
- वियतनाम स्थिर चावल आपूर्ति के लिए फिलीपींस फ्रेमवर्क निर्माण को सालाना 1.5 से 2 मिलियन मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा
- फिलीपींस में आयातित चावल में वियतनामी चावल की हिस्सेदारी 85% है

108. भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: रिपोर्ट और सूचकांक

प्रीलिम्स टेकअवे
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)

समाचार:
- **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट** के अनुसार, 2023 के **भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)** में **भारत 180** देशों में से **93वें** स्थान पर है।
- समग्र स्कोर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा, **वर्ष 2022** में **40** से गिरकर **वर्ष 2023** में **39** हो गया।

भारत के लिए चिंता का विषय
- भारत में चुनावों से पहले **नागरिक स्थान** में और कमी देखी जा रही है।
- इसमें एक **दूरसंचार विधेयक** का पारित होना भी शामिल है जो **मौलिक अधिकारों** के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।
- भारत में स्कोर में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे किसी भी बड़े बदलाव के बारे में ठोस निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

क्षेत्रीय ठहराव
- एशिया **प्रशांत क्षेत्र में** भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में **बहुत कम या कोई सार्थक प्रगति** दर्ज नहीं की गई है।
- क्षेत्र के लिए **औसत CPI स्कोर** लगातार पांच वर्षों से **45** पर स्थिर है।
- **क्षेत्रीय** और **वैश्विक औसत** से नीचे कमजोर स्कोर **भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे** पर डिलीवरी की कमी को दर्शाता है।
  - **एशिया** और **प्रशांत क्षेत्र** के **71%** देशों का **CPI स्कोर क्षेत्रीय** और **वैश्विक औसत** से कम है।

वैश्विक नेता और पिछड़े
- **न्यूज़ीलैंड** (3) और **सिंगापुर (5) भ्रष्टाचार नियंत्रण** में **विश्व स्तर पर शीर्ष** स्थान बनाए रखें।
- **चीन (76)** जो अपनी आक्रामक **भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई** के लिए जाना जाता है, सजा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे **दीर्घकालिक प्रभावशीलता** पर संदेह पैदा होता है।
- **दक्षिण एशिया** में, **पाकिस्तान (133)** और **श्रीलंका (115)** अपने-अपने **ऋण बोझ** और **राजनीतिक अस्थिरता** के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **सूचकांक** के निचले भाग में **उत्तर कोरिया (172)** और **म्यांमार (162)** जैसे सत्तावादी शासन वाले नाजुक राज्य शामिल हैं।
- **अफगानिस्तान (162)** इतिहास के सबसे **खराब मानवीय संकटों** में से एक का सामना कर रहा है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)
- **विशेषज्ञों** और **व्यापारिक** लोगों के अनुसार, **सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र** के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर **180 देशों** और क्षेत्रों को रैंक करता है।
- यह **शून्य** से **100 के पैमाने** का उपयोग करता है, जहां **शून्य अत्यधिक भ्रष्ट** है और **100** बहुत साफ है।
- यह **1995** से **गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- CPI आम तौर पर **भ्रष्टाचार** को **"निजी लाभ** के लिए सौंपी गई शक्ति का **दुरुपयोग"** के रूप में परिभाषित करती है।

सामान्य अध्ययन III

109. केंद्र सरकार ने ने MSP संबंधी चिंताओं को चिह्नित किया: तेल आयात बढ़ने से कम रिटर्न - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विश्व व्यापार संगठन
- MSP

समाचार:
- कैबिनेट ने **18 अक्टूबर, 2023** को विपणन सीजन **वर्ष 2024-25** के लिए **रबी फसलों** के लिए **MSP** में वृद्धि को मंजूरी दे दी।
- RTI दस्तावेजों से फसल विविधीकरण पर उच्च MSP के प्रभाव के संबंध में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाई गई चिंताओं का पता चलता है।

चिंता 1: आयात निर्भरता
- **खाद्य** एवं **सार्वजनि**क वितरण विभाग इस बात पर जोर देता है कि **तिलहनों** के **MSP** से **घरेलू उत्पादन** में वांछित वृद्धि नहीं हुई है।
- **तिलहन उत्पादन** में वृद्धि के अनुमान के बावजूद, **भारत** अभी भी अपनी **खाद्य तेल** की **55% जरूरतों** के लिए आयात पर निर्भर है।
- **विभाग उत्पादन** को **प्रोत्साहित** करने और **अधिक उपज** देने वाली **किस्मों** की ओर बदलाव के लिए तिलहनों के लिए दीर्घकालिक **MSP नीति** और **उच्च MSP** का सुझाव देता है।

चिंता 2: असमान लाभ
- **व्यय विभाग गेहूं खरीद** के **पक्ष** में **झुकाव** को उजागर करता है, जिससे केवल **सीमित संख्या** में **राज्यों** को लाभ होता है।
- नीति आयोग तिलहन और दलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए **14 गैर-मूल्य सिफारिशों** का अनुपालन करने का सुझाव देता है।

चिंता 3: विश्व व्यापार संगठन के दायित्व
- **वाणिज्य विभाग भारत** की **WTO प्रतिबद्धताओं,** विशेष रूप से '**डी-मिनिमिस**' सब्सिडी सीमा के बारे में सावधान करता है।
- भारत द्वारा चावल के लिए **डी-मिनिमिस सब्सिडी** सीमा का उल्लंघन और **MSP-आधारित फसल खरीद** के लिए **पूर्व निर्धारित लक्ष्यों** की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

110. छह साल में 1,117 सीमा चौकियों पर 4G सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी: केंद्र - द हिंदू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना
- 4G

समाचार:
- **केंद्र सरकार** ने **1,100** से अधिक **सीमा चौकियों** पर **4G मोबाइल सेवाओं** के लिए **₹1,545.66 करोड़** आवंटित किए हैं।
- **दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय** और **भारत संचार निगम लिमिटेड** के बीच **त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिंदु

4G संतृप्ति परियोजना के तहत लद्दाख में प्रगति
- लद्दाख के **379 गांवों** और **बस्तियों** में से **नौ स्थानों** पर **मोबाइल टावर** स्थापित किए गए, **34 स्थानों** पर बुनियादी काम पूरा हो गया है।
- पूर्वी लद्दाख में **वर्ष 2020** में **भारत-चीन गतिरोध** के लिए **धीमी प्रगति** को जिम्मेदार ठहराया गया।

सीमा सड़क परियोजनाएँ और बुनियादी ढाँचा विकास

- चालू वर्ष में चीन सीमा पर **48.03 किमी सड़कों** का निर्माण।
- **चार सीमा चौकियों** और **तीन हेलीपैडों** को जोड़ा जाएगा।
- **गलवान घटना** के बाद **चीन सीमा** पर **32 सड़कों** को मंजूरी और **32 हेलीपैड** का निर्माण/उन्नयन।

भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना (ICBR) के चरण

- **चीन सीमा** पर **27 प्राथमिकता** वाली **सड़कों** के लिए **वर्ष 2005** में **ICBR परियोजना** के पहले चरण की शुरुआत।
- आगे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए **21 सितंबर, 2020** को **दूसरे चरण** की मंजूरी।

सीमावर्ती ग्राम विकास एवं कनेक्टिविटी

- सीमावर्ती इलाकों में मजबूत **बुनियादी ढांचे** के विकास पर ध्यान केन्द्रित।
- **कल्याणकारी लाभ** प्रदान करने और **सीमावर्ती गांवों** तक **कनेक्टिविटी** में सुधार के प्रयास।
- पहले चरण में **663 गांवों** को कवर करते हुए **19 जिलों** और **46 सीमावर्ती ब्लॉकों** में व्यापक विकास के लिए **वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम** की शुरूआत।

111. NARCL के स्ट्रेस्ड खातों के अधिग्रहण में तेजी लाएं, धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित करें: वित्त मंत्रालय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
- PSB

समाचार:

- **वित्त मंत्रालय ने PSBs** से **नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL)** द्वारा **स्ट्रेस्ड खातों** के **अधिग्रहण** में तेजी लाने का आग्रह किया है।
- तनावग्रस्त खातों को तेजी से चालू करने की सुविधा के लिए **एनएआरसीएल और बैंकों के बीच नियमित बैठकों पर जोर दिया गया ।**

जमाराशियों का संग्रहण और नवप्रवर्तन

- **वित्त मंत्री** ने **PSB** के लिए **जमा राशि जुटाने** के महत्व पर जोर दिया।
- जमा आधार को बढ़ाने, बढ़े हुए **ऋण विस्तार** को सक्षम करने के लिए नवाचार और **आकर्षक जमा योजनाओं** को प्रोत्साहित किया गया

जिम्मेदार ऋण प्रथाएँ

- वित्त मंत्री ने उधारदाताओं के **वित्तीय स्वास्थ्य** और **अर्थव्यवस्था** में **ऋण प्रवाह** पर जानबूझकर चूक के प्रभाव पर प्रकाश डाला।
- PSB से जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को अपनाने, ऋण वितरण से पहले **उचित परिश्रम बढ़ाने** और **जानबूझकर डिफ़ॉल्ट** के मामलों में **त्वरित कानूनी कार्रवाई** करने का आग्रह किया।

कानूनी कार्रवाई और निष्पादन समीक्षाएँ

- डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी मामलों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए **PSB का प्रतिनिधित्व** करने वाले **वकीलों** के **प्रदर्शन** की **समीक्षा** के लिए कॉल करें।
- **धोखाधड़ी** और **जानबूझकर** चूक करने वाले मिलीभगत करने वाले **अधिकारियों** के खिलाफ **सख्त प्रशासनिक कार्रवाई** करने के निर्देश।

112. भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाने हेतु सार्थक कार्रवाई को बढ़ावा दिया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- जैविक विविधता अधिनियम
- वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

- हरित ऋण कार्यक्रम

समाचार:

- वर्ष 2023 में, **भारत** ने **जलवायु परिवर्तन शमन**, **वन्यजीव संरक्षण** और **जैव विविधता कानूनों** में महत्वपूर्ण प्रगति की।
- हालाँकि, चुनौतियाँ और आलोचनाएँ सामने आईं, विशेष रूप से **चीता स्थानांतरण परियोजना** और **वन** और **जैव विविधता कानूनों** में बदलाव के संबंध में।

जलवायु परिवर्तन पहल

- **COP33 प्रस्ताव**: भारत ने **वर्ष 2028** में **संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP33)** की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा और **जलवायु चुनौतियों** से निपटने के लिए कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित **'ग्रीन क्रेडिट पहल'** शुरू की।
- **दुबई जलवायु शिखर सम्मेलन:** भारत सहित विकासशील देशों ने अमीर देशों से **वर्ष 2050** तक **शुद्ध शून्य** के बजाय **नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन** हासिल करने का आग्रह किया।
- **प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन:** वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति **CO_2 उत्सर्जन** में **5%** की वृद्धि के बावजूद, भारत का स्तर वैश्विक औसत के आधे से भी कम रहा।
- **राष्ट्रीय संचार:** भारत ने UNFCCC को अपना **तीसरा राष्ट्रीय संचार** प्रस्तुत किया, जिसमें **वर्ष 2005** और **वर्ष 2019** के बीच **सकल घरेलू उत्पाद** उत्सर्जन तीव्रता में **33%** की कमी पर प्रकाश डाला गया।

वन्यजीव संरक्षण

- **बाघों की आबादी:** आंकड़ों से पता चला कि बाघों की आबादी में 6% वार्षिक वृद्धि हुई है, जो **वर्ष 2**018 में **2,967** से बढ़कर **वर्ष 2022** में **3,682** हो गई।
- **चीता स्थानांतरण परियोजना**
  - छह आयातित चीतों की मौत पर **चीता संरक्षण परियोजना** को आलोचना का सामना करना पड़ा।
  - चुनौतियों में शीतकालीन कोटों का **अप्रत्याशित विकास** और उसके बाद की **स्वास्थ्य समस्याएं** शामिल थीं।
- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)**
  - अप्रैल में लॉन्च किए गए **IBCA** का लक्ष्य दुनिया की **सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों** का संरक्षण करना है।
  - इसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल हैं।

वन और जैव विविधता कानूनों में बदलाव

- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम**
  - वन (संरक्षण) अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रभावित करते हुए, भूमि की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिए संशोधनों की आलोचना हुई।
  - संशोधित अधिनियम में छूट दी गयी है-
    - सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए **10 हेक्टेयर** तक की वन भूमि
    - "राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं" के लिए **अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा (LoC)** और **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** के **100 किमी** के भीतर आने वाला क्षेत्र।
  - आदिवासी और पारंपरिक वन-निवास समुदायों पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं।
- **जैविक विविधता अधिनियम**
  - संशोधनों का उद्देश्य बढ़ते **औषधीय पौधों** को बढ़ावा देना, **पारंपरिक चिकित्सा** का समर्थन करना, **अनुसंधान, पेटेंट** और **विदेशी निवेश** को सुविधाजनक बनाना है।
- हालाँकि, **लाभ-साझाकरण नियमों** में बदलाव के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिसमें उल्लंघन के लिए जेल की शर्तों की जगह जुर्माना लगाया गया।

113. म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जल्द ही समाप्त होगी, भारत में प्रवेश हेतु वीजा की जरूरत होगी - द हिंदू/ भारत सरकार, म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की योजना बना रही है - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR)
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
- स्थान आधारित प्रश्न

समाचार:
- भारत सरकार ने हाल ही में **भारत-म्यांमार सीमा** पर **फ्री मूवमेंट रिजीम** (FMR) को **समाप्त करने** का निर्णय लिया है।

मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR)
- **FMR** की स्थापना **वर्ष 2018** में **एक्ट ईस्ट नीति** के तहत की गई थी।
- यह **भारत-म्यांमार सीमा** पर रहने वाली **जनजातियों को बिना वीज़ा** की आवश्यकता के **16 किमी** तक एक-दूसरे के क्षेत्र में **आवाजाही की सुविधा प्रदान** करता है।
- यह **पहाड़ी जनजातियों** के सदस्यों को **सीमा पास** के साथ पार करने की अनुमति देता है, जो **एक वर्ष** के लिए वैध होता है और **दो सप्ताह** तक रहता है।
- भारत-म्यांमार सीमा **मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड** और **अरुणाचल प्रदेश राज्यों** में **1,643 किमी** तक फैली हुई है।

सरकार की रणनीति
- यह निर्णय संपूर्ण **भारत-म्यांमार सीमा** पर एक **उन्नत स्मार्ट फेंसिंग प्रणाली** को लागू करके **सीमा सुरक्षा** बढ़ाने की एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में आया है।।
- **FMR ख़त्म करने के कारण**
  - **भारतीय सीमा** पर हमलों और फिर **म्यांमार** में भागने के लिए **विद्रोही समूहों** द्वारा **FMR** के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
  - सीमा पर अवैध अप्रवास, मादक पदार्थों की तस्करी और सोने की तस्करी से संबंधित चिंताओं का समाधान करना।

समाप्ति के लिए मुख्यमंत्री का आह्वान
- **मणिपुर** के **मुख्यमंत्री** ने पहले **अवैध आव्रजन** के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए **केंद्र** से **सितंबर 2023** में **FMR** को स्थायी रूप से **समाप्त करने का आग्रह** किया था।
- राज्य नागरिकों के **राष्ट्रीय रजिस्टर** को लागू करने और **म्यांमार, विशेषकर मणिपुर** के साथ सीमा को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
  - मणिपुर में वर्तमान में **390 किमी** की सीमा में से केवल **10 किमी** पर ही फेंसिंग की गई है।

प्रभाव और भविष्य की योजनाएँ
- **स्मार्ट फेंसिंग** की शुरूआत और **FMR की समाप्ति की** उम्मीद है
  - सीमा सुरक्षा मजबूत करें
  - सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करें
  - भारत-म्यांमार सीमा पर व्यक्तियों की आवाजाही को नियंत्रित करें
- **सुरक्षा उपायों** को बढ़ाने पर **सरकार** का ध्यान **व्यापक भू-राजनीतिक विचारों** और **राष्ट्रीय हितों** के अनुरूप है।

114. आरबीआई ने निष्क्रिय खातों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे
- निष्क्रिय अकाउंट
- भारतीय रिजर्व बैंक

समाचार:
- आरबीआई ने खातों और जमाओं को **निष्क्रिय और अस्वामिक (लावारिस)** के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश पेश किए हैं।
- नियमों के मुताबिक, खाताधारक **केवाईसी दस्तावेज** जमा करके अपने अकाउंट को फिर से सक्रिय कर सकते हैं।

निष्क्रिय खाता और अस्वामिक जमाराशियाँ
- **दो वर्षों** से अधिक समय तक कोई '**ग्राहक प्रेरित लेनदेन**' नहीं हुआ है तो **बचत** या **चालू खाता निष्क्रिय** माना जाता है ।

- ग्राहक प्रेरित लेनदेन में खाताधारक द्वारा शुरू की गई **वित्तीय और गैर-वित्तीय गतिविधियाँ** शामिल हैं।
- **अस्वामिक जमाराशियाँ**
  - बचत/चालू खातों में शेष 10 वर्षों से संचालित नहीं
  - 10 वर्षों के भीतर **अस्वामिक** (लावारिस) सावधि जमा

संशोधित आरबीआई दिशानिर्देश

- बैंकों को एक वर्ष से अधिक समय से **ग्राहक-प्रेरित लेनदेन** की कमी वाले **खातों की वार्षिक समीक्षा** करने की आवश्यकता होती है।
- स्पष्ट सावधि जमा **नवीकरण जनादेश** के बिना मामलों में, बैंकों को उन खातों की समीक्षा करनी चाहिए जहां ग्राहकों ने **परिपक्वता** के बाद **धन वापस** नहीं लिया है या **स्थानांतरित नहीं** किया है।

संचार और पुनः सक्रियण

- बैंकों को पिछले वर्ष की निष्क्रियता के बारे में **खाताधारकों** को **पत्र, ईमेल** या **SMS** के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
- यदि अगले वर्ष कोई परिचालन नहीं होता है, तो खाता **'निष्क्रिय'** हो जाता है, जिसे **पुनः सक्रिय** करने के लिए **केवाईसी दस्तावेज़** जमा करने की आवश्यकता होती है।

खाता वर्गीकरण मानदंड

- किसी अकाउंट को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए केवल **ग्राहक-प्रेरित लेनदेन** पर विचार किया जाता है।
  - इसमें शुल्क और शुल्क जैसे बैंक-प्रेरित लेनदेन शामिल नहीं हैं।
- खाता वर्गीकरण अकाउंट के लिए विशिष्ट है, ग्राहक के लिए नहीं।
- सरकारी लाभार्थियों और छात्र छात्रवृत्ति के लिए **शून्य-शेष खातों** को छूट दी गई है।

पुनः सक्रियण प्रक्रिया

- बैंकों को अनुरोध पर सभी **शाखाओं** में और **वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया** (V-CIP) के माध्यम से **केवाईसी अद्यतनीकरण** की पेशकश करनी चाहिए।
- पुनर्सक्रियण के लिए **केवाईसी दिशानिर्देशों** का पालन करना होगा, और सक्रियण के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

गैर-रखरखाव जुर्माना और ब्याज

- निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर **कोई दंडात्मक शुल्क** लगाने की अनुमति नहीं है।
- बचत खातों पर **ब्याज नियमित रूप** से जमा किया जाना चाहिए, चाहे अकाउंट की **परिचालन स्थिति** कुछ भी हो।

115. स्पेसएक्स के रॉकेट से भारत का GSAT-20 लॉन्च होगा- द हिंदू/संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत स्पेसएक्स रॉकेट का उपयोग करेगा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे

- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)
- GSAT-20 सैटेलाइट
- स्पेसएक्स फाल्कन-9

समाचार:

- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** 2024 की **दूसरी तिमाही** के दौरान **स्पेसएक्स** के **फाल्कन-9** पर **GSAT-20,** जिसे अब नया नाम **GSAT-N2** दिया गया है, लॉन्च करने के लिए तैयार है।

मुख्य बिंदु

- **GSAT-20** एक उच्च-थ्रूपुट **KA-बैंड सैटेलाइट** है जो पूरी तरह से **NSIL** द्वारा स्वामित्व, संचालित और वित्त पोषित है।
- 4700 किलोग्राम वजन के साथ, यह **32 बीम** के साथ **KA-KA-बैंड HTS** क्षमता प्रदान करता है, जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करता है।

- यह लगभग **48 Gbps** की **HTS** क्षमता प्रदान करता है और इसे विशेष रूप से दूरस्थ और असंबद्ध क्षेत्रों की सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ब्रॉडबैंड, **IFMC** और सेलुलर बैकहॉल सेवाओं के लिए लागत प्रभावी **KA-KA-बैंड HTS** क्षमता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्पेसएक्स फाल्कन-9
- फाल्कन-9, स्पेसएक्स द्वारा डिजाइन और निर्मित, एक पुन: प्रयोज्य, दो चरणों वाला रॉकेट है।
- यह दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुन: प्रयोज्य रॉकेट है, जो स्पेसएक्स को सबसे महंगे हिस्सों को उड़ाने की अनुमति देता है, जिससे अंतरिक्ष पहुंच की लागत कम हो जाती है।

सरकारी आदेश
- मिशन में NSIL's की भूमिका **जून 2020** में **भारत सरकार** द्वारा घोषित **अंतरिक्ष क्षेत्र** के सुधारों के अनुरूप है।
- NSIL को उपयोगकर्ता सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **"मांग-संचालित मोड"** में उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व और संचालन करना अनिवार्य है।

पिछली सफलताएँ
- NSIL ने जून 2022 में अपना पहला मांग-संचालित उपग्रह, **GSAT-24** सफलतापूर्वक लॉन्च किया , जो पूरी तरह से वित्त पोषित और **TataPlay** द्वारा सुरक्षित क्षमता के साथ था।
- NSIL वर्तमान में कक्षा में 11 संचार उपग्रहों का मालिक है और उनका संचालन करता है।

116. PMI सर्वेक्षण के मुताबिक दिसंबर में विनिर्माण घटकर 18 माह के निचले स्तर पर- द हिंदू/ विनिर्माण PMI दिसंबर में 18 महीने के निचले स्तर पर - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे
- क्रय प्रबंधक सूचकांक
- कोर सेक्टर

समाचार:
- HSBC इंडिया **मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स** के अनुसार, भारत की **विनिर्माण गतिविधि** हाल ही में **दिसंबर 2023** में **18 महीने** के **निचले स्तर** पर आ गई।
- इस महीने की **रीडिंग** नवंबर में **56** की तुलना में **54.9** रही।
- इस गिरावट का कारण नए **ऑर्डर** और **आउटपुट** में कमजोर वृद्धि को बताया गया।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

- यह एक **सर्वेक्षण-आधारित** उपाय है जो उत्तरदाताओं से पिछले महीने की तुलना में **प्रमुख व्यावसायिक** चर के बारे में उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछता है।
- **उद्देश्य** : कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- इसकी गणना **विनिर्माण** और **सेवा क्षेत्रों** के लिए अलग-अलग की जाती है और फिर एक **समग्र सूचकांक** भी बनाया जाता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि पर** कब्जा नहीं करता है ।
- PMI **0 से 100** तक की संख्या है।
  - 50 से ऊपर प्रिंट का मतलब विस्तार है, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
  - 50 पर रीडिंग कोई बदलाव नहीं दर्शाती है।

PMI का महत्व

- इसे आर्थिक गतिविधि का एक **अच्छा अग्रणी संकेतक** माना जाता है।
  - यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है।
- कई देशों के **केंद्रीय बैंक** भी **ब्याज दरों** पर निर्णय लेने में मदद के लिए **सूचकांक** का उपयोग करते हैं।
- यह **कॉरपोरेट आय** का संकेत भी देता है और **निवेशकों** के साथ-साथ **बांड बाजारों** पर भी इस पर करीबी नजर होती है।
- सूचकांक का अच्छा अध्ययन किसी **अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था** की तुलना में किसी अर्थव्यवस्था के आकर्षण को बढ़ाता है।

117. 'साइबर क्राइम के अधिकांश मामले चीन, कंबोडिया और म्यांमार से - द हिंदू

प्रासंगिकता: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें; मनी-लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम।

प्रीलिम्स टेकअवे
- साइबर सुरक्षा
- भारतीय रिजर्व बैंक

समाचार:

- गृह मंत्रालय (MHA) के **भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C)** के CEO ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में साइबर अपराध पर चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया।
- **राष्ट्रीय हेल्पलाइन** पर **दैनिक साइबर अपराध** की लगभग **50%** शिकायतें **चीन, कंबोडिया** और **म्यांमार** से आती हैं।

मुख्य बिंदु

साइबर क्राइम का पैमाना:

- भारत में प्रतिदिन औसतन **5,000 साइबर शिकायतें** दर्ज की जाती हैं।
- अकेले 2023 में, **15.5 लाख साइबर-अपराध** शिकायतें दर्ज की गईं, जो **वर्ष 2019** में 26,049 से उल्लेखनीय वृद्धि है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति

- इनमें से **40-50% साइबर क्राइम** भारत के बाहर उत्पन्न होते हैं, जिनमें **चीन, कंबोडिया** और **म्यांमार** की उल्लेखनीय भागीदारी है।
- इन गतिविधियों में चीनी ऐप्स के प्रचलन पर जोर दिया गया

हेल्पलाइन और वित्तीय प्रभाव

- **वित्तीय धोखाधड़ी** के शिकार लोग **cybercrime.gov.in** या **1930 हेल्पलाइन** पर **शिकायत** दर्ज करा सकते हैं।
- **अप्रैल 2021** से, विभिन्न बैंक खातों में **₹1127 करोड़ अवरुद्ध** किए गए हैं, लेकिन शिकायतकर्ताओं को केवल **₹100 करोड़ वापस** किए गए हैं।
- अवरुद्ध धनराशि वापस करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास चल रहे हैं।

अवरुद्ध सिम कार्ड और वेबसाइटें

- शिकायतों के आधार पर 2,95,461 सिम कार्ड, 2,810 वेबसाइट, 595 मोबाइल एप्लिकेशन और 46,229 IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं।
- सिम कार्ड धोखाधड़ी के हॉटस्पॉट में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम शामिल हैं।

प्रमुख साइबर-क्राइम रुझान

- वर्ष 2023 में पाँच प्रमुख साइबर-अपराध प्रवृत्तियों की पहचान की गई, जिनमें निम्न से संबंधित घोटाले भी शामिल हैं:
  - निवेश ऐप्स/वेबसाइटें
  - अवैध ऋण ऐप्स
  - ग्राहक सेवा नंबर
  - ओटीपी धोखाधड़ी
  - सोशल मीडिया खातों का प्रतिरूपण या कब्ज़ा, और यौन शोषण।

चुनौतियाँ और पहल

- **ऋण ऐप अपराधों** को संबोधित करने में कठिनाई पर प्रकाश डाला गया और उल्लेख किया गया कि **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** ने उपभोक्ता लाभ के लिए 395 तत्काल ऋण ऐप को श्वेतसूची में डाल दिया है।
- I4C ने ऐसे खातों को ब्लॉक करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करते हुए, बैंकों और फिनटेक **कंपनियों** को **"म्यूल अकाउंट्स"** को भी चिह्नित किया है।

साइबर अपराधों का क्षेत्रीय वितरण

- अधिकांश साइबर अपराध हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा से रिपोर्ट किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी हैं।

118. भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना SKA में शामिल होगा - पीआईबी

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- SKA वेधशाला
- LIGO

समाचार:

- भारत सरकार ने **1250 करोड़ रुपये** की अनुमानित लागत पर **अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना**, **स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA)** में भारत की भागीदारी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- इस अनुमोदन में अगले **7 वर्षों** में **अंतर्राष्ट्रीय SKA वेधशाला (SKAO)** के निर्माण चरण के लिए वित्त पोषण सहायता शामिल है।
- इस परियोजना को **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** और **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा **संयुक्त रूप** से **वित्त पोषित** किया जाएगा, जिसमें **DAE प्रमुख एजेंसी** होगी।
- SKA विभिन्न प्रकार के अ**त्याधुनिक विज्ञान लक्ष्यों** को संबोधित करने के लिए **दुनिया** के **सबसे बड़े** और **सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप** का निर्माण करने वाली एक अ**त्याधुनिक, मेगा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सुविधा** है।
- यूके में परिचालन मुख्यालय के साथ **ऑस्ट्रेलिया (SKA-Low)** और **दक्षिण अफ्रीका (SKA-Mid)** में स्थित SKAO से **रेडियो खगोल विज्ञान** में क्रांति आने की उम्मीद है।
  - कई महत्वपूर्ण नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को आगे बढ़ाते हुए।
  - इस अनुमोदन के बाद, भारत SKA वेधशाला का पूर्ण सदस्य बनने के लिए SKAO संधि पर हस्ताक्षर करेगा।
- इस परियोजना में भागीदारी से **भारतीय उद्योग** और **अनुसंधान संगठनों** में अगली पीढ़ी की **प्रौद्योगिकियों** के **विभिन्न क्षेत्रों** में **विशिष्ट कौशल** के विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
  - जैसे आधुनिक एंटीना डिज़ाइन, परिष्कृत क्रायोजेनिक रिसीवर सिस्टम
- इस परियोजना में भारत की भागीदारी को मंजूरी भारत सरकार द्वारा **बुनियादी, व्यावहारिक** और **उन्नत विज्ञान अनुसंधान** पर दिए गए जोर को रेखांकित करती है।
- वर्ष की शुरुआत में, भारत सरकार **अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE's)** की **फर्मी नेशनल लेबोरेटरी** के प्रति प्रतिबद्ध थी:
- **प्रोटोन इम्प्रूवमेंट प्लान-II एक्सेलेरेटर** का सहयोगात्मक विकास

119. नया एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है - द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- एंटीबायोटिक ज़ोसुराबलपिन
- एसिनेटोबैक्टर बाउमानी

समाचार:
- **शोधकर्ताओं** ने हाल ही में **दवा-प्रतिरोधी जीवाणु, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी** से निपटने की क्षमता वाले **एंटीबायोटिक दवाओं** के एक **नए वर्ग** की पहचान की है।

एंटीबायोटिक ज़ोसुराबलपिन
- शोधकर्ताओं ने **एंटीबायोटिक ज़ोसुराबलपिन** की पहचान और विश्लेषण की सूचना दी जो **एसिनेटोबैक्टर बाउमानी** को नष्ट सकता है।
  - यह जीवाणु, विशेष रूप से इसके **कार्बापेनम-प्रतिरोधी उपभेद (CRAB),** नैदानिक उपचार में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है।
- उन्होंने एक बंधे हुए **मैक्रोसाइक्लिक पेप्टाइड (MCP)** की पहचान की जो चुनिंदा रूप से **ए बाउमानी** को नष्ट करता है।
- प्रभावशीलता और सहनशीलता के अनुकूलन के माध्यम से, **ज़ोसुराबलपिन एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी उपभेदों** से निपटने में एक आशाजनक दवा उम्मीदवार के रूप में उभरा।

कार्रवाई का अनोखा तरीका
- शोधकर्ता इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि **ज़ोसुराबलपिन** क्रिया के एक नए तरीके से संचालित होता है, जो **लिपोपॉलीसेकेराइड (LPS)** के परिवहन को रोकता है।
- ज़ोसुराबलपिन एक **प्रोटीन कॉम्प्लेक्स** को लक्षित करता है जो **ग्राम-नकारात्मक बैक्टीरिया** की **बाहरी-झिल्ली संरचना** बनाने के लिए **LPS** को **बैक्टीरिया** की सतह तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह **LPS परिवहन** को बाधित करता है, जिससे **जीवाणु कोशिका** में **LPS** का संचय होता है , जिससे अंततः जीवाणु की मृत्यु हो जाती है।

CRAB के विरुद्ध प्रभावकारिता
- प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए **100** से अधिक **CRAB नैदानिक नमूनों** के खिलाफ **एंटीबायोटिक** प्रभावी था।
- इसके अलावा, इसने **CRAB-प्रेरित निमोनिया** से पीड़ित चूहों में **बैक्टीरिया** के स्तर को काफी कम कर दिया।
- इसने **सेप्सिस** से चूहों की मृत्यु को भी रोका, जो **CRAB** द्वारा प्रेरित एक असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है।

120. शोधकर्ताओं ने मेटाबोलिक इंजीनियरिंग में प्रगति हासिल की - द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- कैम्पटोथेसीन (CPT)
- नाथापोडाइट्स निमोनियाना
- कैंसर

समाचार:
- **आईआईटी मद्रास** और **मंडी** के **शोधकर्ताओं** ने **कैंसर रोधी दवा कैंप्टोथेसिन (CPT)** के उत्पादन को बढ़ाने के लिए **पौधों की कोशिकाओं** की **मेटाबोलिक इंजीनियरिंग** में प्रगति की है।
- एलोपैथिक दवा **नाथापोडाइट्स निमोनियाना,** एक **देशी लुप्तप्राय पौधे** का उपयोग करके बनाई जाती है।

वर्तमान चुनौतियाँ
- **नाथापोडाइट्स निमोनियाना** से कैंप्टोथेसिन के निष्कर्षण के लिए **1 टन CPT** प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में पादप सामग्री, लगभग **1,000 टन** की आवश्यकता होती है।
- पौधे की **लुप्तप्राय स्थिति ने** इस महत्वपूर्ण **कैंसर-रोधी यौगिक** के लिए **वैकल्पिक स्रोतों** की खोज को प्रेरित किया।

कैम्पटोथेसिन

- इसका उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में किया जाता है, यह पौधा बड़े पैमाने पर केवल चीन और भारत में पाया जाता है।
- कोशिका निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली पौधे की चीनी किस्म को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में यह पौधा पश्चिमी घाट का मूल निवासी है और पिछले दशक में इसकी जनसंख्या में 20% की गिरावट आई है।

अनुसंधान एवं विकास

- वर्ष 2021 में, **आईआईटी मद्रास** के शोधकर्ताओं ने **CPT** के लिए एक **सतत** और **उच्च उपज** वाले वैकल्पिक स्रोत के रूप में एक **सूक्ष्म जीव** की पहचान की है।
- फिर उन्होंने पौधे के **मेटाबॉलिक पाथवे** की समझ को बढ़ाने के लिए **कम्प्यूटेशनल टूल** का उपयोग करके **एन निमोनियाना** पौधे की कोशिकाओं के लिए एक **जीनोम-स्केल मेटाबॉलिक मॉडल** विकसित किया।

सतत उत्पादन दृष्टिकोण

- अध्ययन **CPT** और अन्य **चिकित्सकीय** रूप से महत्वपूर्ण **एल्कलॉइड** के **सतत और कुशल व्यावसायिक उत्पादन** में एक सफलता प्रस्तुत करता है।
- शोधकर्ताओं का **लक्ष्य पौधों** की **कोशिकाओं** की **मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग** करना है
  - लुप्तप्राय पौधों को काटने की आवश्यकता कम करें
  - दवा की बढ़ती बाजार मांग को पूरा करना
- **मेटाबोलिक इंजीनियरिंग** के लिए विकसित किया गया **प्लेटफ़ॉर्म व्यापक अनुप्रयोगों** को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न **उच्च-मूल्य** वाले **फाइटोकेमिकल्स** के उत्पादन को बढ़ा सकता है।

121. भारतीय नौसेना ने मालवाहक जहाज को अपहरण होने से बचाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन - आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
- मार्कोस

समाचार:

- उत्तरी अरब सागर में एक हालिया घटना में, **भारतीय नौसेना मार्कोस** ने **व्यापारिक जहाज लीला नोरफोक** पर अपहरण के प्रयास को सफलतापूर्वक टाल दिया।
- ऑपरेशन के परिणामस्वरूप **15 भारतीयों** सहित सभी **21 चालक दल** के सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया।

अपहरण प्रयास विवरण

- व्यापारिक जहाज **लीला नॉरफ़ॉक** ने **यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल** के माध्यम से अपहरण के प्रयास की सूचना दी, जिसमें कहा गया कि लगभग पांच से छह हथियारबंद व्यक्ति जहाज पर चढ़ गए थे।

भारतीय नौसेना की तीव्र प्रतिक्रिया

- भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जहाज को रोकने के लिए समुद्री डकैती रोधी गश्ती **विध्वंसक INS चेन्नई** को मोड़ दिया।
- **समुद्री गश्ती विमान (MPA)** ने **चालक दल** की **सुरक्षा सुनिश्चित** करते हुए जहाज के साथ संपर्क स्थापित किया।
- **आईएनएस चेन्नई** ने जहाज को रोक लिया और **मरीन कमांडो (मार्कोस)** ने जहाज पर स्वच्छता अभियान चलाया।

व्यापक समुद्री सुरक्षा उपाय

- **भारतीय नौसेना** ने **मध्य** और **उत्तरी अरब सागर** में **समुद्री निगरानी प्रयासों** में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया

- **लाल सागर** और **अरब सागर** में **व्यापारिक जहाजों** पर **हौथी विद्रोहियों** के हमलों के कारण सतर्कता बढ़ा दी गई है।
- भारतीय नौसेना **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** के भीतर बढ़ी निगरानी बनाए रखने के लिए **तटरक्षक बल** के साथ समन्वय कर रही है ।

- **सूचना प्रबंधन** और **विश्लेषण केंद्र (IMAC)** और **हिंद महासागर क्षेत्र** के लिए **सूचना संलयन केंद्र (IFC IOR)** सक्रिय रूप से भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों पर ध्यान देने के साथ व्हाइट शिपिंग की निगरानी कर रहे हैं।

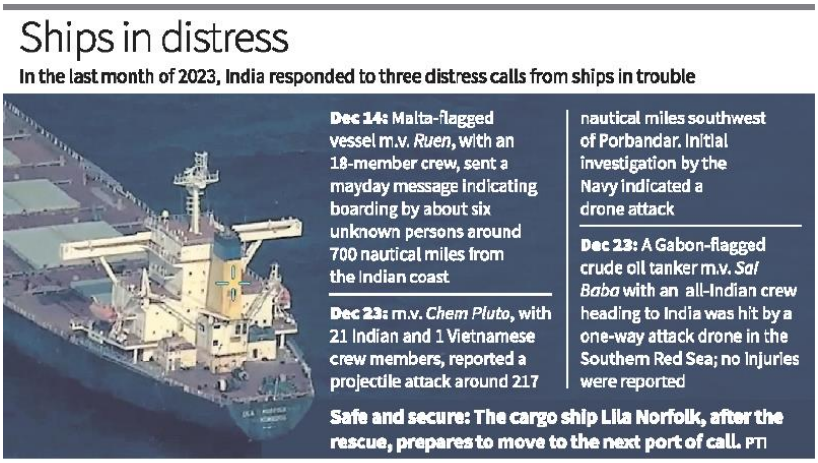

122. ' डीप टेक' नीति को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजी जायेगी - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- CSIR
- डीप टेक

समाचार:
- आने वाले हफ्तों में भारत के लिए नई **'डीप टेक'** नीति पर एक नोट मंजूरी के लिए **केंद्रीय मंत्रिमंडल** को भेजी जायेगी।

मुख्य बिंदु
- जुलाई 2023 में, सरकार ने सार्वजनिक टिप्पणी के लिए नीति के एक मसौदे का अनावरण किया और उद्योग से प्रतिक्रिया के बाद, एक अंतिम संस्करण कथित तौर पर तैयार है।
- **टेक** और **स्टार्टअप जगत** में ' **डीप टेक**' एक प्रचलित शब्द है , जिसकी अभी तक कोई सटीक परिभाषा नहीं है।
- 'डीप टेक' पर भारत के **मसौदा नीति दस्तावेज़** में **स्टार्टअप इंडिया** के डेटाबेस का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि **उद्योग** और **आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** द्वारा मान्यता प्राप्त 10,298 स्टार्टअप हैं।
  - जिन्हें **मई 2023** तक बड़े गहरे **तकनीकी क्षेत्र** के भीतर **विभिन्न उप-क्षेत्रों** में वर्गीकृत किया गया है।
- डीप टेक स्टार्टअप्स ने **बौद्धिक संपदा** विकसित की है जो **व्यापक प्रभाव** का वादा करती है लेकिन अभी तक साकार नहीं हुई है, और **नई वैज्ञानिक सफलताओं** पर आधारित है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन विचारों को आसानी से दोहराया जा सकता है, उन पर आधारित व्यवसाय और **स्टार्टअप डीप टेक स्टार्टअप** के रूप में योग्य नहीं हैं।
- **DSIR** आने वाले दिनों में **मध्यम** और **लघु उद्योगों** में **प्रौद्योगिकी स्थानांतरित** करने पर ध्यान केंद्रित करेगा
- **CSIR** बड़े पैमाने पर उद्योग को लक्षित करेगा और **राष्ट्रीय अनुसंधान** और **विकास निगम**, जो एक **CSIR इकाई** भी है, स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगी।

123. इसरो ने अंतरिक्ष में ईंधन सेल-आधारित बिजली प्रणाली का परीक्षण किया - द हिंदू/इसरो ने ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- ईंधन सेल
- पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (PEM) ईंधन सेल

समाचार:
- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)** ने अंतरिक्ष में **ईंधन सेल** का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके **एक मील** का **पत्थर** हासिल किया है।

परीक्षण

- इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म, **POEM3** पर **100 W** श्रेणी के **पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम (FCPS)** का परीक्षण किया।
- **उद्देश्य:** अंतरिक्ष में पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के संचालन का आकलन करना और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम डिजाइन करने के लिए डेटा इकट्ठा करना।
- **PSLV** के **चौथे चरण** पर तैनात **ईंधन सेल ने** एक **संक्षिप्त परीक्षण** के दौरान **180W बिजली** उत्पन्न की।
- **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC)** द्वारा विकसित ईंधन सेल, अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए भविष्य की बिजली प्रणालियों के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है।

पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (PEM) ईंधन सेल

- इन्हें **प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल** के रूप में भी जाना जाता है, ये **विद्युत रासायनिक** उपकरण हैं जो **रासायनिक ऊर्जा** को **विद्युत ऊर्जा** में परिवर्तित करते हैं।
- वे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक **प्रोटॉन-संवाहक पॉलिमर मेम्ब्रेन** का उपयोग करते हैं और आमतौर पर ईंधन के रूप में **हाइड्रोजन** का उपयोग करते हैं।

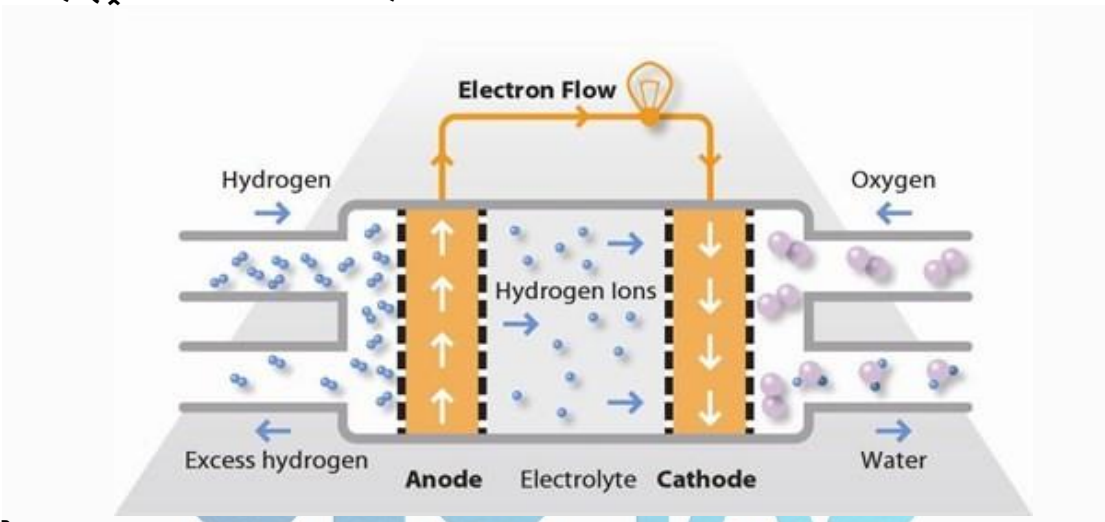

ईंधन सेल का महत्व

- **ईंधन सेल बिजली** उत्पन्न करने के लिए **हाइड्रोजन** और **ऑक्सीजन** का उपयोग करते हैं जबकि **उपोत्पाद** के रूप में **गर्मी और पानी** का उत्पादन करते हैं।
- बिजली पैदा करने और गर्मी और पानी जैसे आवश्यक **उपोत्पादों** के **दोहरे लाभों** के कारण इन्हें मानव **अंतरिक्ष मिशनों** के लिए आदर्श माना जाता है।
- यह **एकीकृत प्रणाली** एक साथ कई मिशन आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
- वे सीधे बिजली का उत्पादन करते हैं और **कुशल, उत्सर्जन-मुक्त** और **अंतरिक्ष अभियानों** के लिए आदर्श हैं।
- **शून्य-उत्सर्जन ईंधन सेल** का पृथ्वी पर **वाहन इंजनों** के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

सिलिकॉन आधारित सेल

- इसरो ने **VSSC** द्वारा विकसित **सिलिकॉन-आधारित सेल** का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जो वर्तमान सेल के लिए एक लागत **प्रभावी** और **हल्का** विकल्प पेश करता है।
- यह नवाचार एक **सिलिकॉन-ग्रेफाइट सम्मिश्र** का उपयोग करता है, जो पारंपरिक **ली-आयन सेल** की तुलना में **प्रति यूनिट वजन** में **उच्च ऊर्जा** उत्पादन प्रदान करता है ।

परिचालन मिशन और बड़े पैमाने पर बचत

- प्रदर्शित **ईंधन सेल** का उपयोग आगामी **परिचालन मिशनों** में किए जाने की उम्मीद है, जिससे **35-40%** की महत्वपूर्ण बैटरी बचत होगी।

- डिज़ाइन में लागत प्रभावी **हार्डवेयर** और **एक क्रिम्प्ड सीलिंग तंत्र** शामिल है, जो निर्माण लागत को कम करता है।

124. जीएसटी राजस्व राज्यों में उपभोग वृद्धि में असंगति को दर्शाता है - द हिंदू

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
- जीएसटी परिषद

समाचार:

Uneven growth

Eight States, including Maharashtra and Tamil Nadu, saw more than 15% growth in GST collections so far this year. While Gujarat and West Bengal are among the top 10 contributors with slower growth

Major States with higher growth		Major States with lower growth	
Madhya Pradesh	18.80%	Gujarat	9.50%
Maharashtra	18.20%	West Bengal	9.80%
Karnataka	18.10%	Odisha	10.70%
Haryana	17.60%	Rajasthan	10.90%
Uttar Pradesh	17.30%	Bihar	11.50%
Tamil Nadu, Telangana	16.90%	Andhra Pradesh	12.50%

Source: Ministry of Finance, Bank of Baroda research

125. आदित्य-L1 सफलतापूर्वक L1 कक्षा में स्थापित हो गया -द हिंदू/आदित्य-L1, अपनी अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आदित्य L1 मिशन
- लैग्रेंज पॉइंट

समाचार:
- इसरो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि हाल ही में **आदित्य-L1 अंतरिक्ष यान** अपने गंतव्य, **लैग्रेंजियन बिंदु L1** पर पहुंच गया है।
- यह **सौर मिशन** सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित **भारत की पहली वेधशाला** है।

आदित्य-L1 मिशन
- **इसरो** द्वारा **L1 कक्षा** में लॉन्च किया गया जो **पृथ्वी** से लगभग **1.5 मिलियन किमी** दूर है।
- **उद्देश्य**
  - सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का अध्ययन करना।
  - सौर गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए, बिना किसी छिपाव के सूर्य की चौबीसों घंटे इमेजिंग करना।
- **मिशन जीवनकाल:** 5 वर्ष

लॉन्च वाहन और पेलोड
- **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) का** उपयोग करके लॉन्च किया गया
  - PSLV ने चंद्रयान-1 (2008) और मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान (2013) भी लॉन्च किया।
- बोर्ड पर **सात पेलोड** अर्थात।
  - दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC)
  - सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)
  - सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS)
  - आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX)

- उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS)
- आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA)
- उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर

- L1 चार पेलोड को सीधे सूर्य को देखने की अनुमति देता है, जबकि **तीन पेलोड** L1 बिंदु पर **कणों** और **क्षेत्रों** का **इन-सीटू अध्ययन** करते हैं।

भविष्य की संभावनाओं

- आदित्य-L1 के अवलोकन **कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम** की **गतिशीलता** और **कण** और **क्षेत्र प्रसार** पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
- उम्मीद है कि उपग्रह अपना पूरा मिशन जीवन L1 के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बिताएगा, जिससे सौर घटनाओं की गहरी समझ में योगदान मिलेगा।

लैग्रेंज पॉइंट

- **लैग्रेंज पॉइंट** अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां एक **छोटी वस्तु दो-पिंड गुरुत्वाकर्षण** प्रणाली में रहती है।
- अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग **अंतरिक्ष यान** द्वारा **कम ईंधन खपत** के साथ इन स्थानों पर बने रहने के लिए किया जा सकता है।
- दो-निकाय गुरुत्वाकर्षण प्रणालियों के लिए, कुल **पांच लैग्रेंज बिंदु** हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया गया है।

L1 प्वाइंट

- **L1** बिंदु **पृथ्वी** से लगभग **1.5 मिलियन किमी** दूर **सूर्य-पृथ्वी रेखा** के **बीच** स्थित है।
- पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी-सूर्य की दूरी का लगभग 1% है।
- यह बिना किसी ग्रहण या ग्रहण के **निरंतर सौर अवलोकन** के लिए एक अनूठा लाभ प्रदान करता है।
- वर्तमान में, **चार परिचालन अंतरिक्ष यान** L1पर तैनात हैं, जो **सौर** और **हेलिओस्फेरिक** अध्ययन में योगदान दे रहे हैं।
- इनमें पवन, **सौर** और **हेलिओस्फेरिक वेधशाला (SOHO), उन्नत संरचना एक्सप्लोरर (ACE)** और **डीप स्पेस क्लाइमेट वेधशाला (DSCOVER**) शामिल हैं।

126. भारत में वेक्टर-जनित रोगों के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी करना जरुरी - हिन्दू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे

- मलेरिया
- डेंगी
- अपशिष्ट जल निगरानी

Identifying priority pathogens

Wastewater surveillance has been routinely used for decades for tracking polio virus

Independent: Wastewater surveillance does not rely on access to healthcare and people getting tested. MANOJ KUMAR

- During the pandemic, countries relied on wastewater surveillance to track new SARS-CoV-2 variants and to know the extent of virus spread in the community
- Many countries have used wastewater surveillance to track other diseases such as monkeypox, influenza and cholera
- U.S. researchers have suggested that wastewater surveillance be expanded to track dengue, malaria, Zika and typhoid
- Unlike in India, malaria and dengue outbreaks are rare in the U.S, and European countries. Developed countries also have excellent sewage network, which makes it easy to track these pathogens
- Besides humans shedding the pathogens through stools, several mammals, including nonhuman primates, serve as reservoir hosts of malaria and dengue
- For vector-borne diseases, wastewater surveillance is not an ideal solution in India

127. ज़ांज़ीबार में समुद्री शैवाल की खेती - डाउन टू अर्थ

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्पंज
- ग्लोबल वार्मिंग

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- जैसे-जैसे महासागर गर्म हो रहे हैं, ज़ांज़ीबार में महिलाएं जीवित रहने के लिए **समुद्री शैवाल** से **जलवायु-लचीला स्पंज खेती** की ओर रुख कर रही हैं

स्पंज

- समुद्री शैवाल के विपरीत, स्पंज में **जलवायु परिवर्तन** के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन होता है
- **डोडोमा विश्वविद्यालय, तंजानिया** के **समुद्री जीवविज्ञानी अज़ीज़ा सैद** के अनुसार, उन्हें न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है, और प्रीमियम बाजार मूल्य की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, स्पंज की खेती के लिए कम **वित्तीय संसाधनों** और **तकनीकी विशेषज्ञता** की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये **जीव प्राकृतिक** रूप से बढ़ते और फैलते हैं।
- अधिकांश **स्पंज उभयलिंगी** होते हैं, जिनमें **नर** और **मादा** दोनों **प्रजनन अंग** होते हैं, जो उन्हें सहजता से स्व-प्रजनन में सक्षम बनाते हैं।
- नए **स्पंज छोटी कलियों** से निकलते हैं जो **मूल स्पंज** से अलग हो जाते हैं और **स्वतंत्र विकास** शुरू करते हैं।
- यहां तक कि **क्षतिग्रस्त** या **खंडित स्पंज** भी नए रूप में **पुनर्जीवित** हो सकते हैं।
- यह उल्लेखनीय **पुनर्योजी क्षमता व्यावसायिक स्पंज खेती** की आसानी और व्यवहार्यता को रेखांकित करती है।
- **सिंथेटिक स्पंज** के विपरीत, **समुद्री स्पंज रसायनों** और **माइक्रोप्लास्टिक** जैसे हानिकारक पदार्थों से मुक्त होते हैं

उपयोग

- इन स्पंजों का उपयोग **स्नान** और **सामान्य स्वच्छता** के लिए किया जाता है
- उनके **कंकाल सिलिकॉन** के सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो **समुद्र** में **कार्बन चक्र** को नियंत्रित करने में मदद करता है और **ग्रीनहाउस प्रभाव** को कम करता है।
- घुला हुआ **सिलिकॉन डायटम,** छोटे जीवों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है जो **प्रकाश संश्लेषण** का उपयोग करके समुद्र में बड़ी मात्रा में **CO_2** को अवशोषित करते हैं।

128. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KRS जलाशय के पास खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

समाचार:
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय** ने **मांड्या जिले** में ऐतिहासिक **कृष्णराजसागर (KRS)** बांध के **20 किलोमीटर** के दायरे में सभी प्रकार की **खनन** और **उत्खनन गतिविधियों** पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु
- यह प्रतिबंध **20 किमी** के दायरे में उन **खनन गतिविधियों** पर भी लागू होगा जिनके लिए अधिकारियों द्वारा पहले ही **अनुमति/लाइसेंस** दिए गए हैं।
  - उच्च न्यायालय ने कहा, या पहले से ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या मुकदमेबाजी के पहले दौर में अदालत के आदेश पर अनुमति दी गई थी।
- अदालत ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन पूरा होने और **बांध सुरक्षा** पर **राज्य समिति** द्वारा निर्णय लेने तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
  - **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021** के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021
- यह अधिनियम देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की **निगरानी, निरीक्षण, संचालन** और **रखरखाव का प्रावधान** करता है।
- ये कुछ डिज़ाइन और संरचनात्मक शर्तों के साथ **15 मीटर** से अधिक **ऊंचाई** या **10 मीटर -15 मीटर** के बीच ऊंचाई वाले बांध हैं।
- **संस्थागत तंत्र**
  - बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (NCDS)
  - राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)
  - राज्य बांध सुरक्षा संगठन
  - बांध सुरक्षा पर राज्य समिति

129. आय असमानता में गिरावट: भारतीय स्टेट बैंक - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे
- K-आकार की पुनर्प्राप्ति
- गिन्नी गुणांक

समाचार:
- भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में भारत में **आय असमानता में गिरावट** की सूचना दी है।
- यह इस गिरावट का कारण **उच्च टैक्स आधार** और **करदाताओं** के निम्न से **उच्च आयकर ब्रैकेट** में बदलाव को बताता है।

उच्च आय वर्ग में स्थानांतरण
- **36.3% करदाता निम्न** से **उच्च आयकर ब्रैकेट** में चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त **आय** में **21.3% की वृद्धि** हुई है।
- निर्धारण **वर्ष 2013-14** और निर्धारण **वर्ष 2021-22** के बीच **5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये** के **बीच आय** वाले व्यक्तियों द्वारा दाखिल **आयकर रिटर्न** में **295%** की वृद्धि हुई।

शीर्ष करदाताओं का योगदान
- **शीर्ष 2.5%** करदाताओं की आय में योगदान **वित्त वर्ष 2014** में **2.81% से** घटकर **वित्त वर्ष 2011** में 2.28% हो गया।

- 100 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले शीर्ष आय वालों की **संयुक्त आय** का हिस्सा वित्त **वर्ष 2014** में **1.64%** से घटकर **वित्त वर्ष 2011** में 0.77% हो गया।

छोटी फर्मों और उपभोग में रुझान

- 19.5% **छोटी कंपनियाँ MSME मूल्य श्रृंखला एकीकरण** के माध्यम से **बड़ी कंपनियों** में परिवर्तित हो गईं।
- महामारी के बाद निचली **90% आबादी** की खपत में **8.2 लाख करोड़ रुपये** की वृद्धि हुई।

K-आकार की पुनर्प्राप्ति

- रिपोर्ट **K-आकार** की पुनर्प्राप्ति के दावों को **"त्रुटिपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण** और **गलत-मनगढ़ंत"** कहकर खारिज करती है।
  - **K-आकार** की रिकवरी की अवधारणा **कोविड 19 महामारी** के दौरान सामने आई।
  - यह एक भिन्न **आर्थिक परिदृश्य** का प्रतीक है जहां **अर्थव्यवस्था** के कुछ क्षेत्र फल-फूल रहे होंगे जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट जारी रहेगी या उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
- सभी **आय वर्गों** में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन मध्य की ओर **आय के अभिसरण** के साथ इसकी विषमता कम हो रही है, जो एक **सकारात्मक आर्थिक प्रवृत्ति** का संकेत है।

अन्य प्रमुख निष्कर्ष

- **वित्त वर्ष 2014-22** के दौरान कर योग्य आय का **गिनी गुणांक 0.472** से घटकर **0.402** हो गया।
- दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट का कारण ग्रामीण संकट नहीं, बल्कि चौपहिया वाहनों की ओर बदलाव है।
- व्यक्तिगत कर दाखिल करने वालों में **महिला टैक्स दाखिलकर्ताओं** की संख्या लगभग **15%** है।
- ज़ोमैटो जैसे प्लेटफ़ॉर्म से उपभोग डेटा संकट के दावों का खंडन करते हुए बढ़ते अनुभव-केंद्रित आय समूहों का सुझाव देता है।

130. वेब ब्लॉकिंग आदेशों में उल्लेखनीय वृद्धि - द हिंदू

प्रासंगिकता: रिपोर्ट और सूचकांक

समाचार:

- **सूचना के अधिकार (RTI)** के हालिया जवाब से पता चलता है कि **वेबसाइट ब्लॉक** करने के **आदेशों** में **उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A
- इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP)

डेटा हाइलाइट्स

- **वेबसाइट ब्लॉक** करने के **ऑर्डर 100 गुना** से अधिक बढ़ गए हैं, जो **वर्ष 2013** में **62** से बढ़कर **अक्टूबर 2023** तक **6,954** हो गए हैं।
- ये आँकड़े **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की **धारा 69A** के तहत जारी आदेशों से संबंधित हैं।
- **दूरसंचार विभाग (DoT)** ने हाल ही में **इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs)** को त्वरित **ब्लॉकिंग** के लिए **भारत** में **सर्वर** के **आईपी पते** संकलित करने का निर्देश दिया था।

इंटरनेट का उपयोग और ब्लॉकिंग ऑर्डर

- **ब्लॉकिंग ऑर्डर** में वृद्धि **इंटरनेट** उपयोग में भारी वृद्धि के साथ मेल खाती है, खासकर **मोबाइल डेटा** की **कीमतों** में **गिरावट** के बाद।
- डेटा विशिष्ट पेजों, **प्रोफाइलों** और **वीडियो** के लिए **सोशल मीडिया** और **सामग्री फर्मों** को भेजे गए **ब्लॉकिंग ऑर्डर** को दर्शाता है।
- हालाँकि, **आईटी मंत्रालय** ने नियमों में गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए इन आंकड़ों का विवरण देने से इनकार कर दिया।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A

- यह **केंद्र सरकार** को भारत की **संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों** या **सार्वजनिक व्यवस्था** के हित में या किसी **संज्ञेय अपराध** के लिए उकसावे को रोकने के लिए **ऑनलाइन सामग्री** को ब्लॉक करने की अनुमति देता है।
- **DoT** का हालिया आदेश तत्काल कार्रवाई के लिए **वेब/एप्लिकेशन सर्वर** के स्थान का पता लगाने पर जोर देता है।
- हालाँकि, उद्योग विशेषज्ञों ने **DoT** के निर्देश की **व्यावहारिकता** और **कार्यान्वयन चुनौतियों** के बारे में चिंता व्यक्त की है।
    - **वेब/एप्लिकेशन सर्वर** के स्थान का पता लगाने में कठिनाई, विशेष रूप से **एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों** और अनुरोध के पैमाने के साथ।

आईपी एड्रेस लिस्टिंग चुनौतियाँ

- कॉर्पोरेट सुरक्षा चिंताओं के कारण लिस्टिंग **आईपी एड्रेस** को **डेटा सेंटर प्रदाताओं** और **वेब होस्टिंग फर्मों** से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- विशेषज्ञ अधिक प्रभावी वेबसाइट अवरोधन के लिए **सामग्री वितरण नेटवर्क (CDNs)** के साथ सहयोग का सुझाव देते हैं।

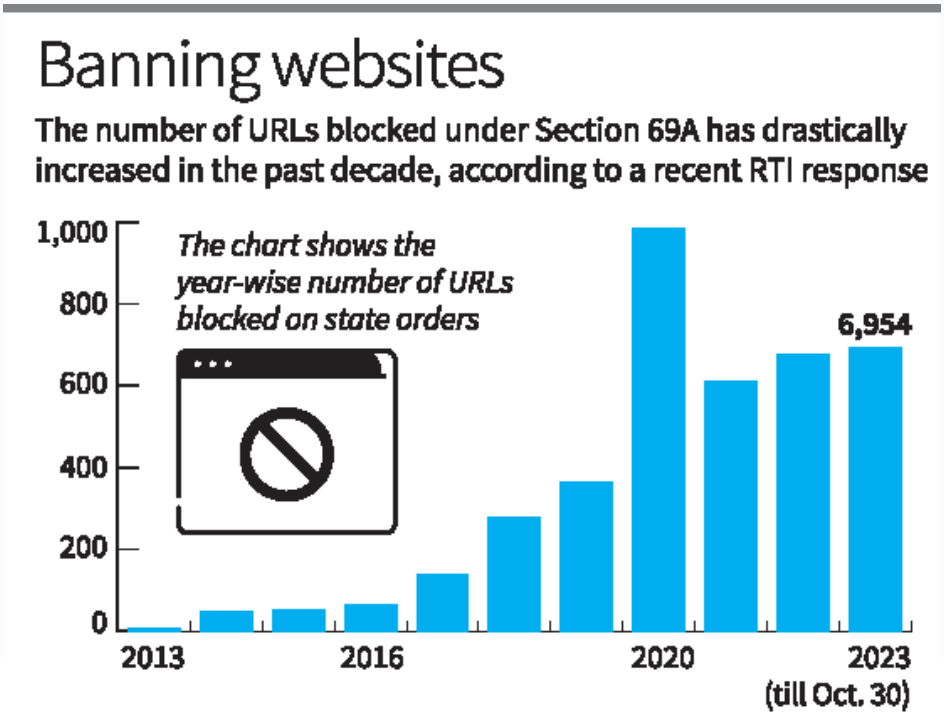

131. सरकार ने व्यापारिक रूकावटें के समाधान हेतु टास्क फोर्स का गठन किया - इंडियन एक्सप्रेस / वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया - द इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गैर टैरिफ बाधाएं
- वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल

समाचार:

- **वाणिज्य मंत्रालय** ने अन्य देशों में **निर्यातकों** के सामने आने वाली **व्यापार बाधाओं** की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए एक **टास्क फोर्स** का गठन किया है
    - एक अधिकारी ने कहा, एक ऐसा कदम जो घरेलू सामानों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

- कई बार **भारत** का **निर्यात** इन बाधाओं से ग्रस्त होता है जैसे कि **पूर्व पंजीकरण** आवश्यकताओं में समय लगता है और कई देशों में **अनुचित घरेलू मानक/नियम** होते हैं।
- मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ **पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRAs)** में सुधार पर भी विचार कर रहा है ताकि **उत्पाद मानक आयातक देशों** की आवश्यकताओं के अनुसार हों।
- अधिकारी ने कहा, **वस्तुओं** और **सेवाओं** के मानकों को **वैश्विक व्यापार** को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए न कि **गैर-टैरिफ बाधाओं** के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को **गैर-व्यापार बाधाओं (NTBs)** को हटाने के लिए **फास्ट-ट्रैक** तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।
  - **वर्ष 2030** तक माल के लिए एक **ट्रिलियन डॉलर** के **आउटबाउंड शिपमेंट** लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका, **चीन** और **जापान** जैसे विभिन्न देशों में **घरेलू निर्यातकों** को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसने उन मामलों में **घरेलू प्रणालियों** को उन्नत करने के लिए कहा है जहां **गुणवत्ता के मुद्दों** के कारण **भारतीय उत्पादों** को अस्वीकार कर दिया जाता है
  - और यदि **अनुचित मानक** या **नियम नई दिल्ली** से **निर्यात** में बाधा डालना जारी रखते हैं तो जवाबी कार्रवाई करना।
- प्रमुख **भारतीय निर्यात** जो **नियमित रूप** से **उच्च बाधाओं** का सामना करते हैं उनमें मिर्च, चाय, बासमती चावल, दूध, मुर्गी पालन, गोजातीय मांस, मछली, यूरोपीय संघ के रसायन उत्पाद शामिल हैं।
  - जापान में तिल के बीज, ब्लैक टाइगर झींगा, औषधियाँ, परिधान; चीन को भोजन, मांस, मछली, डेयरी, औद्योगिक उत्पाद
- रिपोर्ट के अनुसार, अन्य उत्पाद जो इन बाधाओं का सामना करते हैं उनमें **मिस्र** में सिरेमिक टाइलें, मेक्सिको में मिर्च, अर्जेंटीना में दवाएं, सऊदी अरब में सूक्ष्मजीवविज्ञानी अभिकर्मक शामिल हैं।
- अधिकांश **गैर-टैरिफ उपाय (NTMs)** मानव, पशु या **पौधों के स्वास्थ्य** और **पर्यावरण की रक्षा** के उद्देश्य से देशों द्वारा बनाए गए घरेलू नियम हैं।
- NTM विनियम, मानक, परीक्षण, प्रमाणन, प्री-शिपमेंट निरीक्षण या कोटा, आयात लाइसेंसिंग, सब्सिडी, सरकारी खरीद प्रतिबंध जैसे गैर-तकनीकी उपाय जैसे तकनीकी उपाय हो सकते हैं।
- जब **NTM** वैज्ञानिक औचित्य से परे मनमाना हो जाते हैं, तो वे व्यापार के लिए बाधाएं पैदा करते हैं और उन्हें **NTB (गैर-टैरिफ बाधाएं)** कहा जाता है।

132. चंद्रमा की 'स्टिकीनेस की खाड़ी' का पता लगाने हेतु नासा ने पेरेग्रीन लैंडर लॉन्च किया - इंडिया टुडे

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- प्रॉस्पेक्ट आयन-ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर (PITMS)
- पेरेग्रीन मिशन

समाचार:
- **पेरेग्रीन लूनर लैंडर** को **चंद्रमा** का पता लगाने के लिए अपनी अग्रणी यात्रा शुरू करने के लिए **यूनाइटेड लॉन्च अलायंस** के वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।

पेरेग्रीन लैंडर
- इसे **वैज्ञानिक उपकरणों** और अन्य पेलोड को **चंद्रमा** की सतह पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से **साइनस विस्कोसिटैटिस क्षेत्र** को लक्षित करते हुए।

- यह क्षेत्र, जिसे **स्टिकीनेस की खाड़ी** के रूप में भी जाना जाता है, **ओशनस प्रोसेलरम**, या **तूफान** के **महासागर** के पास **ग्रूथीसेन डोम्स** के निकट स्थित है।
- इसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाना, **लैंडर के चारों** ओर **विकिरण** और **गैसों** को **मापना** और **चंद्र बाह्यमंडल** (चंद्रमा की सतह पर गैसों की पतली परत) का मूल्यांकन करना है।

उद्देश्य:

- चंद्र बाह्यमंडल का विश्लेषण करने के लिए, **चंद्र रेजोलिथ** के **थर्मल गुणों** और **हाइड्रोजन सामग्री** का आकलन करें**, चुंबकीय क्षेत्र** का अध्ययन करें, **विकिरण पर्यावरण** की जांच करें और **उन्नत सौर सरणियों** का परीक्षण करें।
- पेरेग्रीन मिशन **1 लगभग दस पेलोड** का परिवहन करेगा, जिनकी कुल द्रव्यमान क्षमता 90 किलोग्राम है।
- वैज्ञानिक **पेलोड में** अत्याधुनिक उपकरण जैसे
  - लेज़र रेट्रो-रिफ्लेक्टर ऐरे (LRA)
  - रैखिक ऊर्जा स्थानांतरण स्पेक्ट्रोमीटर (LETS)
  - नियर-इन्फ्रारेड वोलेटाइल स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम (NIRVSS)
  - प्रॉस्पेक्ट आयन-ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर (PITMS)
  - न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटरपेरेग्रीन लैंडर सिस्टम (NSS)

133. अधिकांश भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार की जरूरत - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
- वायु प्रदूषण

- भारत में **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (NCAP) का लक्ष्य **कणीय पदार्थ** की **सांद्रता** को कम करने पर ध्यान देने के साथ **वायु गुणवत्ता** में सुधार करना है।
- हालाँकि, **रेस्पिरर लिविंग साइंसेज** और **क्लाइमेट ट्रेंड्स** के एक विश्लेषण से विभिन्न शहरों में अलग-अलग सफलता दर का पता चलता है।

मुख्य बिंदु

वास्तविक लक्ष्य और समायोजन

- **NCAP** ने मूल रूप से **वर्ष 2024** तक प्रदूषण में **20-40%** की कमी लाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में **समय सीमा वर्ष 2026** तक बढ़ा दी गई।
- अंतिम लक्ष्य **वर्ष 2017** के स्तर की तुलना में **131 शहरों** में **पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता** में **40% की कमी** करना है।

शहरवार प्रगति

- **पाँच वर्षों** से लगातार **पार्टिकुलेट मैटर डेटा** वाले **49 शहरों** में से केवल **4** ही लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए या उससे अधिक हो गए।
- दिल्ली के **PM 2.5** के स्तर में **5.9%** की कमी आई, जबकि **नवी मुंबई, मुंबई, उज्जैन, जयपुर** और **विशाखापत्तनम** में अलग-अलग स्तर की **वृद्धि** देखी गई।

सकारात्मक आउटलेर्स

- **वाराणसी, आगरा** और **जोधपुर** जैसे शहरों ने **PM 2.5** के स्तर में **50-72%** की कमी हासिल करते हुए उल्लेखनीय प्रगति दिखाई।
- विशेष रूप से, **वर्ष 2026** के लक्ष्य को पूरा करने वाले सभी शहर **उत्तर प्रदेश** से हैं।

निगरानी स्टेशनों का प्रभाव

- **निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटर** की उपलब्धता और **प्रसार वार्षिक प्रदूषक सांद्रता** को प्रभावित करता है।
- **मुंबई** और **दिल्ली** जैसे शहर, जहां कई निगरानी स्टेशन हैं**, पांच से कम स्टेशनों वाले शहरों** की तुलना में **प्रदूषण के स्तर** का **आकलन** करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

भौगोलिक कारक

- **प्रदूषण के स्तर** में **भिन्नता** का कारण **भौगोलिक स्थान, विविध उत्सर्जन स्रोत** और **मौसम संबंधी** प्रभाव हैं।
- **उत्सर्जन** बनाम **मौसम विज्ञान** के **योगदान** के लिए और **अधिक अध्ययन** की आवश्यकता है।

चिंताएँ और सुझाव

- हालाँकि NCAP ने प्रगति की है, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, कुछ शहरों में प्रदूषण में वृद्धि का अनुभव हो रहा है।
- निगरानी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और **वर्ष 2026** तक संशोधित **40% कटौती लक्ष्य** प्राप्त करना **पर्यावरणीय लक्ष्यों** के **प्रति प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

Lagging behind

The table shows PM 2.5 levels (annual average) in India's most polluted cities from 2019 to 2023. It remained higher than the acceptable level of 40 micrograms per cubic metre in all the years

AP

Rank in 2023	City	2019	2020	2021	2022	2023
1	Delhi	108.4	95.3	107.6	99.5	102
2	Patna	119.6	72.8	76.5	91.3	89.5
3	Faridabad	94.5	87.6	95.6	95.3	87.9
4	Muzaffarpur	108.1	67.4	122.6	85.7	83.6
5	Noida	113.8	97.9	100.8	79.3	83.6

134. 'Ai संचालित गलत सूचना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा' - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- ChatGPT

समाचार:

- विश्व आर्थिक मंच की **नवीनतम वैश्विक जोखिम** रिपोर्ट अत्याधुनिक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** द्वारा संचालित झूठी और **भ्रामक जानकारी** से उत्पन्न तत्काल खतरे पर प्रकाश डालती है।
- रिपोर्ट में गलत **सूचना**, **पर्यावरणीय चुनौतियों** और **वैश्विक समाज** पर **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** के प्रभाव से जुड़े जोखिमों की रूपरेखा दी गई है।

मुख्य बिंदु

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित ग़लत सूचना सबसे आगे

- रिपोर्ट उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रसारित **झूठी** और **भ्रामक** जानकारी को **वैश्विक अर्थव्यवस्था** के लिए सबसे **गंभीर अल्पकालिक जोखिम** के रूप में पहचानती है।
- तीव्र तकनीकी प्रगति **मौजूदा समस्याओं** को बढ़ा रही है और नई चुनौतियाँ पैदा कर रही है।

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चिंताएं बढ़ाते हैं

- जेनेरिक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स** का उदय, जिसका उदाहरण **ChatGPT** जैसी प्रौद्योगिकियों द्वारा दिया गया है, को परिष्कृत **सिंथेटिक सामग्री** बनाने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में जाना जाता है।
- चिंताएँ पैदा होती हैं क्योंकि यह **तकनीक अधिक सुलभ** हो जाती है, जिससे **विशेष कौशल** वाले लोगों से परे बड़े समूहों में हेरफेर की अनुमति मिलती है।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित गलत **सूचना विभिन्न देशों** में आगामी चुनावों के साथ मेल खाती है, जिससे **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं** पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- डीपफेक के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** का लाभ उठाने में आसानी से **सामाजिक ध्रुवीकरण** हो सकता है और तथ्यों को सत्यापित करने में चुनौतियाँ आ सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक खतरे:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसे **उपकरण** के रूप में पहचाना जाता है जो **दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं** को सशक्त बना सकता है, जिससे साइबर हमले अधिक **सुलभ, स्वचालि**त और **सशक्त** बन सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता के रूप में

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित** गलत सूचना के बाद, **चरम मौसम** को दूसरे सबसे अधिक दबाव वाले अ**ल्पकालिक जोखिम** के रूप में पहचाना जाता है।
- दीर्घावधि में, **जलवायु परिवर्तन** से संबंधित जोखिम, जिनमें **पृथ्वी प्रणालियों** में महत्वपूर्ण परिवर्तन, **जैव विविधता** की हानि, **पारिस्थितिकी तंत्र** का **पतन** और **प्राकृतिक संसाधनों** की कमी शामिल हैं, को प्राथमिकता दी जाती है।

135. ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट & सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी - द हिंदू

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे

- ILO
- वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट & सोशल आउटलुक ट्रेंड्स

समाचार:

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने **वियना** में अपनी **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट & सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024** रिपोर्ट जारी की
- यह **वर्ष 2024** में **वैश्विक बेरोजगारी** दर में **प्रत्याशित वृद्धि** पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

1. वर्ष 2023 में व्यापक आर्थिक गिरावट

- **बेरोजगारी के महामारी-पूर्व स्तर** से नीचे आने के बावजूद, रिपोर्ट जारी **सामाजिक असमानताओं** और **स्थिर उत्पादकता** के बारे में चिंता जताती है।
- रिपोर्ट में **वर्ष 2023** में **व्यापक आर्थिक माहौल** में महत्वपूर्ण गिरावट का उल्लेख किया गया है।
- **भूराजनीतिक तनाव** और **मुद्रास्फीति** के कारण **केंद्रीय बैंकों** ने आक्रामक कदम उठाए, जिससे **वैश्विक औद्योगिक** गतिविधि, निवेश और व्यापार प्रभावित हुआ।

2. वैश्विक विकास और श्रम बाज़ार का लचीलापन

- **आर्थिक चुनौतियों** के बावजूद, **वर्ष 2023** में **वैश्विक वृद्धि** उम्मीदों से अधिक रही, **श्रम बाजारों** में **लचीलापन** दिखा।
- मजबूत **नौकरी वृद्धि** के कारण **बेरोजगारी दर** और **नौकरियों** के **अंतर दोनों** में सुधार हुआ, हालांकि बाद में यह लगभग **435 मिलियन** पर ऊंचा रहा।

3. संरचनात्मक श्रम बाज़ार असंतुलन के बारे में चिंताएँ

- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि **श्रम बाजार** का **असंतुलन चक्रीय** के बजाय संरचनात्मक हो सकता है, भले ही **वर्ष 2023** में असंतुलन कम हो गया हो।

4. **वास्तविक वेतन में गिरावट और अत्यधिक गरीबी में वृद्धि**

- **मुद्रास्फीति** के मुकाबले वेतन वृद्धि के कारण **अधिकांश G20 देशों** में **वास्तविक मजदूरी** में गिरावट आई है।
- **अत्यधिक गरीबी** में रहने वाले **श्रमिकों** (PPP के संदर्भ में प्रति दिन 2.15 डॉलर से कम कमाई) में **वर्ष 2023** में **वैश्विक स्तर** पर **लगभग दस लाख** की वृद्धि हुई।

5. **भारत और अन्य देशों में सकारात्मक वास्तविक वेतन**

- **अन्य G20 देशों** की तुलना में **भारत** में **वास्तविक मजदूरी** "**सकारात्मक**" बताई गई है, चीन, रूस और मैक्सिको में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
- **उच्च श्रम उत्पादकता वृद्धि** के कारण **चीन** और **रूस** ने सबसे मजबूत वेतन लाभ का अनुभव किया।

136. प्रत्यक्ष कर संग्रह 2023-24 के आंकड़े जारी - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारतीय टैक्स प्रणाली
- इनकम टैक्स
- बजट

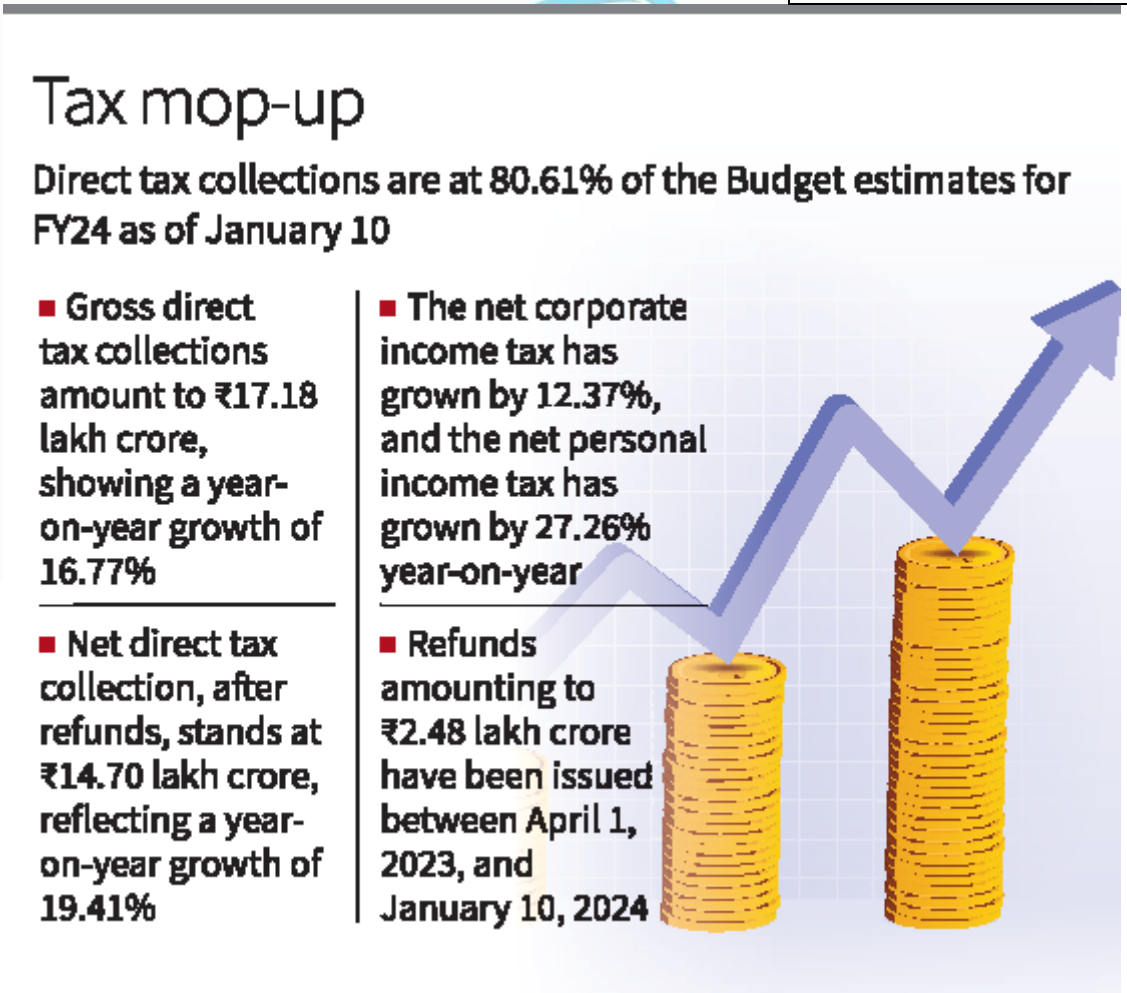

137. ग्रुप इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के लिए विधायी परिवर्तन की आवश्यकता : आरबीआई गवर्नर - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

समाचार:
- आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में **इन्सॉल्वेंसी** और **बैंकरप्सी संहिता (IBC)** के कामकाज को बढ़ाने के लिए समूह दिवाला के लिए एक निर्दिष्ट ढांचे की स्थापना और **स्ट्रेस्ड एसेट्स** के लिए एक जीवंत बाजार के विकास का आह्वान किया।
- **IBC, 2016** भारत का **बैंकरप्सी कानून** है जो **इन्सॉल्वेंसी** और **बैंकरप्सी** से **संबंधित मौजूदा** कानूनों को **समेकित** और **संशोधित** करता है।

ग्रुप इन्सॉल्वेंसी मैकेनिज्म
- एक निर्दिष्ट ढांचे के अभाव के कारण **ग्रुप इन्सॉल्वेंसी मैकेनिज्म** अदालत के मार्गदर्शन में विकसित हो रहा है।
- **उचित सिद्धांतों** को निर्धारित करने के लिए **विधायी परिवर्तनों** की आवश्यकता है।
- **समूह दिवाला प्रक्रिया** में चुनौतियों में परिसंपत्तियों का मिश्रण, **ग्रुप** को **परिभाषित** करना और **सीमा** पार पहलुओं को संबोधित करना शामिल है।

स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए वाइब्रेंट मार्केट
- **स्ट्रेस्ड एसेट्स** के लिए एक **वाइब्रेंट मार्केट** की अनुपस्थिति **IBC** के तहत संभावित समाधान आवेदकों के पूल को सीमित करती है।
- ऋणों के लिए एक मजबूत **द्वितीयक बाज़ार ऋण** देने वाली संस्थाओं द्वारा **ऋण जोखिम** के **प्रबंधन** के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है।

पुनर्प्राप्ति और व्यवहारिक परिवर्तन
- **सितंबर 2023** तक लेनदारों को **9.92 लाख करोड़ रुपये** के स्वीकृत दावों में से **32%** की वसूली दर के साथ **3.16 लाख करोड़ रुपये** की वसूली हुई है।
- **आरबीआई गवर्नर** ने इस बात पर जोर दिया कि **आईबीसी** का सबसे दिलचस्प **परिणाम कोड** द्वारा लाया गया पर्याप्त व्यवहारिक बदलाव है।
  - यह अगस्त 2023 तक **कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस (CIRP)** शुरू करने के लिए **26,518 आवेदनों** को वापस लेने से स्पष्ट है।

IBC की आलोचना
- स्वीकृत दावों की तुलना में **समाधान में लगने वाला समय** और **कटौती की सीमा ।**
- **समाधान प्रक्रियाओं में विलंब**
  - **सितंबर 2023** तक चल रहे **CIRP मामलों** में से **67% 270 दिनों** की कुल **समयसीमा** से अधिक हैं।
- ऋणदाताओं की **समितियों के आचरण पर चिंताएं, परिसंपत्तियों** के मूल्य पर प्रभाव डाल रही हैं।

138. ग्लोबल पल्स कन्वेंशन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल-फसल पैटर्न, - विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन और मुद्दे और संबंधित बाधाएं; किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेफेड(NAFED)
- ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन

समाचार:
- फरवरी में यहां आयोजित होने वाले **ग्लोबल पल्स कन्वेंशन** में **सरकारों** के साथ-साथ **वाणिज्यिक** और **गैर-लाभकारी संगठनों** के लगभग **800 प्रतिनिधि** शामिल होंगे।
- इसका आयोजन **नेशनल एग्रीकल्चरल** को **ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)** और **ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC)** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

मुख्य बिंदु
- सम्मेलन में क्षेत्र के विशेषज्ञ विभिन्न **हितधारकों** और **नीति निर्माताओं** के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे।

- **केंद्रीय उपभोक्ता मामलों** ने कहा कि **भारत में दालों** का **उत्पादन बढ़ा** है और सरकार **वैश्विक स्तर** पर **प्रणालीयों** को सीखने और साझा करने के लिए उत्सुक है।
- **घरेलू किसानों** और **उपभोक्ताओं** के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना एक मुश्किल काम है।
- जब भारत में **खाद्य सुरक्षा** और **पोषण** की बात आती है तो **दालें स्थायी खाद्य प्रणालियों** और **प्रमुख प्रतियोगियों** के विकास में महत्वपूर्ण हैं।

सुपरफ़ूड

- भारत दुनिया भर में **दालों का सबसे बड़ा उत्पादक** और **उपभोक्ता** है अत: **GPC** वैश्विक उद्योग को भारत में ला रहा है ।
- यह सम्मेलन **18 साल** बाद **भारत** में हो रहा है
- दालें **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** में कमी लाने में योगदान करती हैं।
- दालें **उत्पादन** में **विविधता** लाने में मदद करती हैं, क्योंकि इन्हें कम पानी के साथ **शुष्क परिस्थितियों** में भी उगाया जा सकता है।
- यह एक तरह से **सुपरफूड** है, क्योंकि यह **पौष्टिक** और **स्वास्थ्यवर्धक** है।
- यह मिट्टी को **नाइट्रोजन** प्रदान करता है।

139. विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का टेलीस्कोप परियोजना हेतु हवाई का दौरा- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- तीस मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIAP)

समाचार:

- हाल ही में, **विज्ञान** और **प्रौद्योगिकी विभाग** के एक **आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल** ने **थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना** के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए **मौना केआ**, **हवाई** का दौरा किया।

थर्टी मीटर टेलिस्कोप (TMT) परियोजना

- **TMT** एक **30 मीटर व्यास** वाला **ऑप्टिकल** और **इन्फ्रारेड टेलीस्कोप** है जिसे गहरे **अंतरिक्ष** अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अयह एक **सहयोगात्मक प्रयास** है जिसमें **अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा** और **भारत** शामिल हैं।
  - परियोजना में **भारतीय भागीदारी** को **वर्ष 2014** में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- यह अंतरिक्ष में **गहन अन्वेषण** की अनुमति देगा और **अभूतपूर्व संवेदनशीलता** के साथ **ब्रह्मांडीय वस्तुओं** का निरीक्षण करेगा।

TMT परियोजना के समक्ष चुनौतियाँ

- **मूल स्थल** के रूप में चुने गए **मौना** के को **धार्मिक** और **सांस्कृतिक** चिंताओं के कारण **स्थानीय विरोध** का सामना करना पड़ा।
- निर्माण के परमिट को वर्ष 2015 में **हवाई** के **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा अमान्य कर दिया गया था, बाद में **वर्ष 2018** में बहाल कर दिया गया।
- लगातार स्थानीय विरोध के कारण **परियोजना** में देरी हुई है, जिससे **वैकल्पिक साइट** पर विचार किया जा रहा है।
- स्पेन के **कैनरी द्वीप** समूह में ला पाल्मा पर **ऑब्ज़र्वेटेरियो डेल रोके डे लॉस मुचाचोस (ORM)** को एक विकल्प के रूप में माना जाता है।

TMT परियोजना में भारत का योगदान

- उम्मीद है कि **भारत 200 मिलियन डॉलर मूल्य** के **हार्डवेयर, इंस्ट्रुमेंटेशन** और **सॉफ्टवेयर** उपलब्ध कराने में प्रमुख योगदानकर्ता होगा।
- **भारत टेलीस्कोप** के लिए आवश्यक **492 सटीक पॉलिश दर्पणों** में से **83** का योगदान देगा।

- **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIAP)** TMT परियोजना में शामिल **भारतीय संस्थानों** के संघ का नेतृत्व कर रहा है।

प्रगति और भविष्य का निर्णय

- निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आवश्यक घटकों के विकास में प्रगति हुई है।
- अगले **दो वर्षों** में साइट पर निर्णय की उम्मीद के साथ, **स्थानीय लोगों** की सहमति और **समर्थन** सुनिश्चित करने के लिए चर्चा चल रही है।

140. खुदरा मुद्रास्फीति दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मुद्रा स्फ़ीति
- मुद्रास्फीति लक्ष्य

समाचार:

- भारत की **खुदरा मुद्रास्फीति** दिसंबर 2023 में **चार महीने** के **उच्चतम स्तर 5.7%** पर पहुंच गई, जो पिछले महीने में **5.55%** थी।
- दिसंबर की मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी **खाद्य** और **पेय पदार्थ खंड,** विशेष रूप से सब्जियों से प्रेरित थी।
- खाद्य कीमतों में **राष्ट्रीय स्तर पर 9.5%** की **वृद्धि** दर्ज की गई, जबकि शहरी उपभोक्ताओं में **10.42%** की वृद्धि देखी गई।
- शहरी उपभोक्ताओं को **6%** की **उच्च मुद्रास्फीति दर** का सामना करना पड़ा, जबकि **ग्रामीण उपभोक्ताओं** को **खाद्य कीमतों** में थोड़ी कम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा, लेकिन **समग्र मुद्रास्फीति दर लगभग 6%** अधिक थी।

मुद्रा स्फ़ीति

- किसी **अर्थव्यवस्था** में **वस्तुओं** और **सेवाओं** के **सामान्य मूल्य स्तर** में **दीर्घकालिक** वृद्धि है ।
- यह अधिकांश रोजमर्रा या **मानक उत्पादों** और **सेवाओं** के **मूल्य निर्धारण** पर विचार करता है।
  - इनमें भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता सामग्री आदि शामिल हैं।
- यह सकारात्मक है जब यह उ**पभोक्ता मांग** और **खप**त में सुधार करने और **आर्थिक विकास** को संचालित करने में मदद करता है।
- यहां तक कि **मुद्रास्फीति** का मतलब **अपस्फीति को नियंत्रण** में रखना है और यह **अर्थव्यवस्था** पर एक दबाव है।

मुद्रास्फीति लक्ष्य

- यह एक **केंद्रीय बैंकिंग नीति** है जो एक निर्धारित **वार्षिक मुद्रास्फीति** दर प्राप्त करने के लिए **मौद्रिक नीति** में बदलाव पर केंद्रित है।
- धारणा: मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, जो **मुद्रास्फीति** को **प्रबंधित** करके हासिल किया जाता है, **दीर्घकालिक आर्थिक विकास** उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत, **केंद्र सरकार, आरबीआई के परामर्श से, पांच साल में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** के संदर्भ में **मुद्रास्फीति लक्ष्य** निर्धारित करती है ।
- यह **मुद्रास्फीति लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए आवश्यक **नीति दर** निर्धारित करने के लिए **छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC**) के गठन का प्रावधान करता है।
- वर्तमान में, **आरबीआई** का लक्ष्य **मुद्रास्फीति** को **4%** पर रखना है, लेकिन वह **2%** से **6%** के बीच **मुद्रास्फीति** को सहन करेगा।

खुदरा मुद्रास्फीति

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है।
- यह वह दर है जिस पर **उपभोक्ताओं** द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए **खरीदी** जाने वाली **वस्तुओं** और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं।
- यह आम तौर पर घरों द्वारा खरीदी जाने वाली **वस्तुओं** और **सेवाओं** की लागत में बदलाव को मापता है।
  - इनमें भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं।

मूल स्फीति

- यह **वस्तुओं** और **सेवाओं** की लागत में परिवर्तन है लेकिन इसमें **खाद्य** और **ऊर्जा क्षेत्रों** की लागत शामिल नहीं है।
- **खाद्य** और **ऊर्जा** की कीमतों को इस गणना से छूट दी गई है क्योंकि उनकी **कीमतें बहुत अस्थिर** हो सकती हैं या बहुत **उतार-चढ़ाव** हो सकती हैं।

141. भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर 8 महीने के निचले स्तर पर - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- आठ कोर सेक्टर

समाचार:
- नवंबर में भारत की **औद्योगिक उत्पादन वृद्धि** घटकर **आठ महीने** के निचले स्तर **2.4%** पर आ गई।
- यह अक्टूबर में दर्ज **11.6%** की **16 महीने** की **उच्चतम वृद्धि** का अनुसरण करता है।

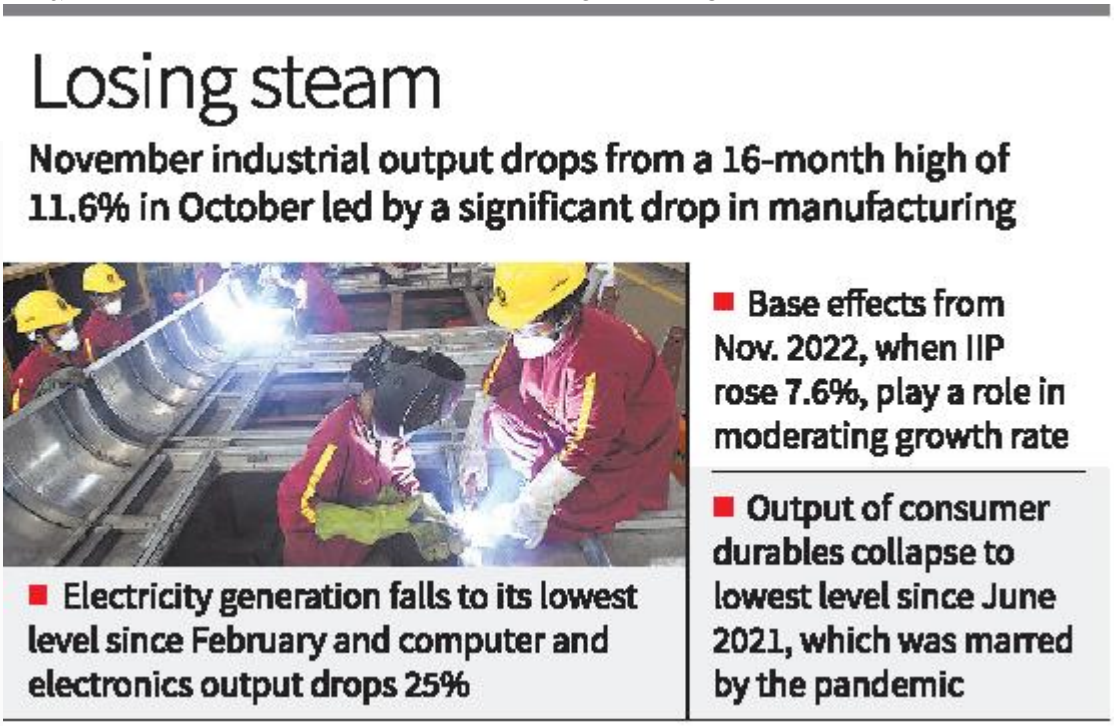

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- **IIP** एक **संकेतक** है जो कि**सी निश्चित अवधि** के दौरान **औद्योगिक उत्पादों** के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- यह एक **समग्र संकेतक** है जो **उद्योग समूहों** की **विकास दर** को मापता है।
- जिन उद्योग समूहों को यह मापता है उन्हें इस प्रकार **वर्गीकृत** किया गया है
  - विनिर्माण, खनन और बिजली जैसे व्यापक क्षेत्र ।
  - **उपयोग-आधारित क्षेत्र** जैसे पूंजीगत सामान, बुनियादी सामान, मध्यवर्ती सामान, बुनियादी ढांचा सामान, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान।
- इसका उपयोग **नीति-निर्माण उद्देश्यों** के लिए **वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक** आदि सहित **सरकारी एजेंसियों** द्वारा किया जाता है।
- इसे **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी** और **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा **मासिक रूप** से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- IIP के लिए आधार वर्ष **2011-2012** है।

आठ कोर सेक्टर
- इनमें **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल **वस्तुओं** का **भार 40.27%** शामिल है।

- आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग अपने भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद > बिजली > इस्पात > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक।

142. पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की द हिंदू -

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गंगाब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली-मेघना-
- मेघना डेल्टा

समाचार:
- **पश्चिम बंगाल** के **सागर द्वीप** में **गंगा सागर मेला**, समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्र तट के कटाव से चुनौतियों का सामना कर रहा है
- इसने **राज्य सरकार** को **धार्मिक मण्डली** के लिए **"राष्ट्रीय मेला"** का दर्जा मांगने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य बिंदु

तीर्थयात्रा पर प्रभाव
- चेतावनी संकेत लगाए गए हैं, और **तीर्थयात्रियों को पवित्र स्नान** के लिए **वैकल्पिक समुद्र तटों** पर भेज दिया गया है।

सरकार की प्रतिक्रिया
- **पश्चिम बंगाल सरकार** के मंत्री **प्रकृति से मुकाबला** करने में लाचारी जता रहे हैं
- कटाव को कम करने के लिए **गंगा सागर** तट पर **टेट्रापोड**, **कंक्रीट तरंग-विघटित** करने वाले **ब्लॉक स्थापित** किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता का आकलन मानसून के बाद किया जाएगा।

वित्तीय निवेश:
- सरकार ने द्वीप की **ड्रेजिंग पर 25 करोड़ रूपये** खर्च किए हैं, जो गंगा सागर मेले के अनुमानित **₹250 करोड़ बजट का 10%** है।

राजनीतिक शर्मिंदगी:
- समुद्र तट का कटाव कटाव शर्मिंदगी का कारण बन जाता है क्योंकि **राज्य सरकार** का लक्ष्य **राष्ट्रीय मेला** का दर्जा प्राप्त करना है।

पर्यावरण और मानवीय कारक
- समुद्र का स्तर बढ़ने से **कपिल मुनि मंदिर** को खतरा है, विशेषज्ञों का कहना है कि पहले के **मंदिर** पहले ही **जलमग्न** हो चुके हैं।
- मेला मैदान के विस्तार के लिए रेत के टीलों को साफ़ करने जैसे **मानवीय हस्तक्षेप,** वेव अटैक को बढ़ाने में योगदान करते हैं।
- सागर द्वीप के निर्माण में **तटीय विनियमन क्षेत्र** के उल्लंघन से समस्या और गंभीर हो गई है।

विशेषज्ञों द्वारा जताई गई चिंता
- **गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली** से **तलछट** के प्रवाह में कमी के कारण **मेघना डेल्टा** की ओर भूमि का संचयन हुआ और **सुंदरवन** में भूमि की हानि हुई।

143. केंद्र सरकार किशोरियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगी द हिंदू -

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- सर्वाइकल कैंसर
- HPV टीका

समाचार:
- **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय** ने अभी तक **मानव पेपिलोमावायरस (HPV)** के खिलाफ **टीकाकरण अभियान** शुरू करने पर निर्णय नहीं लिया है।
- यह **राष्ट्रीय टीकाकरण सलाहकार समूह (NTAGI)** द्वारा **9 से 14 वर्ष** की **किशोरियों** के लिए **टीकाकरण** की सिफारिश की है ।

मुख्य बिंदु

पृष्ठभूमि और सिफ़ारिशें:

- **जून 2022** में, **NTAGI** ने **सर्वाइकल कैंसर** के **बोझ** और **टीके** की प्रभावशीलता पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम** में **HPV वैक्सीन** को शामिल करने का सुझाव दिया।
- प्रस्तावित योजना में **9** से **14 साल** की **लड़कियों** के लिए एक बार का **कैच-अप शॉट** शामिल है, इसके बाद नौ साल की उम्र में अन्य लोगों के लिए **नियमित टीकाकरण** किया जाएगा।

पिछली असफलताएँ और वैक्सीन परीक्षण:

- एक दशक से भी पहले, सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य में उपयुक्त **प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (PATH)** द्वारा आयोजित **टीका परीक्षणों** के दौरान कथित मौतों के कारण **HPV वैक्सीन** को **भारत** में विरोध का सामना करना पड़ा था।
- **संसदीय समिति** ने स्थिति को "**दिलचस्प और संदिग्ध**" बताया और संभावित **व्यावसायिक शोषण** के बारे में चिंता जताई।

वैश्विक और भारतीय सर्वाइकल कैंसर का बोझ:

- सर्वाइकल कैंसर **वैश्विक स्तर** पर **महिलाओं** में **चौथा** सबसे **आम कैंसर** है और **भारतीय महिलाओं** में **दूसरा सबसे आम कैंसर** है। भारत **वैश्विक सर्वाइकल कैंसर** के मामले में सबसे आगे है ।

रोकथाम की संभावना:

- विशेषज्ञ **HPV टीकाकरण** की प्रभावकारिता पर जोर देते हैं, और **90%** से अधिक **HPV -जिम्मेदार कैंसर** को रोकने की इसकी क्षमता का हवाला देते हैं।
- **भारत** और **विदेशों** में किए गए परीक्षणों से संकेत मिलता है कि टीका लगाने वाली **महिलाओं** में **HPV** से जुड़े **कैंसर** का **खतरा 81%** कम हो गया है।

लंबित निर्णय और आगे का रास्ता:

- **सर्वाइकल कैंसर** की **रोकथाम** में संभावित लाभों के बावजूद, **स्वास्थ्य मंत्रालय** ने अभी तक **टीकाकरण अभियान** शुरू करने पर निर्णय नहीं लिया है।

144. भारतीय खाद्य निगम पारदर्शिता और सक्रिय दृष्टिकोण से काम करेगा खाद्य मंत्री : - द हिंदू

प्रासंगिकता: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनरुद्धार; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन का अर्थशास्त्र.

प्रीलिम्स टेकअवे

- ओपन मार्केट सेल योजना
- भारतीय खाद्य निगम

समाचार:

- **खाद्य मंत्री** ने **भारतीय खाद्य निगम** की **60वीं स्थापना वर्षगांठ** पर इसकी भूमिका की सराहना की।
- उन्होंने कहा कि **FCI** को **किसानों** और **देश के लोगों** के एक **विश्वसनीय भागीदार** के रूप में उभरना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** की भूमिका न केवल राशन पहुंचाना है बल्कि **पारदर्शिता, दक्षता** और **जवाबदेही लाकर किसानों** और **लाभार्थियों** में विश्वास पैदा करना भी है।
- **FCI** देश के हर कोने में लाभार्थियों को **राशन प्रदान** करके **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना [PMGKAY]** जैसी प्रमुख **योजनाओं को सुविधाजनक** बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **FCI** को दक्षता में सुधार के लिए **डिजिटलीकरण** और **प्रौद्योगिकी** को अपनाना चाहिए।
- **निरीक्षण, खरीद, परिवहन, वितरण** और **भंडारण** जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता हासिल की जा सकती है
- FCI मार्ग अनुकूलन, **मशीनीकृत लोडिंग/अनलोडिंग, नवीन भंडारण समाधान** और अन्य तरीकों के माध्यम से परिचालन लागत को कम करेगा।

- खुले बाजार में **बिक्री योजना (घरेलू)** संचालन भी **गेहूं** और **चावल** की कीमतों को कम करने में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ था।

ओपन मार्केट सेल योजना (OMSS)

- FCI **खाद्यान्न की आपूर्ति** बढ़ाने के लिए समय-समय पर खुले बाजार में **ई-नीलामी** के माध्यम से **गेहूं** और **चावल** के **अधिशेष स्टॉक** को पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेचता है।
- **OMSS** का उद्देश्य **FCI** द्वारा रखे गए **गेहूं** और **चावल** के **अधिशेष स्टॉक** का निपटान करना और **खुले बाजार में गेहूं** की कीमतों को विनियमित करना है।
- FCI **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX)** के प्लेटफॉर्म पर गेहूं के लिए **OMSS** के लिए **साप्ताहिक नीलामी** आयोजित करता है।
- **NCDEX** भारत में एक **कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म** है जो विभिन्न **कृषि** और **अन्य वस्तुओं** में व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है

145. दिल्ली का AQI गंभीर, वाहनों और निर्माण कार्यों पर रोकइंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- GRAP
- AQI

समाचार:

- दिल्ली में **वायु की गुणवत्ता** (AQI) ' **बहुत गंभीर**' हो गई ।
- इससे **निर्माण** और **BS-III पेट्रोल** और **BS-IV डीजल चार पहिया** वाहनों के चलने पर **प्रतिबंध** लग गया है।
- **BS-III पेट्रोल** और **BS-IV डीजल** चार पहिया वाहन चलाने पर **प्रतिबंध** का उल्लंघन करने पर **जुर्माना 20,000 रुपये** है।

दिल्ली में पर्यावरण परिवेश

- **14 जनवरी 2024** को दिल्ली का औसत **AQI 447** था.
- भारत **मौसम विज्ञान विभाग** ने कम हवा की **गति** और **उच्च नमी के स्तर** को **प्रदूषकों** के संचय के लिए जिम्मेदार ठहराया।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** ने इसके लिए **बड़े पैमाने पर खुले में आग जलाने** सहित स्थानीय **प्रदूषण स्रोतों** को जिम्मेदार ठहराया।
- ऐसे प्रदूषकों पर अंकुश लगाने के लिए **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान** के **चरण III** के तहत **प्रतिबंध** लगाए हैं ।
- प्रतिबंध में **निर्माण** और **विध्वंस गतिविधियों** को शामिल किया जाएगा

प्रतिबंध के अपवाद

- **निम्नलिखित परियोजनाओं स्वीकृत किया गया है:**
  - रेलवे,
  - मेट्रो रेल,
  - हवाई अड्डे, "राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएँ",
  - अस्पताल, जल आपूर्ति और स्वच्छता
  - रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं (सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, राजमार्ग और पाइपलाइन सहित)।

दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण पर हालिया घटनाक्रम

- **नवंबर** और **दिसंबर** में **दिल्ली** की औसत **वायु गुणवत्ता** पिछले वर्षों की तुलना में खराब रही है।
- इन **दो महीनों** में कई बा**र AQI गंभीर (400)** या **'गंभीर +' श्रेणी (450+)** को छूने के साथ
- **CAQM** ने कई बार **GRAP** प्रतिबंध लगाए थे।
- इन्हें **1 जनवरी, 2024** को रद्द कर दिया गया।

GRAP-ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

- GRAP दिल्ली-NCR में **वायु गुणवत्ता** की **गिरावट को रोकने** के लिए लागू किए गए **आपातकालीन उपायों** का एक समूह है।
- GRAP का चरण 1 तब सक्रिय होता है जब AQI 'खराब' श्रेणी (201 से 300) में होता है।
- GRAP का चरण 2 तब सक्रिय होता है जब AQI 'बहुत खराब' श्रेणी (301 से 400) में होता है।
- GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है जब AQI 'गंभीर'' श्रेणी (401 से 450) में होता है।
- GRAP का चरण 4 तब सक्रिय होता है जब AQI 'बहुत गंभीर' श्रेणी (450 से ऊपर) में होता है।

146. भारतीय सेना दिवस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीं :शुभकामनाएं हिंदुस्तान - टाइम्स

प्रासंगिकता: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- फील्ड मार्शल
- सेना दिवस

समाचार:
- **राष्ट्रपति** और **प्रधान मंत्री** ने **15 जनवरी** को **सेना दिवस** के अवसर पर **भारतीय सेना** के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

भारतीय सेना दिवस
- भारतीय सेना दिवस **हर साल 15 जनवरी** को मनाया जाता है।
- सेना दिवस के खास मौके पर अधिकारी **उच्च पदाधिकारियों** की मौजूदगी में परेड करेंगे और इसकी सलामी **भारतीय सेना प्रमुख** लेंगे.

पृष्ठभूमि
- **15 जनवरी 1949** को **फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा भारतीय सेना** के पहले **कमांडर-इन-चीफ** बने और उन्होंने **ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर** से अधिकार ले लिया।
- वह सेना के लंबे, समृद्ध इतिहास में इसकी कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने।
- वर्ष 1949 से वर्ष 2022 तक **सेना दिवस परेड** का आयोजन दिल्ली छावनी के **करियप्पा परेड ग्राउंड** में किया जाता था।
- वर्ष 2023 में **बेंगलुरु** में परेड की जिम्मेदारी **दक्षिणी कमान** के पास थी। यह पहली बार था जब सेना दिवस परेड देश की राजधानी के बाहर आयोजित की गई थी।

फील्ड मार्शल केएम करियप्पा
- वह भारतीय सेना के पहले **भारतीय कमांडर-इन-चीफ** थे और **वर्ष 1947** के **भारत-पाकिस्तान युद्ध** के दौरान **पश्चिमी मोर्चे** पर **भारतीय सेना** का नेतृत्व किया था।
- वह **फील्ड मार्शल** की **सर्वोच्च रैंक** पाने वाले **दो भारतीय सेना अधिकारियों** में से एक हैं (दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं)।
- उन्हें **15 जनवरी 1949** को स्वतंत्र **भारतीय सेना** के पहले **कमांडर-इन-चीफ** के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे **भारतीय सेना दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- उन्होंने अंतिम **ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर FRR बुचर** से **भारतीय सेना** की कमान संभाली।
- भारत सरकार ने वर्ष **1983** में **करियप्पा** को **फील्ड मार्शल की रैंक** से सम्मानित किया।

147. डिजी यात्रा ऐप में सुरक्षा को लेकर शिकायतें द हिंदू -

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
- डिजी यात्रा ऐप

समाचार:
- यात्रियों की सहमति या जानकारी के बिना **हवाई अड्डे** के प्रवेश द्वार पर **डिजी यात्रा ऐप** के लिए चेहरे के **बायोमेट्रिक्स** के **संग्रह** को लेकर चिंताएं पैदा हुईं।

मुख्य बिंदु
हवाई यात्रियों की शिकायतें

- हवाई यात्रियों ने उनकी अनुमति के बिना **डिजी यात्रा** के लिए नामांकन करने वाले **निजी कर्मचारियों** और **CISF** कर्मियों की **"जबरदस्ती और भ्रामक"** गतिविधियाँ के बारे में शिकायतें दर्ज कीं।

डिजी यात्रा और इसके उद्देश्य

- **हवाई अड्डे** की चौकियों के माध्यम से **कागज-रहित** और **निर्बाध आवाजाही** के लिए **यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग** को बढ़ावा देने वाली एक पहल है ।
- 2018 में एक **स्वैच्छिक कार्यक्रम** के रूप में लॉन्च किया गया, डिजी यात्रा दिसंबर 2022 से **तीन हवाई अड्डों** पर लागू की गई थी और **वर्ष 2024** में 24 और **हवाई अड्डों** की **योजना** के साथ **13 हवाई अड्डों** तक विस्तारित हो गई है।

स्वामित्व और कार्यान्वयन

- डिजी यात्रा ऐप का **स्वामित्व एक कंसोर्टियम**, **डिजी यात्रा फाउंडेशन** के पास है, जिसके शेयरधारक **भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण** और **पांच निजी हवाई अड्डे** हैं।
- इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता बढ़ाना, देरी से आने वाले **यात्रियों पर नज़र रखना** और **सुरक्षा** में सुधार करना है।

कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

- सरकार का दावा है कि **यात्री डेटा** का कोई **केंद्रीय भंडारण** नहीं है, इसे **एन्क्रिप्ट** किया गया है और **मोबाइल उपकरणों** पर संग्रहीत किया गया है।
- यात्रा के **दिन प्रस्थान हवाई अड्डे** के साथ साझा किया गया डेटा **24 घंटों** के भीतर मिटा दिया जाता है।
- **डेटा सुरक्षा कानूनों** के **अनुपालन** को लेकर चिंताएं बढ़ीं।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** पारित हो गया है, लेकिन नियम लंबित हैं।
- आलोचनाओं में **डिजी यात्रा नीति में छूट** के साथ तालमेल बिठाते हुए **सरकारी एजेंसियों** को खुद को छूट देने की व्यापक शक्तियां शामिल हैं।
- नीति मौजूदा **प्रोटोकॉल** के आधार पर **सुरक्षा एजेंसियों को यात्री डेटा** तक पहुंच की अनुमति देती है
- यह **बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम** को सुरक्षा कारणों से **डेटा पर्ज सेटिंग्स** को बदलने की क्षमता प्रदान करता है।

148. फिनटेक SRO को विकासोन्मुख, स्वतंत्र होना चाहिए :RBI- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

समाचार:

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने **फिनटेक क्षेत्र** में **स्व-नियामक संगठनों (SRO)** के लिए एक मसौदा रूपरेखा जारी की है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- स्व) नियामक संगठन-SRO)
- फिनटेक उद्योग
- भारतीय रिजर्व बैंक)RBI)

स्व-नियामक संगठन (SRO)

- SRO एक **गैर-सरकारी संगठन** है जो उद्योग में **संस्थाओं (सदस्यों) के आचरण** से संबंधित **नियमों और मानकों** को निर्धारित और लागू करता है ।
- **उद्देश्य:** ग्राहक की **सुरक्षा करना** और **नैतिकता, समानता** और **व्यावसायिकता** को बढ़ावा देना।
- यह एक **प्रहरी** के रूप में कार्य कर सकता है और सदस्यों को **जिम्मेदार** और **नैतिक प्रथाओं** को अपनाने के लिए **प्रोत्साहित** कर सकता है।
- यह कम औपचारिक **सेट-अप** के माध्यम से **नियामक** और **बाजार सहभागियों** के बीच एक **लिंक प्रदान** कर सकता है।
- इससे पहले, **सितंबर 2023** में, **RBI** ने **फिनटेक** को खुद एक **SRO** स्थापित करने के लिए कहा था।

RBI का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क

- **फिनटेक क्षेत्र** में एक **SRO** को **स्वतंत्र रूप** से काम करना चाहिए, **विकासोन्मुख** होना चाहिए और **उद्योग के विकास** में **सक्रिय रूप** से **योगदान** देना चाहिए।
- इसे **निष्पक्षता बनाए** रखनी चाहिए, हितों के टकराव से बचना चाहिए और अपने **सदस्यों पर निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित** करनी चाहिए।

- स्वतंत्रता एक **तटस्थ** और **विश्वसनीय इकाई** के रूप में **SRO-FT** की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, जो **उद्योग प्रतिभागियों** और **नियामकों** दोनों का विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक है।

149. भारत की बहुआयामी गरीबी दर घटकर 11.28% हो गई इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रीलिम्स टेकअवे
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

समाचार:
- **नीति आयोग** के एक हालिया पेपर में **भारत** की **बहुआयामी गरीबी** में एक महत्वपूर्ण सुधार का पता चला है, जिसमें **वर्ष 2013-14** में **29.17%** से घटकर **वर्ष 2022-23** में **11.28%** होने का अनुमान लगाया गया है।
- माना जाता है कि पिछले **नौ वर्षों** में लगभग **24.82 करोड़** लोग **बहुआयामी गरीबी** से बच गए हैं।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
- **MPI गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता है।**
  - वास्तव में, यह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी आंकड़ों का पूरक है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक **MPI** का पुनर्निर्माण करना और **विश्व स्तर** पर **संरेखित** और फिर भी अनुकूलित भारत **MPI** बनाना।
  - वैश्विक **MPI रैंकिंग** में **भारत की स्थिति** में सुधार के बड़े लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार कार्य योजनाएँ तैयार करना।
- यह **12 SDG संरेखित संकेतकों** द्वारा दर्शाए गए **स्वास्थ्य, शिक्षा** और **जीवन स्तर** के **तीन समान** रूप से **भारित आयामों** में एक साथ अभाव को मापता है।
  - इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति शामिल हैं।
- यह **ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** और **UNDP** द्वारा विकसित **विश्व स्तर पर स्वीकृत** और **मजबूत पद्धति** का उपयोग करता है ।

भौगोलिक प्रभाव
- **उत्तर प्रदेश, बिहार**, **मध्य प्रदेश** और **राजस्थान** जैसे राज्यों में गरीब के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या में सबसे तेज गिरावट देखी गई।
- **वर्ष 2015-16** और **वर्ष 2019-21** के बीच अभाव की गंभीरता थोड़ी कम दर से कम हुई ।
- हालाँकि, कुल जनसंख्या में **MPI** गरीबों की हिस्सेदारी में कमी **वर्ष 2015-16** के बाद तेजी से हुई।
  - इसका कारण बाद की अवधि में वर्षों की कम संख्या को माना जाता है।

कोविड-19 का प्रभाव
- गरीबी प**र COVID-19 महामारी** का प्रभाव पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, क्योंकि **वर्ष 2019-21** के बीच एकत्र किए ग**ए NHFS-5** डेटा का हिस्सा महामारी से पहले का था।
- इसके बावजूद, भारत को **SDG** लक्ष्य **1.2 हासिल** करने की उम्मीद है, जिससे गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी आएगी।

जीवन स्तर संकेतकों में सुधार
- जीवन स्तर के आयाम से संबंधित संकेतकों ने **वर्ष 2005-06** में अभाव के उच्चतम स्तर को दर्शाया।
- विशेष रूप से, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता सुविधाओं और बैंक खातों तक पहुंच से संबंधित अभावों में गिरावट आई है।

150. रक्षा मंत्रालय, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकाई के नेतृत्व में सर्वोच्च निकाय - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: रक्षा

समाचार:

- पूर्व प्रधान **वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर** के **विजय राघवन** के नेतृत्व में एक **विशेषज्ञ समिति** ने **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** के निर्माण की सिफारिश की है।
- **उद्देश्य:** भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी **रोडमैप** का निर्धारण करना और **प्रमुख रक्षा परियोजनाओं** और उनके कार्यान्वयन पर निर्णय लेना।

प्रीलिम्स टेकअवे

- रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- DRDO

प्रस्तावित रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद

- **प्रधान मंत्री** की **अध्यक्षता** में
- **उपराष्ट्रपति:** रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
- **कार्यकारी समिति:** इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा की जाती है।
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तीन सेवा प्रमुख और उनके उप प्रमुख सदस्य के रूप में।
- प्रत्येक क्षेत्र से दो सदस्यों के साथ शिक्षा और उद्योग से प्रतिनिधित्व।

पृष्ठभूमि

- रक्षा **अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा **नौ सदस्यीय विजय राघवन पैनल** का गठन किया गया था ।
- यह समीक्षा परियोजना में देरी के बारे में चिंताओं के बीच आई है, जैसा कि **रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति** और **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** ने उजागर किया है।

DRDO पर समिति की टिप्पणियाँ

- DRDO को **रक्षा के लिए अनुसंधान और विकास** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और **उत्पादीकरण, उत्पादन चक्र** और **उत्पाद प्रबंधन** में शामिल होने से बचना चाहिए।
- **विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों** के लिए **भारत** के **भीतर** और **अंतरराष्ट्रीय स्तर** पर विशेषज्ञता की पहचान करने की आवश्यकता है।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** का **लक्ष्य निर्णय** लेने को **सुव्यवस्थित** करना और **विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों** के लिए सही **प्रतिभागियों** की पहचान करना है।

रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विभाग का निर्माण

- **समिति** ने **रक्षा मंत्रालय** के तहत एक अलग **विभाग - रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी** और **नवाचार विभाग** का भी प्रस्ताव रखा।
- एक **टेक्नोक्रेट** के नेतृत्व में
- **उद्देश्य**
  - शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
  - रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- **DTC सचिवालय** के रूप में, यह विभाग **DRDO** और **शिक्षा जगत** से वैज्ञानिकों को आकर्षित करेगा।
- यह **उत्पादन विशेषज्ञता पर ज्ञान का भंडार** बनाएगा और **प्रौद्योगिकी उत्पादन** पर निर्णयों में सहायता के लिए पृष्ठभूमि अनुसंधान करेगा।
- इसके अलावा, **विभाग परीक्षण** और **प्रमाणन** के लिए प्रयोगशालाएं संचालित करेगा।

151. आरबीआई पैनल ने राज्य गारंटी के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव रखा इंडियन - एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

समाचार:

- **रिज़र्व बैंक** के एक **कार्य समूह** ने प्रस्ताव दिया है कि भारत में **राज्य सरकारें ऋणों** पर दी जाने वाली **गारंटी** के लिए न्यूनतम शुल्क वसूलें।

प्रीलिम्स टेकअवे

- राज्य की गारंटी
- भारतीय रिजर्व बैंक

कार्य समूह पृष्ठभूमि

- **जुलाई 2022** में **राज्य वित्त सचिवों** के **32वें सम्मेलन** में **राज्य सरकार** की गारंटी से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की गई।
- समूह का उद्देश्य **राज्य सरकारों** द्वारा उनके **वित्तीय स्वास्थ्य** और **बैंकिंग प्रणाली** पर दी गई गारंटी के **वित्तीय जोखिमों** का आकलन करना है।

मुख्य सिफ़ारिशें

- विस्तारित गारंटी के लिए **राज्य सरकारों** को **न्यूनतम गारंटी शुल्क** लेने की सिफारिश की गई है।
- **जोखिम श्रेणी** और **अंतर्निहित ऋण** की अवधि के आधार पर **अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम का** सुझाव देता है ।
- एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटियों के लिए राजस्व प्राप्तियों का **5%** या **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** का **0.5%**, जो भी कम हो, की सीमा तय करने का प्रस्ताव है।

व्यापक मूल्यांकन और जोखिम वर्गीकरण

- राज्य सरकारों को प**रियोजनाओं/गतिविधियों** को **उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम** और **कम जोखिम** के रूप में वर्गीकृत करने और गारंटी देने से पहले **उचित जोखिम भा**र निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।
- जिस उद्देश्य के लिए स**रकारी गारंटी** जारी की जाती है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय जोखिम मूल्यांकन के संबंध में **सशर्त/बिना शर्त, वित्तीय/प्रदर्शन गारंटी** के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।
- राज्यों को गारंटी लागू होने के जोखिम पर विचार करना चाहिए और केवल **राज्य की गारंटी** पर निर्भर हुए बिना **ऋण प्रस्तावों** का **व्यापक मूल्यांकन** करना चाहिए।

152. ग्रीनलैंड में पहले की अपेक्षा अधिक बर्फ गिरी द हिंदू -

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रीलिम्स टेकअवे
- ग्लोबल वार्मिंग
- ग्रीनलैंड

समाचार:

- शोध के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण **ग्रीनलैंड की बर्फ** की चादर में पहले के अनुमान से **20% अधिक बर्फ कम** हो गई है।
- पहले के अध्ययनों से पता चला है कि पिछले **20 वर्षों** में **ग्रीनलैंड** की **बर्फ की चादर** से लगभग **5,000 गीगाटन बर्फ** की हानि हुई है, जो **समुद्र** के बढ़ते स्तर में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

नई खोज

- शोधकर्ताओं ने **वर्ष 1985** से **वर्ष 2022** तक **ग्लेशियर टर्मिनस** स्थिति की **240,000 उपग्रह छवियों** को संकलित किया।
- पिछले कुछ दशकों में **ग्रीनलैंड** के लगभग हर **ग्लेशिय**र के पतले होने या पीछे हटने का अनुभव हुआ है।
- पिछले **चार दशकों** में **ग्रीनलैंड** के किनारों के आसपास **1,000 गीगाटन** या **20%** से अधिक बर्फ नष्ट हो गई है, जिसका पहले हिसाब नहीं था।

समुद्र के स्तर पर प्रभाव

- किनारों के आसपास की बर्फ, जो पहले से ही पानी में है, वह **समुद्र के स्तर** में **वृद्धि** पर **न्यूनतम प्रत्यक्ष** प्रभाव डालती है।
- हालाँकि, निष्कर्षों से समग्र बर्फ पिघलने की संभावना का पता चलता है, जिससे **ग्लेशियर** का **समुद्र** की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा।

मौसमी संवेदनशीलता और ग्लोबल वार्मिंग

- ग्रीनलैंड के **ग्लेशियर मौसमी परिवर्तनों** (सर्दियों में विस्तार, गर्मियों में पीछे हटना) के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं और **ग्लोबल वार्मिंग** के प्रभाव के प्रति भी सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
  - उन्होंने वर्ष 1985 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण वापसी का अनुभव किया है।
- **ग्रीनलैंड** की **बर्फ की चादर**, जो **अंटार्कटिका** के बाद **दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ** है, का अनुमान है कि **वर्ष 2002** के बाद से **समुद्र के स्तर** में **वृद्धि** में **20%** से अधिक का योगदान है।

153. सरकार ने PLI योजना के तहत 4415 करोड़ रुपये वितरित किये इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- उत्पादन लिंक्ड-) प्रोत्साहनPLI) योजना
- MSMEs

समाचार:
- **केंद्र सरकार** ने **आठ क्षेत्रों** के लिए **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** के तहत **4,415 करोड़ रुपये** सफलतापूर्वक वितरित किए हैं।
- **वर्ष 2021** में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य **विभिन्न उद्योगों** में निवेश, **प्रौद्योगिकी** अपनाने और **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ावा देना है।

नौकरी सृजन संबंधी चिंताएँ और प्रतिक्रिया
- पर्याप्त निवेश के बावजूद **कम रोजगार सृजन** को लेकर चिंताएं रही हैं ।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से **रोजगार सृजन 6.78 लाख** से अधिक बताया गया है।
- सरकार मानती है कि **तकनीक-संचालित** उत्पादन में अक्सर नौकरी के सीमित अवसर होते हैं और **उद्योग 4.0** के आगमन के साथ ऐसी चुनौतियाँ विकसित होने की उम्मीद है।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ और समाधान
- **दावों के प्रसंस्करण** में चुनौतियों की पहचान की गई है, जिसमें **परियोजना निगरानी एजेंसियों (PMA)** और कंपनियों के बीच लंबे समय तक संचार भी शामिल है।
- **सरकार ने मंत्रालयों** और **PMA** को **दस्तावेजों के प्रसंस्करण** को सुव्यवस्थित करने और देरी को कम करने के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** बनाने का निर्देश दिया है।

योजना की उपलब्धियां
- अब तक, **3 लाख करोड़ रुपये** से अधिक के अपेक्षित निवेश के साथ **14 क्षेत्रों** में **746** आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
- **फार्मा** और **टेलीकॉम जै**से क्षेत्रों में लगभग **176 MSMEs PLI** लाभार्थियों में से हैं।
- **PLI योजनाओं** के तहत निर्यात **3.2 लाख करोड़ रुपये** से अधिक हो गया है, जिसमें **इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण** और **दूरसंचार क्षेत्रों** का उल्लेखनीय योगदान है।

विदेशी निवेश और उपलब्धियों को सुगम बनाना
- **उद्योग** और **आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** ने **PLI लाभार्थी कंपनियों** के लिए **वीजा आवेदनों** की सुविधा के लिए एक प्रणाली स्थापित की है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र** के लिए **PLI योजना** की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि** देखी गई है।
- **दूरसंचार क्षेत्र** में **60 प्रतिशत का आयात प्रतिस्थापन** हासिल किया गया है।

154. GM सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगीसरकार - द हिंदू :

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति)GEAC)
- आनुवंशिक रूप से संशोधित)GM) फसलें
- धारा सरसों हाइब्रिड-11 (DMH-11)
- जनहित याचिका)PIL)

समाचार:
- **सुप्रीम कोर्ट** ने हाल ही में **आनुवंशिक रूप से संशोधित** (GM) फसलों, विशेष रूप से **सरसों की खेती** पर विचार-विमर्श किया और **भारत की भलाई** के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
- **सरकार** ने तर्क दिया कि इससे **गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल** अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे देश की **आयात पर निर्भरता** कम हो जाएगी।

सरकार का नजरिया

- **खाद्य तेल की सामर्थ्य:** GM फसलें, विशेष रूप से GM सरसों, घरेलू स्तर पर तिलहन उगाकर आम आदमी के लिए खाद्य तेल को अधिक लागत प्रभावी बनाने में योगदान देंगी।
- **विदेशी निर्भरता में कमी**
  - GM फसलों की खेती बढ़ाना राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है।
  - यह लगभग **50 से 60%** खाद्य तेल **आयात** करने की आवश्यकता को कम करता है, **खाद्य सुरक्षा** को बढ़ावा देता है और **विदेशी निर्भरता** को कम करता है।
- **सांख्यिकीय समर्थन**
  - सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़े पेश किए, जो भारत में खाद्य तेल की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।
  - वर्ष 2020-21 में 54% मांग आयात के माध्यम से पूरी की गई, जो लगभग ₹1,15,000 करोड़ थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

- **सर्वोच्च न्यायालय** ने **राष्ट्रीय हित** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है।
- **PIL याचिकाकर्ताओं** की चिंताओं पर विचार करते हुए, अदालत ने लोगों के **किफायती भोजन के अधिकार** की **रक्षा** करने के सरकार के कर्तव्य पर जोर दिया।

PIL याचिकाकर्ताओं की स्थिति

- **PIL याचिकाकर्ताओं** ने GM फसलों, विशेषकर **धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (DMH-11)** के नाम से ज्ञात **सरसों के आनुवंशिक** रूप से **निर्मित संस्करण** के खुले क्षेत्र में **परीक्षण** से होने वाले **पर्यावरणीय नुकसान** के बारे में चिंता जताई।
- उनका तर्क है कि नियामक प्रणाली, विशेष रूप से **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)** में हितों का टकराव था और पारदर्शिता का अभाव था।

155. एयरबस और CSIR-IIP सतत विमानन ईंधन पर सहयोग करेंगे द हिंदू -

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
• सतत विमानन ईंधन • वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

समाचार:

- **एयरबस** और **CSIR -इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (CSIR-IIP)** ने **नई प्रौद्योगिकियों** को विकसित करने और देश में **स्वदेशी सतत विमानन ईंधन** (SAF) का **परीक्षण** और **अर्हता** प्राप्त करने के लिए एक **समझौता ज्ञापन** पर **हस्ताक्षर** किए हैं।

मुख्य बिंदु

- यह सहयोग **SAF उत्पादन** और **व्यावसायीकरण** का समर्थन करके **भारतीय एयरोस्पेस उद्योग** की **डीकार्बोनाइजेशन** महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करेगा
  - एक **नए HEFA प्रौद्योगिकी मार्ग** और **स्थानीय** रूप से प्राप्त **फीडस्टॉक्स** का उपयोग करना।
- संस्थाएं **SAF** के **उत्पादन** के लिए **तकनीकी मूल्यांकन, अनुमोदन, बाजार पहुंच** और **स्थिरता** मान्यता प्रयासों पर **संयुक्त रूप** से काम करेंगी।
- **CSIR-IIP** द्वारा विकसित **SAF** सहित, उद्योग के **डीकार्बोनाइजेशन** प्रयास पर सबसे बड़े प्रभाव वाले उपाय के रूप में कार्य करेगा।
- सभी एयरबस विमान **50% SAF मिश्रण** पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित हैं, जबकि **लक्ष्य वर्ष 2030** तक **100% SAF** अनुकूलता हासिल करना है।
- जबकि **CSIR-IIP** नए मार्ग के तहत **ईंधन गुणों** और **विमान प्रणालियों** और **पर्यावरण** पर प्रभाव का अध्ययन करेगा

सतत विमानन ईंधन (SAF)

- इसे **बायो-जेट ईंधन** के रूप में भी जाना जाता है, और इसे खाना पकाने के **तेल** और **पौधों** से **तेल-समृद्ध** बीजों का उपयोग करके घरेलू रूप से विकसित तरीकों का उपयोग करके बनाया जाता है।

- **ASTM इंटरनेशनल** से **ASTM D4054** प्रमाणन के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए संस्थानों द्वारा उत्पादित **SAF नमूनों** को **यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंगहाउस** में सख्त परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है।
- **CSIR-IIP** ने विभिन्न सामग्रियों, जैसे गैर-खाद्य और खाद्य तेलों के साथ-साथ खाना पकाने के तेल का उपयोग करके ईंधन बनाया है।
- उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिनमें **पाम स्टीयरिन, सैपियम तेल, पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट, शैवाल तेल, करंजा** और **जेट्रोफा** शामिल थे।

156. जापान चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पांचवां देश बना इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- SLIM
- JAXA

समाचार:
- **जापान** का **स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून (SLIM)** चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा और यह उपलब्धि हासिल करने वाला **पांचवां देश** बन गया।
- मिशन का उद्देश्य **सटीक लैंडिंग तकनीक** का प्रदर्शन करना और **जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम** को पुनर्जीवित करना है।

लैंडिंग और सौर ऊर्जा मुद्दे
- हाल ही में, **SLIM** चंद्रमा पर उतरा और पृथ्वी के साथ फिर से संचार स्थापित किया।
- हालाँकि, संभवतः गलत **एंगलिंग** के कारण इसके **सौर पैनल बिजली** उत्पन्न करने में असमर्थ थे।
- अंतरिक्ष यान वर्तमान में कुछ घंटों की **सीमित जीवन अवधि** के साथ अपनी **बैटरी** पर काम कर रहा है।

जापान की अंतरिक्ष आकांक्षाएँ
- जापान **चीन** के ख़िलाफ़ **अमेरिका** के साथ साझेदारी करके अंतरिक्ष में बड़ी भूमिका चाहता है।
- **JAXA** का लक्ष्य **NASA** के **आर्टेमिस कार्यक्रम** के हिस्से के रूप में एक **अंतरिक्ष यात्री** को **चंद्रमा** पर **भेजना है।**
- **प्रक्षेपण विफलता** सहित **रॉकेट विकास** में हाल की असफलताओं के कारण **अंतरिक्ष अभियानों** में देरी हुई है।

पिछली चंद्र अन्वेषण चुनौतियाँ
- **JAXA** को **चंद्रमा** के **गुरुत्वाकर्षण** के कारण **चंद्र मिशनों** में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे **लैंडर्स** के लिए **दूसरी लैंडिंग** का प्रयास करना मुश्किल हो गया है।
- पिछले वर्ष अन्य संस्थाओं द्वारा **तीन चंद्र मिशन** विफल रहे हैं।

SLIM की विशेषताएँ
- **SLIM** अंतरिक्ष यान **दो मुख्य इंजनों, 12 थ्रस्टर्स, सौर कोशिकाओं, एंटेना, रडार** और **कैमरों** से सुसज्जित है, जो लागत प्रभावी प्रक्षेपण के लिए **लाइटवेट डिजाइन** को बनाए रखता है।
- इसने लैंडिंग पर **मिनी-प्रोब** को सफलतापूर्वक तैनात किया।

सहयोगात्मक विकास
- टेक दिग्गज **सोनी ग्रुप,** टॉय मेकर **टॉमी** और **जापानी विश्वविद्यालयों** ने **संयुक्त रूप** से **SLIM** द्वारा तैनात **रोबोट** विकसित किए हैं।

157. वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- डीप कोरल रीफ्स
- ग्रेट बैरियर रीफ़

समाचार:
- वैज्ञानिकों ने **अमेरिकी अटलांटिक** तट से **सैकड़ों मील दूर समुद्र** की गहराई में **सबसे बड़ी मूंगा चट्टान** का **मानचित्रण** किया है।

मुख्य बिंदु

- जबकि शोधकर्ता **वर्ष 1960** के दशक से जानते हैं कि कुछ **मूंगे अटलांटिक** के बाहर मौजूद थे
  - **चट्टान का आकार** तब तक एक रहस्य बना रहा जब तक कि नई पानी के नीचे **मानचित्रण तकनीक ने समुद्र तल की 3D** छवियां बनाना संभव नहीं बना दिया।
- यह चट्टान **फ्लोरिडा** से **दक्षिण कैरोलिना** तक लगभग **310 मील (499 किलोमीटर)** तक फैली हुई है और कुछ बिंदुओं पर **68 मील (109 किलोमीटर)** चौड़ी तक पहुँच जाती है।
- कुल क्षेत्रफल **येलोस्टोन नेशनल पार्क** के आकार का लगभग **तीन गुना** है।
- चट्टान **655 फीट** से **3,280 फीट (200 मीटर से 1,000 मीटर)** की गहराई पर पाई गई, जहां **सूरज की रोशनी** प्रवेश नहीं करती है।
- उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों के विपरीत, जहां **प्रकाश संश्लेषण विकास** के लिए महत्वपूर्ण है, यहां तक कि **मूंगे को ऊर्जा** के लिए पानी से **खाद्य कणों** को **फ़िल्टर** करना होगा।
- वैज्ञानिकों ने कहा कि डीप कोरल रीफ्स शार्क, स्वोर्डफ़िश, समुद्री तारे, ऑक्टोपस, झींगा और कई अन्य प्रकार की मछलियों के लिए आवास प्रदान करती हैं।
- उष्णकटिबंधीय चट्टानें **वैज्ञानिकों** और **स्नॉर्कलर्स** के लिए बेहतर ज्ञात हैं क्योंकि वे अधिक सुलभ हैं।
- दुनिया की सबसे बड़ी **उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टान प्रणाली**, **ऑस्ट्रेलिया** में **ग्रेट बैरियर रीफ**, लगभग **1,430 मील (2,301 किलोमीटर)** तक फैली हुई है।
- **समुद्र तल** के **मानचित्र जहाजों** पर ले जाए जाने वाले **उच्च-रिज़ॉल्यूशन** वाले **सोनार उपकरणों** का उपयोग करके बनाए जाते हैं।
- **उष्णकटिबंधीय चट्टानों** की तुलना में गहरी चट्टानें **समुद्र तल** का अधिक भाग कवर करती हैं।
- **दोनों प्रकार** के आवास समान जोखिमों के **प्रति संवेदनशील** हैं, जिनमें **जलवायु परिवर्तन** और **तेल** और **गैस ड्रिलिंग** से होने वाली गड़बड़ी शामिल है

158. नासा के अंतरिक्ष यान ने चंद्रयान-3 लैंडर को पिंग किया द हिंदू -

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर
- चंद्रयान 3
- लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे)LRA)

समाचार:

- **नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO)** ने **चंद्रमा** पर अपने और **भारत** के **चंद्रयान-3** लैंडर के बीच **लेजर किरणों** को सफलतापूर्वक **प्रसारित** और **परावर्तित** किया।
- **उद्देश्य:** चंद्रमा की सतह पर लक्ष्य का सटीक पता लगाना, भविष्य के मिशनों के लिए संभावनाएं खोलना।

नासा का लेजर प्रयोग

- **नासा LRO** के **लेज़र अल्टीमीटर** उपकरण ने **चंद्रयान-3** के **विक्रम लैंडर** की ओर **लेज़र पल्स** भेजा।
- **विक्रम लैंडर** पर एक **रेट्रोरिफ्लेक्टर** से वापस लौटी रोशनी का पता लगाने के बाद, **नासा** ने प्रयोग की सफलता की पुष्टि की।
- इस तकनीक में किसी वस्तु की ओर **लेजर पल्स** भेजना और प्रकाश को वापस लौटने में लगने वाले समय को मापना शामिल है, जिसका उपयोग आमतौर पर **पृथ्वी की परिक्रमा** करने वाले **उपग्रहों** को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।

भविष्य में सुधार और अनुप्रयोग

- **नासा** का **लक्ष्य** भविष्य में **रेट्रोरिफ्लेक्टर** का उपयोग करने वाले **मिशनों** के लिए इसे नियमित बनाने के लिए तकनीक में सुधार करना है।
- व्यापक अनुप्रयोगों के लिए तकनीकों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- **नासा** और **इसरो** के बीच **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** के तहत **नासा** के **लेजर रेट्रोरेफ्लेक्टर एरे (LRA)** को **विक्रम लैंडर** पर समायोजित किया गया था ।
- इसमें एक **अर्धगोलाकार** समर्थन संरचना पर **आठ कोने-घन रेट्रोरिफ्लेक्टर** शामिल हैं जिन्हें **चंद्र** सतह पर दशकों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- जबकि **चंद्रमा** पर कई **LRA** तैनात किए गए हैं, **चंद्रयान -3** पर **LRA** एक **लघु संस्करण** है और **दक्षिणी ध्रुव** के पास उपलब्ध एकमात्र है।

महत्व

- **चंद्रयान-3** पर नासा का **LRA** एक दीर्घकालिक **जियोडेटिक स्टेशन** और **स्थान मार्कर** के रूप में काम करेगा, जो **अंतरिक्ष यान** की **कक्षीय स्थिति** के सटीक निर्धारण में सहायता करेगा।
- यह **चंद्र भूगर्भिक फ्रेम** को परिष्कृत करने, **चंद्रमा की गतिशीलता, आंतरिक संरचना** और **गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों** में अंतर्दृष्टि प्रदान करने में योगदान देगा।
- **लेजर प्रयोग** की सफलता **नासा** और **इसरो** के बीच सहयोग में प्रगति का प्रतीक है, जो **चंद्र अन्वेषण** और भविष्य के मिशनों में योगदान दे रही है।

159. अमृत धरोहर पहल से प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा द हिंदू -

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रीलिम्स टेकअवे
- अमृत धरोहर पहल
- रामसर स्थल

समाचार:

- **केंद्र सरकार** ने **पारिस्थितिक रूप** से **संवेदनशील आर्द्रभूमि,** जिसे **रामसर स्थल** के रूप में जाना जाता है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक **मिशन** शुरू किया है।
- लक्ष्य संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और **स्थानीय समुदायों** और **अर्थव्यवस्थाओं** को सशक्त बनाकर **उच्च मूल्य वाले पर्यटन** से **प्रकृति पर्यटन** की ओर स्थानांतरित करना है।

रामसर स्थल

- रामसर स्थल **वर्ष 1971** में हस्ताक्षरित **रामसर कन्वेंशन** के तहत नामित **अंतर्राष्ट्रीय महत्व** की **आर्द्रभूमियाँ** हैं।
- भारत में **75 रामसर स्थल हैं,** जिनमें **चिल्का झील, सुंदरबन और भितरकनिका मैंग्रोव** शामिल हैं।

अमृत धरोहर पहल

- **जून 2023** में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य **रामसर स्थलों** के **संरक्षण मूल्यों** को बढ़ावा देना, **रोजगार पैदा** करना और **स्थानीय आजीविका** का समर्थन करना है।
  - यह पहल **वर्ष 2023-24** बजट घोषणा का एक हिस्सा है।
- यह **केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय** और **पर्यावरण, वन** और **जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई **'अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना' 2023** का हिस्सा है।
- इसे विभिन्न **केंद्र सरकार** के मंत्रालयों, **राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों** और **औपचारिक** और **अनौपचारिक संस्थानों** के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- **उद्देश्य**
  - रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना।
  - संरक्षण कार्यों का समर्थन करके उच्च मात्रा वाले पर्यटन से उच्च मूल्य वाले प्रकृति पर्यटन की ओर बदलाव।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **राज्य पर्यटन विभागों** के सहयोग से **फैसिलिटेटर्स, पर्यटन सेवा प्रदाताओं** और **हितधारकों** को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **बर्डवॉचिंग, हॉटोग्राफी, स्टारगेजिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, शिकार, मछली पकड़ने** और **पार्कों** का दौरा करने जैसी **प्रकृति पर्यटन गतिविधियों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक साइट से **तीस प्रतिभागियों** को **15-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से** गुजरना पड़ता है।

- इसमें वैकल्पिक **आजीविका कार्यक्रम (ALP)** और **पर्यटन नाविक प्रमाणपत्र** (पर्यटन के लिए नाविक प्रमाणन) शामिल हैं।

पायलट प्रोजेक्ट

- **सोलह रामसर स्थलों** की पहचान की गई है, जिनमें से **पांच** को **कौशल विकास** के लिए **पायलट प्रोजेक्ट** के रूप में चुना गया है ।
  - पायलट स्थलों में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), भितरकनिका मैंग्रोव (ओडिशा), चिल्का झील (ओडिशा), सिरपुर (मध्य प्रदेश), और यशवंत सागर (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

160. NISAR मिशन जल्द ही लॉन्च होने की राह परनासा - द हिंदू :

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नासा
- L-Band

समाचार:

- **नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR)** मिशन, पृथ्वी के जटिल **पारिस्थितिक तंत्र** में प्राकृतिक प्रक्रियाओं और परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

मुख्य बिंदु

एनोर्मौस डेटा'

- **लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) वेधशाला** के रूप में डिज़ाइन किया गया, **NISAR मिशन** कई मायनों में अद्वितीय है
  - कम से कम तीन साल के मिशन जीवन में इससे भारी मात्रा में विश्वसनीय**, उच्च रिज़ॉल्यूशन डेटा** की उम्मीद की जाती है।
- डेटा की मात्रा बहुत अधिक होगी, और यह हमें **पृथ्वी** पर किसी भी स्थान पर माप का एक **विश्वसनीय सेट** प्राप्त करने में मदद करता है
  - जहां हम **विज्ञान** या **निगरानी अनुप्रयोगों, वन प्रबंधन, कृषि निगरानी** या यहां तक कि आने वाले तूफान को देखना चाहते हैं
- **मिशन पृथ्वी की भूमि** और **बर्फ** से **ढके क्षेत्रों** को हर **12 दिनों** में **दो बार आरोही** और **अवरोही दर्रे** पर **स्कैन** करने के लिए एक **सिंथेटिक एपर्चर रडार** का उपयोग करेगा।
- बादलों को भेदने और दिन-रात काम करने में सक्षम NISAR से **पृथ्वी-अवलोकन क्षमता** में क्रांति आने की उम्मीद है।
- अन्य बातों के अलावा, यह आपदा निगरानी और शमन के लिए एक **विश्वसनीय डेटा स्रोत** होने की भी उम्मीद है।
- यह **एकल वेधशाला समाधान** नासा द्वारा प्रदान की गई एक **लंबी तरंग दैर्ध्य बैंड (L-Band)** SAR **पेलोड** प्रणाली और एक **छोटी तरंग दैर्ध्य बैंड (S-Band**) इसरो **पेलोड** से सुसज्जित है।
- इसरो के अनुसार, एक साथ काम करते हुए, वे **"स्थानिक** और **अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा"** की आपूर्ति करेंगे
  - पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए।
- उन आपदाओं के लिए जो थोड़ी लंबी अवधि में विकसित होती हैं

161. सरकार ने IFSC में वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- GIFT सिटी
- IFSCs

समाचार:

- सरकार ने **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)** में की जा सकने वाली **गतिविधियों** का दायरा बढ़ा दिया है।
- अब इसमें **बहीखाता** और **लेखा** जैसी सेवाएँ भी शामिल कर दी गई हैं।

मुख्य बिंदु

- **वित्त मंत्रालय** द्वारा जारी **गजट अधिसूचना** के अनुसार, विभिन्न सेवाओं सहित

- बुक कीपिंग
- लेखांकन
- टैक्स निर्धारण
- वित्तीय अपराध अनुपालन को वित्तीय सेवाओं के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

- वित्तीय सेवाएँ **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)** द्वारा **विनियमित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र** में इकाइयों द्वारा पेश की जाएंगी।
- वे उन अनिवासियों को पेशकश करते हैं जिनका व्यवसाय **भारत** में पहले से मौजूद व्यवसाय को विभाजित करके स्थापित नहीं किया गया है
  - या भारत में पहले से मौजूद व्यवसाय का पुनर्निर्माण/पुनर्गठन करना
- अधिसूचना में कहा गया है कि इन **इकाइयों** को **भारत** में अपने **समूह संस्थाओं** से **मौजूदा अनुबंधों** या कार्य व्यवस्थाओं को स्थानांतरित करने या प्राप्त करने के माध्यम से सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

- IFSC उन **वित्तीय सेवाओं** और **लेनदेन** को वापस लाने में सक्षम बनाता है जो वर्तमान में **भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं** द्वारा **अपतटीय वित्तीय केंद्रों** में किए जाते हैं
  - और **भारत** में **वित्तीय संस्थानों** (जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, आदि) की विदेशी शाखाएं/सहायक कंपनियां।
- यह एक **व्यावसायिक** और **विनियामक वातावरण** प्रदान करता है जो **लंदन** और **सिंगापुर** जैसे दुनिया के अन्य प्रमुख **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों** के बराबर है।
- **IFSCs** का उद्देश्य **भारतीय कॉरपोरेट्स** को **वैश्विक वित्तीय बाजारों** तक आसान पहुंच प्रदान करना और **भारत में वित्तीय बाजारों** के आगे के विकास को पूरक और बढ़ावा देना है।
- **भारत** में पहला **IFSC गांधीनगर** में **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी)** में स्थापित किया गया है।

162. MNRE ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट।

प्रीलिम्स टेकअवे
- SIGHT प्रोग्राम
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- हरित हाइड्रोजन

समाचार:

- भारत में **केंद्रीय नवीन** और **नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** ने **हरित हाइड्रोजन** खरीद को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** के तहत दिशानिर्देशों और प्रोत्साहनों का अनावरण किया है।
- **मिशन** के तहत, **ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT)** कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए **17,490 करोड़ रुपये** अलग रखे गए हैं।

हरित हाइड्रोजन संक्रमण (SIGHT) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप

- **उद्देश्य:** घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना।
- प्रोत्साहन लागत में कमी और तेजी से विस्तार की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  - **पेट्रोल** और **डीजल** के उत्पादन के लि**ए कच्चे तेल में सल्फर सामग्री** को **हटाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन** महत्वपूर्ण है।
- **Mode-2B** के तहत कार्यान्वित इस योजना में प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से **हरित हाइड्रोजन** के लिए मांग एकत्र करना और बोलियां मांगना शामिल है।

तेल और गैस संस्थाओं की भूमिका

- योजना का कार्यान्वयन **केंद्रीय पेट्रोलियम** और **प्राकृतिक गैस मंत्रालय** द्वारा नामित एजेंसियों, मुख्य रूप से **तेल और गैस कंपनियों** को सौंपा जाएगा।
- **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT)** द्वारा निर्देशित **तेल और गैस संस्थाएं हरित हाइड्रोजन** के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां तलाशेंगी।

- प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, बोलीदाताओं को '**राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मानक**' में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- CHT सचिवीय, **प्रबंधकीय** और **कार्यान्वयन** सहायता प्रदान करेगा।

निगरानी एवं समीक्षा

- **MoPNG** और **MNRE** के सचिवों की **सह-अध्यक्षता** वाली एक योजना **निगरानी समिति** समय-समय पर प्रदान की गई क्षमताओं के कार्यान्वयन और प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।
- समिति चुनौतियों से निपटने के उपाय भी सुझाएगी।

163. भारतीय शेयर बाजार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
- सेबी

समाचार:

- **दक्षिण एशियाई देश** के लिए एक और उपलब्धि हासिल करते हुए **भारत का शेयर बाजार** पहली बार **हांगकांग** से आगे निकल गया है

मुख्य बिंदु

- इसकी **विकास संभावनाओं** और **नीतिगत सुधारों** ने इसे निवेशकों का प्रिय बना दिया है।
- **भारतीय एक्सचेंजों** पर सूचीबद्ध शेयरों का **संयुक्त मूल्य हांगकांग** के लिए **$4.29 ट्रिलियन** के मुकाबले **$4.33 ट्रिलियन** तक पहुंच गया
  - ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, यह भारत को विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनाता है।
- बढ़ते खुदरा **निवेशकों के आधार** और **कॉर्पोरेट आय** के कारण **भारत में इक्विटी** में तेजी आ रही है।
- **दुनिया का सबसे** अधिक आबादी वाला देश **वैश्विक निवेशकों** के लिए एक **वैश्विक स्थान** बन गया है।
- **भारतीय शेयर बाजार** में बढ़ती तेजी **हांगकांग में ऐतिहासिक मंदी** के साथ मेल खा रही है।

शेयर बाजार

- **शेयर बाज़ार** वे स्थान हैं जहाँ **खरीदार** और **विक्रेता सार्वजनिक निगमों** के **इक्विटी शेयरों** का **आदान-प्रदान** करने के लिए मिलते हैं।
- शेयर बाज़ार एक **मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था** के घटक हैं क्योंकि वे **निवेशकों को व्यापार** और **पूंजी** के आदान-प्रदान तक **लोकतांत्रिक** पहुंच प्रदान करते हैं।
- **मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था** एक **आर्थिक प्रणाली** है जिसमें **वस्तुओं और सेवाओं** की कीमतें सरकारी **विनियमन के हस्तक्षेप** के बिना, **आपूर्ति और मांग** द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- भारत में **दो स्टॉक एक्सचेंज** हैं - **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज** (BSE) और **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज** (NSE)।
- सेबी भारत में **प्रतिभूति बाजार** का **नियामक** है, वे **कानूनी ढांचा** तय करते हैं और **बाजार में परिचालन** में रुचि रखने वाली **सभी संस्थाओं** को **विनियमित** करते हैं।

164. सीमा सुरक्षा बल का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार द हिंदू -

प्रासंगिकता: रक्षा

प्रीलिम्स टेकअवे
- बीएसएफ
- अनुच्छेद 131

समाचार:

- **पंजाब** में **बीएसएफ क्षेत्राधिकार** पर केंद्र और **राज्य सरकारों** के बीच अपर्याप्त परामर्श से **मुकदमेबाजी** उत्पन्न होती है।

पृष्ठभूमि

- **पंजाब** ने **बीएसएफ** की **परिचालन सीमा** को **15 किमी से 50 किमी** तक बढ़ाने के **केंद्र सरकार** के फैसले को चुनौती देते हुए **अनुच्छेद 131** के तहत मुकदमा दायर किया।

अन्य राज्यों में भी ऐसी ही चिंताएँ

- **पश्चिम बंगाल** ने **पंजाब की चिंताओं** को साझा किया, **बीएसएफ विस्तार** के **खिलाफ प्रस्ताव** पारित किया।
- **दोनों राज्य** इसे **संघीय सिद्धांतों** का उल्लंघन और **राज्य पुलिस** की **कानून और व्यवस्था शक्तियों** का उल्लंघन मानते हैं।

केंद्र सरकार की अधिसूचना

- **बीएसएफ अधिनियम** के तहत **अक्टूबर 2021** की **अधिसूचना परिचालन क्षेत्राधिकार** का **मानकीकरण** करती है।
- **पंजाब, पश्चिम बंगाल** और **असम** में **15 किमी से 50 किमी** की वृद्धि देखी गई है, **गुजरात में 80 किमी** से **घटकर 50 किमी** हो गया है, और **राजस्थान 50 किमी** पर बना हुआ है।

चिंताएँ बढ़ीं

- **वैध कारणों** के बावजूद, **केंद्र सरकार** को **सार्वजनिक व्यवस्था** और **पुलिस शक्तियों** के लिए **राज्य सरकारों** की **संवैधानिक जिम्मेदारियों** का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए।

बीएसएफ की भूमिका और सीमाएँ

- **बीएसएफ सीमा** पार **अपराधों को रोकने** पर **ध्यान केंद्रित** करता है लेकिन उसके पास जांच या मुकदमा चलाने की शक्ति का अभाव है।
- यह स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग करता है, और **क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव** से बचा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्न

- क्या **केंद्र** की **अधिसूचना राज्य सरकार** के **अधिकार क्षेत्र** का अतिक्रमण करती है?
- **"भारत की सीमाओं** से **सटे क्षेत्रों** की **स्थानीय सीमा"** का निर्धारण करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

165. बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी घाटा उच्च स्तर पर इंडियन एक्सप्रेस -

प्रासंगिकता: अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली में **लिक्विडिटी 3.4 लाख करोड़ रुपये** के ऐतिहासिक घाटे पर पहुंच गई है।
- इस घाटे का कारण **सरकारी व्यय में कमी, उच्च कर बहिर्प्रवाह** और **धीमी बैंक** जमा वृद्धि है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- खुला बाजार परिचालन
- वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन

लिक्विडिटी की कमी में योगदान देने वाले कारक

- इस लिक्विडिटी घाटे का प्राथमिक कारण **सरकारी व्यय** में कमी है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के बहिर्प्रवाह ने **लिक्विडिटी** को और प्रभावित किया।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs)** से अधिक निकासी के कारण भी **बैंकिंग प्रणाली** में **लिक्विडिटी** का दायरा बढ़ा है।
- साल-दर-साल आधार पर बैंक जमा में 13% की वृद्धि हुई, जबकि ऋण में 20% की वृद्धि हुई।
- बड़ी मात्रा में **खुदरा जमाओं के म्यूचुअल फंड** में स्थानांतरित होने से भी जमा में धीमी वृद्धि हुई है।

RBI की प्रतिक्रिया और वर्तमान तरलता उपाय

- **बैंकिंग प्रणाली** की **लिक्विडिटी**, जैसा कि **RBI** द्वारा **बैंकिंग प्रणाली** में डाली गई **धनराशि** से पता चलता है, पिछले **महीने से घाटे** की स्थिति में है।
- शुद्ध आधार पर, RBI ने 16 दिसंबर, 2023 से 14 जनवरी, 2024 तक औसतन 1.8 ट्रिलियन रुपये की लिक्विडिटी डाली है।
- RBI बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी लाने के लिए **VRR नीलामी** आयोजित कर रहा है, जिसमें **नवीनतम 24 जनवरी** को **2.5 लाख करोड़ रुपये** का **15-दिवसीय VRR** है।

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

- **लिक्विडिटी घाटे** की स्थिति को कम करने के लिए **खुले बाजार संचालन (OMO)** खरीद जैसे स्थायी **लिक्विडिटी उपायों** की घोषणा कर सकता है ।

- अस्थायी **लिक्विडिटी** लाने के लिए परिवर्तनीय **रेपो दर नीलामी (VRR)** के बजाय।

- **उपभोक्ता-मूल्य मुद्रास्फीति (CPI)** लगातार **4% लक्ष्य** से अधिक होने के कारण **RBI लिक्विडिटी** को कम करने में अनिच्छुक हो सकता है ।

संभावित निहितार्थ

- **बैंकिंग प्रणाली** में **लिक्विडिटी** की निरंतर तंगी **उधारकर्ताओं** के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है।
  - अगर सरकारी खर्च में सार्थक तरीके से तेजी नहीं आई तो स्थिति और खराब हो सकती है।
- **रुख** और **कार्रवाई** में **निरंतरता** बनाए रखने के लिए **मौद्रिक नीति रुख** को '**समायोजन वापस** लेने' से 'तटस्थ' में बदलना चाहिए।

166. फ्लैश इंडिया PMI के अनुसार जनवरी में निजी क्षेत्र कीऔद्योगिक और सेवा गतिविधियों में तेजी द हिंदू -

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- क्रय प्रबंधक सूचकांक)PMI)
- कोर सेक्टर

समाचार:

- नए **HSBC फ्लैश इंडिया** PMI के अनुसार इस महीने **निजी क्षेत्र** की **औद्योगिक और सेवा गतिविधियों** में तेजी आई है

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

- यह एक **सर्वेक्षण-आधारित** उपाय है जो उत्तरदाताओं से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चर के बारे में उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछता है।
- यह **विनिर्माण** और **सेवा क्षेत्रों** में **आर्थिक रुझानों** की प्रचलित दिशा का एक **सूचकांक** है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य कंपनी के निर्णय **निर्माताओं, विश्लेषकों** और **निवेशकों** को **वर्तमान** और **भविष्य** की **व्यावसायिक स्थितियों** के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- इसकी गणना **विनिर्माण** और **सेवा क्षेत्रों** के लिए अलग-अलग की जाती है और फिर एक **समग्र सूचकांक** भी बनाया जाता है।
- PMI 0 से 100 तक की संख्या है।
- **50 से ऊपर का प्रिंट का मतलब विस्तार है**, जबकि उससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
- **50** पर रीडिंग कोई बदलाव नहीं दर्शाती है।
- यदि पिछले महीने का **PMI चालू महीने** के **PMI से अधिक** है, तो यह दर्शाता है कि **अर्थव्यवस्था संकुचन** कर रही है।
- यह आमतौर पर **हर महीने** की शुरुआत में जारी किया जाता है।
- इसलिए, इसे **आर्थिक गतिविधि** का एक अच्छा **अग्रणी संकेतक** माना जाता है।

Flashing green

Private sector industrial and services activity rebounded this month as per a new HSBC Flash India Purchasing Managers' Index

- The HSBC Flash India Composite PMI Output Index was at 61 compared with 58.5 in December
- Flash PMI is based on responses from about 75-85% of 800 services, industry firms that are surveyed each month
- Operating capacities remained under pressure, encouraging firms to hire additional workers

167. सफ्रान भारत में लड़ाकू विमान तकनीक हस्तांतरित करने को तैयार - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति
- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA)
- F-414 इंजन
- कावेरी परियोजना

प्रासंगिकता : प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

समाचार :
- भारत अपने **पांचवीं पीढ़ी** के **लड़ाकू विमान** के लिए **इंजन के निर्माण पर फ्रांस** के साथ सहयोग कर रहा है।
- नया इंजन **एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)** को शक्ति देने के लिए है।

मुख्य बिंदु
- **सफरान** और **रक्षा अनुसंधान** एवं **विकास संगठन** की **वैमानिकी विकास एजेंसी** और **गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान** के बीच चर्चा चल रही है।।
- वे विशिष्टताओं के एक सेट पर पहुंच रहे हैं जो देश की भविष्य की **लड़ाकू जेट आवश्यकताओं** का अनुपालन करता है।
- भारत **विनिर्माण प्रौद्योगिकी** के **हस्तांतरण** और **वास्तविक डिजाइन चरण, धातुकर्म पहलुओं** आदि में काम करना चाहता है।
- **एयरोस्पेस** और **रक्षा क्षेत्रों** में काम करने वाली **फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी सफरान** ऐसा करने को तैयार है।

भारत और अमेरिका के बीच F-414 इंजन डील
- F-414 इंजन के **विनिर्माण लाइसेंस** के लिए **जनरल इलेक्ट्रिक (GE)** के साथ सौदे को **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
- इस सौदे के साथ F-414 इंजन का **निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड** द्वारा किया जाना तय है।
- **जेट इंजन** के निर्माण में शामिल कई **प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक** प्रक्रियाओं तक पहुंच प्रदान करेगा ।
- **F-414 इंजन स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA)-MK2** को शक्ति देने के लिए हैं।
- **AMCA** के विकास की योजना **दो चरणों** में बनाई गई है: **F-414 इंजन के साथ MK1**

GEO IAS It's about quality
+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

- फ्रांस के सहयोग से अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ Mk2

प्रोजेक्ट कावेरी-1989

- भारत ने पहले **कावेरी परियोजना** के तहत **जेट इंजन प्रौद्योगिकी** पर मालिकाना अधिकार पाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा।
- इस **परियोजना** को **वर्ष 1989** में सुरक्षा पर **कैबिनेट समिति (CCS)** द्वारा मंजूरी दी गई थी।

168. अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दी - द हिंदू

प्रासंगिकता : द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारतीय हितों को प्रभावित करते हैं

प्रीलिम्स टेकअवे

- F-16
- एफ-35
- कुर्द आतंकवादी संगठन

समाचार :

- **अमेरिका** ने **तुर्की** को **F-16 फाइटर जेट** बेचने की मंजूरी दे दी है।
- इस सप्ताह **NATO** में **स्वीडन** की सदस्यता के **तुर्की सरकार** के अनुसमर्थन के बाद यह मंजूरी दी गई।
- यह कदम NATO गठबंधन के विस्तार में एक महत्वपूर्ण विकास है,

मुख्य बिंदु

- **अमेरिकी कांग्रेस** ने **तुर्की** को **23 अरब डॉलर** की **F-16** बिक्री को मंजूरी दे दी है।
- **कांग्रेस** ने **ग्रीस** को उन्नत **F-35 लड़ाकू विमानों** की **8.6 बिलियन डॉलर** की बिक्री को भी मंजूरी दे दी।
- यह कदम **तुर्की** द्वारा **वाशिंगटन** के साथ **स्वीडन के NATO** में शामिल होने के लिए अपना "**अनुमोदन पत्र**" जमा करने के कुछ ही घंटों बाद आया।
- **तुर्की** को बिक्री में **40** नए **F-16** और उसके मौजूदा **F-16** बेड़े में से 79 को आधुनिक बनाने के उपकरण शामिल हैं।
- **ग्रीस** को बिक्री में **40 F-35 लाइटनिंग II ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर्स** और **संबंधित उपकरण** शामिल हैं।

बहुपक्षीय क्षितिज पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास

- तुर्की ने **स्वीडन** की **NATO सदस्यता** को मंजूरी देने में **एक वर्ष** से अधिक की देरी की थी।
- **स्वीडन** ने **तुर्की** की **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं** को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें **कुर्द उग्रवादियों** के खिलाफ उसकी लड़ाई भी शामिल थी।
- तुर्की ने **नए विमानों की बिक्री** की मंजूरी पर **स्वीडन की सदस्यता** का अनुसमर्थन किया था ।
- तुर्की द्वारा **मानवाधिकार संबंधी चिंताओं** के कारण **संयुक्त राज्य अमेरिका** में कई **सीनेटरों** ने आपत्ति व्यक्त की।

रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर NATO का विस्तार

- **NATO** ने **स्वीडन** और **फिनलैंड को** गठबंधन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है
  - **फरवरी 2022** में **यूक्रेन** पर **रूस** के आक्रमण के बाद **नॉर्डिक राज्यों** ने अपनी लंबे समय से चली आ रही **सैन्य तटस्थता** को समाप्त कर दिया।
- **स्वीडन** का **NATO** में **औपचारिक प्रवेश** अब **हंगरी** पर निर्भर करता है , जो **NATO** का आखिरी शेष सहयोगी है जिसने इसकी सदस्यता को मंजूरी नहीं दी है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** इस समझौते के साथ चल रही **रूसी आक्रामकता** के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने **वैश्विक सहयोगियों** को भी इकट्ठा कर रहा है।

169. लाल सागर संकट: भारतीय निर्यातकों ने केंद्र से अधिक ऋण का अनुरोध किया - द इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता : भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- केप ऑफ़ गुड होप
- लाल सागर

समाचार :
- **भारतीय निर्यातकों** ने **केंद्र सरकार** से **लाल सागर** में व्यवधान के कारण **माल परिवहन दरों** के रूप में **अधिक ऋण की सुविधा प्रदान** करने में मदद करने को कहा है।

मुख्य बिंदु
- **लाल सागर क्षेत्र** में **नौकाय**न करने वाले जहाजों पर बढ़ते हमलों ने **निर्यातकों** को **केप ऑफ गुड होप** के पार **लंबा रास्ता अपनाने** के लिए मजबूर कर दिया है।
- इससे डिलीवरी का समय **15 से 20 दिन** बढ़ गया है।
- **लाल सागर मार्ग** में व्यवधान के कारण **माल परिवहन दरों** में लगभग **300 प्रतिशत** का उछाल आया है।
- इससे **माल परिवहन दरों** और **बीमा प्रीमियम** में वृद्धि के कारण पारगमन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है।
- **फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO)** टिप्पणियों पर कड़ी नजर रख रहा है।

भारतीय निर्यात वस्तुओं पर प्रभाव
- **भारतीय कंपनियां यूरोप**, **उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका** और **पश्चिम एशिया** के कुछ हिस्सों के साथ व्यापार करने के लिए **स्वेज नहर** के माध्यम से **लाल सागर मार्ग** का उपयोग करती हैं।
- **क्रिसिल (CRISIL)** के अनुमान के अनुसार, **वर्ष 2022-23** में भारत के **18 लाख करोड़ रुपये** के **निर्यात** का **50 प्रतिशत और 17 लाख करोड़ रुपये** के **आयात का 30 प्रतिशत** इन क्षेत्रों से आया।
- समुद्री खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से **श्रिम्प** और **झींगा** पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है
  - चूँकि उत्पादन का **80-90 प्रतिशत निर्यात** किया जाता है, इसका आधे से अधिक हिस्सा **लाल सागर** के माध्यम से होता है।
- उनकी खराब होने वाली **प्रकृति और कम मार्जिन निर्यातकों** को बढ़ती **माल परिवहन लागत और लैटिन अमेरिकी** आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी दबाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- यह **वैश्विक शिपिंग लाइनों** को लंबे **व्यापार मार्ग** अपनाने के लिए **मजबूर** कर रहा है, जो अंततः बासमती चावल जैसी कम मूल्य वाली **वस्तुओं के निर्यात** को प्रभावित कर रहा है।
- **बासमती चावल के उत्पादन** का **30-35% लाल सागर** के माध्यम से भेजा जाता है।
- **सुचारू व्यापार भुगतान** सुनिश्चित करना एक और चुनौती है।

170. केंद्र ने OMCs में FY24 पूंजी निवेश आधा कर दिया -द हिंदू बिजनेसलाइन

प्रासंगिकता : पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति
- व्यय वित्त समिति

समाचार :
- सरकार ने **राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों** को दी जाने वाली **पूंजी सहायता** की मात्रा **आधी** कर दी है।

मुख्य बिंदु
- इस समर्थन का उद्देश्य **आधिकारिक तौर** पर **ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं** में निवेश को बढ़ाना था।

- यह प्रावधान **तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं** को मुआवजा देने के लिए किया गया था, जिन्हें **वर्ष 2022** में भारी नुकसान हुआ था।
- घाटा तब हुआ जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बरकरार रखीं
    - यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद।

पूंजीगत सहायता के लिए बजटीय प्रावधान

- **FY24** के लिए **केंद्रीय बजट** में **₹30,000 करोड़** की **पूंजी** सहायता का प्रावधान किया गया है
    - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)।
- **वित्त मंत्री** ने रणनीतिक **भूमिगत भंडारों** को भरने के लिए **कच्चा तेल खरीदने** के लिए **₹5,000 करोड़** का प्रस्ताव दिया था
    - कर्नाटक के मंगलुरु और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में।
- **वित्त मंत्रालय** द्वारा **इक्विटी समर्थन** आधा कर **15,000 करोड़** कर दिया गया है और **रणनीतिक भंडार** भरने की योजना को स्थगित कर दिया गया है।
- यह निर्णय **नवंबर, 2023** में व्यय **वित्त समिति** की बैठक की पृष्ठभूमि है।
- **EFC** की सिफारिशों के **आधार** पर **CCEA** (आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति) की मंजूरी मांगी जा रही है।

हरित ऊर्जा के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन

- **वर्ष 2022-23** में **OMC** को दी जाने वाली **इक्विटी इन्फ्यूजन** का उपयोग **हरित ऊर्जा पहल** के लिए किया जाएगा।
- हरित ऊर्जा पहल में **ऊर्जा संक्रमण, शुद्ध शून्य** और **ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों** को प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- **31 मार्च 2024** तक संशोधित **पूंजी निवेश योजना** होगी।

171. भारतीय परमाणु संयंत्रों से न्यूनतम रेडियोधर्मी निर्वहन: अध्ययन - द हिंदू

- **प्रासंगिकता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।
- **समाचार:**

प्रीलिम्स टेकअवे

- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- विखंडन और संलयन
- क्रिटिकैलिटी

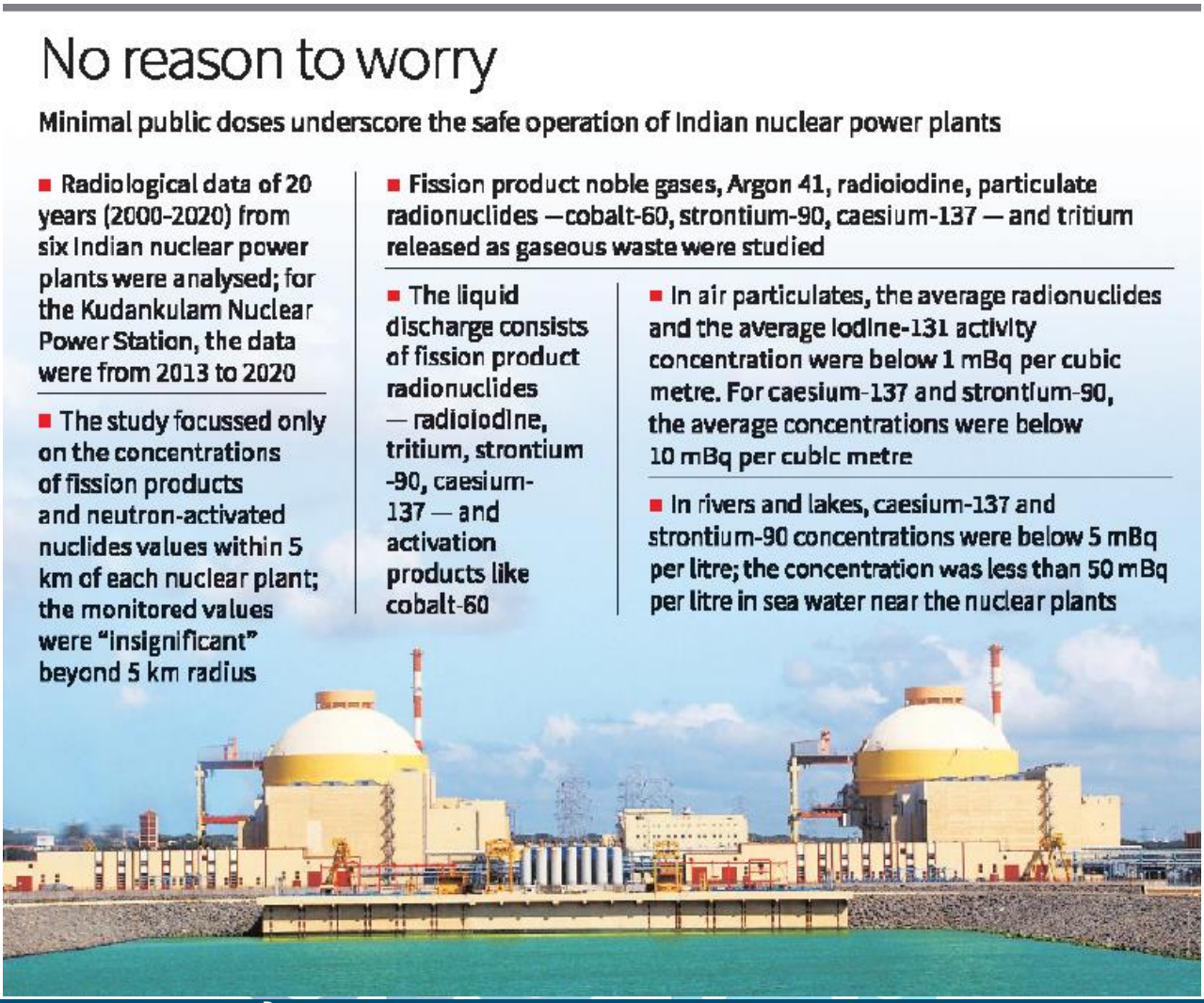

172. सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों को मूल्य नियंत्रण के-दायरे में लाया इंडियन - एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनरुद्धार; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन का अर्थशास्त्र.

प्रीलिम्स टेकअवे
- गैरयूरिया उर्वरक-
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी

समाचार:
- **भारत सरकार पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS)** समर्थन प्राप्त करने वाले उर्वरकों को **"उचित मूल्य निर्धारण"** नियंत्रण के तहत ले आई है।

मुख्य बिंदु
- सरकार **डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)**, **म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)** और ऐसे अन्य सभी उर्वरकों को "**उचित मूल्य निर्धारण**" नियंत्रण के तहत अधिसूचित करेगी।
- यूरिया के विपरीत **NBS उर्वरक**, जिसका अधिकतम **खुदरा मूल्य (MRP)** सरकार द्वारा तय किया जाता है तथा **तकनीकी रूप** से नियंत्रणमुक्त हैं।
- **अप्रैल 2010** में शुरू की गई **NBS योजना** के तहत, उनके **MRP** को बाजार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और उन्हें बेचने वाली **व्यक्तिगत कंपनियों** द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
- सरकार इनमें से **प्रत्येक उर्वरक** पर केवल एक **निश्चित प्रति टन सब्सिडी** का भुगतान करती है, जो उनके पोषक तत्व या **नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटेशियम (K) और सल्फर (S)** के विशिष्ट प्रतिशत से जुड़ी होती है।

- दिशानिर्देशों में **अधिकतम लाभ मार्जिन** निर्धारित किया गया है जो **उर्वरक कंपनियों** के लिए **आयातकों** के लिए **8%, निर्माताओं** के लिए **10%** और **एकीकृत निर्माताओं** के लिए **12%** होगा।
- नए दिशानिर्देश **गैर-यूरिया उर्वरकों** पर **अप्रत्यक्ष MRP नियंत्रण** लगाते हैं, जिससे कंपनियां अपनी बिक्री से जो मुनाफा कमा सकती हैं, उसे सीमित कर दिया जाता है।
- ये उनकी **"बिक्री की कुल लागत"** पर आधारित होगी, जिसमें **उत्पादन/आयात** की लागत**, प्रशासनिक ओवरहेड्स, बिक्री** और **वितरण ओवरहेड्स,** और **शुद्ध ब्याज** और **वित्तपोषण शुल्क** शामिल होंगे।
- **डीलर** के मार्जिन में कटौती **DAP** और **MOP** के लिए **MRP** के 2% और अन्य सभी **NBS** उर्वरकों के लिए **4%** की सीमा तक की अनुमति दी जाएगी।
- दिशानिर्देशों में **उर्वरक कंपनियों** को लागत **लेखा परीक्षक** की रिपोर्ट के साथ-साथ उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित **लेखा परीक्षित लागत डेटा** के आधार पर अनुचित लाभ का **"स्व-मूल्यांकन"** करने का आदेश दिया गया है।
- यह रिपोर्ट और डेटा अगले **वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर** तक **DoF** को प्रस्तुत किया जाना है।
- **"गैर-यूरिया उर्वरक** पहले से ही **अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण** में हैं, जो निश्चित रूप से **लोकसभा चुनाव** खत्म होने तक जारी रहेगा।

173. NIA ने नेशनल टेरर डेटाबेस फ़्यूज़न एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध।

प्रीलिम्स टेकअवे
- टेरर डेटाबेस फ़्यूज़न एंड एनालिसिस सेंटर)NTDFAC)
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी)NIA)

समाचार:
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** ने हाल ही में दिल्ली में अपने **मुख्यालय** में **टेरर डेटाबेस फ़्यूज़न एंड एनालिसिस सेंटर (NTDFAC)** की स्थापना की।

टेरर डेटाबेस फ़्यूज़न एंड एनालिसिस सेंटर (NTDFAC)
- यह केंद्र, **अमेरिकी वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस** के समान, आतंकवादियों के बारे में जानकारी समेकित करता है।
  - जिनमें इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों जैसे समूहों से जुड़े लोग शामिल हैं।
- इसमें केस इतिहास, **उंगलियों के निशान, वीडियो, चित्र** और **सोशल मीडिया प्रोफाइल** शामिल हैं।
- यह बेहतर पहचान के लिए आवाज के नमूनों को शामिल करके अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की कल्पना करता है।
- **NTDFAC में, NIA के पास** -
  - **92 लाख** से **अधिक रिकॉर्ड** के साथ **राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट** पहचान प्रणाली
  - 22,000 आतंकवादी मामलों के डेटा के साथ आतंकवाद की एकीकृत निगरानी
  - **गिरफ्तार नार्को-अपराधियों** पर **राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस** जिसमें **5 लाख** से अधिक **नार्को अपराधियों** आदि का डेटा शामिल है।

अग्रिम प्रणालियाँ
- **NTDFAC** में एक चेहरा **पहचान प्रणाली** शामिल है, जो **CCTV फुटेज** से संदिग्धों की **स्कैनिंग** को सक्षम बनाती है।
- इसका उद्देश्य **आतंकवादियों** की कुशलता से पहचान करने और उनका पता लगाने में **NIA अधिकारियों** और **राज्य पुलिस बलों** की सहायता करना है।

174. EPFO ने "कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने" हेतु नया सर्वेक्षण शुरू किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- EPFO
- LFPR

समाचार:

- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** और **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD)** ने **"कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने"** पर एक **नया सर्वेक्षण शुरू** किया है।

मुख्य बिंदु

- सर्वेक्षण में इस बात पर भी जवाब मांगा गया है कि क्या **पुरुष** और **महिला श्रमिकों** के लिए '**समान काम के लिए समान वेतन**' है, साथ ही **महिलाओं के लिए फ्लेक्सिबल या दूरस्थ कार्य घंटों** की उपलब्धता पर भी सवाल उठाया गया है।
- **EPFO** द्वारा देश भर में अपने लगभग **30 करोड़ ग्राहकों** के साथ **सर्वेक्षण प्रश्नावली** साझा की गई है।
- नियोक्ता **रेटिंग सर्वेक्षण श्रम** और **रोजगार मंत्रालय** और **WCD मंत्रालय** द्वारा "**विकसित** भारत के लिए **कार्यबल में महिलाएं"** कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।
- आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)** में सुधार हुआ है, लेकिन इसमें से अधिकांश वृद्धि अवैतनिक कार्य श्रेणी में देखी गई है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार , **महिला भागीदारी दर** वर्ष 2017-18 में **17.5 प्रतिशत** से बढ़कर वर्ष **2022-23** में **27.8 प्रतिशत** हो गई।
- लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा उन महिलाओं का है जिन्हें "**घरेलू उद्यमों में सहायक**" के रूप में बताया गया है, जिन्हें अपने काम के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है।
- **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी** के अनुसार, महिला LFPR **2017-18** में **11.80 प्रतिशत** से घटकर **वर्ष 2022-23** में **8.73 प्रतिशत** हो गई।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला** LFPR **वर्ष 2017-18** में **12.16 प्रतिशत** से घटकर **वर्ष 2022-23** में **9.68 प्रतिशत** हो गई।
  - जबकि शहरी क्षेत्रों में यह **वर्ष 2017-18** में **11.10 प्रतिशत** से कम होकर **वर्ष 2022-23** में **6.90 प्रतिशत** हो गया।
- वैश्विक स्तर पर, **दक्षिण एशिया क्षेत्र** में **वर्ष 2022** में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर **26 प्रतिशत** थी
  - **विश्व बैंक** के अनुसार **भारत के पड़ोसी देशों** में **महिला LFPR** पंजीकृत है
    - श्रीलंका में 33 प्रतिशत
    - पाकिस्तान में 25 प्रतिशत
    - नेपाल में 29 प्रतिशत
    - बांग्लादेश में 38 प्रतिशत
    - चीन में 61 प्रतिशत

175. दिल्ली HC ने GST के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों को बरकरार रखा - इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

प्रीलिम्स टेकअवे
- इनपुट टैक्स क्रेडिट
- वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST)

समाचार:

- **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** अधिनियम के तहत **मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों** की **संवैधानिक वैधता** को बरकरार रखा।
- हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन, एबॉट, पतंजलि और DLF समेत **100 से ज्यादा कंपनियों** शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

- इसने प्रावधानों के साथ-साथ **राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA)** द्वारा लगाए गए जुर्माने को भी चुनौती दी थी।
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश** और **न्यायमूर्ति** की पीठ ने कहा कि **जीएसटी कानून** एक **"उपभोक्ता-केंद्रित"** लाभकारी कानून है जो कई प्रकार के टैक्स की वसूली को समाप्त करता है।

- आतिथ्य, फास्ट-मूविंग उपभोक्ता सामान और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने जुर्माना लगाने वाले NAA के आदेश को चुनौती दी थी
  - जीएसटी कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों की वैधता और ब्याज के साथ अपने उपभोक्ताओं को टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट की दर में कमी का आनुपातिक लाभ देने में विफल रहने के लिए।
- टैक्स दरों में कमी या निर्माता, आपूर्तिकर्ता या वितरक द्वारा **इनपुट टैक्स क्रेडि**ट की उपलब्धता के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों को अनुचित रूप से बनाए रखने की अनुमति देने के लिए कोई जगह नहीं है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान "**मूल्य-निर्धारण तंत्र**" का गठन नहीं करते हैं।
  - मुनाफाखोरी का पता लगाने के लिए कोई पूर्व निर्धारित या गणितीय फॉर्मूला स्थापित नहीं किया जा सकता है।

176. IVF तकनीक से सफेद गैंडों को विलुप्त होने से बचाया जायेगा - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे
- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)
- सरोगेसी

समाचार:
- वर्ष 2015 में, वैज्ञानिकों के एक **अंतरराष्ट्रीय संघ, बायोरेस्क्यू ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)** के माध्यम से उत्तरी **सफेद गैंडे के पुनर्निर्माण** के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी ।
- हाल ही में, **वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला** में निर्मित भ्रूण को **सरोगेट दक्षिणी सफेद गैंडे** में स्थानांतरित करके पहली बार गैंडे के गर्भधारण की घोषणा की।

उत्तरी सफेद गैंडा
- वर्ष 2018 में आखिरी नर उत्तरी सफेद गैंडे की मौत ने इसके विलुप्त होने को अपरिहार्य बना दिया।
- सींगों के लिए संगठित शिकार के कारण वर्ष 2008 में उत्तरी सफेद गैंडे को आधिकारिक तौर पर जंगल में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

प्रक्रिया में चुनौतियाँ
- बाकी मादाओं की प्रजनन में असमर्थता के कारण सरोगेसी ही एकमात्र विकल्प है।
- **सरोगेट दक्षिणी श्वेत मादा** को तैयार करने में एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें अलगाव और **जीवाणु संक्रमण** से सुरक्षा शामिल है।
- **भ्रूण प्रत्यारोपण** के लिए **उपजाऊ खिड़की** की पहचान करना, जिसे **ऑस्ट्रस** के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

आनुवंशिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ
- **दो मादाओं** के **अंडों** और **मृत चिड़ियाघर** के **नर के शुक्राणु** से सीमित **आनुवंशिक विविधता** एक **व्यवहार्य उत्तरी सफेद** आबादी के लिए चुनौतियां खड़ी करती है।
- संरक्षित ऊतक नमूनों से निकाली गई स्टेम कोशिकाओं से शुक्राणु और अंडे बनाना एक संभावित समाधान है, लेकिन गैंडों में इसकी सफलता अनिश्चित है।

IVF संतानों में व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ
- जबकि **IVF** या **स्टेम सेल प्रौद्योगिकियों** में सफलता से उत्तरी सफेद गैंडे के बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनमें प्रजातियों के रूप में व्यवहार करने के लिए आनुवंशिक कठोरता का अभाव है ।
- भावी पीढ़ियों के लिए **महत्वपूर्ण सामाजिक** और **व्यवहारिक कौशल** सीखने के लिए पहले **IVF बछड़ों** को जीवित **उत्तरी सफेद वयस्कों** द्वारा बड़ा करने की आवश्यकता है।
- जीवित मादाओं के सीमित जीवनकाल के कारण IVF बच्चे पैदा करने की तात्कालिकता पर बल दिया जाता है ।
- **संसाधन आवंटन** के बारे में भी चिंताएं हैं और क्या **परियोजना प्रजातियों** के **प्राकृतिक आवास** के खतरों को संबोधित करती है।

फैक्ट फटाफट

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के कनाडा स्थित सदस्य लखबीर सिंह लांडा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 35 के तहत "व्यक्तिगत आतंकवादी" के रूप में नामित किया है।
- वर्ष 1967 में पारित UAPA का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संगठनों की प्रभावी रोकथाम करना है।
  - गैरकानूनी गतिविधि से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई से है।
- अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है।
- UAPA के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं।
- वर्ष 2004 के संशोधन में आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधों की सूची में "आतंकवादी अधिनियम" जोड़ा गया, जिसके तहत 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- संसद ने अधिनियम में दिए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को भी मंजूरी दे दी।
- अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है।
- यह अधिनियम एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को राज्य में डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी द्वारा किए गए आतंकवाद के मामलों के अलावा आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

2. 16वाँ वित्त आयोग

- नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- वित्त आयोग की निम्न सिफ़ारिशें शामिल होंगी -
  - संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
  - राज्यों के बीच आवंटन
  - भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांत
  - पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य समेकित निधि बढ़ाने के उपाय।
- आयोग को आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण के लिए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
- इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधि का आकलन करना और प्रासंगिक सिफारिशें करना शामिल है।
- उम्मीद है कि वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2026 से पांच साल की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- इस अवधि के दौरान सिफ़ारिशें राजकोषीय नीतियों, संसाधन आवंटन और आपदा प्रतिक्रिया वित्तपोषण को आकार देंगी।

3. राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) लॉन्च किया।
- उद्देश्य: देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन को सुविधाजनक बनाना।
- NTPS की कल्पना "वन नेशन-वन पास" व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी।

- वर्तमान में, राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं।

- यह निर्बाध पारगमन परमिट प्रदान करता है, निजी भूमि, सरकारी स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य परिवहन दोनों के लिए रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है।
- NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति देगा।
- इसे उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें आसान पंजीकरण और परमिट अनुप्रयोगों के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं।
- पारगमन परमिट उन वृक्ष प्रजातियों के लिए जारी किए जाएंगे जो विनियमित हैं, जबकि उपयोगकर्ता छूट प्राप्त प्रजातियों के लिए स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं।
- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

4. भारत का पहला पूर्णतः कन्या सैनिक स्कूल

- रक्षा मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया।
- संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल नामक इस संस्थान को महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है।
- उद्देश्य: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कैरियर के अवसर प्रदान करना।
- स्कूल लगभग 870 छात्रों को समायोजित करता है और CBSE संबद्धता के तहत संचालित होता है।
- प्रशिक्षण पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं।
- यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के उनके अधिकार को मान्यता देते हुए महिलाओं को सशस्त्र बलों में एकीकृत करने की व्यापक दृष्टि को दर्शाता है।
- यह स्कूल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी संस्थाओं और राज्य सरकार के स्कूलों के सहयोग से 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल का एक हिस्सा है।
- रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के चरणबद्ध प्रवेश को मंजूरी दी थी।

5. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

- इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय संपत्तियाँ शामिल हैं।
- यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल है।
- FPI FDI की तुलना में अधिक तरल, अस्थिर और इसलिए जोखिम भरा है।
- किसी अर्थव्यवस्था में परेशानी के पहले संकेत पर भागने की प्रवृत्ति के कारण FPI को अक्सर "हॉट मनी" कहा जाता है।
- यह किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा है और इसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दिखाया जाता है।
- उदाहरण: स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें (ADRs) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (GDRs)।

6. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)

- CBAM "2030 पैकेज में 55 के लिए फिट" का हिस्सा है, जो वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करने की यूरोपीय संघ की योजना है।
- यह एक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हैं।

7. चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
- वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में काम करते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अधिकृत जारीकर्ता है और बांड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
- SBI 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बांड जारी करता है।
- पार्टियों को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा।
- भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा डिजिटल रूप से या चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
- खरीदा गया व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है।
- धारक को मांग पर देय और ब्याज मुक्त।
- जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध।
- नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से।
- राजनीतिक दल प्राप्त धन के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं।
- राजनीतिक दलों की पात्रता
  - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल
  - लोक सभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल करना चाहिए।

8. साल्टन सागर

- अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हाल ही में कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा है।
- साल्टन सागर एक उथली, खारी झील है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के निचले कोलोराडो रेगिस्तान में स्थित है।
- यह पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और समुद्र तल से नीचे स्थित एक भूवैज्ञानिक अवसाद है।
- वह क्षेत्र जो अब झील है, पहले एक नमक से ढका सिंक या अवसाद (प्रागैतिहासिक झील काहुइला का अवशेष) था।
- इसकी लवणता (लगभग 45 भाग प्रति हजार) समुद्री जल से कहीं अधिक है।
- यह प्रवासी जलपक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु है और दक्षिण से मैक्सिको और मध्य अमेरिका की ओर जाने वाले पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।]

9. "न्यायपालिका की स्थिति" रिपोर्ट

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा 'स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।
- मुख्य निष्कर्ष
  - भारत में लगभग पाँचवें (19.7%) जिला अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं।
  - मौजूदा महिला शौचालयों में अक्सर टूटे दरवाजे और अनियमित पानी की आपूर्ति होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं की स्वच्छता और गरिमा से समझौता होता है।
  - कुछ अदालत परिसरों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों के लिए साझा शौचालय हैं।
  - जिला अदालत परिसरों में केवल 6.7% महिला शौचालय सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों से सुसज्जित हैं।
  - अधिकांश जिला अदालतों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से नामित शौचालयों का अभाव है।
  - कुछ मामलों में न्यायाधीश शौचालयों की सफ़ाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सफ़ाईकर्मियों और सफ़ाईकर्मियों को नियुक्त करते हैं।

10. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन

- यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "डेजर्ट साइक्लोन 2024" का उद्घाटन संस्करण है।
- यह राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा
- इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

11. सरना धर्म

- मध्य भारत में आदिवासी संस्कृति, वन संरक्षण और जंगल की आग पर आईआईटी इंदौर का एक हालिया अध्ययन सरना धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है।
- छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से स्वदेशी धार्मिक आस्था का पालन किया जाता है।
- मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के आदिवासी बेल्ट राज्यों में केंद्रित है।
- सरना मत के अनुयायी प्रकृति पूजक हैं।
- सरना आस्था का पवित्र आधार है - जल, जंगल, ज़मीन ।
- इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों से प्रार्थना करते हैं।
- सरना धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते, न ही वे वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग-नर्क आदि की अवधारणा का पालन करते हैं।
- महत्वपूर्ण त्यौहार: सरहुल, करम, फग्गू

12. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

- NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री के समन्वय से विकसित किया गया है।
- डेटा को कनेक्टेड जिला और तालुका अदालतों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है।
- राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP) के अनुरूप, NJDG केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, संस्था, लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़ों तक पहुंच सकता है।

13. मनरेगा योजना

- मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना है।
- यदि किसी ग्रामीण वयस्क को काम मांगने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिल पाता है तो 'बेरोजगारी भत्ता' दिया जाता है।
- अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कार्यों की अनुशंसा करने का आदेश देता है जो किए जाने हैं और कम से कम 50% कार्यों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए।
- मनरेगा कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लागत का 60% केंद्र वहन करता है और शेष 40% राज्य सरकारें प्रदान करती हैं।

14. साइबर किडनैपिंग

- यह एक ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जहां 'अपहरणकर्ता' अपने शिकार को छिपने के लिए मना लेते हैं, और फिर फिरौती के लिए अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं।
- पीड़ित को तस्वीरें भेजने के लिए भी कहा जाता है जिससे ऐसा लगे कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है या उनका मुंह बंद कर दिया गया है।
- दोनों पक्षों का मानना है कि यदि वे अपहरणकर्ताओं के कहे अनुसार नहीं करेंगे तो उनके प्रियजनों को नुकसान होगा।
- 'अपहरणकर्ता', हालांकि शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, वीडियो-कॉल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पीड़ित की ऑनलाइन निगरानी करते हैं।

15. भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC)

- भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वैज्ञानिक संगठन है जिसकी सालाना बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में होती है।
- इसकी स्थापना 1914 में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
- यह न केवल प्रमुख संस्थानों और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बल्कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी एक साथ लाता है।
- यह विज्ञान से संबंधित मामलों पर छात्रों और आम जनता के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA) आधिकारिक निकाय है जो इस कार्यक्रम का आयोजन करता है।
  - ISCA, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पेशेवर निकाय है।

16. हट्टी समुदाय

- हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी की।
- वे एक घनिष्ठ समुदाय हैं जिनका नाम कस्बों में 'हाट' कहे जाने वाले छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसलें, मांस और ऊन आदि बेचने की उनकी परंपरा से मिला है।
- उनकी मातृभूमि गिरी और टोंस नदियों (यमुना की सहायक नदियाँ) के बेसिन में हिमाचल-उत्तराखंड सीमा तक फैली हुई है।
- ट्रांस-गिरि और जौनसार बावर में दो हाटी कुलों की परंपराएं समान हैं और अंतर-विवाह आम हैं।
- वर्ष 1815 में जौनसार बावर के अलग होने तक हाटी एक समय सिरमौर की शाही संपत्ति का हिस्सा थे।
- वे खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होते हैं।
- इस समुदाय के पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।

17. नरसंहार कन्वेंशन 1948

- हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका ने एक तत्काल आदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया, जिसमें घोषणा की गई कि इज़राइल 1948 के नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।
- 'नरसंहार' शब्द को नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके परिभाषित किया गया है।
- नरसंहार का अर्थ है किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कार्य, जैसे कि
  - समूह के सदस्यों को मारना
  - समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना
  - जान-बूझकर समूह पर जीवन की ऐसी स्थितियाँ थोपना जिससे उसका संपूर्ण या आंशिक भौतिक विनाश हो सके
  - समूह के भीतर जन्मों को रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

- समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना
- इस सम्मेलन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है चाहे वह युद्धकाल में किया गया हो या शांतिकाल में।
- भारत ने वर्ष 1959 में इस सम्मेलन का अनुमोदन किया; लेकिन इस विषय पर कोई कानून नहीं है।

18. कर्मन रेखा

- समुद्र तल से 100 किमी (62 मील) ऊपर स्थित, यह एक काल्पनिक रेखा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल का सीमांकन करती है।
- इसकी स्थापना 1960 के दशक में फेडरेशन एयरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI) नामक एक रिकॉर्ड-कीपिंग संस्था द्वारा की गई थी।
- यह इस अर्थ में भौतिक वास्तविकता पर आधारित है कि यह मोटे तौर पर उस ऊंचाई को चिह्नित करता है जहां पारंपरिक विमान अब प्रभावी ढंग से उड़ान नहीं भर सकते हैं।
- कर्मन रेखा के ऊपर यात्रा करने वाली किसी भी चीज़ को एक प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उत्पन्न लिफ्ट पर निर्भर नहीं होती है।
- जो कोई भी इस रेखा को पार करता है वह अंतरिक्ष यात्री के रूप में योग्य हो जाता है।
- महत्व
  - वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि कहती है कि अंतरिक्ष सभी देशों के लिए सुलभ होना चाहिए और इसकी स्वतंत्र और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सकती है।
  - क्या और कहाँ स्थान की कानूनी सीमा निर्धारित करने से विवादों से बचने और अंतरिक्ष गतिविधियों और मानव अंतरिक्ष यात्रा पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है।

19. वीवीपैट (VVPAT) मशीनें

- वीवीपीएटी (VVPAT) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट सटीक रूप से दर्ज किया गया है।
- जैसे ही मतदाता EVM पर बटन दबाता है, वीवीपीएटी (VVPAT) मशीन लगभग 7 सेकंड के लिए उस पर्ची को प्रिंट करती है जिसमें उस पार्टी का नाम और प्रतीक होता है जिसे उन्होंने वोट दिया है।
- पारदर्शिता बढ़ाने और EVM की सटीकता के बारे में संदेह को खत्म करने के लिए उन्हें पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत में पेश किया गया था।
- वीवीपीएटी (VVPAT) मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुंच सकते हैं।
- ईसीआई के अनुसार, EVM और वीवीपीएटी (VVPAT) अलग-अलग इकाइयां हैं और किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं हैं।

20. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- I4C के एक विश्लेषण के अनुसार, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) धोखाधड़ी उन साइबर वित्तीय घोटालों का 11% थी जिनकी उत्पत्ति 2023 में भारत में हुई थी।
- I4C देश में साइबर अपराध से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक पहल है।
- अक्टूबर 2018 में स्वीकृत, यह साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- I4C के कार्य
  - एलईए की अनुसंधान समस्याओं/जरूरतों की पहचान करें और नई प्रौद्योगिकियों और फोरेंसिक उपकरणों के विकास में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां शुरू करें।
  - चरमपंथी और आतंकवादी समूहों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए साइबरस्पेस के दुरुपयोग को रोकें
  - तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए साइबर कानूनों में यदि आवश्यक हो तो संशोधन का सुझाव दें

- गृह मंत्रालय में संबंधित नोडल प्राधिकारी के परामर्श से साइबर अपराध से संबंधित अन्य देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करना।

21. शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्यधारा में लाने का दायरा (स्मार्ट) 2.0 कार्यक्रम

- सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) के साथ मिलकर हाल ही में 'SMART 2.0' प्रोग्राम लॉन्च किया है।
- यह कार्यक्रम आपसी सहयोग के माध्यम से देश भर में आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों/अस्पतालों के साथ आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देता है।
- उद्देश्य: अंतःविषय अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुवाद करने के लिए ठोस सबूत उत्पन्न करना।
- अध्ययन का उद्देश्य बाल कासा, कुपोषण, अपर्याप्त स्तनपान, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, रजोनिवृत्त महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और मधुमेह मेलिटस (डीएम) II के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में सुरक्षा, सहनशीलता और आयुर्वेद फॉर्मूलेशन का पालन करना है।

22. स्वदेश दर्शन 2.0 योजना

- पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- उद्देश्य: देश में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना।
- योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है।
- पर्यटन मंत्रालय ने सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना (स्वदेश दर्शन 2.0) को नया रूप दिया है।
- स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि की परिकल्पना है।

23. प्रोजेक्ट चीता

- चीता को भारत वापस लाने की चर्चा 2009 में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई थी।
- 'भारत में चीता के पुनरुत्पादन के लिए कार्य योजना' के तहत, 5 वर्षों में अफ्रीकी देशों से 50 चीतों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में लाया जाएगा।
- सबसे उपयुक्त स्थल: अपने उपयुक्त आवास और पर्याप्त शिकार आधार के कारण मध्य प्रदेश में कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी)।
- कुनो भारत की चार बड़ी बिल्लियों को आश्रय देने की संभावना भी प्रदान करता है। बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता, उन्हें अतीत की तरह सह-अस्तित्व में सक्षम बनाते हैं।
- इस परियोजना के हिस्से के रूप में, 20 चीतों (8 नामीबिया से और 12 दक्षिण अफ्रीका से) को केएनपी में (पिछले साल से) पेश किया गया था ताकि 70 साल पहले भारत में उनके विलुप्त होने के बाद पहली बार एक स्वतंत्र आबादी स्थापित की जा सके।

24. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART)

- ART मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अंडे की कोशिकाओं को संभालकर और महिला के प्रजनन पथ में भ्रूण को स्थानांतरित करके गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है।

- यह भारत में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (विनियमन) अधिनियम 2021 द्वारा विनियमित है।
- भारत में ART को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- ART क्लीनिकों की मान्यता, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश 2005 में स्थापित किए गए थे।
- ART में शुक्राणु दान, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), और गर्भकालीन सरोगेसी सहित विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- इसमें निषेचन और भ्रूण के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोगशाला सेटिंग में शुक्राणु और अंडे की कोशिकाओं को संभालना शामिल है।

25. वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली

- वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली को मंजूरी दी।
- यह उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।
- यह शहरी और उपनगरीय वातावरण में आर्द्रभूमियों के महत्व को भी पहचानता है और इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करता है।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी और पेरी-शहरी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय आबादी के लिए स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ भी है।

26. पॉलीगोनम चतुर्भुजनम

- हाल ही में, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व (PTR) के गोल पहाड़ी द्वीप पर पॉलीगोनम जीनस की एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है।
- पॉलीगोनम चतुर्भुजनम नाम की नई पौधे की प्रजाति एक जड़ी बूटी है।
- पेंच में भारत की स्थानिक छह पौधों की प्रजातियाँ भी पाई गई हैं।
- वे हैं एजिनेटा इंडिका, बोएरहविया क्रिस्पा, हेबेनेरिया गिब्सोनी वेर फोएटिडा, इफिजेनिया पलिडा, पेटालिडियम बारलेरियोइड्स और बारलेरिया गिब्सोनि।

27. सिमिलिपाल काई चटनी

- हाल ही में, ओडिशा के मयूरभंज जिले (ओडिशा) के आदिवासी लोगों द्वारा लाल वीवर चींटियों से बनाई गई सिमिलिपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ।
- मसालेदार चटनी अपने उपचार गुणों के लिए मयूरभंज क्षेत्र में लोकप्रिय है और आदिवासी लोगों की पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
- मयूरभंज जिले के कई स्वदेशी लोग काई पिंपुडी (लाल वीवर चींटी) इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में जाते हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाएं
  - वैज्ञानिकों ने लाल वीवर चींटियों का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें मूल्यवान प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B -12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड आदि शामिल हैं।
  - प्रजातियों के सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।
  - आदिवासी चिकित्सक एक औषधीय तेल भी तैयार करते हैं जिसमें वे शुद्ध सरसों के तेल के साथ चींटियों को डुबाते हैं जिसका उपयोग शिशुओं के शरीर के तेल के रूप में और जनजातियों द्वारा गठिया, गठिया, दाद और अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
  - स्थानीय लोग फिट और ताकतवर रहने के लिए भी इसका सेवन करते हैं।

28. पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता

- विशेषज्ञों के एक समूह ने IUCN से पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता की स्थिति को 'असुरक्षित' से 'लुप्तप्राय' श्रेणी में पुन: वर्गीकृत करने की अपील की है।
- पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता, जिसे सूडान चीता के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका के हॉर्न में पाया जाता है।

- यह उप-प्रजाति सहारन चीता आबादी की तुलना में दक्षिणी अफ्रीकी चीता से अधिक निकटता से संबंधित है।
- चीते की लंबी पूंछ उसे पीछा करने के बीच में दिशा बदलते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। स्वरूप: पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता काफी बड़ा होता है। शारीरिक रूप से, यह पूर्वी अफ्रीकी चीते जैसा दिखता है।
- वितरण: दक्षिण सूडान और इथियोपिया; विस्तृत खुली भूमि, घास के मैदानों, अर्ध-शुष्क क्षेत्रों और अन्य खुले आवासों में रहते हैं जहाँ शिकार प्रचुर मात्रा में होता है जैसे कि पूर्वी सूडानी सवाना में।
- उप-प्रजाति के शावकों की लाल सागर के पार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे अरब देशों में भारी तस्करी की जा रही है।
- IUCN स्थिति: असुरक्षित

29. आईएनएस चेन्नई

- यह भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है।
- यह कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (प्रोजेक्ट 15A) का तीसरा और आखिरी जहाज है।
- इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया था।
- इसे 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- इसकी लंबाई 163 मीटर है और इसका बीम 17.4 मीटर है।
- विस्थापन: 7,500 टन से अधिक।
- शीर्ष गति: 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी/घंटा)
- यह चार प्रतिवर्ती गैस टरबाइन इंजनों द्वारा संचालित है।
- इसमें 350 से 400 लोग सवार हो सकते हैं।
- आयुध: यह वर्टिकल लॉन्च और लंबी दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों जैसे सुपरसोनिक ब्रह्मोस, 'बराक -8' लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है।

30. पृथ्वी पहल

- यह पृथ्वी और इसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक पहल है।
- 2021-26 की अवधि के लिए 4,797 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस व्यापक पहल का उद्देश्य मौसम, जलवायु, महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान, मॉडलिंग और सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।
- पृथ्वी योजना पांच मौजूदा उप-योजनाओं को एकीकृत करती है:
  - वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (ACROSS)
  - महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (O-SMART)
  - ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (PACER)
  - भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान (SAGE)
  - अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (REACHOUT)।

31. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

- हाल ही में, भारत में जीएसटी अधिकारियों ने अक्टूबर-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान लगभग 12,036 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की संदिग्ध चोरी में लगी 4,153 फर्जी फर्मों की पहचान की है।
- फर्जी फर्मों की संख्या और संदिग्ध कर चोरी की मात्रा के मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली सूची में शीर्ष पर हैं।
- जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
- उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन सामान और सेवाएँ बेचने वाले व्यवसायों द्वारा इसे सरकार को भेजा जाता है।

- वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू।
- मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित।
- भारत में दोहरा जीएसटी है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाते हैं।
- वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाता है और लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधीन होता है।
- जीएसटी दरों पर केंद्र और राज्य परस्पर सहमत हैं।
- दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाती हैं।

32. कारगिल एएलजी पर नाईट लैंडिंग

- भारतीय वायु सेना (IAF) C-130I ALG सुपर हरक्यूलिस सामरिक परिवहन विमान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित कारगिल हवाई पट्टी पर नाईट लैंडिंग की।
- यह उपलब्धि कारगिल में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) पर पहली रात्रि लैंडिंग का प्रतीक है और इसमें गरुड़ विशेष बलों की एक टीम शामिल थी।
    - कारगिल ALG लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें उबड़-खाबड़ इलाकों से घिरी यूनिडायरेक्शनल दृष्टिकोण वाली एक प्रतिबंधित हवाई पट्टी है।
- लैंडिंग ने चुनौतीपूर्ण इलाकों में चौबीसों घंटे विशेष मिशनों को क्रियान्वित करने की बढ़ी हुई क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- व्यापक क्षेत्र में, भारतीय वायु सेना ने श्रीनगर, अवंतीपोरा, उधमपुर, जम्मू, लेह, थोइस, न्योमा, फुकचे और दौलत बेग ओल्डी (DBO) सहित विभिन्न स्थानों पर हवाई क्षेत्र स्थापित किए हैं।
- रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीमा के करीब उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (ALG) को उन्नत और संचालित करने की परियोजनाएं शुरू की हैं।

33. प्रोजेक्ट वीर गाथा

- यह वर्ष 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल (GAP) के तहत स्थापित रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
- उद्देश्य: देशभक्ति की भावना बढ़ाने और नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित करने के लिए छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों का विवरण प्रसारित करना।
- यह स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक परियोजनाओं/गतिविधियों को करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इसके हिस्से के रूप में, छात्र इन वीरता पुरस्कार विजेताओं पर कला, कविताएं, निबंध और मल्टीमीडिया जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं तैयार करते हैं।
- सर्वोत्तम परियोजनाओं को रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

34. सोहराई पेंटिंग

- हाल ही में, बंगाल के एक गांव ने अपने नए साल की शुरुआत प्राचीन स्वदेशी कला यानी सोहराई पेंटिंग पर कार्यशाला के साथ की है।
- यह एक स्वदेशी भित्ति कला है जो मेसो-ताम्रपाषाण काल (9000-5000 ईसा पूर्व) की है।
- थीम: ब्रह्मांड के प्राकृतिक तत्व जिसमें जंगल, नदियाँ, जानवर और अन्य शामिल हैं।
- ये प्राचीन पेंटिंग आदिवासी महिलाओं द्वारा लकड़ी का कोयला, मिट्टी या मिट्टी जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाती हैं।
- सोहराई कला का सबसे आदिम रूप गुफा चित्रों के रूप में था।
- यह विशेष रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्वदेशी समुदायों द्वारा अभ्यास किया जाता है।

- झारखंड के हज़ारीबाग़ क्षेत्र को इस कला के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
- यह कुर्मी, संथाल, मुंडा, उराँव, अगरिया, घटवाल जनजातियों की महिलाओं की कला है।
- सोहराई पेंटिंग अपने जीवंत रंगों, जटिल पैटर्न और प्रतीकात्मक रूपांकनों के लिए विशिष्ट हैं;
- कटाई के मौसम और सर्दियों के आगमन को चिह्नित करते हुए, हर साल सोहराई त्योहार आयोजित किया जाता है।

35. चंद्रा एक्स-रे वेधशाला

- चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने हाल ही में 30 डोरैडस B की एक आश्चर्यजनक छवि खींची।
  - यह एक सुपरनोवा अवशेष है जो अंतरिक्ष के एक जीवंत क्षेत्र का हिस्सा है जहां लाखों वर्षों से तारे बन रहे हैं।
- इसे नासा द्वारा 23 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक दूरबीन है जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड के बहुत गर्म क्षेत्रों, जैसे विस्फोटित तारे, आकाशगंगाओं के समूह और ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ से एक्स-रे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- क्योंकि एक्स-रे पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित होते हैं, चंद्र को अंतरिक्ष में 139,000 किमी (86,500 मील) की ऊंचाई तक, इसके ऊपर परिक्रमा करनी चाहिए।

36. इंद्रायणी नदी

- यह भीमा नदी की एक सहायक नदी है, जो कृष्णा नदी की भी एक सहायक नदी है।
- इसका उद्गम महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में एक हिल स्टेशन लोनावाला के पास कुरवंडे गांव से होता है।
- वर्षा से पोषित होकर, यह वहां से पूर्व की ओर बहती हुई भीमा नदी में मिलती है।
- यह मुख्यतः पुणे शहर के उत्तर में एक मार्ग का अनुसरण करता है।
- इस नदी का बहुत धार्मिक महत्व है और दो पवित्र शहर आलंदी और देहू इसके तट पर स्थित हैं।
  - देहू को कवि संत तुकाराम का गृहनगर होने के कारण एक पवित्र स्थान माना जाता है, जो महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय संत थे।
  - अलंदी के पास कवि ज्ञानेश्वर की समाधि है।
- इंद्रायणी नदी पर स्थित कामशेत में वलवन बांध एक जलविद्युत उत्पादन केंद्र है।

37. पलास फिश ईगल

- 10 वर्षों के बाद, चिल्का वन्यजीव प्रभाग द्वारा की गई पक्षी गणना के दौरान हाल ही में पलास फिश ईगल को चिल्का में देखा गया।
- पलास समुद्री ईगल या बैंड-टेल्ड फिश ईगल के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बड़ा, भूरे रंग का समुद्री ईगल है।
- इसे झीलों, दलदलों और बड़ी नदियों के पास, निचले इलाकों से लेकर 5,000 मीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है।
- यह आंशिक रूप से प्रवासी है और मुख्य रूप से मछली खाता है।
- यह आमतौर पर पानी के पास एक ऊंचे पेड़ पर बने बड़े घोंसले में प्रजनन करता है।
- यह कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के पूर्वी पेलेरक्टिक में पाया जाता है।
- IUCN स्थिति: लुप्तप्राय
- मनुष्य निवास स्थान के क्षरण, प्रदूषण और झीलों के जल निकासी या अत्यधिक मछली पकड़ने के माध्यम से इस प्रजाति के पतन में योगदान करते हैं।

38. तंजावुर डॉल

- तंजावुर डॉल को श्रमिकों की गंभीर कमी और मिट्टी की कमी के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- इस शिल्प को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा शासक राजा सर्फ़ोजी द्वारा तंजावुर लाया गया था।

- तंजावुर डॉल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक बॉबल-हेड संस्करण है, और दूसरी झुकी हुई डॉल संस्करण है।
- प्रयुक्त सामग्रियाँ
  - डॉल -निर्माता शरीर के लिए पपीयर-मैचे, POP और अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं।
  - गुड़ियों के आसन बनाने के लिए वंदल मन (पानी की तेज़ धाराओं द्वारा जमा की गई महीन गाद), काली मन (नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी) और मनल (ढीला समुच्चय) के मिश्रण की आवश्यकता होती है।
  - कॉपर सल्फेट पाउडर को कवकनाशी के रूप में मिलाया जाता है।
- डांसिंग डॉल में चार खंड होते हैं, प्रत्येक आंतरिक धातु लूप हुक की मदद से दूसरे पर संतुलन बनाता है जो हल्की बॉबिंग मूवमेंट बनाता है।
- इसने वर्ष 2009 में भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया था ।

39. प्रथम अग्रिम अनुमान

- पहले अग्रिम अनुमान (FAE) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2023-24) में भारत की जीडीपी 7.3% बढ़ेगी।
- FAE हर साल जनवरी के पहले सप्ताह के अंत में प्रस्तुत किया जाता है और यह उस वित्तीय वर्ष के लिए विकास का पहला अनुमान है।
  - फरवरी के अंत तक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) दूसरा अग्रिम अनुमान जारी करता है और मई के अंत तक, अनंतिम अनुमान जारी करता है।
- FAE पहले 7 महीनों में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आधारित है, और वार्षिक तस्वीर पर पहुंचने के लिए डेटा का अनुमान लगाया जाता है।
- वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट (जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है) को अंतिम रूप दिए जाने से पहले जारी किए गए अंतिम जीडीपी आंकड़े हैं।
- इस प्रकार, FAE बजट संख्याओं का आधार बनते हैं।
- इस साल के FAE कुछ अतिरिक्त महत्व रखते हैं क्योंकि वे वर्तमान सरकार के 10 वर्षों में आर्थिक विकास की पहली पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं।

40. ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य

- यह पश्चिम कामेंग जिले, अरुणाचल प्रदेश की हिमालय तलहटी में भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है।
- यह उत्तर-पूर्व में सेसा ऑर्किड अभयारण्य और पूर्व में कामेंग नदी के पार पाखुई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है।
- यह पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है और 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है।
- यह कामेंग हाथी रिजर्व का भी एक हिस्सा है।
- प्रजातियों की असाधारण विविधता, संख्या और पहुंच के कारण यह एक प्रमुख पक्षी विहार स्थल के रूप में उल्लेखनीय है।
- इसका नाम भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन से लिया गया है जो वर्ष 1950 के दशक में इस क्षेत्र में तैनात था।
- वनस्पति: समशीतोष्ण बादल वन घने बांस के टुकड़ों और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन के साथ एक विस्तृत ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिश्रित होते हैं, जिनमें उच्च ऊंचाई पर शंकुधारी और रोडोडेंड्रोन होते हैं।
- जीव-जंतु: कैप्ड लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, लाल पांडा, एशियाई काला भालू, अरुणाचल मकाक और गौर।

41. बोब्बिली वीणा

- यह बोब्बिली की एक पारंपरिक 'सरस्वती वीणा' है और अपनी बेहतरीन धुन और विशिष्ट नोट्स के लिए प्रसिद्ध है।
- यह कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा तार वाला वाद्य यंत्र है।
- वीणा का निर्माण 17वीं शताब्दी में बोब्बिली संस्थानम के राजा पेद्दा रायडू के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, जो संगीत के महान संरक्षक थे।
- ये वीणाएं बोब्बिली (आंध्र प्रदेश) के एक शहर गोलापल्ली में जैक-वुड पेड़ के लॉग से तैयार की गई हैं।

- जैक-वुड को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह हल्का होता है और लकड़ी का अनोखा दाना स्वर या टोन की गुणवत्ता प्रदान करता है।
- इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े का उपयोग किया जाता है, जिसे 'एकंदी वीणा' नाम दिया गया है।
- 17वीं शताब्दी में अपनी उत्पत्ति के साथ, इन वीणाओं को एक विशिष्ट शैली में बजाया जाता है, जिससे 'बोब्बिली वीणा संप्रदाय' का सिक्का भी चला।
- इसने अपने अद्वितीय डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल के लिए वर्ष 2012 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग अर्जित किया।

42. आईडेक्स (iDEX) योजना

- यह वर्ष 2018 में शुरू की गई भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, MSME, इनक्यूबेटर्स और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- आईडेक्स (iDEX) भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस में भविष्य में अपनाने की महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करता है।
- यह वर्तमान में लगभग 400+ स्टार्टअप और MSME के साथ जुड़ा हुआ है।
- इसे रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गेम-चेंजर के रूप में मान्यता प्राप्त है, iDEX को रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए पीएम पुरस्कार मिला है।
- फंडिंग: इसे 'डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO)' द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसे दो संस्थापक सदस्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 'लाभकारी नहीं' कंपनी के रूप में बनाया गया है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs) - HAL और BEL।

43. ट्राइकोडर्मा

- 'ट्राइकोलिम' नाम का फॉर्मूलेशन, ट्राइकोडर्मा और चूने को एक ही उत्पाद में एकीकृत करता है, जिससे किसानों के लिए इसका उपयोग आसान हो जाता है।
- ट्राइकोडर्मा एक फंगल बायोकंट्रोल एजेंट है, जो कई मिट्टी-जनित पौधों के रोगजनकों को दबाने में प्रभावी साबित हुआ है और फसल उत्पादन में एक सफल जैव-कीटनाशक और जैव-उर्वरक के रूप में कार्य करता है।
- ट्राइकोडर्मा के महत्व और पारंपरिक चूने के अनुप्रयोगों से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानते हुए, IISR के वैज्ञानिकों ने चूने और ट्राइकोडर्मा को एकीकृत करने के लिए 'ट्राइचोलिम' विकसित किया।

44. भौगोलिक संकेत (GI) टैग

- यह उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- इसका उपयोग आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन और स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
- वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है

45. कारावास सजा में क्षमादान

- जेल एक राज्य सूची का विषय है, प्रत्येक राज्य में जेल के नियम छूट को नियंत्रित करते हैं, जहां कैदी सुधारात्मक और पुनर्वास गतिविधियों के माध्यम से अपनी सजा से कुछ दिन की छूट पा सकते हैं।

- विशेष रूप से आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को सजा माफी के पात्र बनने से पहले कम से कम 14 साल की सजा काटनी होगी।
- हालाँकि, छूट के लिए आवेदन करना इसकी मंजूरी की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि प्रत्येक मामले पर एक समिति द्वारा व्यक्तिगत विचार किया जाता है।
- समिति लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (वर्ष 2000) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लिखित कारकों का आकलन करती है।
    - इनमें अपराध की प्रकृति, दोबारा अपराध करने की संभावना, दोषी की आपराधिक गतिविधि की क्षमता, निरंतर कारावास का उद्देश्य और दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ शामिल हैं।
- ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (वर्ष 2006) एससी निर्णय: यह केवल गलत इरादों, अप्रासंगिक कारकों पर विचार करने या मनमानी के मामलों में छूट के आदेशों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है।

46. चंदूबी महोत्सव

- यह हर साल नए साल के पहले दिन से चंदुबी झील के किनारे पांच दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो असम राज्य में स्थित है।
- उद्देश्य: असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना।
- जलाशय का संरक्षण, जिसका जल स्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कम हो रहा है, हर साल उत्सव आयोजित करने का मकसद रहा है।
- यह त्यौहार विभिन्न जनजातियों जैसे राभा, गारो, गोरखा और चाय जनजातियों को आजीविका उत्पन्न करने का अवसर प्रदान कर रहा है।
- चंदुबी उत्सव का मुख्य आकर्षण स्थानीय लोक संस्कृति, जातीय व्यंजन, स्थानीय हथकरघा और पोशाक, नौका विहार आदि हैं।

47. सिसल पौधा

- हाल ही में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध टीम ने सिसल-आधारित सामग्री की अवशोषण क्षमता को वाणिज्यिक मासिक धर्म पैड की तुलना में अधिक पाया है।
- सिसल पौधा एक जेरोफाइटिक, मोनोकार्प, अर्ध-बारहमासी पत्ती फाइबर उत्पादक पौधा है।
- पत्तियाँ मोटी, मांसल होती हैं और अक्सर मोमी परत से ढकी होती हैं, जो जेरोफाइटिक पौधों की विशिष्ट विशेषता है।
- इसका प्रसार मुख्यतः वानस्पतिक साधनों जैसे 'बल्बिल्स' और 'सकर्स' द्वारा किया जाता है।
- यह शुष्क वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है क्योंकि यह प्रजाति प्रकृति में जेरोफाइटिक है।
- यह अधिकतम तापमान 40-45°C सहन कर सकता है और 60-125 सेमी की समान रूप से वितरित वर्षा के साथ अच्छी तरह से बढ़ता है।
- यह अच्छी मात्रा में चूना सामग्री (Ca और Mg) के साथ सूखी, पारगम्य, रेतीली-दोमट मिट्टी पर सबसे अच्छा पनपता है।
- भारत में इसे अच्छी जल निकासी वाली हल्की चूनायुक्त और कंकरीली मिट्टी में उगाया जाता है।
- यह मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग और कई दक्षिणी राज्यों में अच्छी तरह से अनुकूलित है।

48. अग्निपथ योजना

- यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।
- इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। युवा कम अवधि के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे।

- नई योजना के तहत, सालाना लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, और अधिकांश केवल चार वर्षों में सेवा छोड़ देंगे।
- हालाँकि, चार वर्षों के बाद, बैच के केवल 25% को 15 वर्षों की अवधि के लिए, उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।

49. अलीगढ आंदोलन

- यह एक प्रणालीगत आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार करना था।
- इस आंदोलन ने केवल पारंपरिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंग्रेजी को सीखने और पश्चिमी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाकर मुस्लिम शिक्षा को आधुनिक बनाने का काम किया।
- सर सैयद ने मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार करने के लिए पश्चिमी कार्यों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए वर्ष 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की।
- सर सैयद द्वारा प्रकाशित पत्रिका, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, साइंटिफिक सोसाइटी का एक अंग था

50. कॉकस सिस्टम

- आयोवा राज्य 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि रिपब्लिकन कॉकस के लिए इकट्ठा होते हैं, जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनने में पहला कदम है। कॉकस एक अनूठी प्रक्रिया है जहां मतदाता पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं।
- प्राइमरीज़ के विपरीत, कॉकस की देखरेख राज्य पार्टी द्वारा की जाती है, न कि सरकार द्वारा, और इसमें पारंपरिक मतदान स्थल शामिल नहीं होते हैं।
- आयोवा में रिपब्लिकन स्थानीय स्थानों पर छोटे समूहों में जुटेंगे, जहां प्रतिनिधि भाषणों के माध्यम से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की वकालत करेंगे।
- वोट गुप्त मतपत्रों के माध्यम से डाले जाते हैं, और परिणाम काउंटी सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों के चयन का निर्धारण करते हैं।
- अंतिम परिणाम राज्य पार्टी को सूचित किए जाते हैं, और परिणाम आम तौर पर कुछ घंटों के भीतर घोषित किए जाते हैं

51. कोहरा

- कोहरा मौसम की एक आम घटना है, जिसमें वाष्पीकृत पानी के ठंडा होने और संघनित होने पर पानी की छोटी-छोटी बूंदें बनती हैं।
- यह तब होता है जब जमीन और हवा के बीच तापमान में असमानता होती है, जो भारतीय सर्दियों के दौरान आम है।
- कोहरे का निर्माण कम तापमान, उच्च आर्द्रता और सतह के पास प्रचुर मात्रा में नमी की उपस्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होता है।
- कोहरे के निर्माण में योगदान देने वाले दो प्राथमिक तंत्र अवरक्त शीतलन और विकिरण कोहरा हैं।
- उत्तरी भारत सहित संपूर्ण सिन्धु-गंगा के मैदानी इलाकों में विशिष्ट परिस्थितियों के कारण सर्दी के मौसम में कोहरे का खतरा रहता है।
- कम तापमान, कम हवा की गति, नमी की उपलब्धता और एरोसोल की उच्च सांद्रता क्षेत्र में कोहरे के निर्माण में योगदान करती है।
- पश्चिमी विक्षोभ या अरब सागर से नमी का प्रवेश हो सकता है, जिससे कोहरे का निर्माण और बढ़ सकता है।

52. प्रसादम्

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन, महाकाल लोक में 'प्रसादम' का उद्घाटन किया।

- प्रसादम देश की पहली "स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट" है।
- यह देश के हर कोने में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा।
- यह प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 1-1.5 लाख भक्तों के लिए सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है।
- फूड स्ट्रीट को बच्चों के खेल क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

53. स्काई ड्यू

- हाल ही में, हिज़्बुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर इज़राइल ने लेबनानी सीमा पर स्काई ड्यू को तैनात किया था।
- स्काई ड्यू फूले हुए विमान के आकार की एक विशाल गुब्बारे जैसी संरचना है।
- उच्च ऊंचाई वाला अवलोकन गुब्बारा छोटे मानवरहित विमानों और क्रूज मिसाइलों के लिए एक डिटेक्शन रडार ब्लिप के रूप में कार्य करता है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ख़तरे की चेतावनी देने वाली प्रणालियों में से एक है।
- यह परियोजना पूरी तरह से अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित थी।
- गुब्बारे पर लगा रडार 250 किमी की दूरी से निरीक्षण करने और कम ऊंचाई वाले और घाटियों सहित कई लक्ष्यों पर नज़र रखने में सक्षम है।
- यह ईंधन या चालक दल के प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बिना विस्तारित अवधि तक निगरानी में रहने की अपनी क्षमता में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

54. उग्रम

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में 'उग्रम' नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है।
- इसे एक निजी उद्योग भागीदार के सहयोग से DRDOकी एक इकाई, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (GSQR) के अनुसार 100 दिनों से भी कम समय में विकसित किया गया था।

55. दृष्टि 10 'स्टारलाइनर'

- नौसेना प्रमुख ने हाल ही में नौसेना के लिए पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 'स्टारलाइनर' मानव रहित हवाई वाहन (UAV) को हरी झंडी दिखाई।
- यह 36 घंटे की सहनशक्ति और 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला एक उन्नत खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) प्लेटफॉर्म है।
- यह हर मौसम में काम करने वाला सैन्य प्लेटफॉर्म है जिसे अलग और अलग दोनों तरह के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की मंजूरी है।
- UAV की स्वायत्त प्रकृति, इसके मिशन प्रभावशीलता और पेलोड कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों के साथ मिलकर, इसे रणनीतिक संचालन के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है।
- इसकी न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताएं इसे लागत प्रभावी और परिचालन रूप से कुशल बनाती हैं।
  - यह बढ़ी हुई परिचालन तत्परता, डाउनटाइम को कम करने और तैनाती के अवसरों को अधिकतम करना सुनिश्चित करता है।
- यह उन्नत संचार प्रणालियों से सुसज्जित है, जिसमें उपग्रह संचार और लाइन-ऑफ-साइट (LOS) डेटा लिंक शामिल हैं, जो विश्वसनीय और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करते हैं।

56. गणतंत्र दिवस की झाँकियाँ

- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने एक रोलओवर योजना का प्रस्ताव दिया है, जहां प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए तीन साल के भीतर अवसर मिलेगा।
- रक्षा मंत्रालय (MoD) के परिपत्र के अनुसार, चुनिंदा संख्या में "राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय या विभाग" हर साल गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियां भेजते हैं।
- चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है।

1. **प्रथम चरण**
   - इसमें प्रारंभिक प्रस्तावों और रक्षा मंत्रालय को भेजे गए डिज़ाइन स्केच/ब्लूप्रिंट का मूल्यांकन शामिल है।
   - समिति संशोधनों का सुझाव देती है (यदि आवश्यक हो) और कई प्रस्तावों को इस चरण में ही अस्वीकार किया जा सकता है।
2. **चरण 2**
   - इसमें प्रस्तावों के 3-डी मॉडल का मूल्यांकन शामिल है।
   - यदि समिति मॉडल से संतुष्ट है, तो झांकी का चयन किया जाता है और आगे निर्माण के लिए भेजा जाता है।

- कौन सी झांकी चुनी जाए (हर साल लगभग 15) इस पर अंतिम फैसला समिति का होता है और वह किसी भी तरह के संशोधन का आदेश दे सकती है, जिसे वह आवश्यक समझती है।

57. शास्त्रीय भाषा

- हाल ही में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बंगाली को आधिकारिक तौर पर "शास्त्रीय भाषा" के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए कहा।
- वर्तमान में भारत में छह भाषाएँ हैं जिन्हें 'शास्त्रीय' दर्जा प्राप्त है, अर्थात् तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), और उड़िया (2014)।
- सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है।
  - 1500-2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलिखित इतिहास की उच्च प्राचीनता
  - प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक संग्रह, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है
  - साहित्यिक परंपरा मौलिक हो और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार न ली गई हो
  - शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से भिन्न है
- एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है।
  - शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
  - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध है कि कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में घोषित शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक अध्यक्षों की स्थापना की जाए।

58.स्पाइरल गैलेक्सी

- हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में सर्पिल आकाशगंगा, MCG-01-24-014 की एक छवि खींची, जिसमें 'निषिद्ध' प्रकाश की रहस्यमय सुंदरता का पता चला।
- स्पाइरल गैलेक्सी तारों और गैस का बना हुआ संग्रह हैं जिनमें अक्सर सुंदर आकार होते हैं और गर्म, नए तारों से बने होते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि सभी आकाशगंगाओं में से लगभग 60% स्पाइरल गैलेक्सी हैं।
- ऐसा माना जाता है कि जैसे-जैसे सर्पिल पुराने होते जाते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी अण्डाकार आकाशगंगाओं में विकसित होती जाती हैं।
- आकाशगंगा, गैलेक्सी जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल शामिल है, एक सर्पिल आकाशगंगा का एक उदाहरण है।
- संरचना

- अधिकांश स्पाइरल गैलेक्सी में एक केंद्रीय उभार होता है जो तारों की एक सपाट, घूमती हुई डिस्क से घिरा होता है।
- केंद्र में उभार पुराने, मंद तारों से बना है और माना जाता है कि इसमें एक अतिविशाल ब्लैक होल है।
- लगभग दो-तिहाई स्पाइरल गैलेक्सी में भी उनके केंद्र के माध्यम से एक बार संरचना होती है, जैसा कि आकाशगंगा में होता है।
- उभार की परिक्रमा करने वाले तारों की डिस्क आकाशगंगा का चक्कर लगाने वाली भुजाओं में अलग हो जाती है।
- इन सर्पिल भुजाओं में प्रचुर मात्रा में गैस और धूल और युवा तारे होते हैं जो अपने त्वरित निधन से पहले चमकते हैं।

59. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA)

- हाल ही में, असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) शुरू किया।
- उद्देश्य: ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें प्रति सदस्य 1 लाख रुपये की वार्षिक आय के लक्ष्य के साथ "ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों" में बदलना।
- लाभार्थी सरकार द्वारा तैयार 145 व्यावसायिक योजनाओं में से चुन सकते हैं।
- पहले वर्ष में, पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये मिलते हैं, उसके बाद सरकार से 12,500 रुपये और अगले दो वर्षों में 12,500 रुपये का बैंक ऋण मिलता है।
- शर्तों में राज्य की जनसंख्या मानदंड नीति के अनुरूप बच्चों की संख्या की सीमा तय करना शामिल है।
  - योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य और ओबीसी महिलाएं तीन से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, जबकि एसटी और एससी को चार बच्चों तक की अनुमति है।
  - मुख्यमंत्री ने बाल सीमा को उचित ठहराते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहने के बजाय व्यवसाय के लिए धन का उपयोग करें।
- ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में शामिल 39 लाख में से लगभग 5 लाख महिलाएं बाल सीमा के कारण बाहर हो सकती हैं।
- लाभार्थियों को दो अन्य शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् लड़कियों को स्कूल में नामांकित करना और सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए पेड़ों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना।
- दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों पर पिछला प्रतिबंध जनवरी 2021 से लागू किया गया था।

60. मछली रोग ऐप की रिपोर्ट

- जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) परियोजना ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप 'रिपोर्ट मछली रोग' पेश किया है।
- उद्देश्य: देश भर में मछली रोगों पर नज़र रखना और निगरानी करना।
- मोबाइल एप्लिकेशन का उद्देश्य मछली किसानों को उनके खेतों में बीमारियों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक और कुशल मंच प्रदान करना है।
- ऐप एक आसान रोग रिपोर्टिंग प्रारूप प्रदान करता है, जहां किसान स्थान, प्रभावित प्रजातियां, देखे गए लक्षण और चित्र जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके रोग के प्रकोप की आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं।
- जियो-टैगिंग तकनीक अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती है और प्राप्तकर्ताओं को उनके रिपोर्ट किए गए मामलों की स्थिति पर वास्तविक समय पर अपडेट मिलता है।
- ऐप एक सूचना केंद्र के रूप में भी काम करता है, जो किसानों को बीमारी की रोकथाम, उपचार और सर्वोत्तम जलीय कृषि प्रथाओं पर मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है।

61. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL)

- प्रधानमंत्री समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 22 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) उर्फ अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक का उद्घाटन करेंगे।
- यह अरब सागर में ठाणे क्रीक पर 22 किलोमीटर लंबा ट्विन-कैरिजवे छह-लेन पुल है, जो द्वीप शहर मुंबई में सेवरी को मुख्य भूमि पर रायगढ़ जिले में चिरले से जोड़ता है।
- इसमें 16.5 किमी का समुद्री लिंक और 5.5 किमी की संचयी लंबाई के साथ दोनों छोर पर भूमि पर वायाडक्ट शामिल हैं।
- उद्देश्य: मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले शामिल हैं, और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

62. कतील यक्षगान मेला

- कर्नाटक उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद दक्षिण कन्नड़ में एक सदी पुराना यक्षगान मेला पूरी रात फिर से शुरू होगा।
- कतील यक्षगान मेला 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ एक प्रसिद्ध यक्षगान मंडली है।
- यक्षगान तटीय कर्नाटक में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक-नृत्य है।
- यह नृत्य, संगीत, गीत, विद्वतापूर्ण संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक दुर्लभ संयोजन है।
- परंपरागत रूप से, पुरुष सभी भूमिकाएँ निभाते हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, हालाँकि अब महिलाएँ यक्षगान मंडली का हिस्सा हैं।
- एक विशिष्ट मंडली में 15 से 20 अभिनेता और एक भागवत होते हैं, जो समारोहों के मास्टर और मुख्य कथाकार होते हैं।
- यक्षगान के तत्व
  - अधिनियम: प्रत्येक प्रदर्शन आम तौर पर रामायण या महाभारत के प्राचीन हिंदू महाकाव्यों से एक छोटी उप-कहानी ('प्रसंग' के रूप में जाना जाता है) पर केंद्रित है।
  - इस शो में प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा मंचीय प्रदर्शन और पारंपरिक संगीत के साथ कमेंट्री दोनों शामिल हैं।
  - संगीत: संगीत वाद्ययंत्रों में चंदे (ड्रम), हारमोनियम, मैडेल, ताल (मिनी मेटल क्लैपर्स) और बांसुरी शामिल हैं।
  - पोशाक: बड़े आकार की टोपी, रंगीन चेहरे, पूरे शरीर पर विस्तृत पोशाकें और पैरों पर संगीत की माला (गेज्जे)।

63. व्यायाम सी ड्रैगन-24

- यह एक विशिष्ट बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच पेशेवर आदान-प्रदान और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है।
- भाग लेने वाले देश: भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका।
- इस अभ्यास का उद्देश्य कई हवाई और जमीनी-आधारित कार्यों के माध्यम से विभिन्न समुद्री युद्ध क्षेत्रों में कौशल में सुधार करना है
  - पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW): समुद्र के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना।
  - सतही युद्ध: बेहतर हथियार और रणनीति का उपयोग करके शत्रु सतह के जहाजों पर समन्वित हमले।
  - वायु रक्षा: मित्र सेनाओं को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य वायु अवरोध स्थापित करना।
  - खोज और बचाव (SAR): जरूरतमंद समुद्री कर्मियों का पता लगाना और उन्हें बचाना।
  - संचार और समन्वय: कई प्लेटफार्मों पर गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करना और निर्बाध तरीके से सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

64. आइंस्टीन जांच (EP)

- चीनी विज्ञान अकादमी (CAS) का एक मिशन जो टाइम-डोमेन उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी को समर्पित है।
- उद्देश्य: क्षणिक और परिवर्तनशील एक्स-रे आकाश का पता लगाना, न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल के विलय जैसी वस्तुओं से निकलने वाली उच्च-ऊर्जा प्रकाश के शक्तिशाली विस्फोटों को कैप्चर करना।

- इसे वर्ष 2024 में चीन के ज़िचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से "लॉन्ग मार्च-2C" रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
- पारंपरिक एक्स-रे दूरबीनों के विपरीत, आइंस्टीन प्रोब का अनूठा डिज़ाइन इसे एक साथ आकाश के लगभग दसवें हिस्से की निगरानी करने की अनुमति देता है।
  - जैसे ही वे एक्स-रे में प्रकाश डालते हैं, नए स्रोतों की खोज करते हैं
  - विस्तारित अवधि में ज्ञात और नई खगोलीय घटनाओं के गहन अध्ययन को सक्षम बनाना
- यह गामा-किरण विस्फोट, सुपरनोवा, अन्य सितारों से चमक, और सौर मंडल के भीतर की घटनाओं, जैसे धूमकेतु से उत्सर्जन, से प्रकाश का भी पता लगाएगा।

65. कालाराम मंदिर

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर का दौरा किया।
- वर्ष 1792 में बने कालाराम मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की एक काली मूर्ति और हनुमान की एक काली मूर्ति है।
- मंदिर का नाम भगवान राम की एक काली मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जिसे काला राम के नाम से जाना जाता है, और हिंदू धर्म में इसका महत्व है।
- गोदावरी में भगवान राम की काली मूर्ति का सपना देखने वाले सरदार रंगाराव ओढेकर ने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- मुख्य मंदिर में प्रतीकात्मक तत्व हैं, जिनमें राम के 14 साल के वनवास का प्रतिनिधित्व करने वाली 14 सीढ़ियाँ और 84 लाख प्रजातियों के चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 84 स्तंभ शामिल हैं।
- इस मंदिर का रामायण में महत्व है, भगवान राम ने अपने वनवास के शुरुआती वर्ष इसी क्षेत्र में बिताए थे।
- वर्ष 1930 में, बीआर अंबेडकर और पांडुरंग सदाशिव साने ने हिंदू मंदिरों में दलितों की पहुंच की मांग को लेकर एक आंदोलन का नेतृत्व किया।
- अम्बेडकर ने दलितों के प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए कालाराम मंदिर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जो वर्ष 1935 तक जारी रहा।

66. युवा निधि योजना

- कर्नाटक सरकार ने हाल ही में युवा निधि योजना शुरू की है।
- उद्देश्य: उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना।
- स्नातक और डिप्लोमा धारकों को राज्य सरकार के कौशल कनेक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- यह योजना डिग्री धारकों को ₹3,000 प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को ₹1,500 प्रति माह प्रदान करती है, जिन्होंने पिछले छह महीनों में नौकरी हासिल नहीं की है और उच्च अध्ययन नहीं कर रहे हैं।
- वित्तीय सहायता अधिकतम दो वर्षों के लिए या लाभार्थी को रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी।
- पंजीकृत व्यक्तियों को उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

67. वाइपर (VIPER) रोवर

- वाइपर(VIPER) चंद्रमा पर नासा का पहला मोबाइल रोबोटिक मिशन है।
- यह चार मुख्य मिट्टी के वातावरण के भीतर अलग-अलग गहराई और तापमान की स्थिति में चंद्रमा की सतह और उपसतह पर बर्फ का सीधे विश्लेषण करेगा।
- वाइपर(VIPER) डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजता है, वैज्ञानिकों को संसाधन मानचित्र तैयार करने में सहायता करता है जो चंद्र बर्फ के स्थान और एकाग्रता का विवरण देता है, बर्फ के क्रिस्टल या रासायनिक रूप से बंधे अणुओं जैसे विभिन्न रूपों के बीच अंतर करता है।

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चुनौतीपूर्ण इलाके को पार करते हुए, वाइपर(VIPER) महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करता है जो चंद्रमा के इतिहास और आसपास के वातावरण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है जहां नासा आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का इरादा रखता है।
- मिशन की अवधि: 100 पृथ्वी दिवस, चंद्र दिन और रात के 3 चक्रों को कवर करते हुए।
- यह वर्ष 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।

68. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) योजना

- MSME मंत्रालय की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) योजना ने हाल ही में 1 लाख प्रमाणीकरण मील का पत्थर हासिल किया है।
- अक्टूबर 2016 में लॉन्च की गई, ZED योजना पर्यावरण के प्रति जागरूक विनिर्माण के लिए प्रमाणन प्रदान करती है।
- उद्देश्य
  - ZED विनिर्माण के बारे में MSME में उचित जागरूकता पैदा करना और उन्हें ZED रेटिंग के लिए अपने उद्यम के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना।
  - पर्यावरण (शून्य प्रभाव) को प्रभावित किए बिना शून्य-दोष उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देना।
  - MSME को उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - "मेक इन इंडिया" अभियान का समर्थन करना।
- वर्तमान में, यह योजना केवल MSME विनिर्माण के लिए लागू है।
- पंजीकरण और ZED प्रतिज्ञा लेने के बाद MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन तीन स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है
  - प्रमाणन स्तर 1: कांस्य
  - प्रमाणन स्तर 2: रजत
  - प्रमाणन स्तर 3: सोना
- उन्हें 20 प्रदर्शन-आधारित मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे गुणवत्ता प्रबंधन, समय पर वितरण, प्रक्रिया नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि।

69. HD 63433d

- यह एक पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट है जो HD 63433 (जिसे TOI 1726 भी कहा जाता है) नामक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है।
- तारा सूर्य से लगभग 73 प्रकाश वर्ष दूर है और एक साथ घूमने वाले तारों के समूह का हिस्सा है जो उरसा मेजर तारामंडल बनाते हैं।
- तारा HD 63433 आकार और प्रकार में हमारे सूर्य के समान है, लेकिन काफी छोटा है, लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना है।
- यह सबसे छोटा पुष्टिकृत एक्सोप्लैनेट है, जो 500 मिलियन वर्ष से भी पुराना है।
- यह अब तक खोजा गया पृथ्वी के आकार का सबसे निकटतम ग्रह भी है, और यह लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना है।

70. AN-32 विमान

- AN-32 (एंटोनोव AN-32)) एक सोवियत मूल का सैन्य परिवहन विमान है।
- इसे भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए यूक्रेन के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- इसे भारत ने वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा था। IAF के पास लगभग 100 AN-32 विमानों का बेड़ा है।
- इसका नाटो रिपोर्टिंग नाम क्लाइन है।

- विमान को उष्णकटिबंधीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, यहां तक कि गर्म जलवायु परिस्थितियों (55 डिग्री सेल्सियस तक) में भी दिन-रात उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह दो सिंगल-शाफ्ट टर्बोप्रॉप इंजन द्वारा संचालित है।
- An-32 अधिकतम 530 किमी/घंटा की गति से उड़ सकता है, और इसकी क्रूज़ गति 470 किमी/घंटा है।
- विमान की रेंज और सर्विस सीलिंग क्रमशः 2,500 किमी और 9,500 मीटर है।

71.राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार'

- भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में "राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार" की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय पुरस्कार शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरक वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार योगदान को मान्यता देता है।

पुरस्कारों की श्रेणियाँ

- विज्ञान रत्न (VR): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी दिए गए क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम तीन पुरस्कार दिए जाएंगे।
- विज्ञान श्री (VS): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दिए गए क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।
- विज्ञान युवा: शांति स्वरूप भटनागर (VY-SSB पुरस्कार: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।

72.ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

- GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है।
- इसे वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- यह योजना पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA), राज्य सरकार और विशेषज्ञों के बीच कई बैठकों के बाद तैयार की गई थी।
- GRAP केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है।
- योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूरे वर्ष की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है

73.थर्टी मीटर टेलीस्कोप)TMT)

- इसकी कल्पना 30 मीटर व्यास वाले प्राथमिक-मिरर ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड टेलीस्कोप के रूप में की गई है जो गहरे अंतरिक्ष में अवलोकन को सक्षम करेगा।
- इसे संयुक्त सहयोग के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसमें दक्षिण, जापान, चीन, कनाडा और भारत के संस्थान शामिल हैं।
- यह दुनिया की सबसे उन्नत और सक्षम ग्राउंड-आधारित ऑप्टिकल, निकट-अवरक्त और मध्य-अवरक्त वेधशाला होगी।
- यह परिशुद्धता नियंत्रण, खंडित दर्पण डिजाइन और अनुकूली प्रकाशिकी में नवीनतम नवाचारों को एकीकृत करेगा।
- टेलीस्कोप के केंद्र में खंडित दर्पण है, जो 492 अलग-अलग खंडों से बना है। सटीक रूप से संरेखित, ये खंड 30 मीटर व्यास की एकल परावर्तक सतह के रूप में काम करेंगे।

74.काबो वर्डे

- इसे केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है जिसमें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह शामिल है।
- यह सेनेगल के पास स्थित है और महाद्वीप का निकटतम बिंदु है।

- इस ज्वालामुखीय द्वीपसमूह में दस द्वीप और पांच टापू शामिल हैं, जो हवा की ओर (बारलावेंटो) और लीवार्ड (सोटावेंटो) समूहों में विभाजित हैं।
- जलवायु: आम तौर पर मध्यम, जलवायु की विशेषता अत्यधिक शुष्कता के साथ स्थिर तापमान है।
- काबो वर्डे द्वीपों का भूभाग पूर्व में भौगोलिक रूप से पुराने, समतल द्वीपों और पश्चिम में नए, अधिक पहाड़ी द्वीपों से भिन्न है।
- जनसंख्या: काबो वर्डे की अधिकांश आबादी मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल की है और इसे अक्सर मेस्टिको या क्रिओलो कहा जाता है।

75.हिमालयी वुल्फ (भेड़िया)

- हिमालयन वुल्फ (कैनिस ल्यूपस चांको), हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है।
- इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं और आनुवंशिक रूप से भूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं।
- इतनी ऊंचाई पर रहते हुए, इन भेड़ियों ने आनुवंशिक रूप से खुद को कम ऑक्सीजन (हाइपोक्सिक) स्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है।
- चीन में, हिमालयी भेड़िया गांसु, किंघई, तिब्बत और पश्चिमी सिचुआन प्रांतों में तिब्बती पठार पर रहता है।
- उत्तरी भारत में, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उत्तरपूर्वी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में होता है।
- संरक्षण स्थिति: IUCN: वल्नरबेल
  - उद्धरण: परिशिष्ट I.
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I.

76.PM-eBus सेवा योजना

- PM-eBus सेवा योजना के तहत, देश के शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
- सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को धीमी गति से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत सिटी बस संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर किया जाएगा।
- यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
- राज्य/शहर बस सेवाएं चलाने और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।

77.भारत का प्रथम डार्क स्काई पार्क

- महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR) भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, जो टाइगर रिज़र्व के भीतर पार्क के चारों ओर के क्षेत्रों को चिह्नित करता है, जो स्टारगेज़र्स के लिए प्राचीन अंधेरे आसमान तक पहुंचने के लिए प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है।
- डार्क स्काई प्लेस प्रमाणन प्रकाश नीति, डार्क स्काई-अनुकूल रेट्रोफिट्स, आउटरीच और शिक्षा और रात के आकाश की निगरानी पर केंद्रित है।
- यह पदनाम PTR को एक अभयारण्य के रूप में स्थापित करता है जहां पर्यटक कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण के घुसपैठ से बचाकर आकाशीय चमत्कार देख सकते हैं।
- PTR एशिया का पांचवां ऐसा पार्क बन गया।
- यह प्रमाणन इंटरनेशनल डार्क-स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जो खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक डार्क-स्काई आंदोलन है।

78.आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति)GEAC)

- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए "खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के नियम (नियम, 1989)" के तहत गठित वैधानिक समिति है।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) के तहत कार्य करता है।
- कार्य: यह के लिए जिम्मेदार है
  - पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक जीवित सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों की मंजूरी।
  - प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर (GE) जीवों और उत्पादों की रिहाई से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन।
- समिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।
- संघटन
  - GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है।
  - वर्तमान में, इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा के लिए हर महीने बैठक होती है।
  - सदस्यों में अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ ICAR, ICMR, CCMB आदि संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

79. ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट (SGRTD) योजना

- यह पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक पहल है।
- यह योजना निवासी व्यक्तियों, गैर-व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय (NRI) ग्राहकों के लिए खुली है।
- मौजूदा ढांचा हरित जमा को केवल रुपये में मूल्यवर्गित करने की अनुमति देता है।
- यह निवेशकों को तीन अलग-अलग अवधियों में से चुनने की सुविधा प्रदान करता है: 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन।
- यह संबंधित अवधि के लिए खुदरा और थोक जमा के लिए कार्ड दर से 10 आधार अंक (bps) कम ब्याज दरों की पेशकश करेगा।
- वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक जनता के लिए लागू दर पर अतिरिक्त ब्याज दर के पात्र हैं।
- अतिरिक्त ब्याज का लाभ NRI वरिष्ठ नागरिकों/NRI स्टाफ को नहीं मिलेगा।
- योजना के तहत समय से पहले निकासी और जमा राशि के बदले ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति है।

80. पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क)PNHZP)

- दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZP) ने 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं का सफलतापूर्वक प्रजनन किया है।
- पहले इसे हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना अगस्त, 1958 में दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में की गई थी।
- पार्क निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पूर्वी हिमालय में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयासरत है
  - लुप्तप्राय हिमालयी पशु प्रजातियों का पूर्व-स्थाने संरक्षण और बंदी प्रजनन।
  - हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ आगंतुकों को शिक्षित करना, प्रेरित करना और जागरूकता अभियान शुरू करना।
  - पशु जीव विज्ञान, व्यवहार और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यावहारिक अनुसंधान शुरू करना।
- चिड़ियाघर भारत में लुप्तप्राय पूर्वी हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन के लिए अग्रणी रहा है।
- पहला पूर्व-स्थाने संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में हिम तेंदुए संरक्षण प्रजनन परियोजना के रूप में शुरू हुआ।

- रेड पांडा परियोजना 1990 में शुरू की गई थी।
- यह देश का सबसे बड़ा ऊँचाई पर स्थित चिड़ियाघर है।

81.कच्छी खरेक

- कच्छ की देशी खजूर की किस्म कच्छी खरेक, भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है।
- कच्छ (कच्छ) में खजूर की उपस्थिति लगभग 400-500 वर्ष पुरानी मानी जाती है।
- ऐसा माना जाता है कि भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर खजूर के पेड़ उन बाशिंदों द्वारा फेंके गए बीजों से विकसित हुए हैं, जो हज के लिए मध्य-पूर्व के देशों में जाते थे।
- कच्छ में उगाए जाने वाले खजूरों की कटाई खलल अवस्था में की जाती है, वह अवस्था जब फल परिपक्व हो जाते हैं, सुक्रोज जमा हो जाता है, और लाल या पीले हो जाते हैं लेकिन अभी भी कुरकुरे होते हैं क्योंकि वे नम मौसम का सामना नहीं कर सकते हैं।
- कच्छ खजूर का मौसम आम तौर पर हर साल 15 जून को शुरू होता है, और पेड़ लवणता के प्रति सहनशीलता और अत्यधिक सूखे और गर्मी की स्थिति के प्रति अनुकूलनशीलता के लिए जाने जाते हैं।
- कच्छ दुनिया भर में एकमात्र स्थान है जहां ताजा खजूर की आर्थिक रूप से खेती, विपणन और खपत की जाती है।
- भारत में कुल खजूर की खेती का 85% से अधिक क्षेत्र इसी क्षेत्र में होता है।

82.बहुआयामी गरीबी

- एक व्यक्ति जो गरीब है, उसे एक ही समय में कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या कुपोषण हो सकता है, साफ पानी या बिजली की कमी हो सकती है, काम की गुणवत्ता खराब हो सकती है या स्कूली शिक्षा कम हो सकती है।
- अकेले आय जैसे एक कारक पर ध्यान केंद्रित करना गरीबी की वास्तविक वास्तविकता को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- बहुआयामी गरीबी गरीबी का एक माप है जो 2.15 डॉलर अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (विश्व बैंक के अनुसार) पर आय या उपभोग के अलावा शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में कमी को दर्शाता है।
- विश्व बैंक मौद्रिक मूल्य को मापने के लिए प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर (2017 क्रय शक्ति समता शर्तों में) पर अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को परिभाषित करता है।

83.प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि)PM-KISAN)

- योजना के तहत, केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।
- यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है।
- उद्देश्य
  - उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।
  - ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में पीएम-किसान योजना के तहत जोड़ा गया हर चौथा लाभार्थी एक महिला है।

84.फ़ारसी भाषा

- विदेश मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फ़ारसी को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है।
- फ़ारसी, जिसे फ़ारसी भाषा के रूप में भी जाना जाता है, इंडो-ईरानी भाषाओं की ईरानी शाखा का सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली सदस्य है, जो इंडो-यूरोपीय भाषाओं का एक उपपरिवार है।
- यह ईरान की आधिकारिक भाषा है, और फ़ारसी की दो किस्में जिन्हें दारी और ताजिक के नाम से जाना जाता है, क्रमशः अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- फ़ारसी बोलने वालों की महत्वपूर्ण आबादी फारस की खाड़ी के अन्य देशों के साथ-साथ अमेरिका के बड़े समुदायों में भी पाई जा सकती है।
- ईरान में फ़ारसी विभिन्न प्रकार की अरबी लिपि में लिखी जाती है जिसे फ़ारसी-अरबी कहा जाता है, जिसमें फ़ारसी ध्वन्यात्मक अंतर को ध्यान में रखते हुए कुछ नवीनताएँ हैं।

85. अप्रत्याशित टैक्स

- यह कुछ उद्योगों के विरुद्ध सरकारों द्वारा लगाया गया कर है जब आर्थिक स्थितियाँ उन उद्योगों को औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने की अनुमति देती हैं।
- शब्द "अप्रत्याशित लाभ" का तात्पर्य मुनाफे में अप्रत्याशित वृद्धि से है, और अप्रत्याशित लाभ पर कर को अप्रत्याशित कर के रूप में जाना जाता है।
    - इन राजस्वों को कंपनी द्वारा सक्रिय रूप से अपनाई जाने वाली किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसे कि उसकी व्यावसायिक रणनीति या विस्तार।
- इसका ताजा उदाहरण रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल और गैस उद्योगों के मुनाफे में अचानक वृद्धि है।
- उद्देश्य
    - जब ऊंची कीमतें उपभोक्ताओं की कीमत पर उत्पादकों को लाभ पहुंचाती हैं तो अप्रत्याशित लाभ का पुनर्वितरण
    - सामाजिक कल्याण योजनाओं को वित्तपोषित करना
    - सरकार के लिए एक पूरक राजस्व स्रोत के रूप में
    - सरकार के लिए देश के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने का एक तरीका

86. 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल

- हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, एक FASTag' पहल शुरू की।
- NHAI ने टैगिंग उपयोगकर्ताओं को निष्क्रियता से बचने के लिए 31 जनवरी के अंत तक अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रिया को पूरा करने का सुझाव दिया।
- उद्देश्य
    - इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाना और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करना।
    - एकाधिक वाहनों के लिए एकल FASTag का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिए एकाधिक FASTags को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना।

87. एल नीनो और ला नीना

- एल नीनो और ला नीना दो विपरीत जलवायु रुझान हैं जो सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होते हैं और आम तौर पर नौ से बारह महीने तक चलते हैं, लेकिन अक्सर बढ़ सकते हैं।
- ये घटनाएँ औसतन हर दो से सात साल में होती हैं (एल नीनो ला नीना की तुलना में अधिक बार होता है), लेकिन नियमित आधार पर नहीं और वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) चक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- एल नीनो को आम तौर पर गर्म चरण (भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैलने वाला गर्म पानी का एक बैंड) के रूप में जाना जाता है और ला नीना को ईएनएसओ के ठंडे चरण (ठंडे पानी का एक बैंड पूर्व-पश्चिम में फैलता है) के रूप में पहचाना जाता है।

- एल नीनो और ला नीना दोनों का मौसम, जंगल की आग, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थशास्त्र पर वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है।

88.पैरामाइरोथेसियम इंडिकम

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल में फाइटोपैथोजेनिक फंगस की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम 'पैरामाइरोथेसियम इंडिकम' है।
  - फाइटोपैथोजेंस एक परजीवी हैं जो एक पौधे के मेजबान पर जीवित रहते हैं।
- ये "पौधों की गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं जो फसल उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।"
- पैरामाइरोथेसियम पत्ती के धब्बे एक प्रकार का कवक रोग है जो विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रभावित कर सकता है।
- पैरामाइरोथेसियम की कुछ प्रजातियाँ जैव-शाकनाशी क्षमता वाले द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करती हैं और इसलिए, खरपतवारों को नियंत्रित करने में उनका उपयोग हो सकता है।

89.पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव

- अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF) का 9वां संस्करण पक्के केसांग जिले के सेइजोसा में होने वाला है।
- उद्देश्य
  - पक्के टाइगर रिजर्व (PTR) में हॉर्नबिल के संरक्षण में न्यीशी आदिवासी समूह द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानना।
  - क्षेत्र के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत जुटाना
  - PTR और इसके आसपास के क्षेत्रों के आश्चर्यों के बारे में शेष भारत में जागरूकता पैदा करना।
- वर्ष 2023की थीम: "डोमुतोह दोमुतोह, पागा हम दोमुतोह" जिसका निशी भाषा में अनुवाद 'लेट अवर हॉर्नबिल्स रिमेन' है।
- इस वर्ष के उत्सव का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित पक्षियों के संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करना है।

90.पनामा नहर

- यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
- यह पनामा के इस्तमुस को पार करता है और समुद्री व्यापार के लिए एक माध्यम है।
- यह दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है, दूसरा स्वेज नहर है।
- इसमें तालों की एक श्रृंखला होती है जो महाद्वीपीय विभाजन के माध्यम से जहाजों के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए जल स्तर को बढ़ाती और घटाती है।
- हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पनामा नहर में लगभग 22 मिलियन वर्ष पुराना एक खोया हुआ जंगल खोजा है।

91.नीली अर्थव्यवस्था

- विश्व बैंक के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था "समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है।"
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि ब्लू इकोनॉमी के अभिन्न अंग हैं, जो दुनिया के प्रोटीन स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में सतत अभ्यास आवश्यक हैं।
- जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देकर, ब्लू इकोनॉमी समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का समर्थन करती है।
- स्वस्थ महासागर जलवायु विनियमन और कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- तटीय और समुद्री पर्यटन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

92. ग्रीनलैंड

- ग्रीनलैंड एक द्वीप देश है जो डेनमार्क का हिस्सा है।
- यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है।
- ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
- इन देशों के सभी नागरिक डेनिश नागरिक हैं।
- 56,081 (2020 डेटा) की आबादी के साथ, यह दुनिया में सबसे कम घनी आबादी वाला क्षेत्र है।
- ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक है, लगभग एक तिहाई आबादी नुउक में रहती है।
- यह ग्रीनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
- उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा होते हुए भी ग्रीनलैंड राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है।

93. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग)CCI)

- यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और जो रहा हो
  - उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है
  - अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्षों का पेशेवर अनुभव है जो केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।
- आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है।

94. स्टीडफ़ास्ट डिफेंडर 2024

- नाटो शीत युद्ध के बाद से अपना सबसे व्यापक अभ्यास शुरू कर रहा है, जो "निकट-समकक्ष" प्रतिद्वंद्वी के साथ संघर्ष की स्थिति में रूस और उसके पूर्वी हिस्से की सीमा से लगे यूरोपीय सहयोगियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- लगभग 90,000 सैनिक स्टीडफ़ास्ट डिफेंडर-2024 अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो मई तक जारी रहेगा।
- इस अभ्यास में विमान वाहक से लेकर विध्वंसक तक 50 से अधिक जहाज, 80 से अधिक लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन, साथ ही 133 टैंक और 533 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों सहित कम से कम 1,100 लड़ाकू वाहन शामिल होंगे।
- यह अभ्यास पिछली घटनाओं के पैमाने को पार करता है, अंतिम तुलनीय अभ्यास शीत युद्ध के दौरान 1988 में रिफॉर्गर था, जिसमें 125,000 प्रतिभागी शामिल थे, और वर्ष 2018 में ट्राइडेंट जंक्चर था, जिसमें 50,000 प्रतिभागी थे।
- अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का पूर्वाभ्यास करना है, जो दशकों में विकसित गठबंधन की पहली रक्षा योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह समकालीन सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए नाटो के सक्रिय दृष्टिकोण का प्रतीक है, विशेष रूप से रूस जैसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी से जुड़े संभावित संघर्षों के संबंध में।

95. डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर)DAT-SG)

- इसरो ने हाल ही में दूसरी पीढ़ी के डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (DAT-SG) के साथ समुद्री सुरक्षा में एक मील का पत्थर हासिल किया है।
- वर्ष 2010 से चालू, यह समुद्र में मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है, जो वास्तविक समय संकट संकेत क्षमताओं की पेशकश करता है।
  - DAT-SG 2010 में लॉन्च किए गए प्रारंभिक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकास है।
- यह सुविधा न केवल आपातकालीन संदेशों की प्राप्ति की पुष्टि करती है बल्कि मछुआरों को यह भी आश्वस्त करती है कि उनके संकेतों पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है।
- संकट संकेतों को प्रसारित करने के अलावा, DAT-SG नियंत्रण केंद्र से संदेश प्राप्त कर सकता है।
- यह दो-तरफ़ा संचार सिस्टम की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में अधिक व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।

96.तिरुवल्लुवर दिवस

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- तिरुवल्लुवर एक कवि और दार्शनिक थे, और उन्हें तमिलों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है।
- उनका सबसे लोकप्रिय काम थिरुक्कुरल है, जो नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रेम पर दोहों का संग्रह है।
- उनके प्राथमिक कार्य तिरुक्कुरल में 1330 दोहे (कुराल) हैं जो 10-10 दोहों के 133 खंडों में विभाजित हैं।
- पाठ को धर्म, अर्थ और काम (सदाचार, धन और प्रेम) पर शिक्षाओं के साथ तीन भागों में विभाजित किया गया है।
- प्रत्येक अनुभाग विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है और पाठकों को नैतिक, नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- दोहे संक्षिप्त और काव्यात्मक रूप में रचे गए हैं, जिससे वे आसानी से यादगार और उद्धृत किए जा सकते हैं।

97.क़नात प्रणाली

- यह एक प्राचीन प्रकार की जल-आपूर्ति प्रणाली है, जो दुनिया के शुष्क क्षेत्रों में विकसित और अभी भी उपयोग की जाती है।
- यह जलोढ़ पंखे की ऊपरी पहुंच के नीचे और नीचे फंसे भूमिगत पर्वतीय जल स्रोतों का दोहन करता है और धीरे-धीरे ढलान वाली सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से पानी को नीचे की ओर प्रवाहित करता है।
  - पहाड़ों से आने वाले पानी की गुणवत्ता मैदानी इलाकों के पानी से कहीं बेहतर होती है।
  - इसमें लवणता कम होगी और यह फसलों और लोगों के लिए बेहतर होगा।
- क़नात का उपयोग सदियों से उत्तरी अफ़्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के शुष्क और अर्ध-शुष्क भागों में किया जाता रहा है, जहाँ पानी की आपूर्ति सीमित है।
- इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, उत्तरी अफ्रीका में "फोगारा", ओमान में "फलाज" और एशिया के कुछ हिस्सों में "क़रेज़"।
- कई पुराने क़ानात अभी भी ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- क्षेत्र की कुछ क़ानत प्रणालियाँ, जैसे कि ईरान में, विरासत की स्थिति के तहत संरक्षित हैं।
- क़ानात टिकाऊ है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करता है और बिजली की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

98.रोगाणुरोधक प्रतिरोध)AMR)

- एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक सहित रोगाणुरोधी - ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों और पौधों में संक्रमण को रोकने और इलाज करने के लिए किया जाता है।
- AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

- दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतों के लिए बैक्टीरियल AMR सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 4,95 मिलियन मौतें दवा प्रतिरोधी संक्रमण से जुड़ी थीं।

99.GM फसल

- पारंपरिक पादप प्रजनन में संतानों को पेरेंट्स दोनों के वांछित गुण प्रदान करने के लिए एक ही जीनस की प्रजातियों को पार करना शामिल है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बीजों में एक विदेशी जीन को शामिल करके जीनस बाधा को पार करना है।
- विदेशी जीन किसी पौधे, जानवर या मिट्टी के जीवाणु से भी हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए बीटी कपास में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंगिएन्सिस (Bt) से विदेशी जीन होते हैं।
- यह फसल को एक प्रोटीन विकसित करने की अनुमति देता है, जो सामान्य कीट गुलाबी बॉलवर्म के लिए विषैला होता है।
- बीटी ब्रिंजल में, एक जीन पौध को फल और शूट बोरर के हमलों से सुरक्षित रखने की अनुमति देता है।
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उत्पादित बीजों को आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज कहा जाता है।

100. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- इसे प्रमुख घासभूमि प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी आबादी अधिकतर राजस्थान र)ाज्य पक्षीऔर गुजरात तक ही सीमित है। (
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटी आबादी पाई जाती है।
- खतरेविद्युत का झटका/बिजली पारेषण लाइनों के साथ टकराव :, शिकार (पाकिस्तान में अभी भी प्रचलित), व्यापक कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप निवास स्थान की हानि और परिवर्तन, आदि।
- GIB की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
  - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)MoEFCC) के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है।
  - MoEF&CC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान)WII) ने जून 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की है।
  - प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान सरकार द्वारा प्रजातियों के लिए प्रजनन बाड़ों के निर्माण और इसके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- सुरक्षा की स्थिति
  - IUCN: गंभीर रूप से लुप्तप्राय
  - प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन)CMS): परिशिष्ट I।
  - वन्यजीव अधिनियम (संरक्षण), 1972: अनुसूची I।

101. जगन्नाथ मंदिर

- हाल ही में, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विशाल विरासत गलियारे का अनावरण किया।
- पुरी, ओडिशा में स्थित यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है।
- यह हिंदू देवता विष्णु के एक रूप, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है।
- ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव के शासनकाल के दौरान किया गया था।
- जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो ओडिशा क्षेत्र में प्रचलित एक विशिष्ट शैली है।

- मंदिर की मुख्य संरचना, गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ (गर्भगृह), बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं।
- रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक हिंदू त्योहार है।
- सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव आषाढ़ के चंद्र माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है और नौ दिनों (जुलाई-जून) तक चलता है।

102. रोगाणुरोधक प्रतिरोध)AMR)

- यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
- परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतों के लिए बैक्टीरियल AMR सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 4,95 मिलियन मौतें दवा प्रतिरोधी संक्रमण से जुड़ी थीं।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ने के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से एंटीबायोटिक्स लिखते समय सटीक कारण लिखने का आग्रह किया है।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी फार्मासिस्टों से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची H और H1 को सख्ती से लागू करने की भी अपील की है।
  - एंटीबायोटिक्स अनुसूची एच के तहत निर्दिष्ट दवाओं की सूची में शामिल हैं; केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर)RMP) के नुस्खे पर खुदरा बिक्री की जाएगी।
  - कुछ उच्च गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक्स H1 दवाओं की सूची में शामिल हैं।

103. खेलो इंडिया योजना

- इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अपने पांच कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देते हैं।
- खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल प्रदर्शित करने का बुनियादी मंच है।
- इस योजना के 'प्रतिभा खोज और विकास' वर्टिकल के तहत, खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर की मल्टीस्पोर्ट प्रतियोगिताओं, अर्थात् खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करता है।
- TOPS (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक और प्रमुख कार्यक्रम है जो भारत (के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है।

104. गुरुवयूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर

- इसे दक्षिण की द्वारका के रूप में भी जाना जाता है, यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के युवा रूप को समर्पित है।
- यह केरल के त्रिशूर जिले के छोटे से शहर गुरुवायूर में स्थित है।
- सबसे पुराने मंदिर के रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी के हैं, लेकिन अन्य साहित्यिक ग्रंथों और किंवदंतियों से संकेत मिलता है कि मंदिर लगभग 5000 साल पुराना हो सकता है।
- भगवान कृष्ण, या गुरुवायूरप्पन, इस मंदिर के मुख्य देवता हैं।
- यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है।
- माना जाता है कि केंद्रीय मंदिर का पुनर्निर्माण 1638 ईमें किया गया था .
- नालम्बलम (गर्भगृह के चारों ओर मंदिर की संरचना), बालिक्कल (यज्ञ का पत्थर), और दीपस्तंभम (रोशनी का स्तंभ) जैसी संरचनाएं मंदिर परिसर में स्थित हैं।
- गर्भगृह की दीवार 17वीं सदी के प्राचीन भित्तिचित्रों से सुसज्जित है।

105. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के भ्रामक नाम के तहत मिठाई की बिक्री के लिए अमेज़ॅन को नोटिस जारी किया।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण।
- उद्देश्यएक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना :, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना।
- इसके प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त और सदस्य के रूप में केवल दो अन्य आयुक्त होते हैं।
  - माल से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे
  - दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा।
- शक्तियाँ
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और शिकायतेंमुकदमा चलाना/
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश
  - अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दें
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओंप्रकाशकों पर जुर्माना लगाएं।/समर्थकों/
- नोडल मंत्रालयउपभोक्ता मामले :, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

106. कैडिसफ्लाइज़

- शोधकर्ताओं ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कैडिसफ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम रयाकोफिला मसुदी है।
- कैडिसफ्लाइज़ पतंगे जैसे कीड़े हैं जो रात में रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और झीलों या नदियों के पास रहते हैं।
- ये दुनिया भर में, आमतौर पर मीठे पानी के आवासों में और अक्सर खारे और ज्वारीय पानी में भी पाए जाते हैं।
- विशेषताएँ
  - वयस्क कैडिसफ्लाइज़ आमतौर पर 3 से 15 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं।
  - आम तौर पर हल्के भूरे रंग के, वयस्क कैडिसफ्लाइज़ बालों वाले पंखों और लंबे एंटीना के साथ पतंगों के समान होते हैं।
  - हालाँकि, इनके पास तितलियों और पतंगों की तरह लंबे समय तक चलने वाले मुखांग नहीं होते हैं।
  - जब ये उड़ नहीं रहे होते हैं तो वे अपने पंखों को तंबू की तरह अपने शरीर के ऊपर रखते हैं।
- ये मुख्य रूप से पौधों के रस और फूलों के रस पर भोजन करते हैं, हालांकि कुछ शिकारी होते हैं।
- महत्वये : विभिन्न मछली प्रजातियों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में काम करते हैं, और शैवाल और अन्य संभावित समस्याग्रस्त जीवों को फ़िल्टर करके जल शुद्धिकरण में भी योगदान देते हैं।

107. भारतीय गिद्ध

- भारतीय गिद्ध एशिया का मूल निवासी पुरानी दुनिया का गिद्ध है।
- तुलनात्मक रूप से लंबी चोंच के कारण इन्हें भारतीय लंबे चोंच वाले गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक मध्यम आकार का और भारी भरकम जीव है जो ज्यादातर मृत जानवरों के शवों को खाता है।
  - इस प्रजाति की मादाएं नर की तुलना में छोटी होती हैं।
- ये भारत, पाकिस्तान और नेपाल के मूल निवासी हैं।
- वे आमतौर पर सवाना और गांवों, शहरों और खेती वाले क्षेत्रों के आसपास अन्य खुले आवासों में पाए जाते हैं।
- पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनाक के कारण होने वाले जहर के कारण भारतीय गिद्ध की आबादी में 99% की कमी आई है।
  - काम करने वाले जानवरों को डिक्लोफेनाक दिया जाता है क्योंकि यह जोड़ों के दर्द को कम करता है और उन्हें लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाता है।
- IUCN स्थितिगंभीर रूप से लुप्तप्राय :

108. ग्लोबल एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी-

- भारत ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए "ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी -" की स्थापना की है।
- यह दावोस में 54वीं वार्षिक विश्व आर्थिक मंच)WEF) की बैठक के मौके पर भारत द्वारा स्थापित 'ग्लोबल एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी-' एक नया गठबंधन है।
- यह महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश के अवसरों को एक साथ लाएगा।
- इसने भारतीय उद्योग परिसंघ)CII) के माध्यम से उद्योग जगत के नेताओं से समर्थन प्राप्त किया है।
- बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित, गठबंधन का आयोजन और संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा।
- WEF एक 'नेटवर्क पार्टनर' के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक 'संस्थागत भागीदार' के रूप में शामिल हुआ है।

109. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

- स्थानजगदलपुर :, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में।
- यह खोलाबा नदी के तट पर स्थित है। (गोदावरी नदी की सहायक नदी)
- पूरा पार्क मुख्य क्षेत्र है और कोई बफर जोन नहीं है।
- यह तीन असाधारण गुफाओं का घर है, जो अपनी अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक-टैलाग्माइ्सट्स और स्टैलेक्टाइट्स के लिए प्रसिद्ध हैं।
- यह तीन असाधारण गुफाओं का घर है, जो अपनी अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कुटुंबसर, कैलाश, और दंडकस्टैलाग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स।-
- यह स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट संरचनाओं वाली भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है।
- पार्क में तीरथगढ़ झरना स्थित है।
- फ्लोरामिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन जिनमें साल :, सौगौन, सागौन और बांस के पेड़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
- प्रमुख जंगली जानवरों में बाघ, माउस हिरण, तेंदुए, जंगली बिल्ली, सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, लंगूर, सियार, रीसस मकाक, उड़ने वाली गिलहरी आदि शामिल हैं।
- पार्क में हवाई जीवों में आम पहाड़ी मैना, लाल जंगली मुर्गी, चित्तीदार उल्लू, रैकेटटेल्ड ड्रोंगो-, तोते आदि शामिल हैं।

110. मधिका

- करिवेलूर ग्राम पंचायत के पास सुदूर कूकनम कॉलोनी में, चकलिया समुदाय को अपनी अनूठी भाषा, मधिका के आसन्न विलुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है।
- मधिका, बिना लिपि के, कन्नड़ से मिलती जुलती है लेकिन इसमें तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का प्रभाव शामिल है।
- चाकलिया समुदाय, जो कभी थिरुवेंकटरमण और मरियम्मा के खानाबदोश उपासक थे, सदियों पहले कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार में चले गए थे।
- शुरुआत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, बाद में वे केरल में अनुसूचित जाति श्रेणी का हिस्सा बन गए।
- कोई दस्तावेज न होने के कारण, मधिका का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि यह भाषा पूरी तरह से मौखिक रूप से प्रसारित होती है।
- सामाजिक कार्यकर्ता मधिका की उपेक्षा का कारण चकलिया समुदाय से जुड़े ऐतिहासिक सामाजिक कलंक को मानते हैं।

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

- अछूत समझे जाने के कारण उन्हें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई लोग अपनी भाषा से अलग हो गए और मलयालम को प्राथमिकता देने लगे।

111. मॉस्किटोफिश

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)ICMR) ने मलेरिया से निपटने के लिए वर्ष 1928 में मॉस्किटोफ़िश की शुरुआत की।
- रणनीति यह थी कि ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा का शिकार करें, जिससे मच्छरों की आबादी कम हो जाए। हालाँकि, जांच से भारत में मॉस्किटोफिश के व्यापक वितरण का पता चलता है, जिसका देशी जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे देशी मछलियाँ, उभयचर और विभिन्न मीठे पानी के समुदाय विलुप्त हो जाते हैं।
- मॉस्किटोफिश को सौ सबसे हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है।
- वर्ष 1960 के दशक में, गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया होलब्रूकी जैसी मॉस्किटोफिश की शुरूआत ने कीटनाशकों के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की।
- WHO द्वारा 1982 में मच्छर नियंत्रण के लिए गंबूसिया की सिफारिश को रोकने और 2018 में उन्हें आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में नामित करने के बावजूद, भारत ने इन मछलियों को पेश करना जारी रखा है, जिससे स्वदेशी जैव विविधता को नुकसान हो रहा है।

112. कुमकी

- कुमकी (मलयालम में थप्पना के नाम से भी जाना जाता है) भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
- इनका उपयोग जंगली हाथियों को फंसाने के ऑपरेशन में किया जाता है, कभी-कभी किसी घायल या फंसे हुए जंगली हाथी को बचाने या चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- कुमकी का उपयोग जंगली हाथियों को पकड़ने, शांत करने और चराने के लिए या संघर्ष की स्थिति में जंगली हाथियों को दूर ले जाने के लिए किया जाता है।

113. टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल (THCBD)

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में, वैज्ञानिकों ने कैनबिस-व्युत्पन्न यौगिकों में फाइटोकैनाबिनोइड्स नामक एक संभावित समाधान की खोज की है।
- उन्होंने कैनबिस से कैनबिडिओल निकाला और उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन और पैलेडियम का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से THCBD को संश्लेषित किया।
- यह स्टैफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल (THCBD), एक सेमीसिंथेटिक फाइटोकैनाबिनोइड के एंटीबायोटिक गुणों पर प्रकाश डालता है।
  - यह एक बैक्टीरिया है जो वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी मौतों के लिए जिम्मेदार है।
- हालाँकि, भारत में भांग अनुसंधान से जुड़ी कानूनी बाधाएँ और नियामक चुनौतियाँ बाधाएँ पैदा करती हैं।
- THCBD, अपनी क्षमता के बावजूद, घुलनशीलता चुनौतियों का सामना करता है जिन्हें आगे दवा विकास के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

114. वैक्सीन 'हेविश्योर

- हाल ही में, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) ने हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन 'हेविश्योर' लॉन्च किया।
  - IIL राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह दो खुराक वाला टीका है जिसमें पहली खुराक 12 महीने की उम्र के बाद दी जाती है और दूसरी पहली खुराक के कम से कम छह महीने बाद दी जाती है।

- नियमित टीकाकरण के हिस्से के रूप में बच्चों के साथ-साथ उच्च हेपेटाइटिस A प्रसार वाले क्षेत्रों की यात्रा या जोखिम के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए इसकी सिफारिश की जाती है।
- इसके अलावा व्यावसायिक रूप से संक्रमण के जोखिम वाले और पुरानी जिगर की बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी हेपेटाइटिस A टीकाकरण की आवश्यकता होती है।

115. परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व

- स्थान: केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में पश्चिमी घाट पर्वत का नेलियामपैथी-अनामलाई परिदृश्य।
- रिज़र्व विविध आवास प्रकारों का समर्थन करता है, जैसे सदाबहार, अर्ध-सदाबहार, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और शोला वन।
- अन्य अद्वितीय आवास जैसे पर्वतीय और दलदली घास के मैदान, जिन्हें स्थानीय रूप से 'वायल' के नाम से जाना जाता है, भी पाए जाते हैं।
- फ्लोरा
  - रिजर्व में सागौन, शीशम, चंदन और नीम के पेड़ हैं।
  - इसे दुनिया में सागौन के पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित वृक्षारोपण का श्रेय दिया जाता है।
  - यह दुनिया के सबसे पुराने और ऊंचे सागौन के पेड़ 'कन्नीमारा' का घर है, जो 450 साल पुराना है और 40 मीटर की ऊंचाई पर है।
- जीव-जंतु
  - पाए जाने वाले सामान्य जानवर हैं तेंदुआ, हाथी, गौर, चित्तीदार हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण, सामान्य लंगूर, नीलगिरि लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी, स्लॉथ भालू और जंगली कुत्ता।
  - एकमात्र दक्षिण भारतीय जंगली बकरी, नीलगिरि तहर बाघ अभयारण्य में उच्च ऊंचाई वाली चट्टानी पहाड़ियों और घास के मैदानों पर पाई जाती है।
- टाइगर रिज़र्व टारेंटयुला (बड़े शरीर वाली मकड़ियों) जैसे कई दुर्लभ छोटे जानवरों का भी घर है।

116. अनुच्छेद 341

- राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में
  - जहां यह वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा एक राज्य है
  - उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट करें जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा।
  - उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, जैसा भी मामला हो।
- अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में,
  - और जहां यह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद
  - सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट करें
  - जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्से या समूह जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

117. नवाचार के लिए महामारी की तैयारी का गठबंधन)CEPI)

- यह भविष्य की महामारी को रोकने के लिए टीके विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है।
- इसकी स्थापना नॉर्वे और भारत की सरकारों, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दावोस (स्विट्जरलैंड) में की गई थी।
- लक्ष्य: जब भी उपयुक्त हो, किसी महामारी रोगज़नक़ की पहचान के 100 दिनों के भीतर टीके प्रारंभिक प्राधिकरण और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए तैयार होने चाहिए।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार IndCEPI मिशन 'रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट के माध्यम से भारत केंद्रित महामारी की तैयारी: भारतीय वैक्सीन विकास का समर्थन' को लागू कर रहे हैं।
- इस मिशन के उद्देश्य CEPI के साथ संरेखित हैं और इसका उद्देश्य भारत में महामारी संभावित रोगों के लिए टीकों और संबंधित दक्षताओं/प्रौद्योगिकियों के विकास को मजबूत करना है।

118. एक्सरसाइज साइक्लोन

- भारतीय सेना की टुकड़ी हाल ही में भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंची।
- यह एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण है जो मिस्र के अंशास में आयोजित किया जाएगा।
  - अभ्यास का पहला संस्करण पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था।
- उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत रेगिस्तानी/अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना।
- इसे द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करने और चर्चाओं के संचालन और सामरिक सैन्य अभ्यास के पूर्वाभ्यास के माध्यम से दो सेनाओं के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें उप पारंपरिक डोमेन में विशेष संचालन की योजना और कार्यान्वयन शामिल होगा और तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और मिस्र के दल का प्रतिनिधित्व मिस्र के कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून द्वारा किया जा रहा है।

119. मत्स्य पालन पर FAO की समिति

- भारत को खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन समिति (COFI) की मत्स्य पालन प्रबंधन उप-समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
- यह 1965 में FAO सम्मेलन द्वारा स्थापित खाद्य और कृषि संगठन की एक सहायक संस्था है।
- कार्य
  - अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि मुद्दों को संबोधित करना, मत्स्य पालन प्रबंधन पर नीति मार्गदर्शन की पेशकश करना, वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करना और मछली पकड़ने के उद्योग की पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक समाधान की वकालत करना।
  - FAO परिषद या उसके महानिदेशक को सिफारिशें प्रदान करता है और वैश्विक समझौतों और गैर-बाध्यकारी उपकरणों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - यह परिषद द्वारा संदर्भित मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित विशिष्ट मामलों की भी समीक्षा करता है।
- विशेष रूप से, रोम में मत्स्य पालन पर एफएओ समिति (COFI) के 35वें सत्र के दौरान 2022 में COFI के तहत एक नया उप-समूह, मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप-समिति की स्थापना की गई थी।
- यह उप-समिति जलीय कृषि पर मौजूदा उप-समिति और मछली व्यापार पर उप-समिति के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए तैयार है।

120. फ़िलोबॉट

- हाल ही में, FiloBot नामक एक नया इनोवेटिव प्लांट-प्रेरित रोबोट विकसित किया गया है जो बेलों पर चढ़ने की तरह संरचनाओं पर चढ़ जाता है।
- यह पारंपरिक चढ़ाई वाले रोबोट से अलग है क्योंकि यह पूर्व-क्रमादेशित गतिविधियों पर निर्भर नहीं करता है।
- इसके बजाय यह अपने सिर के माध्यम से 3डी प्रिंटिंग फिलामेंट को अवशोषित करता है और एक लता की तरह समय के साथ इसकी लंबाई बढ़ाता है।
- टीम ने फोटोट्रोपिज्म, नकारात्मक फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म जैसे पौधों के व्यवहार के संयोजन का उपयोग किया और उच्च तकनीक वाले रोबोटों में इन स्वाभाविक रूप से होने वाले व्यवहारों का उपयोग किया।

121. स्क्रब सन्निपात

- तमिलनाडु के वेल्लोर में किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, वर्षा में प्रत्येक मिलीमीटर वृद्धि से मासिक स्क्रब टाइफस में 0.5 से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
- स्क्रब टाइफस एक संक्रामक रोग है जो ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया से होता है।
- यह संक्रमित घुनों के माध्यम से फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।
- लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने शामिल होते हैं।
- गंभीर मामलों में, संक्रमण से श्वसन संबंधी परेशानी, मस्तिष्क और फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की विफलता और बहु-अंग विफलता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मृत्यु हो सकती है।
- वेक्टर बहुतायत, जलवायु कारक, खेती जैसे जोखिम और घरेलू जानवर रखने, बाहरी गतिविधियाँ और स्वच्छता जैसे कई कारक इसकी व्यापकता को प्रभावित करते हैं।
- यह रोग ठंडे महीनों में अधिक फैलता है।
- उपचार: एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किसी भी उम्र के व्यक्ति में किया जा सकता है।
- इस बीमारी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

122. कर्पूरी ठाकुर

- केंद्र ने हाल ही में घोषणा की कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करेगा
- उन्हें लोकप्रिय रूप से "जन नायक" के नाम से जाना जाता था।
- दिसंबर 1970 से जून 1971 तक (सोशलिस्ट पार्टी/भारतीय क्रांति दल) और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक (जनता पार्टी) बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
- भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपना ग्रेजुएट कॉलेज छोड़ दिया।
- उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए।
- वर्ष 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान P&T कर्मचारियों का नेतृत्व किया।
- वर्ष 1970 में, उन्होंने टेल्को मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया।

123. मेलानिस्टिक टाइगर सफारी

- ओडिशा सरकार ने हाल ही में मयूरभंज के जिला मुख्यालय बारीपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना का अनावरण किया।
- उद्देश्य पर्यटकों को विशेष रूप से सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले दुर्लभ और राजसी मेलानिस्टिक बाघों : को देखने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करना।
    - जैसा कि 2018 ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन में बताया गया है, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व विश्व स्तर पर जंगली बाघों के लिए एकमात्र निवास स्थान है।
- NH--18 के किनारे 200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व से लगभग 15 किमी दूर स्थित होगी।
- मेलेनिन की अधिकता के कारण गहरे रंग के कोट वाले मेलेनिस्टिक बाघों को ओडिशा के जंगलों में लगाए गए कैमरों में कैद किया गया है।
- सफारी मेलानिस्टिक बाघों की संरक्षण आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपनी अनूठी जैव विविधता के संरक्षण के लिए ओडिशा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

124. अरामबाई तेंगगोल

- अरामबाई तेंगगोल भारतीय राज्य मणिपुर में एक मैतेई कार्यकर्ता संगठन है, जिसे अक्सर एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में वर्णित किया जाता है।

- शुरुआत में 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में स्थापित, यह एक कट्टरपंथी संगठन में बदल गया है।
- यह एक पुनरुत्थानवादी संगठन भी है जिसका उद्देश्य मेइती लोगों के बीच पूर्वहिंदू-, मूल सनमाही धर्म को फिर से स्थापित करना है।
- इसे मणिपुर के नामधारी राजा और सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा के साथ साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त-है।
- ऐसा संदेह है कि इस समूह ने मई 2023 में शुरू हुई मैतेईकुकी झड़पों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।-

125. भारत रत्न

- यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी।
- यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की/मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है।
- जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है।
- हालांकि आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया जाता है, लेकिन भारत रत्न एक प्राकृतिक नागरिक, मदर टेरेसा और दो गैरभारतीयों-, पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है।
- मूल क़ानून में मरणोपरांत पुरस्कारों का प्रावधान नहीं था लेकिन उन्हें अनुमति देने के लिए 1955 में संशोधन किया गया था।
  - पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने।
- भारत रत्न के लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं और इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।
- किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम तीन तक सीमित है।
- पुरस्कार प्रदान किए जाने पर, प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पदक प्राप्त (प्रमाण पत्र) होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है।

126. बताद्रवा थान

- बोर्डोवा थान के नाम से भी जाना जाने वाला यह असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।
- यह असम के नागांव जिले में स्थित है।
- यह श्रद्धेय वैष्णव सुधारकसंत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान पर एक मंदिर परिसर है।-
- विशेषताएँ
  - यह एक ईंट की दीवार से घिरा हुआ है और इसमें दो प्रवेश द्वार हैं।
  - कीर्तन घर, एक विशाल प्रार्थना घर, शुरू में अस्थायी सामग्रियों का उपयोग करके शंकरदेव द्वारा बनाया गया था।
  - कीर्तन घर से जुड़ा हुआ मणिकुट है, जो पवित्र ग्रंथों, धर्मग्रंथों और पांडुलिपियों को रखने के लिए समर्पित स्थान है।
  - परिसर में नटघर (नाटक हॉल), अलोहिघर अ)तिथि कक्ष(, सभाघर (असेंबली हॉल), राभाघर (संगीत कक्ष), हटीपुखुरी, आकाशी गंगा, डोल मंदिर और अन्य जैसी विविध संरचनाएं शामिल हैं। (उत्सव मंदिर)
- एक बहुत बड़ा त्योहार "दौल महोत्सव" (होलीबोरदोवा में भक्तों के लिए एक वार्षिक आकर्षण है। (

127. रेटबा झील

- रेटबा झील का पानी वस्तुतः जीवन से रहित है और प्रदूषण और खनन के कारण लुप्त होने की कगार पर है।
- इसे लैक रोज़ के नाम से भी जाना जाता है (गुलाबी झील), यह सेनेगल के कैप वर्ट प्रायद्वीप के उत्तर में, डकार (सेनेगल) पूर्व में स्थित है।-के उत्तर
- गुलाबी रंग हेलोफिलिक हरे शैवाल (नमकीन वातावरण में रहने वाले), डुनालीला सलीना के प्रसार के कारण होता है, जिसमें लाल रंगद्रव्य होते हैं।
  - शैवाल हेलोबैक्टीरियम जीनस के हेलोफिलिक बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है।

- नमक के प्रति इस सूक्ष्म शैवाल का प्रतिरोध कैरोटीनॉयड वर्णक की उच्च सांद्रता के कारण होता है, जो इसे प्रकाश और इसकी उच्च ग्लिसरॉल सामग्री से बचाता है।
- दरअसल, डुनालीएला सलीना में कम से कम चार एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट कैरोटीन-बीटा), एस्टैक्सैन्थिन, ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिनहोते हैं (, जो विटामिन और ट्रेस तत्वों से भरपूर होते हैं।
- जब लवणता अधिक होती है, तो लाल रंग वाले शैवाल पनपते हैं, और जब लवणता कम होती है, तो वे हरे रंग वाले अन्य शैवालों को रास्ता दे देते हैं।

128. भारतीय दंड संहिता)IPC) की धारा 420

- IPC की धारा 420, या IPC 420 जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रेरित करने के कृत्य से संबंधित है
  - व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए धोखा दिया है
  - कोई भी चीज़ जो हस्ताक्षरित या सीलबंद हो और मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम हो।
- IPC की धारा 415 धोखाधड़ी के अपराध को परिभाषित करती है।
- सरल शब्दों में, धोखाधड़ी एक बेईमान कार्य है जो इससे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- IPC की धारा 420 धोखाधड़ी का एक गंभीर रूप है जिसमें संपत्ति के साथ-साथ मूल्यवान प्रतिभूतियों की डिलीवरी के मामले में प्रलोभन (किसी को नेतृत्व करना या स्थानांतरित करना) शामिल है।
- यह धारा उन मामलों पर भी लागू होती है जहां संपत्ति का विनाश धोखाधड़ी या प्रलोभन के कारण होता है।
- इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

129. यूरोपीय बंदरगाह एलायंस

- यूरोपीय संघ ने बंदरगाहों पर नशीली दवाओं की तस्करी और आपराधिक समूह की घुसपैठ से निपटने के तरीकों को सुव्यवस्थित करने के लिए "यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन" शुरू किया है।
- इस पहल का उद्घाटन बेल्जियम के एंटवर्प बंदरगाह पर किया गया, जो यूरोप में प्रवेश करने वाले कोकीन के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- इसमें यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों और 16 यूरोपीय संघ के बंदरगाहों और समुद्री परिवहन संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया।
- मुख्य लक्ष्य बंदरगाह गतिविधियों से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग और समन्वय बढ़ाना है।

130. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)

- शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के निष्कर्षों का खुलासा किया है।
- वर्ष 2011 में शुरू किया गया यह वार्षिक सर्वेक्षण पूरे भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को व्यापक रूप से शामिल करता है।
- रिपोर्ट में समग्र नामांकन में पर्याप्त वृद्धि और विभिन्न श्रेणियों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।
- सकल नामांकन अनुपात (GER) में महत्वपूर्ण उछाल आया है, जो शैक्षिक भागीदारी में उत्साहजनक रुझान का संकेत देता है।
- पीएचडी नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो उन्नत शैक्षणिक गतिविधियों में सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।
- स्नातक डिग्रियों का प्रचलन प्रमुख बना हुआ है, जो शैक्षिक परिदृश्य की नींव को दर्शाता है।

- जैसा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में सामाजिक विज्ञान प्रमुख बनकर उभरा है।
- रिपोर्ट STEM विषयों (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में नामांकन के रुझान पर प्रकाश डालती है, जो शैक्षिक परिदृश्य की विकसित गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- सर्वेक्षण में शामिल अतिरिक्त पहलुओं में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सर्वेक्षण किए गए संस्थानों की कुल संख्या और संकाय के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।

131. पद्म पुरस्कार-2024

- भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म पुरस्कार, तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री।
- गणतंत्र दिवस से पहले प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं।
- वर्ष 2024 के लिए, कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 2 युगल मामले भी शामिल हैं जहां पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है।
- सूची में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण के 5 प्राप्तकर्ता, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले 17 प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और पद्म श्री से सम्मानित 110 प्रेरक व्यक्ति शामिल हैं।
- पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं, और भारत में जड़ें रखने वाले 8 अनिवासी या विदेशी पुरस्कार विजेताओं को भी मान्यता दी गई है।
- चयनित पुरस्कार विजेताओं में से नौ को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा।

132. ब्लैक टाइगर सफारी (ओडिशा)

- ओडिशा ने हाल ही में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है, जो सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के बगल में स्थित है।
- प्राथमिक उद्देश्य पर्यटन को बढ़ाना और बेहतर अनुसंधान के अवसर प्रदान करना है, साथ ही दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघों तक सार्वजनिक दृश्य पहुंच को बढ़ाना है, जिन्हें वन क्षेत्रों में देखना चुनौतीपूर्ण है।
- काले बाघ, जिन्हें छद्म-मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है, अनिवार्य रूप से नियमित बंगाल बाघ हैं, जिनमें बढ़े हुए मेलेनिन उत्पादन की विशेषता होती है।
- ये बाघ आमतौर पर बंगाल के बाघों से जुड़े पारंपरिक नारंगी और काले पैटर्न के बजाय गहरे रंग की धारियों का प्रदर्शन करते हैं।
- विशेष रूप से, अद्वितीय काले बाघ वर्तमान में विशेष रूप से ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (STR) में पाए जाते हैं।

133. भूटान चुनाव

- 10 जनवरी को, चुनाव आयोग ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) को भूटान नेशनल असेंबली चुनाव में 47 में से 30 सीटें हासिल करके विजेता घोषित किया।
- देश के लोकतंत्रीकरण के बाद से इस चौथे नेशनल असेंबली चुनाव में भूटान टेंड्रेल पार्टी 17 सीटों के साथ विपक्ष के रूप में उभरी।
- विशेष रूप से, मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, जो दो राउंड के लिए 63% और 65.6% तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2018 में यह 66.36% और 71.46% दर्ज किया गया था।
- भूटान में वर्ष 2008 में पूर्ण राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र के साथ संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन हुआ।
- द्विसदनीय संसद में राष्ट्रीय परिषद (उच्च सदन) और नेशनल असेंबली (निचला सदन) शामिल हैं।

- नेशनल असेंबली चुनाव में दो दौर की मतदान प्रणाली लागू होती है, जिसमें सभी दलों के साथ एक प्राथमिक दौर और शीर्ष दो दावेदारों के बीच एक आम चुनाव शामिल होता है।

134. इकोवास (ECOWAS)

- बुर्किना फासो, माली और नाइजर में सैन्य शासन ने हाल ही में ECOWAS से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा की।
- यह पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र का क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी।
- उद्देश्य: एक समान मुद्रा रखना और उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, वित्तीय मुद्दों और सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों के क्षेत्रों में एक एकल, बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाना।
- आर्थिक सहयोग के लक्ष्यों से परे, ECOWAS ने क्षेत्र में सैन्य संघर्षों को दबाने का प्रयास किया है।
- ECOWAS ने वर्ष 1990 और वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में नाइजीरिया के नेतृत्व में ECOMOG के नाम से जाना जाने वाला एक क्षेत्रीय शांति अभियान भी संचालित किया था।
- सदस्य: बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
  - इन देशों के बीच सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक दोनों संबंध हैं और साझा आर्थिक हित हैं।
- मुख्यालय: अबुजा, नाइजीरिया

135. वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV)

- दिसंबर 2023 में, WHO को अर्जेंटीना में वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV) के एक मानव मामले के बारे में सूचित किया गया था, जो वर्ष 1996 के बाद पहला था।
- तब से इसका प्रकोप बढ़कर 21 पुष्ट मानव मामलों तक पहुंच गया है।
- WEEV एक मच्छर जनित संक्रमण है जो वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (WEEV) के कारण होता है।
- यह वायरस टोगाविरिडे परिवार के वायरस से संबंधित है, जिसमें गंभीर मामलों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण होते हैं और इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- इसमें लगभग 11.5 किलोबेस लंबा सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है।
- यह ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफलाइटिस वायरस (EEEV) और सिंदबिस-जैसे वायरस का पुनः संयोजक है।
- पैसरीन पक्षियों को जलाशय और अश्व प्रजाति को मध्यवर्ती मेजबान माना जाता है।
- एक्सपोज़र में पशु चिकित्सा कार्य, निर्माण और बाहरी गतिविधियाँ शामिल हैं।

136. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE)

- एन्क्रिप्शन डेटा को अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से बचाने का एक तरीका है।
- यह डेटा को एक गुप्त कोड में परिवर्तित करके काम करता है जिसे केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही समझ सकता है।
- यह विभिन्न मामलों के लिए उपयोगी है, जैसे ऑनलाइन संचार सुरक्षित करना, संवेदनशील जानकारी संग्रहीत करना और डिजिटल पहचान सत्यापित करना।
- एन्क्रिप्शन के दो मुख्य प्रकार हैं
  - सिमेट्रिक: यह डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही कुंजी का उपयोग करता है।
  - असिमेट्रिक:यह कुंजी की एक जोड़ी का उपयोग करता है अर्थात एक सार्वजनिक और एक निजी। सार्वजनिक कुंजी को किसी के साथ साझा किया जा सकता है, लेकिन निजी कुंजी को गुप्त रखा जाना चाहिए।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डेटा की सुरक्षा करता है क्योंकि इसे एक स्थान के बीच स्थानांतरित किया जाता है जो कि जहां भी जानकारी का तेजी से आदान-प्रदान होता है वहां महत्वपूर्ण है।
- E2EE-सक्षम ऐप में, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ओर से केवल एक ही व्यक्ति आदान-प्रदान किए गए संदेशों को पढ़ सकता है।

137. सपिंडा विवाह

- HMA की धारा 3(f)(ii) के अनुसार, सपिंडा विवाह में निर्दिष्ट डिग्री के भीतर करीबी रूप से संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- गृह मंत्रालय वंशानुगत लग्न की एक निश्चित सीमा के भीतर सपिंडा विवाह पर रोक लगाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्धारित सीमा के भीतर समान वंश लग्न वाले व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं होते हैं।
- सपिंडा विवाह जो धारा 5(v) का उल्लंघन करते हैं और उन्हें अनुमति देने वाली स्थापित परंपरा का अभाव है, उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाता है।
- इस निषेध का एकमात्र अपवाद तब उत्पन्न होता है जब दोनों पक्षों के रीति-रिवाज सपिंडा विवाह की अनुमति देते हैं, जैसा कि HMA की धारा 3(a) में परिभाषित किया गया है।

138. पूजा स्थल अधिनियम, 1991

- इसे धार्मिक पूजा स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि ये 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे।
- यह किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और उनके धार्मिक चरित्र के रखरखाव को सुनिश्चित करता है।
- धर्मांतरण पर रोक (धारा 3)
  - किसी पूजा स्थल को, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में या एक ही संप्रदाय के भीतर परिवर्तित करने से रोकता है।
- धार्मिक चरित्र का रखरखाव (धारा 4(1))
- यह सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थल की धार्मिक पहचान वही बनी रहे जो 15 अगस्त, 1947 को थी।

139. ग्रांथम शिलालेख

- क्रमशः 11वीं और 16वीं शताब्दी के 'ग्रांथम' और तमिल के दो शिलालेख हाल ही में कंगायम के पास पझनचेरवाज़ी गांव में खोजे गए थे।
- ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लिपि है जिसका उपयोग कभी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और बड़े तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था।
- जब मलयालम भाषा ने शब्दों के साथ-साथ व्याकरण के नियमों को भी संस्कृत से स्वतंत्र रूप से उधार लेना शुरू कर दिया, तो उस भाषा को लिखने के लिए इस लिपि को अपनाया गया और इसे आर्य एज़ुथु के नाम से जाना गया।
- ग्रंथ और तमिल दोनों लिपियाँ आधुनिक रूपों में एक जैसी दिखाई देती हैं। ब्राह्मी से प्राप्त दोनों लिपियों का विकास भी कमोबेश एक जैसा था।
- तमिलनाडु में ग्रंथ लिपि के विकास को चार अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् पुरातन और सजावटी (आमतौर पर पल्लव ग्रंथ के रूप में जाना जाता है), संक्रमणकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक शामिल हैं।

140. हम्बोल्ट एनिग्मा

- यह शब्द इस पहेली का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्यों कुछ पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता है।
- यह 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है, जिन्होंने तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता और जैव विविधता के बीच संबंधों का पता लगाया था।
- यह पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है कि सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र तराई के उष्णकटिबंधीय वन हैं।
- उष्ण कटिबंध से दूर विविधता कम हो जाती है, लेकिन पहाड़ एक महत्वपूर्ण अपवाद रहे हैं जो हम्बोल्ट की पहेली का सार है।
- पहाड़ों पर जैव विविधता को चलाने वाले कारक जलवायु, भूविज्ञान और विकासवादी प्रक्रियाएं हैं।
- पूर्वी हिमालय को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है जहां जलवायु असमानता और विविध भूवैज्ञानिक संरचना उच्च जैव विविधता में योगदान करती है।

141. नाइट्रोजन हाइपोक्सिया

- हाइपोक्सिया शरीर में अपर्याप्त ऑक्सीजन की स्थिति के लिए एक चिकित्सा शब्द है।
- नाइट्रोजन हाइपोक्सिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस, या इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस जो कि घातक हो, श्वास के साथ अंदर ले ली जाती है जिससे दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- यह घातक इंजेक्शन और बिजली के झटके जैसी मृत्युदंड के अधिक सामान्य रूपों का अपेक्षाकृत नया विकल्प है।
- फांसी की इस पद्धति में, कैदी के चेहरे पर एक श्वासयंत्र मास्क लगाया जाता है, और ऑक्सीजन के बजाय शुद्ध नाइट्रोजन को व्यक्ति के फेफड़ों में पंप किया जाता है।
- इससे बेहोशी आ जाती है और फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है।
- हाल ही में, अलबामा ने नाइट्रोजन हाइपोक्सिया नामक एक नई विधि का उपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को सफलतापूर्वक मार डाला, जिसने कई दशकों तक मौत की सजा का सामना किया था।

142. अल्पेंग्लो

- यह एक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य के उदय या अस्त होने पर पर्वतीय ढलानें सूर्य से प्रकाशित होती हैं।
- सूर्य के कोण और वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर ढलानें गुलाबी, लाल या नारंगी रंग में बदल जाती हैं।
  - ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों (प्रकाश) की सबसे लंबी गर्म किरणें हैं जो विभिन्न सतहों तक पहुंचती हैं।
  - ठंडी किरणें छोटी होती हैं और वायुमंडल में तेजी से गायब हो जाती हैं।
- यह सूर्यास्त से पहले या बाद में गोधूलि घंटों के दौरान होता है और सूरज उगने या डूबने के बाद पहले मिनटों में भी हो सकता है।
- किसी भी दिन सूरज कितनी तेजी से डूबता है, इसके आधार पर यह तेजी से बदल सकता है।

143. सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व

- यह अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित 17 वर्ग किलोमीटर का जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जैसे कि पसेरिन पक्षी बुगुन लिओसिचला (लियोसिचलाबुगुनोरम), जिसका नाम बुगुन्स समुदाय के नाम पर रखा गया है।
- यह 1947 में देश की आजादी के बाद भारत में खोजी जाने वाली पहली पक्षी प्रजातियों में से एक थी, और यह केवल बुगुन्स समुदाय की भूमि पर रहती है।
- बुगुन लगभग 2,000 लोगों की आबादी वाला एक स्वदेशी समुदाय है, जो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों के बाहर स्थित 12 गांवों में फैला हुआ है।

144. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

- ICJ, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में काम शुरू हुआ।
- यह एक रजिस्ट्री, इसके स्थायी प्रशासनिक सचिवालय द्वारा समर्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।
- ICJ की सभी सुनवाईयाँ सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाती हैं। न्यायालय की आधिकारिक भाषाएँ फ्रेंच और अंग्रेजी हैं।
- ICJ दो मुख्य कार्य करता है।
  - विवादास्पद मामले: यह दो सदस्य देशों के बीच विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है, जो भूमि सीमाओं, समुद्री सीमाओं, क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनयिक संबंधों आदि जैसे कई मुद्दों को संबोधित करता है।
  - सलाहकार राय: यह संयुक्त राष्ट्र निकायों या विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान कर सकता है, जो सदस्य राज्यों के संबंध में वैध कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने या प्राधिकरण को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

- विवादास्पद मामलों में अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और मामले के पक्षों पर अपील के बिना बाध्यकारी होते हैं।
- संघटन
  - इसमें विभिन्न देशों के 15 न्यायाधीश शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में बहुमत से नौ साल के लिए चुना जाता है।
    - हर तीन साल में एक तिहाई न्यायाधीश चुने जाते हैं।
  - ICJ क़ानून किसी मामले में शामिल राज्य पक्ष को उस विशिष्ट मामले के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसमें उसकी राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश नहीं है।

145. शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद

- ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी वर्ष 1618 में उसी परिसर में एक मंदिर बनवाया था और वर्ष 1670 में औरंगजेब ने पहले के मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाई थी।
- माना जाता है कि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का निर्माण लगभग 2,000 साल पहले, पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था।
- हिंदू प्रतिनिधियों द्वारा उस परिसर के पूर्ण स्वामित्व की मांग के कारण एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है जहां वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया गया था।
- इस क्षेत्र को पहले मराठों और फिर अंग्रेजों के स्वामित्व वाली नजूल भूमि, गैर-कृषि राज्य भूमि माना जाता था।
- यह मंदिर मूल रूप से 1618 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसका संरक्षण औरंगजेब के भाई और प्रतिद्वंद्वी दारा शुकोह ने किया था।
- वर्ष 1815 में, बनारस के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 13.77 एकड़ जमीन खरीदी।
- बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई

146. नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)

- NCIIPC एक सरकारी संगठन है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (CII) की सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है।
- NCIIPC का मिशन महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, अक्षमता या विनाश से बचाना है।
- यह साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध और अन्य खतरों से महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को कम करने के लिए सलाह भी प्रदान करता है।
- NCIIPC CII को कंप्यूटर संसाधनों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कमजोर प्रभाव पड़ेगा।

147. स्नो लेपर्ड

- अपनी तरह के पहले चार साल के आकलन अभ्यास के अनुसार, भारत में जंगली में अनुमानित 718 हिम तेंदुए हैं।
- बिल्लियों की अधिकतम संख्या लद्दाख (477) में होने का अनुमान है, इसके बाद उत्तराखंड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21), और जम्मू और कश्मीर (9) हैं।
- भारत में स्नो लेपर्ड की जनसंख्या आकलन (SPAI) 2019 में शुरू हुआ।
- इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूरु के साथ-साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) शामिल हैं।
- स्नो लेपर्ड मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- भारत में यह जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है।
- हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए की अच्छी उपस्थिति है।

- वे एक शीर्ष शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनके उच्च-ऊंचाई वाले निवास स्थान के स्वास्थ्य और पर्वतीय वातावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेतक है।
- खतरे: स्वतंत्र कुत्ते, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार।
- संरक्षण की स्थिति
  - IUCN लाल सूची: असुरक्षित
  - उद्धरण: परिशिष्ट।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची।

148. अगस्त्यगमा किनारा

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के जैव विविधता वाले जंगलों में छोटी छिपकलियों की एक नई प्रजाति की खोज की, और उन्हें "छोटा ड्रैगन" बताया।
- अगस्त्यगामा एज या उत्तरी कंगारू छिपकली नाम की छिपकली, अगामिडी परिवार से संबंधित है।
  - बेडडोमी या भारतीय कंगारू छिपकली के बाद यह अगस्त्यगामा जीनस का दूसरा प्रजाति है, जो पहले तमिलनाडु में शिवगिरी पहाड़ियों से रिपोर्ट किया गया था।
- यह इडुक्की के कुलमावु में दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
- विशेषताएँ
  - अधिकतम थूथन-वेंट लंबाई 4.3 सेमी।
  - पर्वतारोहियों में कमजोरी के कारण पैर की पांचवीं उंगली कम हो जाती है, जिससे वे स्थलीय बन जाते हैं
  - छोटे कीड़ों को खाता है, तेज़ दौड़ता है, और शिकारियों से बचने के लिए सूखी पत्तियों के भीतर छिप जाता है।
  - सघन पत्ती कूड़े वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - थोड़ा गहरा सिर के साथ एक समान सुस्त जैतून-भूरे रंग का शरीर।
  - सफ़ेद गला जिसके ओसलेप पर एक चौड़ी गहरे भूरे रंग की धारी और बाहर की तरफ ईंट की पीली शल्कें हैं।

149. माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफ़ेक्टर F (MceF)

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफ़ेक्टर F (MceF) नामक एक पूर्व अज्ञात प्रोटीन की खोज की।
- यह एक जीवाणु प्रोटीन है जो मानव कोशिकाओं को तब भी स्वस्थ रखने में सक्षम है, जब कोशिकाओं पर बैक्टीरिया का भारी बोझ हो।
- यह कॉक्सिएला बर्नेटी, एक ग्राम-नेगेटिव इंट्रासेल्युलर जीवाणु द्वारा निर्मित होता है।
- मेजबान कोशिकाओं पर आक्रमण करने के बाद, कॉक्सिएला बर्नेटी कोशिकाओं में MceF छोड़ता है।
- MceF एक एंटी-ऑक्सीकरण प्रभाव को बढ़ावा देकर माइटोकॉन्ड्रियल फ़ंक्शन को बेहतर बनाने के लिए ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज 4 (GPX4) के साथ इंटरैक्ट करता है जो कोशिका क्षति और मृत्यु को रोकता है।
  - GPX4 माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है।

150. एक्सरसाइज -सदा तनसीक

- हाल ही में, भारत और सऊदी अरब की सेनाएं राजस्थान के महाजन में सदा तनसीक नाम से अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही हैं।
- उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना।
- यह दोनों पक्षों को उप-पारंपरिक डोमेन में संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा।
- इससे दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच अंतरसंचालनीयता, सौहार्द्र और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।

- इसमें मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना, घेरा और तलाशी अभियान, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग, स्लिथरिंग और स्नाइपर फायरिंग शामिल होगी।

GEO IAS It's about quality

+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005

info@geoias.com

www.geoias.com

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com